राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 142

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 31 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

क्रिकेट मैच के आयोजन से बड़ा मुद्दा है प्रदूषण

>>2

एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना साकार

ऐतिहासिक क्षण ▶ देश के नक्शे पर दिखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश, जीसी मुर्मू श्रीनगर तो आरके माथुर लद्दाख में लेंगे उपराज्यपाल की शपथ

जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और कानून पूरी तरह निष्प्रभावी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

31 अक्टूबर गुरुवार की सुबह उम्मीदों का नया सूरज लेकर आएगी और 70 वर्षों की लंबी जद्दोजहद के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना साकार होगा। जम्मू-कश्मीर राज्य अतीत का हिस्सा बन जाएगा और दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के नक्शे पर उभर आएंगे। दोनों ही जगह अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जिसकी कमान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल संभालेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर श्रीनगर स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे, जबकि राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में लेह में शपथ लेंगे। लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित

जीसी मुर्मू

आरके माथुर (फाइल)

राज्य होगा, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल सुबह लेह में आरके माथुर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और उसके बाद वह विशेष विमान में श्रीनगर पहुंचेगी और यहां जीसी मुर्मू को शपथ दिलाएंगी। जीसी मुर्मू बुधवार को श्रीनगर पहुंच गए।

समारोह की पूरी तैयारी : पूर्व रक्षा सचिव माथुर सुबह 7.45 बजे लेह स्थित सिंधु संस्कृति केंद्र में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह सुबह 7.30 बजे शुरू होगा। इसकी तैयारियों की देखरेख कर रहे कमिश्नर सचिव लद्दाख रिगजिन सम्पेल ने बताया कि सभी प्रबंध हो गए हैं। वहीं श्रीनगर में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जीसी मुर्मू को सुबह पौने बारह बजे शपथ दिलाने का कार्यक्रम है। मुख्य न्यायाशीध गीता मित्तल को लेह से आना है। अगर उनके पहुंचने में देरी होती है तो शपथ ग्रहण पौने एक बजे होगा। समारोह में निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मौजूदगी की कोई सूचना नहीं है। उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना क्षेत्र के अस्तित्व से जुड़ा अहम मसला था। ऐसा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर दिया है। हमें कश्मीर केंद्रित सरकारों के भेदभाव से आजादी मिल गई है। अब क्षेत्र में तेज विकास का इतिहास रचा जाएगा।

-जामियांग सेरिंग नामग्याल
सांसद, भाजपा

जम्मू-कश्मीर गुरुवार से नया केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इसके मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर में बाजार में तैनात सुरक्षाकर्मी। प्रेट्र

समारोह में कोई केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा : दोनों ही जगह शपथ ग्रहण समारोह में फिलहाल किसी भी केंद्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री के आगमन की सूचना नहीं है। पीएमओ में राज्यमंत्री व जम्मू संभाग के डोडा-कठुआ संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह भी किसी समारोह में शामिल नहीं होंगे। वह 31 अक्टूबर को दिल्ली में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टेचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एक समारोह में भाग लेंगे, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरि झंडी दिखाएंगे।

नरूला बने माथुर के सलाहकार, खंडारे लद्दाख के पुलिस प्रमुख : केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नौकरशाह और राज्य के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रधान सचिव उमंग नरूला को केंद्र शासित लद्दाख के पहले उपराज्यपाल आरके माथुर का सलाहकार नियुक्त किया है। नरूला 1965 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वह जम्मू प्रांत के मंडलायुक्त भी रह चुके हैं। लद्दाख में पुलिस प्रशासन की कमान 1995 बैच के आइपीएस एसएस खंडारे को सौंपी गई है। दोनों अधिकारी 31 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे।

इसलिए चुना गया 31 अक्टूबर का दिन

6 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर दो अलग-अलग केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर व लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएगा। केंद्र सरकार ने देश के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को 31 अक्टूबर को प्रभावी बनाने का फैसला किया है। पटेल ने भारत-पाक विभाजन के बाद विभिन्न रियासतों के भारत में विलय में अहम भूमिका निभाई थी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था नारा : भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक विधान और एक निशान का नारा दिया था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी।

महिलाओं का बढ़ेगा विश्वास

अनुच्छेद 370 व 35 ए के खत्म होने तथा जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से महिलाओं में भी विश्वास जगा है। पहले जो महिला दूसरे राज्य में शादी करती थी तो शादी के बाद उसके यहां के सभी अधिकार समाप्त हो जाते थे। अब यहां की महिलाएं पूरी तरह से अपने आपको सुरक्षित मान रही हैं और उन्हें काफी खुशी भी है। तीन तलाक का डर भी अब समाप्त हो जाएगा क्योंकि जो पूरे देश में तीन तलाक का कानून बना है अब वह जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा।

विशेष पेज-5

सरोकार

इस सरकारी स्कूल की सभी छात्राएं 'भारतीय'

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित शासकीय आदर्श कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्राओं का एक ही सरनेम होता है- 'भारतीय'। देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को ये बालिकाएं निराले तरीके से परिभाषित कर रही हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

कड़ा हुआ कानून तो झारखंड में धर्म नहीं बदल रहे लोग

रांची : झारखंड सरकार द्वारा फरवरी में धर्मांतरण कानून (झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017) लागू कर देने के बाद राज्य में धर्मांतरण अप्रत्याशित रूप से थम गया है। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, कोडरमा सहित अन्य प्रमुख जिलों में की गई पड़ताल पर आधारित रिपोर्ट। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

भारत-सऊदी अरब के बीच सुरक्षा संबंधों की नई शुरुआत

नई दिल्ली : सऊदी अरब और भारत के बीच सुरक्षा संबंधों की नई शुरुआत हुई है। बढ़ते सुरक्षा सहयोग की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत-ऊदी अरब के बीच हुए 12 समझौतों में से तीन सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

सोने के रूप में रखा कालाधन वैध बनाने का मौका देगी सरकार

नई दिल्ली : सोने के रूप में रखे कालेधन को रिकवर करने के लिए सरकार गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में है। नई योजना के तहत अघोषित सोने की जानकारी और उस पर टैक्स देकर इसे वैध सोने में बदला जा सकेगा।

अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मसला

यूरोपीय संघ के सांसदों ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार की हवा निकाली

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर के जमीनी हालात का जायजा लेने आए यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसदों ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार की हवा निकाल दी। सांसदों ने साफ कहा, अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। हमारा भारत की अंदरूनी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कश्मीर को दूसरा सीरिया व अफगानिस्तान न बनने देने की संकल्पबद्धता दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा साथ दिया जाएगा। हमने पाया कि यहां (कश्मीर) आतंकी हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका है।

ज्ञात हो, ईयू सांसदों का 23 सदस्यीय दल दो दिनी दौरे पर गत मंगलवार को श्रीनगर पहुंचा था। बुधवार को मीडिया से बातचीत में इन सांसदों ने न सिर्फ कश्मीर के हालात पर बेबाक राय रखी बल्कि अपने ऊपर लगे आरोपों को भी नकारा। पाक के संबंध में कहा, वहां ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक नहीं है। उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। कश्मीर में आम लोगों के साथ बातचीत में पाया कि यहां भी आतंकी हिंसा में पाक की भूमिका है। अधिकारियों और विभिन्न संगठनों से चर्चा

श्रीनगर में बुधवार को ईयू के सांसद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए। (वीडियो ग्रैब)। प्रेट्र

के दौरान भी कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकियों की फंडिंग में पाकिस्तान का हाथ होने के कई सुबूत दिखाए गए।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ : यूरोपीय संघ में फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाले हेनरी ने कहा, अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मसला है। इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा और चिंता का विषय आतंकवाद है। भारत इससे लड़ रहा है और इस लड़ाई में हम उसके साथ हैं। हम कुलगाम में पांच श्रमिकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। हम लोगों ने यहां सेना, पुलिस और कश्मीर की युवा पीढ़ी से बातचीत करते हुए शांति बहाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

यहां के लोग शांति और विकास चाहते हैं : ब्रिटेन से संबंधित न्यूटन डन ने कहा, यहां लोग आतंकवाद से पूरी तरह तंग हैं। वह शांति और विकास चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। हम भारत को दुनिया का सबसे शांत राष्ट्र देखना चाहते हैं और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम उसके साथ हैं। हमने यहां जो देखा और महसूस किया है, दुनिया में जहां भी मौका मिलेगा, उस पर बात करेंगे।

भारत सरकार सही दिशा में काम कर रही : जर्मनी के लार्स पेट्रिक बर्ग ने कहा, यह यूरोपीय संघ का आधिकारिक दौरा नहीं है। हम चाहते थे कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसकी सच्चाई को जाना जाए। यहां हालात सामान्य बनाने के लिए भारत सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हम यहां कश्मीरियों के मित्र बनकर आए हैं।

कश्मीर में आतंकवाद नहीं चाहते : फ्रांस के थेरी मैरानी ने सीरिया में अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि मैने देखा है कि किस तरह आतंकवाद किसी राज्य, क्षेत्र और समाज को बरबाद करता है। पिछले माह मैं सीरिया में ही था, वहां आतंकवाद से हुई तबाही को देखा है। हम नहीं चाहते कि कश्मीर का भी यही हाल हो। कश्मीर को दूसरा सीरिया और अफगानिस्तान नहीं बनने दे सकते।

दौरे को लेकर विवाद अनावश्यक पेज>>6

यह भी बोले

- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा साथ देंगे यूरोपीय देश
- कश्मीर को दूसरा सीरिया व अफगानिस्तान कतई नहीं बनने देंगे
- कश्मीर में आतंकी हिंसा में पड़ोसी मुल्क की भूमिका, दहशतगर्दों को वित्त मुहैया कराने में भी पाकिस्तान का हाथ

अयोध्या का मामला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक : जस्टिस बोबडे

नई दिल्ली, जेएनएन

भारत के नामित मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि अयोध्या का मामला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। सोशल मीडिया पर जजों के कामकाज की आलोचना पर अफसोस जताते हुए कहा, अधिकांश जज जिनकी चमड़ी मोटी नहीं है, वह इससे क्षुब्ध हो जाते हैं। फैसले की आलोचना के बजाय जज की आलोचना से मानहानि का मामला बनता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट सुस्त पड़ चुके संवैधानिक मामलों से निपटने के लिए पांच जजों की स्थायी संवैधानिक पीठ बना सकती है।

18 नवंबर को 47वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस बोबडे ने बुधवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि अयोध्या मामला निश्चित रूप से अहम है। बोबडे भी इस मामले की संविधान पीठ का हिस्सा हैं। इस मामले में फैसला 17 नवंबर से पहले आना है। चूंकि इसी दिन मौजूदा सीजेआइ रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस बोबडे 17 महीनों के लिए सीजेआइ के पद पर रहेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति 23 अप्रैल, 2021 को होनी है।

शरद अरविंद बोबडे फाइल

नामित सीजेआइ ने जजों के कामकाज की आलोचना पर अफसोस जताया

63 वर्षीय बोबडे ने कोलेजियम में उच्च न्यायालयों के लिए जजों के चयन की मंत्रणा को सार्वजनिक नहीं करने का पक्ष लेते हुए कहा, यह कोई बात गुप्त रखने का मामला नहीं है, बल्कि निजता के लिहाज से निजी रखने का विषय है। किसी की नकारात्मक बातें बेवजह सबके सामने क्यों लाई जाएं। जनता की कुछ जानने की इच्छा को पूरा करने के लिए लोगों की साख को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। कोलेजियम में विचार किए गए उन नामों को सामने लाया जा सकता है, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन वह नाम नहीं जिन्हें खारिज किया गया। उन्हें रिजेक्ट करने के कारण भी सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। ज्ञात हो, 2017 में तत्कालीन सीजेआइ दीपक मिश्रा ने कोलेजियम की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डालने का निर्णय लिया था।

राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले से पहले संघ परिवार में मंथन तेज

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

- दिल्ली में तीन दिवसीय विशेष बैठक शुरू, भागवत और अमित शाह हुए शामिल

सुप्रीम कोर्ट से अगले माह राम मंदिर पर फैसला आने से पहले संघ परिवार में मंथन तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में तीन दिनी विशेष बैठक बुधवार को शुरू हुई। इस बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ट्वीट कर कहा है कि श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी आए उसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, यह सबका दायित्व है।

दिल्ली के छतरपुर के ध्यान साधना केंद्र में बैठक के पहले दिन बुधवार को आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। सर संघचालक मोहन भागवत व सरकार्यवाह भैय्या जी जोशी की विशेष मौजूदगी के अलावा सभी सह सरकार्यवाह और क्षेत्रीय प्रचारकों को भी विशेष रूप से बुलाया गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। पहले यह बैठक 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हरिद्वार में होनी थी, जो किन्हीं कारणों से निरस्त हो गई।

संघ के एक पदाधिकारी ने कहा, अयोध्या पर कोर्ट के फैसले को लेकर यह आपात बैठक हो रही है। इसमें सभी संभावित फैसलों के साथ उसके विकल्पों पर भी विचार-विमर्श हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, संघ फैसला पक्ष में आने को लेकर आश्वस्त है। कोई पेच फंसने की स्थिति में आगे की रणनीति क्या हो सकती है? किस तरह राम भक्तों को संतुष्ट किया जा सकता है? इन सब सवालों का हल तलाशा जा रहा है।

जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार : फड़नवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- फिर चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता, मोदी-शाह के साथ उद्धव का भी जताया आभार
- कई भाजपा नेताओं ने माना, शिवसेना के साथ जारी है सरकार बनाने की अनौपचारिक बातचीत

सहयोगी दल शिवसेना के तमाम नखरों और 'विकल्प खुले रहने' की धमकियों के बीच पुनः भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फड़नवीस ने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में 'महागठबंधन' की सरकार बनेगी और पूरे पांच साल चलेगी। फड़नवीस के विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही भाजपा ने शिवसेना के साथ अनौपचारिक वार्ता का दौर तेज कर दिया है। कई भाजपा नेताओं ने स्वीकार किया कि शिवसेना से सरकार बनाने की अनौपचारिक बातचीत जारी है।

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फड़नवीस ने अब तक मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ-साथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का भी आभार व्यक्त किया। फड़नवीस ने कहा, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने जनादेश महागठबंधन के पक्ष में दिया है इसलिए बहुत जल्द महागठबंधन राज्य में सरकार बनाने जा रहा है। शिवसेना द्वारा 'विकल्प खुले रहने' की बात पर उन्होंने कहा, 'वैकल्पिक सरकार' की भी अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन यह मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं है। फड़नवीस के अनुसार, 1995 के बाद से किसी भी दल को 75 से ज्यादा सीटें नहीं मिली थीं, लेकिन भाजपा को पिछले चुनाव में 122 और इस बार 105 सीटें मिली हैं। माना जा रहा है कि भाजपा शिवसेना को उपमुख्यमंत्री पद के साथ उसके संख्या बल के अनुसार, पिछली सरकार के बराबर मंत्री पद देने पर राजी हो जाएगी। गृह, नगर विकास, राजस्व और सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय पर शिवसेना के साथ कोई समझौता होने की गुंजाइश कम है।

मुंबई में बुधवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडनवीस (मध्य में) को बधाई देते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर (दाएं से दूसरे)। साथ में मौजूद महासचिव भूपेंद्र यादव (दाएं) भाजपा की राज्य प्रभारी सरोज पांडे (बाएं)। प्रेट्र

इससे पहले भाजपा ने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पूर्ण की। सभी विधायक सिर पर भगवा साफा बांधकर विधान भवन में आयोजित बैठक में पहुंचे। वे 'जय शिवाजी' और 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर व अविनाश राय खन्ना भी उपस्थित थे।

शिवसेना विधायक आज चुनेंगे नेता : शिवसेना के विधायक गुरुवार को मध्य मुंबई स्थित सेना भवन में अपना नेता चुनेंगे। इस बीच, दो निर्दलीय विधायकों मंजुला गावित और चंद्रकांत निंबा पाटिल ने उद्धव ठाकरे से भेंट के बाद शिवसेना को समर्थन की घोषणा की। छह निर्दलीय विधायक पहले ही भाजपा को समर्थन दे चुके हैं। ये भाजपा के ही बागी नेता हैं।

संजय राउत बोले, शिवसेना का भाजपा गठबंधन में रहना जरूरी पेज>>4

हाल-बेहाल

गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, 14 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में आठ शहर उत्तर प्रदेश के रहे, दिल्ली एनसीआर में धुंध के साथ ही वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा

उत्तर भारत में और जहरीली हुई हवा

जेएनएन, नई दिल्ली

दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में हवा और जहरीली हो गई है। बुधवार को भी दिन में वायु प्रदूषण के चलते दृश्यता कम रही। दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा में भी खासा इजाफा देखने को मिला। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 400 के अंक पर था। बुधवार को इसमें 19 बिंदुओं का इजाफा हुआ और यह 419 हो गया। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। शाम चार बजे हवा में पीएम 10 की मात्रा 451 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 की मात्रा 273 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मानकों के अनुसार, हवा में पीएम 10 की मात्रा 100 और पीएम 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण हरियाणा और पंजाब में जलाई गई पराली को बताया जा रहा है।

गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। देश के 14 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में आठ शहर उत्तर प्रदेश के रहे। लखनऊ की हवा में भी प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। लखनऊ में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स बढ़कर 326 के स्तर में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन भी देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। यहां एक्यूआइ 478 के स्तर में दर्ज किया गया। बागपत 461 और नोएडा में 450 रिकार्ड हुआ। उधर, हरियाणा स्थित पानीपत अचानक प्रदूषण के स्तर में चार सौ का आंकड़ा पार करते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया। देश के 12 शहर एक्यूआइ में 400 से आगे रहे।

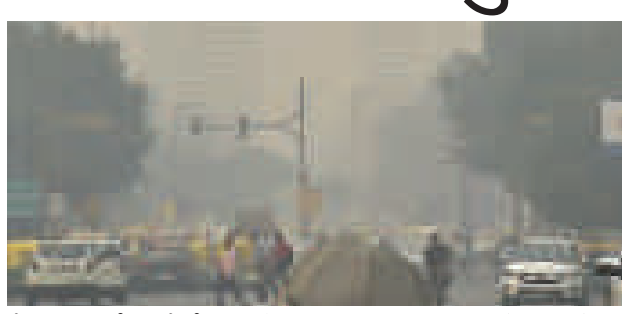

धुंध में दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में धुंध और धुएं की मोटी परत छाई हुई है। यह दृश्य बाराखंबा रोड पर बुधवार को दोपहर 1.10 बजे का है। संजय

अरब सागर के ऊपर बने सुपर साइक्लोन का है असर : मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि अरब सागर के ऊपर बने सुपर साइक्लोन का असर उत्तराखंड सहित पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छायी धुंध के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार दीपावली के दिन से समूचे उत्तर भारत में जो धुंध छायी हुई है उसके अन्य कारकों में पटाखों से फैले प्रदूषण भी है। उत्तराखंड में एक माह से बारिश नहीं होने से भी धूल के कणों के अधिक ऊंचाई तक पहुंचने से धुंध अधिक दिखाई दे रही है।

शहरों का एयर इंडेक्स

शहर	एयर इंडेक्स
फरीदाबाद	404
गाजियाबाद	478
नोएडा	450
ग्रेटर नोएडा	438
गुरुग्राम	365

इंडेक्स का स्तर और श्रेणी

0 से 50	अच्छा
50 से 100	संतोषप्रद
100 से 200	सामान्य
200 से 300	खराब
300 से 400	बहुत खराब
400 से ऊपर	गंभीर / आपातकालीन

फिर रद हुई पिथौरागढ़ की फ्लाइट

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ की फ्लाइट बुधवार को फिर रद कर दी गई। पिथौरागढ़ में बेहद कम दृश्यता के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया। मंगलवार को भी हिंडन से पिथौरागढ़ के लिए उड़े विमान को देहरादून में लैंड कराया गया था।

गो तस्करी मामला : पहलू खान समेत चार के खिलाफ दर्ज केस होगा रद

जागरण संवाददाता, जयपुर

- राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए आदेश, कहा- मामला साबित नहीं हुआ
- पहलू के दोनों बेटों और ट्रक चालक की ओर से दायर की गई थी याचिका

देश के चर्चित पहलू खान गो तस्करी मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्मादी हिंसा (मॉब लिंचिंग) में मारे गए पहलू खान, उसके दोनों बेटों इरशाद और आरिफ के साथ ही ट्रक चालक खान मोहम्मद के खिलाफ पुलिस में दर्ज एफआइआर रद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस चारों के खिलाफ गो तस्करी का मामला साबित नहीं कर सकी है।

पहलू खान, उसके दोनों बेटों और खान मोहम्मद के खिलाफ पुलिस ने गो तस्करी को लेकर अप्रैल 2017 में एफआइआर दर्ज की थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी ने एफआइआर रद करने के आदेश दिए। एफआइआर रद करने को लेकर इरशाद, आरिफ और खान मोहम्मद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि पहलू खान, उसके दोनों बेटों और ट्रक चालक के पास से बरामद की गई गायें दुधारू थीं। इन गायों के साथ दो बछड़े भी थे। पहलू खान के पास जयपुर के पशु हटवाड़ा से गाय खरीदने की रसीद (रवन्ना) भी थी। इन गायों को हरियाणा के नूंह स्थित डेयरी में ले जाने के प्रमाण भी मिले हैं।

पुलिस चारों पर गो तस्करी का मामला साबित नहीं कर सकी है। पहलू खान की मौत होने के कारण उसके खिलाफ तो मामला स्वतःही समाप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था।

क्या है मामला पेज>>7

30.8 डिग्री सेल्सियस रहा बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले दो दिन स्मॉग, प्रदूषण और हवा की धीमी गति के चलते गर्मी महसूस होगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 31 अक्टूबर 2019

चिंताजनक ▸ 419 रिकॉर्ड किया गया दिल्ली का एयर इंडेक्स, सीपीसीबी ने लिया निर्णय

निर्माण कार्यों पर शनिवार तक रहेगी रोक

पीएम 10 एवं पीएम 2.5 की मात्रा में भी दर्ज की गई वृद्धि

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा में भी खासा इजाफा देखने को मिला। मंगलवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 400 के अंक पर था। बुधवार को यह 419 हो गया। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सप्ताह भर पूर्व लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को दो नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब निर्माण कार्य एवं कोयला आधारित उद्योग शनिवार तक बंद रहेंगे। पहले यह प्रतिबंध शाम छह से सुबह छह बजे तक था। अब इसे शाम छह से सुबह 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी संस्था सफर के मुताबिक पराली के धुएं ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों का दम घोंटना शुरू कर दिया है। वातावरण में दिवाली के पटाखों का धुआं तो पहले से ही मौजूद था, पराली के धुएं ने स्थिति को और बदतर कर दिया है। सफर के मुताबिक बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 35 फीसद तक हो गई, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। हालांकि गुरुवार को इसमें कुछ कमी आने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में थोड़ी कमी आई है। पहले जहां पराली जलाने की 2577 घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं अब यह 1057 रह गई हैं। इससे उम्मीद है कि पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण में गुरुवार को थोड़ी कमी आएगी। वैसे कमी के बावजूद इसके 27 फीसद के लगभग रहने की संभावना है।

दिवाली के बाद से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के पांच सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों का चयन किया है। सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में वजीरपुर, आनंद विहार, अशोक विहार, विवेक विहार और बवाना क्षेत्र हैं।

पराली न जलाएं किसान, दें बेहतर सुविधाएं : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पड़ोसी राज्यों में जलाए जा रहे पराली को लेकर केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्लीवासियों की ओर से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार से विनती कर रहे हैं कि वे अपने किसानों को सुविधाएं मुहैया कराएं ताकि उनको फसलें जलाने की जरूरत न पड़े। दिल्ली के लोग और हमारी सरकार अपनी तरफ से जो भी कर सकती है, वह किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ से धुआं पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से है। मैं भाजपा से अपील करता हूं कि हरियाणा सरकार पर दबाव बनाएं जिससे वे किसानों को पराली नष्ट करने की तकनीक मुहैया कराएं। मैं कांग्रेस पार्टी से भी अपील करता हूं कि वह पंजाब सरकार को कहकर वहां के किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया कराएं। मेरे अपने स्तर पर हरियाणा और पंजाब में कई लोगों से बातचीत हुई, किसानों से भी बातचीत हुई, किसान बिल्कुल तैयार हैं। किसानों का मानना है कि अगर उन्हें कोई ऐसी तकनीक उपलब्ध कराई जाए जिससे कि पराली को काट सकें और दो पैसे कमा सकें, तो वह पैसे ही कमाना चाहेंगे, न कि पराली जलाना चाहेंगे। कहीं कमी सरकारों की तरफ से ही नजर आ रही है।

लेजर शो से कम जले पटाखे : मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली पर कनॉट प्लेस में चार दिन का लेजर शो हिट रहा है। हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। लेजर शो में दिखाया गया कि सब लोग एकजुट होकर दिवाली मनाते हैं और 14 साल के वनवास के बाद जब श्री राम घर वापस आए तो उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मैं उपराज्यपाल का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी वजह से यह कार्यक्रम इतना कामयाब हो सका। मेरा यह मानना है कि अगर लेजर शो का आयोजन न होता तो लोग 30 से 40 फीसद और अधिक मात्रा में पटाखे जलाते।

एक नवंबर को स्कूलों में मास्क बांटने का शुभारंभ करेंगे : केजरीवाल ने कहा कि एक नवंबर को स्कूलों में मास्क बांटने का शुभारंभ करेंगे। एक हफ्ते तक स्कूलों के जरिये हम घर-घर तक मास्क पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को दो-दो मास्क दिए जाएंगे। एन 95 मास्क दिया जा रहा है। 50 लाख मास्क आ रहे हैं। 15 अक्टूबर से पराली जलने के बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। ग्रेप के सभी नियम दिल्ली में लागू कराए जा रहे हैं। मेरी भूरे लाल से शुक्रवार को बैठक होनी है। उनसे भी सुझाव मांगकर लागू किए जाएंगे।

दफ्तर के समय बदलने पर की चर्चा : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) के सीईओ ओपी अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने यातायात सुगम करने तथा वायु प्रदूषण कम करने के लिहाज से दफ्तरों में कामकाज के समय को अलग-अलग पालियों में बदलने के विषय पर उनसे चर्चा की। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आने वाले सर्दियों के मौसम के हिसाब से हरसंभव कदम उठा रही है जब पराली जलाने के मामले सामने आएंगे और प्रदूषण बढ़ेगा। अग्रवाल परिवहन और शहरी नीति के मुद्दों पर जानेमाने विशेषज्ञ हैं। डब्ल्यूआरआइ कई मार्गों पर अनेक तरह के उपाय उठाने में दिल्ली सरकार के साथ जुड़ा रहा है।

पंजाब और हरियाणा भवन के सामने आज करेगी आप प्रदर्शन : गोपाल राय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा है कि गुरुवार को पार्टी पराली जलाने की घटनाओं की बढ़ती संख्या के खिलाफ पंजाब और हरियाणा भवन के सामने प्रदर्शन करेगी। कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से आप की मदद करने और इसमें शामिल होने की अपील करता हूं। नासा सहित अन्य रिपोर्टों के अनुसार यह स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसी कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले साल 27 अक्टूबर तक 9,600 पराली जलने की घटनाएं दर्ज की गईं। इस साल यह आंकड़ा 12,027 तक पहुंच गया है।

ऑड-इवेन के दौरान राजधानी में स्कूल भी हो सकते हैं बंद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में जहरीली होती जा रही हवा की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो ऑड-इवेन के दौरान दिल्ली में स्कूल भी बंद हो सकते हैं। इस बारे में दिल्ली सचिवालय में पूछे जाने पर कि प्रदूषण को देखते हुए क्या स्कूल बंद करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। रोजाना की स्थिति को देखते हुए फैसला लेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो स्कूल भी बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज 30 तारीख है। ऑड-इवेन में किस दिन क्या स्थिति रहती है वह उसी समय के हालात पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि ऑड-इवेन के दौरान लोगों को परेशानी न हो इसका दिल्ली सरकार ख्याल रखेगी।

भूरेलाल बोले, पांच लाख लोगों की मनमानी पड़ रही भारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष भूरेलाल ने दिल्ली- एनसीआर की हवा के दमघोंटू होने पर पंजाब व हरियाणा को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त यहां के गंभीर हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ पराली का धुआं ही जिम्मेदार है। बुधवार को जागरण से बातचीत में ईपीसीए अध्यक्ष ने कहा कि इन दोनों राज्यों के करीब पांच लाख किसानों की मनमानी दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इन राज्यों की सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोक नहीं पा रही हैं और जिसका धुआं हवा के साथ दिल्ली-एनसीआर तक पहुंचकर यहां की हवा को जहरीला बना रहा है।

अपनी सेहत अपने हाथ

स्मॉग से बचने के लिए खुद रहें जागरूक, वर्ना लगाने पड़ सकते हैं डॉक्टरों के चक्कर

नई दिल्ली में मॉस्क का इस्तेमाल करता एक परिवार • एएनआइ

एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में स्मॉग छाया हुआ है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के दौरान इस मौसमी विकृति की मौजूदगी बरकरार रहने वाली है। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में पराली जलाने की घटनाएं और दीपावली के प्रदूषण ने इसे गहरा कर दिया है। रही सही कसर एनसीआर में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों ने पूरा कर दिया है। स्मॉग के कारण आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, एलर्जी के लक्षण पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार स्मॉग की वजह से दर्जनों बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है जिन्हें पहले से ही सांस या हृदय संबंधी बीमारी है। ये तो तात्कालिक दुष्प्रभाव हैं, इसके दीर्घाकालीन परिणामों का भगवान ही मालिक। ऐसे में जरा सी सतर्कता से हम सभी स्मॉग के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर को कम कर सकते हैं। पेश हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझाव व टिप्स :

डॉ. नरेश कुमार
विभागाध्यक्ष, फिजियोथेरेपी, श्री अग्रसेन इंटनेशनल हॉस्पिटल

- स्मॉग से बचने के लिए वयस्कों को प्राणायाम करना चाहिए।
- भ्रामरी, भस्तिका, अनुलोम-विलोम के साथ ही अन्य ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें।
- स्मॉग छाया रहने की स्थिति में आजकल मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए बाहर न निकलें। घर में ही एक्सरसाइज कर लें।
- खुले में निकलने से बचें।
- अपने घर के आसपास अधिक से अधिक नीम व पीपल के पौधे लगाएं।

डॉ. अमित रंजन
असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबलिटेशन विभाग, सफदरजंग अस्पताल

- सुबह सूरज की किरणों के साथ स्मॉग और भी खतरनाक हो जाता है। हो सके तो घर के अंदर ही व्यायाम करें।
- आजकल बाजार में घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए एयर प्यूरीफायर भी आ गए हैं। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लें।

डॉ. विजय दत्ता
कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, स्पाइनल इंजरी सेंटर

- बच्चे बीमारी का शिकार जल्दी होते हैं इसलिए उन्हें धूमपान करने वालों से दूर रखें।
- बच्चों में अगर एलर्जी, आंखों में जलन आदि की शिकायत हो तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं।
- बच्चों को बैक्टीरियल व वायरल निमोनिया से बचाने के लिए टीके अवश्य लगवाएं। बिना टीके के संक्रमण की आशंका अधिक होती है।

डॉ. प्रियंका यादव
कम्यूनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ

- किसी भी तरह के सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से बचें।
- घर से बाहर अति आवश्यक होने पर ही निकलें।
- मुंह पर एन-95 मास्क पहनें या फिर कोई सूती कपड़ा लपेटकर ही बाहर निकलें।
- बाहर से आने के बाद मुंह-हाथ गर्म पानी से धोएं।
- तली-भुनी चीजें न खाएं।
- धूमपान न करें। धूम्रपान करने वाले लोगों से भी दूर रहें।
- स्मॉग के दौरान मेट्रो व सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करें ताकि प्रदूषण कम करने में आप कुछ सहयोग कर सकें

डॉ. अभिषेक शंकर, पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर एवं इंचार्ज, प्रिवेंटिव आंकोलॉजी इन कैंसर सेंटर, एम्स

- स्मॉग के दौरान घरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।
- घर में साफ-सफाई रखें, धूल आदि न आने दें।
- घरों के आसपास के पेड़-पौधों पर पानी का छिड़काव करें।
- सीट्रिक एसिड के स्रोत फल जैसे संतरा, मौसमी, अनार आदि का सेवन करें।

इनपुट : अरविंद द्विवेदी, नई दिल्ली

यूनीटेक का सेक्टर-113 स्थित आवासीय भूखंड निरस्त

जागरण संवाददाता, नोएडा

नोएडा प्राधिकरण ने सबसे बड़े बकायेदार यूनीटेक के सेक्टर 113 स्थित भूखंड संख्या जीएच 01 को निरस्त कर दिया है। यूनिटेक के ग्रुप हाउसिंग के भूखंड पर 1203.45 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करते हुए मेसर्स सेठी रेजिडेंट्स व मेसर्स जीएमए डेवलपर्स के साथ 19,181.50 वर्गमीटर पर एग्रीमेंट टू सेल कर थर्ड पार्टी बनाने, तय अवधि तक निर्माण कार्य पूरा न कर अधिभोग प्रमाणपत्र न लेने, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 17 टावरों का आंशिक व पूर्ण निर्माण करने के तहत कार्रवाई की गई है। 21 अक्टूबर को आवंटन निरस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने 15 दिन में भूखंड पर कब्जा करने का आदेश दिया है।

प्राधिकरण ने यूनीटेक को सेक्टर-113 जीएच-1 व सेक्टर-117 में जीएच-1 आवंटित किया है। इसमें सेक्टर-113 वाले भूखंड के लिए 1203.45 करोड़ व सेक्टर-117 के लिए 1539.84 करोड़ रुपये का भुगतान बिल्डर ने प्राधिकरण को नहीं किया है। इस भूखंड के एवज में बकाया रकम जमा करने पर प्राधिकरण ने 24 अगस्त 2019 व 30 अगस्त 2019 को नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसे में सेक्टर 113 में कई अनियमितता सामने आने पर ये कार्रवाई की गई है।

प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि यूनीटेक ने जीएच-1 सेक्टर-113 पर बकाया होने के बावजूद बिना मानचित्र पास कराए 17 टावरों का आंशिक एवं पूर्ण निर्माण करवा लिया गया है, जोकि नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशन 2010 के अध्याय-2 की धारा-4 का उल्लघंन है।

क्रिकेट मैच से अधिक दिल्ली के प्रदूषण के बारे में चिंतित होना चाहिए : गंभीर

नई दिल्ली, एएनआइ : दिल्ली में होने वाले भारत बनाम बांग्लादेश टी-20 मैच को लेकर पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैच तो होते रहेंगे, लेकिन लोगों को दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ऐसे वातावरण में खेलना चाहते हैं, जो सभी के लिए बेहतर हो। चाहे खिलाड़ी हो या कोई और, लेकिन अगर प्रदूषण का स्तर वास्तव में ऊंचा हो तो आप किसी वैकल्पिक स्थल के बारे में सोचने को मजबूर हो जाते हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन नवंबर को होना है। दिवाली के बाद बढ़ा दिल्ली का वायु प्रदूषण खिलाड़ियों और हजारों की तादाद में दर्शकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मालूम हो कि दिसंबर 2017 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने मास्क पहनकर दिल्ली में मैच खेला था, हालांकि कुछ खिलाड़ी फिर भी बीमार हो गए थे।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन नवंबर को खेला जाना है पहला टी-20

भाजपा सांसद गंभीर ने कहा कि प्रदूषण यहां दिल्ली में होने वाले क्रिकेट या किसी अन्य खेल से अधिक गंभीर मुद्दा है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को यहां होने वाले क्रिकेट मैच के बजाय प्रदूषण के स्तर के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए।

इससे पहले पर्यावरणविदों ने बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली को पत्र लिखा था कि दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण के कारण मैच दिल्ली के बाहर कराया जाए। यहां की जहरीली हवा में तीन-चार घंटे खेलने से खिलाड़ियों की सेहत पर असर पड़ सकता है। हजारों की तादाद में आने वाले दर्शकों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह होगा।

सीएम ने जताई थी मैच होने की उम्मीद : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई थी कि इस मैच पर प्रदूषण का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता बेहतर करने के लिए उपाय कर रही है।

1,797 में 66 अनधिकृत कॉलोनियां नहीं होंगी नियमित

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

▸ **वन विभाग, यमुना खादर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जमीन और मास्टर प्लान रोड पर बसी हुई हैं ये कॉलोनियां, अधिसूचना हुई जारी**

सप्ताह भर पहले घोषणा भले ही 1,797 कॉलोनियों को नियमित करने की हुई हो, लेकिन मालिकाना हक केवल 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को ही मिलेगा। इन कॉलोनियों की सूची में से 66 कॉलोनियों के नाम हटा दिए गए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इस आशय की गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में कुल 18 सौ अनधिकृत कॉलोनियों के नाम शामिल थे। इनमें से सैनिक फार्म, अनंतराम डेयरी व महेंद्रू एंक्लेव के नाम तो पहले ही बाहर हो गए थे। घोषित 1,797 कॉलोनियों में से भी विभिन्न कारणों के चलते 66 अनधिकृत कॉलोनियों के नाम हटा दिए गए हैं। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक यह वे कॉलोनियां हैं, जो वन विभाग, यमुना खादर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जमीन और मास्टर प्लान रोड पर बसी हुई हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि इन कॉलोनियों में जमीन काफी महंगी है इसलिए इन्हें इतने सस्ते दाम पर नियमित करने की छूट नहीं दी जा सकती। इन कॉलोनियों में प्लॉट भी बड़े आकार वाले हैं और उनमें रहने वाले भी सियासी रसूख रखने वाले और आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं।

> केंद्र सरकार के निर्देशानुसार डीडीए ने अपना काम शुरू कर दिया है। कॉलोनियों की मैपिंग के बाद इनकी चारदीवारी करने और पोर्टल तैयार होते ही मालिकाना हक के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जनवरी या फरवरी में कॉलोनियों को नियमित करने का काम आरंभ हो जाएगा।
>
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, दिल्ली**

केंद्र सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बना रहा पोर्टल : डीडीए के जिस पोर्टल पर उक्त कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए आवेदन करेंगे, वह केंद्र सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तैयार कर रहा है। यह पोर्टल ढाई से तीन माह में तैयार हो जाएगा।

एक साथ नहीं होगा सभी कॉलोनियों पर काम

1,731 कॉलोनियों का नियमितीकरण एक साथ नहीं, बल्कि कुछ-कुछ कॉलोनियों के समूह में किया जाएगा। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक अभी इन सभी कॉलोनियों की मैपिंग का काम चल रहा है। इसके बाद इनकी चारदीवारी की जाएगी। जिस कॉलोनी की मैपिंग और चारदीवारी हो जाएगी, उसका पोर्टल पर पंजीकरण होने लगेगा। इसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

सर्किल रेट पॉश कॉलोनी का, लेकिन देना होगा महज 0.5 फीसद

अभी ये अनधिकृत कॉलोनियां किसी भी सर्किल में शामिल नहीं हैं इसलिए इनकी जमीन का कोई सर्किल रेट भी नहीं है। इसके लिए यह फार्मूला निर्धारित किया गया है कि जिस अनधिकृत कॉलोनी के पास, जो पॉश कॉलोनी लगती होगी, उसे उसी सर्किल में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में उसका सर्किल रेट भी वही हो जाएगा जो समीपवर्ती पॉश कॉलोनी का है। हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल इन कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए सर्किल रेट के हिसाब से भी महज 0.5 फीसद का ही भुगतान करने को कहा है।

दिल्ली में अब मेरी सभी बहनें वीआइपी हैं : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर शुरू करने के बाद दूसरे दिन खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बस यात्री बने। बुधवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में सवार होकर महिला यात्रियों से योजना पर प्रतिक्रिया मांगी। महिलाओं ने खुशी का इजहार करते हुए इस योजना के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

सुबह साढ़े 11 बजे मुख्यमंत्री आनंद विहार बस टर्मिनल के लिए आइटीओ स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय से बस नंबर 85 पर सवार हुए। वह फिर निर्माण विहार मेट्रो बस स्टॉप पर उतर गए। वहां से शाहदरा टर्मिनल की ओर जाने वाली बस संख्या 720 पर सवार हो गए। इस दौरान वह जगतपुरी और आजाद नगर स्टॉप पर रुके। उन्होंने साथी सवारियों के साथ बस का इंतजार किया। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। जगतपुरी में बस से उतरने के दौरान एक दिव्यांग महिला बस में चढ़ रही थीं। सीएम ने उनको बस में चढ़ाने में सहयोग किया। अरविंद केजरीवाल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सामाजिक कार्य के लिए लगभग दस साल सुंदर नगरी जाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते थे। सीएम ने उस दौर को याद किया।

सीएम ने ट्वीट किया, अब दिल्ली में हमारी सभी बहनें वीआइपी हैं। अब तक केवल सांसदों और विधायकों को ही मुफ्त परिवहन भत्ते मिलते थे। मैं महिलाओं से सीधे संवाद के लिए कुछ बसों में सवार हुआ। छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, खरीदारी के लिए जाने वाली महिलाओं के अलावा मैं कुछ ऐसी महिलाओं से भी मिला, जिन्हें नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वे भी बहुत खुश हैं।

सीएम को देख आगे बढ़ महिला ने तुरंत दिखाया गुलाबी पास : केजरीवाल आनंद विहार जाने के लिए आइटीओ पर जैसे ही बस में चढ़े बस में सवार रानी देवी उन्हें अपना गुलाबी पास दिखाने के लिए आगे आईं। उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि हर महीने 1000-2000 रुपये बचेंगे। इंटीरियर डिजाइन की छात्रा सोनल ने केजरीवाल से हाथ मिलाया और कहा अब मेरा किराया भी बच जाएगा।

जब महिलाओं ने कहा, सरकार के पक्ष में करेंगी वोट : आगामी चुनाव में किसे वोट देंगी, इस सवाल का महिलाओं ने जवाब दिया कि वे दिल्ली सरकार के पक्ष में हैं। यह सरकार महिलाओं के लिए है। सीएम ने कहा कि अगर जनता खुश होगी तो हम एक बार फिर चुने जाएंगे। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के लोग खुश रहें। सीएम केजरीवाल ने सभी यात्रियों को यह भी आश्वासन दिया कि अगले छह महीनों में 3,000 और बसें आ जाएंगी। अभी 150 बसें आ चुकी हैं।

मेट्रो में भी महिलाओं की मुफ्त सफर योजना पर कर रहे हैं काम : सीएम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि हम उस पर भी काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा अधिक समय लग रहा है क्योंकि हमें इसे केंद्र के साथ मिलकर करना है। यह योजना जल्द ही शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने सभी बसों में मार्शल लगा दिए हैं। केजरीवाल ने बुधवार को इस व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान बसों में कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री के साथ साझा किया कि वे दिन भर बसों में वर्दीधारी बस मार्शल की उपस्थिति से बेहद सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुफ्त योजना के साथ ही सभी शिफ्टों में दिल्ली की सभी बसों में 13,000 मार्शल तैनात किए गए हैं। विपक्ष की आलोचना पर उन्होंने कहा कि जब भी हमने इस तरह के अच्छे कदम उठाए हैं, विपक्ष ने हमारी आलोचना की है। जब हमने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की तब भी उन्होंने हम पर हमला किया। यदि यह एक चुनावी स्टंट है, तो इसका विरोध करने के बजाय जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां ऐसे कदम क्यों नहीं उठाते। उन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, गोवा में ऐसी योजनाएं लानी चाहिए।

सिख दंगा पीड़ितों को मिलेगी 400 यूनिट मुफ्त बिजली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : 1984 के सिख दंगा पीडितों को 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और पिछले तीन वर्ष के उनके बिजली के बकाया बिल माफ करने की योजना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दंगा पीड़ित सिखों को 400 यूनिट तक के बिजली खपत के बिल को 100 फीसद माफ करने की मंजूरी मिल गई है।

इसके साथ ही 2017-18 के बिजली बिल को भी माफ किया गया है। इस पर 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। अब तक सिख दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिजली दर का भुगतान नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिक्स चार्ज, सरचार्ज के अलावा 400 यूनिट से अधिक बिजली आने पर पूरा भुगतान करना पड़ता था। मगर नई योजना में 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर भी 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। केवल 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर अतिरिक्त यूनिट का ही भुगतान करना होगा। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2020 तक मिलेगा।

संकल्प

राष्ट्रपति ने कहा, धर्म, अध्यात्म, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का केंद्र बना जामिया हमारी साझा संस्कृति के लिए है मिसाल, दीक्षा समारोह में दस हजार छात्रों को डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान की गई

भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में करना है स्थापित : कोविंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्थापना दिवस के एक दिन बाद दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्त अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए शैक्षिक वातावरण में बदलाव करती रही है। पूरा विश्व भारत के छात्रों की असाधारण प्रतिभा से अवगत है। हमें भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए इस प्रतिभा के समुचित इस्तेमाल के लिए देश के सभी शैक्षिक संस्थाओं को योगदान करना होगा। जामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से इस दिशा में विशेष योगदान की आशा है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे बताया गया है कि केंद्र सरकार के उन्नत भारत अभियान के तहत जामिया द्वारा पांच गावों को गोद लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि इस अभियान के लक्ष्यों के लिए काम करने के साथ-साथ यहां के छात्र उन गांवों में दो महीने के अंतराल पर जाएं। यदि संभव हो तो रात में वहां रुकें और गांव वालों के साथ मिल-बैठकर उनके मसलों को समझने की कोशिश करें।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हाथ से बनी उनकी तस्वीर को स्मृति चिह्न के रूप में भेंट करतीं कुलपति प्रो. नजमा अख्तर। साथ में एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं जामिया की कुलाधिपति डॉ. नजमा हेपतुल्ला। सौजन्य : जामिया

उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को जामिया ने स्थापना दिवस मनाया। अगले वर्ष विश्वविद्यालय को सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास के साथ जुड़ी है। विदेशी हुकूमत के खिलाफ चल रहे अंहिसापूर्ण आंदोलन के दौरान, आज से ठीक सौ साल पहले, 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद देश में स्वाभिमान और जागरण की एक नई लहर उठी थी। 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलनों ने जोर पकड़ा और सामाजिक एकता और भाई-चारे की भावनाओं को बल मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने छात्रों से यह अपील की थी कि वे विदेशी हुकूमत की मदद से चलने वाले शिक्षण संस्थानों को छोड़ दें। साथ ही उन्होंने आह्वान भी किया कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए।

स्वतंत्रता संग्राम का मार्गदर्शन करने वालों की पुकार सुनकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉ. एमए अंसारी, हकीम अजमल खान और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे लोग आगे आए और इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की। जामिया शिक्षा और पुर्नजागरण का माध्यम बना। धर्म, अध्यात्म, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का केंद्र बना जामिया हमारी साझा संस्कृति के लिए मिसाल बना। दीक्षा समारोह में 2017 एवं 2018 में पास हुए कुल 10 हजार छात्र-छात्राओं को डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान किए गए।

जामिया में चार नए विभागों की शुरुआत होगी

जासं, नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से जल्द ही विदेशी भाषाओं, जलवायु परिवर्तन, अस्पताल प्रबंधन और डिजाइन जैसे चार नए विभाग शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने कहा कि इन चार विभागों के शुरू होने से इनके अधीन छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने बताया कि अभी तक जामिया में कुछ विभागों के अधीन ही विदेशी भाषाओं को पढ़ाया जाता है। अब यह एक ही विभाग के अधीन आ जाएंगे, इससे छात्रों को फायदा होगा। साथ ही अस्पताल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम में बताया जाएगा कि किस तरीके से अस्पताल में प्रशासनिक दायित्व को संभालना जाता है। इसके अलावा प्रो. नजमा अख्तर ने बताया कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में गुणवत्ता को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अकादमी और उद्योग को साथ में लाया जा रहा है।

रन फॉर यूनिटी आज, दो घंटे बंद रहेंगे कई मार्ग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजपथ और रफी मार्ग गुरुवार की सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े आठ बजे तक बंद किए जाएंगे। इस दौरान रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में करीब 15 हजार लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।

दिल्ली के संयुक्त आयुक्त (यातायात) एनएस बुंदेला ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों से अपील की है कि वे कार्यक्रम के दायरे में आने वाले मार्गों की ओर कार्यक्रम के समय आवाजाही न करें। रन फॉर यूनिटी का रूट राजपथ क्रॉसिंग से रफी मार्ग होते हुए राजपथ पर समापन से पहले सी-हेक्सन मार्ग से इंडिया गेट होते हुए बनाया गया है। इस दौरान बस पार्किंग कस्तूरबा गांधी मार्ग, तिलक मार्ग, नेशनल स्टेडियम, जाकिर हुसैन मार्ग और भैरों मार्ग पर होगी।

इसके अलावा जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के वाहनों की पार्किंग विज्ञान भवन पर होगी। इस दौरान कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। वाहन चालक परेशानी से बचने के लिए मार्गों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के दिशा-निर्देश का पालन करें।

1,540 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है देश में मौजूदा समय में। 1947 (आजादी के समय) यह आंकड़ा 5,000 घन मीटर था। ध्यान रहे भारत में प्रति वर्ष 400 करोड़ घन मीटर पानी वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है।

भारत और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा संबंधों की नई शुरुआत

पीएम की यात्रा के दौरान किए गए 12 समझौतों में से तीन सुरक्षा से जुड़े

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विगत में पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों की वजह से भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने से परहेज करने वाले सऊदी अरब ने अपनी स्पष्ट राय बना ली है। सऊदी अरब ने भारत को न सिर्फ एक मजबूत रणनीतिक साझीदार के तौर पर चिन्हित किया है बल्कि उसे भविष्य में रक्षा उपकरणों के आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी देख रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच हुए 12 समझौतों में से तीन सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।

सऊदी अरब और भारत के बीच किया गया सबसे अहम समझौता रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन से संबंधित है। जबकि दूसरा अहम समझौता सुरक्षा सहयोग से जुड़ा है। तीसरा समझौता दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच किया गया है जो इनके बीच हथियारों की खरीद-बिक्री, हथियारों के विकास व शोध के काम से

पाक से ज्यादा भरोसेमंद रक्षा सहयोगी के तौर पर होगी भारत की पहचान

रियाद में रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पीएम मोदी। प्रेट्र

जुड़े सहयोग को स्थापित करेंगे। जानकारों की मानें तो सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ वर्ष 1982 का सुरक्षा सहयोग समझौता भी इतना व्यापक नहीं है। खासतौर पर रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन को लेकर पाकिस्तान के मीडिया व राजनीति में काफी हड़कंप मचा हुआ है। सऊदी अरब ने इसके पहले सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के साथ ऐसा समझौता किया है। भारत चौथा देश है, जबकि आगे जापान, कोरिया, अमेरिका और रूस के साथ ऐसा ही समझौता करने की घोषणा की गई है। इसकी अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि परिषद की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान करेंगे। इसमें दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री सदस्य होंगे। इसके तहत कई उपसमितियां काम करेंगी जो समूचे रणनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सलाह देने का काम करेगी।

विदेश मंत्रालय के उच्चस्तरीय अधिकारियों के मुताबिक, सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में आयाम पूरी तरह बदलने लगे हैं। पहले दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ कच्चे तेल की खरीद-बिक्री तक सीमित थे जिसमें भारत की स्थिति कमोबेश एक याचक जैसी होती थी। लेकिन हालात बदलने लगे हैं और अगले चार-पांच वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र के परस्पर हित एक-दूसरे से जुड़े होंगे। सऊदी अरब की कंपनी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हिस्सेदार होगी और यहां के पेट्रोलियम रिटेल में भी उसकी हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा भारत के पेट्रोलियम रणनीतिक भंडार से भी सऊदी अरब का सीधा हित जुड़ा होगा। इसके लिए भी दोनों देशों के बीच मंगलवार को एक समझौता किया गया है।

मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त दत्ता पडसलगीकर बने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त व महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दत्ता पडसलगीकर को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी-एनएसए) नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल के साथ आइबी में काम कर चुके हैं।

1982 बैच के आइपीएस अधिकारी पडसलगीकर ने 26 वर्षों तक खुफिया विभाग में सेवा दी। उन्हें वर्ष 2016 में मुंबई का पुलिस आयुक्त बनाया गया। वह 2018 में महाराष्ट्र के डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए। महाराष्ट्र पुलिस के उनके सहयोगी 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की जांच में पडसलगीकर की भूमिका की सराहना करते हैं। पडसलगीकर ने आतंकियों के बीच हुई बातचीत का वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी अमेरिका से हासिल कर लिया था। जिंदा पकड़े गए पाक आतंकी अजमल कसाब के मामले में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उनके साथी बताते हैं, 'मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद जब पडसलगीकर को सरकारी आवास आवंटित किया जाना था, वह वर्ली में आइपीएस अफसरों के भोजनालय में रहते थे। वह हर सुबह बिना सुरक्षा के पास की बेकरी में जाते थे।' गणेश उत्सव जैसे अवसरों पर अपने ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी के घर उनसे मिलने जाते थे।

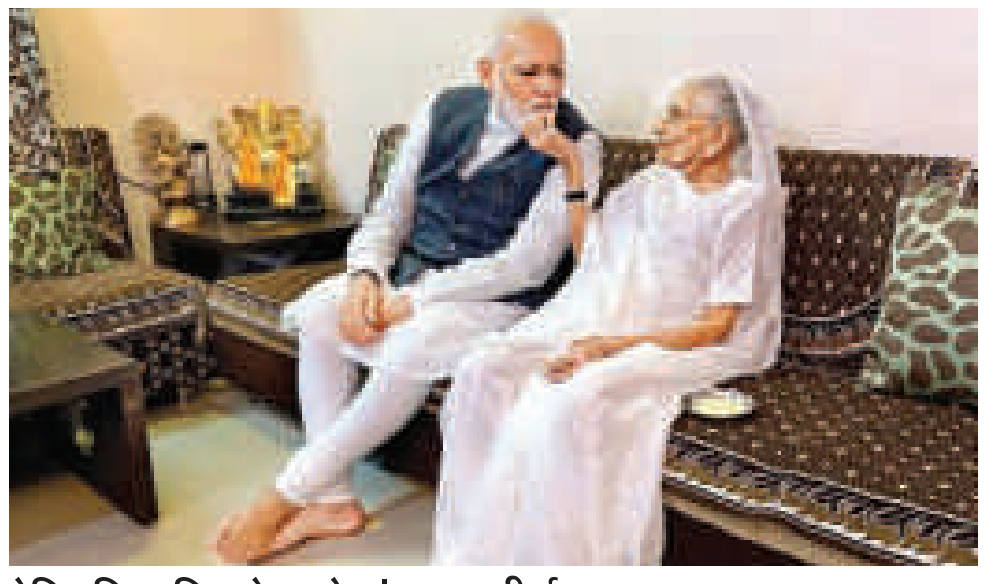

ऐतिहासिक दिन से पहले मां का आशीर्वाद

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को देश के दो नये केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। इस ऐतिहासिक दिन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गांधीनगर स्थित अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री गुरुवार (आज) को देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। उनकी जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। एएनआइ

मोदी ने कर्मचारियों से कहा, दूसरों के लिए आदर्श बने पीएमओ

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्मचारियों से कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पूरे सरकारी तंत्र के लिए आदर्श की तरह काम करे और अन्य मंत्रालयों को रास्ता दिखाने के लिए प्रेरणा एवं नेतृत्व प्रदान करे।

अपने आवास पर आयोजित 'दिवाली मिलन' कार्यक्रम के दौरान पीएमओ में कार्यरत कर्मियों को संबोधित करते हुए मोदी ने ये बातें कही। मोदी ने कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, सरकार की ओर से किए गए परिवर्तनकारी कार्य उनके अथक प्रयास और नियमित कोशिश से संभव हुआ है। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पीएम ने कर्मियों से गत वर्ष किए गए काम का आकलन करने और आने वाले साल के लिए ऊंचे लक्ष्य तय करने को कहा। उन्होंने कर्मचारियों से अपनी नैतिकता एवं प्राथमिकता के जरिये सरकार के अन्य हिस्सों के लिए प्रेरणा बनने का आह्वान किया। उन्होंने 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पूरे किए जाने वाले लक्ष्यों को रेखांकित किया।

कर्नाटक सरकार पाठ्यक्रम से हटाएगी टीपू सुल्तान के चैप्टर

बेंगलुरु, एजेंसियां : कर्नाटक की भाजपा सरकार स्कूली इतिहास की किताबों से 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से संबंधित चैप्टर हटाएगी । कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा, 'टीपू सुल्तान पर चैप्टर पाठ्यपुस्तकों में नहीं होने चाहिए, हम उन्हें जारी नहीं रहने देंगे। हम पहले ही 10 नवंबर को टीपू जयंती को राजकीय समारोह के तौर पर नहीं मनाने का फैसला कर चुके हैं। क्योंकि वह विवादित शासक था और वह जबरन धर्मांतरण, मंदिरों के विध्वंस व हिंदुओं के उत्पीड़न में लिप्त था। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि टीपू सुल्तान स्वाधीनता सेनानी था।'

इससे पहले 28 अक्टूबर को राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसायटी के प्रबंध निदेशक को भाजपा विधायक ए. रंजन के प्रस्ताव पर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। रंजन ने इतिहास की सभी पाठ्यपुस्तकों से टीपू सुल्तान का संदर्भ हटाने का प्रस्ताव किया था। सुरेश कुमार को लिखे पत्र में रंजन का कहना था कि पाठ्यपुस्तकों में टीपू को स्वाधीनता सेनानी के तौर पर दर्शाया गया है और इतिहास को गलत तथ्यों के आधार पर नहीं लिखा जाना

कांग्रेस ने सरकार के कदम को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

चाहिए। उनका कहना था, 'टीपू कोडागु, मेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों में अपने राज्य का विस्तार करने आया था। वह यहां सिर्फ लोगों का धर्मांतरण कराने और अपने राज्य को बढ़ाने आया था। उसके मन में कन्नड़ भाषा के लिए कोई सम्मान नहीं था क्योंकि उसकी प्रशासनिक भाषा फारसी थी। उसने कई स्थानों के नाम भी बदले थे, मसलन मदिकेरी का जाफराबाद और मेंगलुरु का जलालाबाद। उसने कई मंदिरों और ईसाई चर्चों को भी लूटा था। कोडगु में उसने 30 हजार कोडावा लोगों का धर्मांतरण कराया था।'

टीपू सुल्तान के वंशज मुहम्मद शाहिद आलम ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए पूर्व शासक को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने भाजपा को धर्मांध बताते हुए कहा, 'पाठ्यपुस्तकों से टीपू के चैप्टर हटाना इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने जैसा है। टीपू ने ब्रिटिश से लड़ाई की थी, यह सच है या झूठ? इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना नहीं चाहिए। हमें बच्चों को इतिहास पढ़ाना होगा और उससे सीखना होगा।'

विदेश अदालत में ईडी की अर्जी खारिज न्यायिक हिरासत में भेजे गए चिदंबरम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया डील से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक दिन की रिमांड लेने के लिए अर्जी दायर की, जिसे विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने चिदंबरम की खराब तबीयत को देखते हुए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चिदंबरम को सुरक्षा के बीच अलग बैरक में रखा जाएगा। उन्हें घर का खाना और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

आइएनएक्स मीडिया डील मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। कई दिन की रिमांड के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 सितंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वहीं दो सप्ताह पहले ईडी ने याचिका दायर कर चिदंबरम को हिरासत में ले लिया था। आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को

एक दिन के लिए रिमांड पर लेना चाहता था प्रवर्तन निदेशालय

कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम बुधवार को नई दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के समक्ष पेश हुए। प्रेट्र

दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। वहीं न्यायिक हिरासत में जाने के बाद चिदंबरम ने अदालत के बाहर कटाक्ष किया। चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर में यूरोपीय संघ के सांसदों के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें संसद में आमंत्रित किया जा सकता है और सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं। चिदंबरम ने कहा कि कौन जानता है कि ऐसा हो भी सकता है?

डीके शिवकुमार की पत्नी और मां के खिलाफ नया समन

जासं, नई दिल्ली : ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की पत्नी और मां के खिलाफ नया समन जारी किया गया है। हालांकि, दूसरी तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ को बताया कि अब तक उन्हें कोई समन नहीं मिला है। इस पर पीठ ने सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। डीके शिवकुमार फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनकी पत्नी ऊषा और मां गौवरम्मा की तरफ से दायर अलग-अलग याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही है। ईडी के वकील अमित महाजन ने पीठ को बताया कि जांच एजेंसी ने नया समन जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दयन कृष्णन ने दलील दी थी कि ईडी जब भी नया समन जारी करेगा उसे सीआरपीसी के प्रावधान का पालन करना होगा। इसके तहत 15 साल से कम की किशोरी और 65 साल से अधिक उम्र की महिला को थाने नहीं बुलाया जा सकता। गौरम्मा 85 वर्ष की हैं और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहता है, तो वह उनके घर जा सकता है।

पानी नहीं बचाया तो केप टाउन बन जाएंगे चेन्नई व बेंगलुरु : शेखावत

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में गहराते जल संकट पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर लोग पानी नहीं बचाने को लेकर गंभीर नहीं होंगे तो देश की बहुत बड़ी आबादी इससे बुरी तरह प्रभावित होगी और चेन्नई और बेंगलुरु केप टाउन बन जाएंगे।

बता दें कि वर्ष 2017-18 में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन शहर में पानी लगभग पूरी तरह खत्म हो गया था। इसके बाद वहां 'जीरो डे' का विचार आया। 'जीरो डे' का अर्थ उस दिन से है जब शहर के सभी नलों को बंद कर दिया जाता था। यहां 13वें विश्व एक्वा कांग्रेस में शेखावत ने कहा कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता आजादी के समय 5,000 घन मीटर से घटकर 1,540 घन मीटर रह गई है। अगर इसी तरह की गिरावट जारी रही और आबादी बढ़ती रही तो चेन्नई, बेंगलुरु , केपटाउन बन जाएंगे और देश की आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा।

शेखावत ने कहा कि तेजी से शहरीकरण, बढ़ती आबादी और खराब जल प्रबंधन के कारण बेंगलुरु में नलकूप सूखने, भूजल स्तर गिरने और झीलें जहरीली होने लगी हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पास नल वाला पानी नहीं पहुंच रहा है और वे पानी के टैंकरों पर निर्भर

दक्षिण के दो राज्यों में जल संकट पर जलशक्ति मंत्री ने चेताया

दो साल पहले बूंद-बूंद पानी को तरस गई थी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी

गजेंद्र सिंह शेखावत फाइल फोटो

हैं। देश के एक और महानगर, चेन्नई में स्थिति बेहतर नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औसतन भारत में प्रति वर्ष 1,068 मिमी बारिश और 4,00 करोड़ घन मीटर पानी वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर भी देश में जल संकट है। इजराइल में प्रति वर्ष 100 मिमी बारिश होती है। उतने में ही वह अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हुए वह पानी का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति भारत में जिम्मेदारी की भावना का अभाव है।

अरुणाचल के जरिये अमेरिका का चीन पर निशाना

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले पर चुप्पी साधने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया है जो एशिया में बदलते महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। इस बार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता का जोरदार समर्थन करते हुए पड़ोसी देश चीन की तरफ इशारा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह संकेत तब आया है जब भारत में उसके राजदूत केन जस्टर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए हैं। जस्टर अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में आयोजित एक फेस्टिवल में न सिर्फ बतौर प्रमुख अतिथि शामिल हुए बल्कि उन्होंने अमेरिकी सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने की घोषणा भी की।

तवांग को लेकर चीन हमेशा से सबसे ज्यादा संवेदनशील रहा है। विदेशी राजनयिकों को छोड़ दिया जाए तो वह भारत के आला अधिकारियों के वहां जाने को लेकर भी आपत्ति जताता रहा है। तवांग पर चीन आधिकारिक तौर पर दावा करता रहा है और दो वर्ष पहले तवांग का चीनी भाषा में नाम भी अलग रख चुका है। ऐसे में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के अपने मायने निकाले जा रहे हैं।

- **अमेरिकी विदेश मंत्रालय का अहम बयान, भारत की संप्रभुता को पूरा समर्थन**
- **राजदूत केन जस्टर के अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद आया बयान**
- **तवांग पर चीन आधिकारिक तौर पर दावा करता रहा है**

सातवें तवांग महोत्सव के उद्घाटन पर भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर को प्रतीक चिह्न भेंट करते अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू। एएनआइ

जस्टर ने ट्विटर पर तवांग फेस्टिवल में मनाए गए उत्सव की कई फोटो ट्वीट किए हैं।

बुधवार देर शाम अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिणी एवं केंद्रीय एशियाई मामलों के विभाग ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जस्टर के फोटो और सूचना को रिट्वीट किया और लिखा, 'अमेरिकी राजदूत की तवांग यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि अमेरिका भारत की अखंडता में पूरी तरह से सहयोग करता है और स्थानीय साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। अमेरिका अरुणाचल में स्वास्थ्य व सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है।' अमेरिका का यह आधिकारिक बयान ऐसे समय आया है जब पैसिफिक फ्लीट कमांडर के एडमिरल जॉन सी एक्वीलिनो ने दिल्ली में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर तल्ख टिप्पणी की थी। एक्वीलिनो ने कहा था कि जिस तरह से चीन हिंद महासागर में हथियारों की तैनाती कर रहा है उसने कई देशों के लिए चुनौती पैदा कर दी है। उन्होंने कहा, चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना आर्थिक नहीं सैन्य ताकत का प्रसार है। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन की तरफ से बढ़ता खतरा भारत और अमेरिका के बीच नौसैनिक सहयोग की गति को तेज करेगा।

तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का हुआ तबादला

नई दिल्ली, प्रेट्र : तीन हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों और दो हाई कोर्टों के जजों का बुधवार को तबादला कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही को मद्रास हाई कोर्ट भेजा गया है। सितंबर में जस्टिस विजया ताहिलरमानी के इस्तीफे के बाद से जस्टिस विनीत कोठारी मद्रास हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का काम कर रहे हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करौल को जस्टिस साही के स्थान पर पटना हाई कोर्ट भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के जज अकिल कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप पदोन्नत करने की सिफारिश की थी क्योंकि सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने पर आपत्ति व्यक्त की थी।

पटना हाई कोर्ट के जज का भी तबादला : पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भेजा गया है। इसी तरह, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अमित रावल का केरल हाई कोर्ट में तबादला किया गया है।

मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राज कुंद्रा से नौ घंटे पूछताछ

मुंबई, प्रेट्र : इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने बुधवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा से पूछताछ की। वह सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय पहुंचे थे और उनसे करीब नौ घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी इस इस मामले में गिरफ्तार बिंद्रा की कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवेलपर्स में निदेशक धीरज वाधवान से भी पूछताछ करने की तैयारी में है।

अफसरों ने बताया कि ईडी ने कुंद्रा को समन जारी कर पूछताछ के लिए चार नवंबर को पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता बताकर पहले हाजिर होने की इजाजत मांगी थी। इस मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि कुंद्रा का रंजीत बिंद्रा व बास्टियन हॉस्पिटैलिटी के साथ लेनदेन का मिर्ची मामले से ताल्लुक है या नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच लेनदेन के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए थी, इसलिए कुंद्रा को समन भेजा गया। हालांकि, इससे पहले कुंद्रा कह चुके हैं कि उन्होंने कारोबार में कुछ भी गलत नहीं किया। एजेंसी पिछले साल कुंद्रा से बिटकॉइन घोटाले में भी पूछताछ कर चुकी है।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा से पिछले साल भी ईडी ने की थी पूछताछ

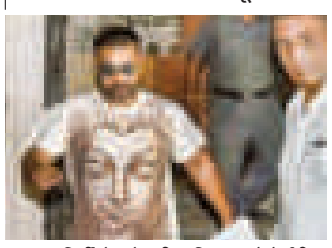

इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के मुंबई स्थित कार्यालय से पूछताछ के बाद बाहर आते बिजनेसमैन राज कुंद्रा। प्रेट्र

इकबाल मिर्ची गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का बहुत करीबी था और उसके अवैध काम को संभालता था। वर्ष 2013 में मिर्ची की लंदन में मौत हो गई थी। ईडी ने मिर्ची, उसके परिवार व अन्य के खिलाफ मुंबई में संपत्तियों की खरीदारी के मामले में मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। उसने मुंबई पुलिस की तरफ से दर्ज दर्जनों मुकदमे के आधार पर पीएमएलए की रिपोर्ट दाखिल की है। इस सिलसिले में ईडी ने पिछले कुछ महीनों में दर्जनों जगहों पर छापेमारी की है।

सहिष्णुता भारतीय बहुसंख्यकों के डीएनए में : नकवी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि सहिष्णुता एवं सामाजिक सद्भाव भारत के बहुसंख्यक समाज के डीएनए में है। भारत में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सूत्रों के अनुसार, नकवी ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता विषय पर शीर्ष अमेरिकी राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को अपने मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं एवं उनके सकारात्मक प्रभाव से भी अवगत कराया। इस मुलाकात के बाद नकवी ने ट्वीट किया, 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक सशक्तीकरण तथा रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई।' सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक घंटे तक चली मुलाकात के दौरान नकवी ने अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों, खासकर लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए चलाए जा रहे छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। कहा, गत पांच वर्षों में स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर 70 से 35 फीसद हो गई है।

घेराबंदी का प्रयास

बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर सरकार की घेराबंदी के लिए बैठक की पहल कर रही कांग्रेस, 5 से 15 नवंबर के बीच पार्टी देश भर में करेगी आंदोलन, संसद सत्र के दौरान सोनिया-मनमोहन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की करेंगे अगुआई

मंदी, रोजगार संकट पर होगी विपक्षी दलों की साझा बैठक

संजय मिश्र, नई दिल्ली

लगातार बिगड़ रही अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर चुकी कांग्रेस इस मसले पर साझा विपक्षी घेराबंदी के प्रयास में भी जुट गई है। पार्टी का मानना है कि आर्थिक मंदी ने रोजगार के संकट को गंभीर कर दिया है। ऐसे में सरकार को हालात की गंभीरता का अहसास कराने के लिए विपक्षी दलों की संयुक्त घेराबंदी जरूरी है। कांग्रेस इसी मकसद से विपक्षी दलों की साझा बैठक बुलाने की पहल कर रही है।

कांग्रेस के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति पर विपक्षी नेताओं से अनौपचारिक चर्चाएं चल रही है। अधिकतर विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से सरकार की घेराबंदी की जरूरत को स्वीकार किया है। इसीलिए अगले चंद दिनों के भीतर ही आर्थिक मंदी की चुनौतियों पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। वामदलों के नेताओं ने बैठक के प्रस्ताव पर हामी भर दी है। सूत्रों के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर विपक्षी दलों के संयुक्त आंदोलन की फिलहाल कोई रूपरेखा नहीं बन रही। साझा बैठक का मकसद विपक्षी दलों की एकजुट ताकत से सरकार पर दबाव बढ़ाना है। कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान कर चुकी है और मंगलवार को इसकी रूपरेखा भी जारी कर दी गई। पार्टी का मानना है कि वैसे भी आर्थिक मंदी, रोजगार के संकट, कृषि संकट और किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाने की मुसीबत के अलावा मुक्त व्यापार से जुड़े आरसेप समझौते पर हस्ताक्षर की सरकार की तैयारी जैसे मसलों पर विपक्षी दलों की राय बहुत इतर होगी इसकी गुंजाइश नहीं है। वैसे विपक्षी दलों की एक बैठक आगामी संसद के शीत सत्र की संयुक्त रणनीति को लेकर भी होगी।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा की घोषणा की। इसके तहत पांच से 15 नवंबर के बीच प्रदेश की राजधानियों और हर जिले में लोगों को मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से रूबरू कराया जाएगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में संसद के शीत सत्र के दौरान दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में इस आंदोलन को परिणति होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह इस प्रदर्शन की अगुआई करेंगे। राज्यों में विरोध आंदोलन में हीलाहवाली पर नजर रखने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने 21 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है।

आर्थिक मंदी पर सरकार की घेराबंदी के आंदोलन को लेकर पार्टी की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोनिया गांधी ने दो नवंबर को सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और एआइसीसी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें मोदी सरकार की दूसरी पारी में कांग्रेस के इस पहले आंदोलन को कामयाब बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। आंदोलन को सियासी गरमी देने के लिए पार्टी 35 प्रमुख शहरों में प्रेस कांफ्रेंस के लिए प्रमुख नेताओं को भेजेगी, जो तथ्यों व आंकड़ों के साथ पर मोदी सरकार की विफलताएं गिनाएंगे।

'ध्यान' के लिए राहुल विदेश यात्रा पर, जल्द लौटेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'ध्यान' के लिए विदेश यात्रा पर हैं और उनके जल्द लौटने की संभावना है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की अनुपस्थिति के बारे में अटकलों का जवाब देते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वह अपनी नियमित 'ध्यान' यात्रा गए हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ध्यान सत्र के लिए संभवत: इंडोनेशिया में हैं। सुरजेवाला ने आगे बताया कि कांग्रेस ने आर्थिक मंदी, कृषि संकट, बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियां छिनने और आरसीईपी (रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) व्यापार समझौते के परिणाम जैसे मुद्दों पर पांच से 15 नवंबर तक देशव्यापी प्रदर्शनों की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, 'पूरा कार्यक्रम उनके निर्देश और उनकी सलाह से ही तैयार किया गया है। उन्होंने उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों और मुद्दों पर पार्टी का मार्गदर्शन किया है। जिस बैठक में कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया गया उसमें राहुल गांधी उपस्थित थे। राज्य और जिला स्तरीय इन कार्यक्रमों में न तो सोनिया गांधी और न ही राहुल गांधी हिस्सा लेने जा रहे हैं।'

कह के रहेंगे माधव जोशी

90 कंपनियां तैनात की जाएंगी झारखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान। इनमें 70 कंपनियां केंद्रीय बलों की और झारखंड पुलिस की विभिन्न इकाई की 20 कंपनियों की भी तैनाती होगी। 9,000 से ज्यादा जवान मुस्तैद रहेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 31 अक्टूबर 2019

अजीत पवार होंगे महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष

मिली भूमिका ▸ पिछली विधानसभा में कांग्रेस के पास था यह पद

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

शरद पवार के गढ़ बारामती से छठवीं बार विधायक चुनकर आए उनके भतीजे एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को बुधवार को राकांपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि अजीत पवार ही इस बार सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे।

पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस के पास था क्योंकि उसके 41 और राकांपा के 40 विधायक चुनकर आए थे। इस बार राकांपा के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक चुनकर आए हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष का पद राकांपा के खाते में जाएगा। राकांपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अजीत पवार ने अपने पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए संकेत दिए कि वह कृषि संकट और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं रखेंगे। बता दें कि पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते रहे कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। यहां तक कि उनके कांग्रेस में रहते हुए ही उनके पुत्र डॉ. सुजय पाटिल अहमदनगर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। इसलिए पाटिल पर यह आरोप लगता है कि वह नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए फड़नवीस सरकार के मित्र की भूमिका निभाते रहे। विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते ही उन्हें फड़नवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। माना जा रहा था कि उनके भाजपा में शामिल होने से उनके गृह जनपद अहमदनगर की सभी 12 सीटें भाजपा-शिवसेना के खाते में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

मुंबई में बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को राकांपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। प्रेट्र

राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने विधायक दल के नेता के रूप में अजीत पवार के नाम का प्रस्ताव करने से पहले अहमदनगर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि जहां उनकी पार्टी का सूपड़ा साफ होने की बात की जा रही थी, वहां उसे छह सीटें हासिल हुई हैं। बता दें कि 2014 में भी विधानसभा में राकांपा विधायक दल के नेता अजीत पवार ही थे। यह कयास भी लगाया जा रहा था कि राकांपा इस बार पंकजा मुंडे को हराकर आए उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे को विधायक दल का नेता चुन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कार्टून के जरिये कसा तंज : राकांपा प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने एक कार्टून जारी कर भाजपा-शिवसेना पर तंज किया है। कार्टून में शिवसेना के चुनाव चिन्ह 'धनुष और तीर' से कमल पर निशाना साधे हुए दिखाया गया है। कार्टून में मराठी में कैप्शन लिखा है, 'एक कहावत है, सिर पर लटकना...।' इसी के समान हिंदी में एक मुहावरा है, 'सिर पर तलवार लटकना...' इन मुहवरों का अर्थ है कि कोई खतरा मंडरा रहा है।

शिवसेना का भाजपा गठबंधन में रहना जरूरी : राउत

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

रुख में नरमी दिखाते हुए शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के व्यापक हित में और सम्मान से समझौता किए बगैर शिवसेना का भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन में रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगली सरकार के गठन की कोई जल्दी नहीं है। साथ ही उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि सरकार गठन में देरी हुई तो शिवसेना में विभाजन हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, 'व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि राज्य के हित अहम हैं।' जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा ने शिवसेना को उपमुख्यमंत्री पद और 13 मंत्रालयों का प्रस्ताव दिया है, इस पर राउत ने कहा, 'हम बहीखाता लेकर नहीं बैठे हैं।'

कांग्रेस ने कहा, शिवसेना को समर्थन का सवाल ही नहीं : सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन की अटकलों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के प्रभारी कांग्रेस महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिवसेना को समर्थन का कोई सवाल ही नहीं है, कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। हालांकि वरिष्ठ पार्टी नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि शिवसेना की ओर से ठोस प्रस्ताव पर विचार होगा।

केंद्र में मंत्री पद के लिए जदयू ने बढ़ाया दबाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ महाराष्ट्र में शिवसेना के दबाव के बीच जदयू ने उठाई उचित प्रतिनिधित्व की मांग

▸ नीतीश कुमार अगले तीन साल के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित

मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना के घमासान के बीच बिहार में भाजपा के सहयोगी घटक जदयू ने भी केंद्र सरकार में संख्या के अनुपात में भागीदारी की मांग दोहराई है। अगले तीन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह केंद्र में जदयू को सांसदों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का फैसला करते हैं तो पार्टी उसका स्वागत करेगी। गौरतलब है लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सिर्फ एक मंत्री पद के ऑफर को जदयू ने ठुकरा दिया था।

जदयू के राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार के संबोधन व पार्टी से संबंधित अन्य मुद्दों पर बोलते हुए केसी त्यागी ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ फैसला दिया था। इसके बावजूद 2017 में गठबंधन बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को सरकार में बराबर की भागीदारी दी और उपमुख्यमंत्री का पद दिया। वैसे उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि जदयू को केंद्र सरकार में कितने मंत्री पद चाहिए और न ही इसकी कोई समय सीमा बताई। उन्होंने साफ कर दिया कि जदयू केंद्र में मंत्री पद के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। लेकिन यह इशारा जरूर कर दिया कि केंद्र सरकार में जदयू का प्रतिनिधित्व बाकी है और उसे सांसदों की संख्या के अनुपात मंत्री पद दिये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बिहार को केंद्र सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और सरकार के सामाजिक दायरे का भी विस्तार होगा।

नई दिल्ली में बुधवार को जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार। साथ में पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और अन्य नेता। प्रेट्र

बिहार में जदयू और भाजपा नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी के बीच केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि 2021 में भाजपा-जदयू गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और 2010 के विधानसभा चुनाव से भी अधिक सीटें जीतेगा। ध्यान देने की बात है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा-जदयू गठबंधन 243 में 206 सीटें जीतने में सफल रहा थी।

राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के संबोधन के बारे में बताते हुए केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार की तर्ज पर पूरे देश में शराबबंदी को लागू करने की जरूरत बताई। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के विकास के लिए उठाए कदमों की जानकारी दी और राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष की आलोचना को खारिज कर दिया।

नीतीश कुमार ने मूल्य आधारित राजनीति की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि गांधीजी के 'सात पाप' के सिद्धांत को राजनीतिक प्रचार में शामिल किया जाना चाहिए। इस बीच, जदयू के प्रवक्ता पवन वर्मा ने कश्मीर गए यूरोपीय संघ के सांसदों के वहां जाने के औचित्य पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि विदेशी सांसदों को कश्मीर का दौरा कराया गया, जबकि देश के सांसदों को कश्मीर जाने से रोका जा रहा है।

न्यूज गैलरी

तेजस्वी ने उठाए शराबबंदी की सफलता पर सवाल

पटना : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी की सफलता पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि गरीबों को जेल भेजने और पुलिस को भ्रष्ट एवं नकारा बनाने के लिए ही शराबबंदी लागू की गई है। अबतक डेढ़ लाख लोगों को शराब पीने-रखने के आरोप में जेल भेज दिया गया है, लेकिन एक भी सीनियर अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी ने बिहार पुलिस को खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी और कहा कि अगर पुलिस में दम है तो मुझे गिरफ्तार करे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जदयू के कई कार्यकर्ता शराब माफिया बने बैठे हैं। किंतु पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। जो पकड़े भी जाते हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाता है। शराब पीते हुए कई नेताओं के वीडियो वायरल हुए हैं। किंतु गिरफ्तारी गरीबों की हो रही है। (राब्यू)

अब लालू यादव पर भोजपुरी फिल्म 'लालटेन'

बलिया : अब तक कई राजनेताओं पर फिल्में बन चुकी है, लेकिन जल्द ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर भोजपुरी फिल्म 'लालटेन' बन रही है। इसमें भोजपुरी स्टार और जिले के बेल्थरा तहसील क्षेत्र के चैनपुर गुलौरा निवासी यश कुमार लालू यादव का किरदार निभाएंगे। बता दें कि राजद का चुनाव चिह्न लालटेन है। अगले वर्ष फरवरी में रिलीज होने वाली इस फिल्म को यूपी और बिहार में खासा पसंद किया जाएगा। बुधवार को वार्ता के दौरान भोजपुरी फिल्म अभिनेता यश कुमार ने खुद यह जानकारी दी। बताया कि फिल्म में राजनीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बड़े ही रोचक तरीके से दिखाया जाएगा। फिल्म में अभिनेत्री स्मृति सिन्हा लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की भूमिका में होंगी। (जासं)

जल्द सुलझ जाएगा महाराष्ट्र का मसला : माथुर

जयपुर : महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर का कहना है कि महाराष्ट्र का मामला एक-दो दिन में सुलझ जाएगा। भाजपा को आंख दिखाने की क्षमता अब किसी में बची नहीं है। मीडिया से बातचीत में माथुर ने कहा कि पिछले चुनाव में वे महाराष्ट्र के प्रभारी थे और उस समय भी शिवसेना ने ऐसी कोशिश की थी और यही कारण रहा कि शिवसेना के रवैये के चलते पिछली बार गठबंधन नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। हरियाणा चुनाव परिणाम के बारे में कहा कि ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। (राब्यू)

मोदी और शाह ने मनोहर को दिया सरकार चलाने का मंत्र

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार सुबह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर दोपहर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन मुलाकातों में मोदी और शाह ने मनोहर लाल को पूरे पांच साल जजपा के साथ गठबंधन सरकार चलाने का मंत्र भी दे दिया। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के लिए पिछले दो दिन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में ही हैं। सीएम रविवार चंडीगढ़ में शपथ लेने के बाद सोमवार शाम दिल्ली पहुंच गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मंगलवार रात्रि तक दिल्ली पहुंचने की सूचना थी, इसलिए मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी इसलिए ही दिल्ली में की थी। मंगलवार दिन में मनोहर लाल ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से भेंट की थी।

तय हो गया जजपा के साथ गठबंधन सरकार का प्रारूप : राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दो दिन तक केवल इसलिए ही दिल्ली में जमे रहे कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व से गठबंधन सरकार चलाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश लेने थे।

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सौजन्य से डीपीआर

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ताजा घटनाक्रमों की भी मोदी व शाह को जानकारी देते हुए राज्य मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विधानसभा सत्र में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को बनाए जाने सहित जजपा के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार मनोहर लाल ने पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात इसलिए की कि उनसे मिले दिशा-निर्देशों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श किया जा सके। सूत्र तो यह भी जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जजपा नेता दुष्यंत चौटाला के व्यवहार की भी जानकारी मुख्यमंत्री से हासिल की। मुख्यमंत्री ने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष दुष्यंत चौटाला को एक समझदार और व्यवहारकुशल युवा नेता बताया है।

अब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होगा चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री अगले दो दिन अब चंडीगढ़ में ही रहेंगे। वे पहले चुनाव के दौरान अव्यवस्थित हुए प्रशासनिक कामकाज को ढर्रे पर लाएंगे। इसके बाद वह उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी मुलाकात करेंगे ताकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा शीघ्र दोनों पार्टियों के पास आ जाए।

मनोहर के बाद दुष्यंत भी पहुंचे शाह दरबार

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को दिल्ली में काफी सक्रिय रहे। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात की। इसके बाद वह राजनीतिक मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित शाम को केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद दुष्यंत की शाह से मुलाकात के दौरान अब मंत्रिपरिषद के गठन से लेकर गठबंधन की मजबूती का खाका भी तैयार हो गया है। दुष्यंत ने शाह से मुलाकात को भी शिष्टाचार भेंट बताया, मगर उन्होंने अपने नजदीकी मित्रों को बता दिया है कि शाह उनसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं। आने वाले दिनों में जजपा को कई खुशखबरी मिलेंगी। भाजपा के नेता उनकी सक्रियता पर पैनी नजर रख रहे हैं।

दुष्यंत बुनेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की रणनीति का ताना-बाना : दुष्यंत चौटाला अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी करिश्मा दिखाने को तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार दुष्यंत चौटाला सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लगते दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं।

अजय चौटाला बोले-कांग्रेस हमारे लिए अछूत है

जागरण संवाददाता, जयपुर

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला का कहना है कि हमारा परिवार हमेशा कांग्रेस विरोधी राजनीति करता रहा है। ऐसे में कांग्रेस हमारे लिए राजनीतिक रूप से अछूत है।

जयपुर में अजय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चौटाला परिवार का कभी भी कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति करने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी (जजपा) के बीच गठबंधन मजबूत रहेगा। दोनों पार्टियां मिलकर राज्य का विकास करेंगी।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उसके साथ खड़ा होना तो दूर की बात है, हम उससे हाथ मिलाने की भी नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला में क्षमता है और वह भाजपा के साथ मिलकर हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कामयाब होंगे। हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया है। कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया था। हरियाणा का आम आदमी परेशान था, इसी कारण लोगों ने कांग्रेस को हराकर दूसरी बार भाजपा और जजपा की सरकार बनाई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोग से हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

जजपा राजस्थान और दिल्ली में करेगी विस्तार

राजस्थान से दो बार विधायक रहे अजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जजपा की मजबूती के बाद अब राजस्थान और दिल्ली में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। दोनों राज्यों के पुराने नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। चौटाला मंगलवार रात जयपुर में जजपा के महासचिव संजय चौपड़ा के आवास पर पहुंचे थे।

सपा के कुछ खुराफाती लोग उड़ा रहे विलय की अफवाह : शिवपाल

जागरण संवाददाता, रामपुर : प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ खुराफाती लोग सपा से उनकी पार्टी के विलय की अफवाह उड़ा रहे हैं। हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी में विलय होने की कोई संभावना नहीं है।

वह मंगलवार की रात दादा मियां की दरगाह लखनऊ के सज्जादानशीन सबाहत मियां के चाचा एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फरहत मियां के यहां शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण कुछ लोग बौखला गए हैं और तरह-तरह की अफवाह फैलाने में लगे हैं। अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो जाएगा। यह सरासर गलत है।

समाजवादी पार्टी के कुछ खुराफाती लोगों द्वारा यह हरकत की जा रही है। कहा कि 2022 में हमारा संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। सपा से विलय नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो किसी भी धर्मनिरपेक्ष दल के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं।

हर घर को नौकरी, किसानों का होगा कर्ज माफ : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ निशाने पर रहे रघुवर दास, आरपीएन ने कहा, बेइमानों के हैं खास

▸ कहा, भाजपा का सपना रहेगा 65 के पार जनता नहीं होने देगी 25 के पार

▸ सरकार बनी तो छह माह में भरेंगे सभी रिक्त पद : रामेश्वर उरांव

विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले कांग्रेस ने जनता से कई लुभावने वादे किए हैं। बुधवार को रांची के विधानसभा मैदान में आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय जन आक्रोश रैली में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी। किसानों की कर्ज माफी से लेकर हर घर को नौकरी देने, नौकरी नहीं देने पर भत्ता देने जैसे लोक-लुभावन वादे किए गए। यह बताने का प्रयास भी किया गया कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण जनता में आक्रोश है। आदिवासी नेताओं ने सीएनटी और भूमि अधिग्रहण कानून का मामला उठाते हुए आदिवासियों में आक्रोश होने की बात कही।

रैली में प्रदेश नेताओं के वादों का समर्थन करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर हर घर को नौकरी नहीं तो भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार के मंत्री ही सरकार पर घोटालों के आरोप लगाते हैं। कहा, मुख्यमंत्री रघुवर दास, बेइमानों के खास हैं। अपने जन आशीर्वाद यात्रा में कांग्रेस के विरुद्ध भद्दी-भद्दी बातें करते हैं और उनके ही राज्य छत्तीसगढ़ के एक विधायक ऐसा कर छत्तीसगढ़ को बदनाम नहीं करने की नसीहत देते हैं। सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री जनता के समक्ष आशीर्वाद लेने जाते हैं या कांग्रेस को गालियां देने जाते हैं? कार्यकर्ताओं से वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा भाजपा झारखंड में 65 पार का नारा दे रही है, लेकिन यहां की जनता महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह 25 के पार नहीं होने देगी।

कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के साथ आक्रोश रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता। प्रेट्र

इससे पहले, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने, छह माह में सभी रिक्त पदों को भरने, नियमित छात्रवृत्ति देने तथा भ्रष्टाचार रहित शासन देने का वादा किया। उन्होंने गांवों में टूटी-फूटी सड़कों, नदारद बिजली तथा पानी नहीं होने का हवाला देते हुए कहा कि इससे जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है। सीएनटी को खत्म करने के प्रयास से आदिवासियों में रोष है। कहा, सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करती है, जबकि कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जहां घूसखोरी नहीं है। उरांव ने गिरिडीह में मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में बच्चों को खड़ा किए जाने पर सवाल उठाया।

कांग्रेस ऑनलाइन बनाएगी सदस्य, दो नवंबर को बैठक

नईदुनिया, रायपुर : कांग्रेस के ऑनलाइन सदस्यता अभियान को लेकर शनिवार को दिल्ली में बैठक रखी गई है। इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा प्रदेश महामंत्री प्रशासनिक, जिलाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के प्रभारी सचिवों को बुलाया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश महामंत्री गिरिश देवांगन व अण भद्रा और जिलाध्यक्ष रवाना होंगे।

मिशन-2024 के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया है। पिछले माह उन्होंने प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं की दो दिन बैठक लेकर मिशन-2024 पर चर्चा की थी। दोनों दिन उन्होंने सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया था। सोनिया ने 2022 तक सदस्यता अभियान को गंभीरता से चलाने के लिए कहा है। हर राज्य को सदस्यों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य मिला है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग छह लाख सदस्य हैं, जिसे बढ़ाकर 12 लाख करना है। अभी तक कांग्रेस रसीद बुक के माध्यम से सदस्य बनाया करती थी, लेकिन अब रसीद बुक के अलावा ऑनलाइन सदस्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पार्टी एप जारी करेगी। प्रदेश पदाधिकारियों का कहना है कि दो नवंबर को होने वाली बैठक में एप का प्रेजेंटेशन होगा।

बायोडाटा, आधार कार्ड अपलोड करना होगा : प्रदेश पदाधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन सदस्यता अभियान में नए सदस्यों को डिजिटल फॉर्म भरना होगा। उसके साथ उन्हें अपना बायोडाटा, फोटो, वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें ईमेल या मैसेज के माध्यम से सदस्यता क्रमांक भेजा जाएगा। जिन स्थानों पर इनेनट या ऑनलाइन सदस्य बनाने की सुविधा नहीं होगी, वहां रसीद काटकर सदस्य बनाए जाएंगे।

बंगाल विस उपचुनाव

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने पार्टी लाइन में संशोधन के दिए संकेत, बैठक में सूर्यकांत मिश्रा, सोमेन मित्रा और विमान बोस रहे मौजूद

कांग्रेस दो और माकपा एक सीट पर उतारेगी प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▸ बंगाल में खोते जनाधार के बीच एक दूसरे का जनाधार बने कांग्रेस और माकपा

▸ बैठक में गठबंधन के भविष्य के साथ ही दोनों दलों की आगामी रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद

▸ बीते लोकसभा चुनाव में माकपा नहीं खोल सकी थी खाता

सीताराम येचुरी। फाइल

राज्य में खोते जनाधार के बीच वजूद बचाने को एक-दूसरे का हाथ थाम कांग्रेस-माकपा वैतरणी पार करने को बेताब हैं और यही वजह है कि राज्य के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनाव में जीत दर्ज करने को माकपा किसी भी समझौते को तैयार है। वहीं वाम दलों के बैठक में खड़गपुर सदर और कालियागंज सीट कांग्रेस को देने व करीमपुर सीट पर प्रत्याशी उतारने की बात पर मुहर लगी है। बैठक में राज्य माकपा सचिव सूर्यकांत मिश्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा और वाममोर्चा अध्यक्ष विमान बोस मौजूद रहे। सूत्रों की मानें तो बैठक में गठबंधन के भविष्य के साथ ही दोनों दलों की आगामी रणनीति समेत अन्य कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दरअसल, बीते लोकसभा चुनाव में रायगंज सीट पर बात न बनने की सूरत में माकपा-कांग्रेस गठबंधन की गांठ बंधते-बंधते रह गई थी, जिसका खामियाजा दोनों ही दलों को भुगतना पड़ा। ऐसे में पिछली गलतियों से सीख लेते हुए दोनों ही दलों ने साथ मिलकर आगे चलने का निर्णय लिया है और इसके लिए हर मोर्चे पर माकपा समझौते को तैयार नजर आ रही है। गौर हो कि बीते लोकसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस को दो सीटें तो माकपा व उसके सहयोगी दलों का तो खाता भी नहीं खुल सका था। ऐसे में दोनों ही दलों को यह बात समझ में आ गई है कि अगर राज्य की सियासत में खुद के वजूद को बचाए रखना है तो गठबंधन ही एक मात्र जरिया है। हालांकि, माकपा में कुछ निर्दिष्ट पार्टी लाइन निर्धारित है। जिसके तहत वे कांग्रेस के साथ कोई सियासी समझौता नहीं कर सकते है, लेकिन माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने संकेत दिए हैं कि निर्धारित मसौदे में कुछ संशोधन किए जाएंगे और इसके पीछे वजह है कि पार्टी फिलहाल अकेले चुनावी मैदान में उतर जीत दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। माकपा नेताओं की मानें तो गठबंधन के जरिए ही राज्य में भाजपा व सत्ताधारी दल तृणमूल को रोकना संभव है। इसके लिए जरूरी है कि माकपा व कांग्रेस सीट बंटवारे से पहले क्षेत्रवार अपनी शक्ति का सही तरीके से आकलन करे और फिर उम्मीदवार देने की दिशा में अग्रसर हो या फिर दावेदारी पेश करें। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि ये गठबंधन केवल उपचुनाव के लिए ही नहीं, बल्कि आगामी नगर निगम व पालिका चुनाव भी जस की तस रहेगी। बता दें कि आगामी 25 नवंबर को कालियागंज, खड़गपुर सदर और करीमपुर विधानसभा में उपचुनाव को मतदान होना हैं, जबकि 28 नवंबर को मतगणना होगी।

मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन करेगी भाजपा, दिग्गजों ने बनाई रणनीति

नईदुनिया, भोपाल

▸ इंदौर सहित जबलपुर और अन्य शहरों में भी होंगे आंदोलन

मध्य प्रदेश में विपक्षी दल के रूप में भाजपा की 15 साल पुरानी धमक अब एक बार फिर सुनाई देगी। भाजपा अब कमलनाथ सरकार को घेरने के लिए एक के बाद एक आंदोलन करने की रणनीति बना रही है। पार्टी के कोर ग्रुप यानी दिग्गज नेताओं ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में इस बारे में मंथन किया। इसमें कई चरणों के आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। इसमें सबसे पहले भोपाल नगर निगम के बंटवारे और नगरीय निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष आधार पर करवाए जाने के खिलाफ आंदोलन होगा।

इंदौर-जबलपुर नगर निगम को बांटने पर भी पार्टी सड़क पर उतरेगी। पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त वैट से लेकर भाजपा उन मुद्दों के खिलाफ माहौल बनाएगी, जिन्हें कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया था। बैठक में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे।

जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' के साथ बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि फिलहाल सभी बड़े नेताओं के साथ बातचीत करके सुझाव लिए गए हैं। आगे इन पर व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आंदोलन की तारीख और स्थान आदि का चयन भी अलग से किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश में कमलनाथ सरकार की असफलताओं के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहती है। प्रस्तावित संगठन चुनाव के बाद प्रदेश में पार्टी का नया संगठन खड़ा हो जाएगा। बूथ से लेकर जिला और प्रदेश में नई टीम के साथ पार्टी वैसे ही आंदोलन खड़ा करना चाहती है, जैसे 15 साल पहले विपक्ष में रहते हुए भाजपा किया करती थी।

नए सूरज के उदय के साथ राज्य में बदल जाएंगे राजनीतिक–प्रशासनिक तौर–तरीके

111 विस सीटें एकीकृत जम्मू–कश्मीर में

04 सीटें लद्दाख क्षेत्र की, जिनका अस्तित्व खत्म

24 आरक्षित सीटें गुलाम कश्मीर के लिए

83 सीटें बचेंगी केंद्र शासित जम्मू–कश्मीर में

02 सीटें मनोनयन के जरिये भरी जाएंगी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। मुख्यमंत्री के अधिकार भी सीमित रहेंगे। विधानसभा की सीटों की संख्या 107 होगी, जिसे परिसीमन के बाद 114 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के संवैधानिक मुखिया राज्यपाल नहीं होंगे। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल ही प्रमुख प्रशासक होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में विधान परिषद नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर विधान परिषद को 17 अक्टूबर को ही राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 57 के तहत समाप्त कर दिया था।

एकीकृत जम्मू-कश्मीर जिसका लद्दाख भी हिस्सा रहा है, में विधानसभा की 111 सीटें थीं। इनमें चार सीटें लद्दाख प्रांत की हैं, जिन्हें हटाए जाने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 107 सीटें रह गई हैं। लद्दाख के अलग केंद्र शासित क्षेत्र बन जाने से उसकी चारों विधानसभा सीटों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मौजूदा परिस्थितियों में अगर विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो 83 सीटों पर ही चुनाव होगा। इसके अतिरिक्त दो सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। गुलाम कश्मीर के लिए आरक्षित 24 सीटों पर पहले की तरह ही कोई चुनाव नहीं होगा। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों को 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा।

श्रीनगर स्थित राज्य सचिवालय में राष्ट्रध्वज के साथ लहराने वाला जम्मू–कश्मीर का ध्वज 67 साल बाद 25 अगस्त को उतार दिया गया। ● फाइल फोटो

अधिकतम नौ मंत्री बन सकेंगे

केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति पूरी तरह दिल्ली और केंद्र शासित पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के समान होगी। मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में अधिकतम नौ विधायकों को ही मंत्री बना सकेंगे। इसके अलावा राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू किया जा सकेगा। उपराज्यपाल चाहें तो किसी भी बिल या प्रस्ताव को नकार सकते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री या राज्य विधानसभा के प्रस्ताव को मंजूरी देना बाध्यकारी नहीं होगा। राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी पांच साल ही रहेगा, जबकि एकीकृत जम्मू कश्मीर में यह छह साल था।

राजस्व विभाग राज्य सरकार के होगा अधीन

राजस्व विभाग पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन होगा। कृषि भूमि, कृषि ऋण, कृषि भूमि के हस्तांतरण–स्थानांतरण के अधिकार, उद्योगों के लिए जमीन देना राज्य सरकार के अधीन ही होगा। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी अधिकार भी राज्य सरकार के अधीन ही रहेंगे।

केंद्र शासित राज्य में हम सब होंगे हिंदुस्तानी

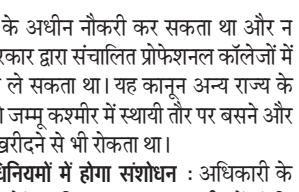

अनुच्छेद 370 और 35ए की बेड़ियों में जकड़ी 'जन्नत' होगी आजाद, सभी राज्यों के लोगों को समान अधिकार

राज्य ब्यूरो, जम्मू : नये जम्मू कश्मीर में हर रोज की तरह 31 अक्टूबर को भी सूरज निकलेगा, लेकिन इसकी लालिमा जुदा होगी। नया जोश, नया उत्साह और नई व्यवस्था होगी। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी एक विधान, एक संविधान और एक निशान होगा। जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित हो जाएगा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर और राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। बेड़ियों में जकड़ा जम्मू कश्मीर सही मायने में अब आजाद होगा।

70 वर्षों से भेदभाव, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद की राजनीति का कारण अस्तित्व में रहा अनुच्छेद 370 और 35ए 31 अक्टूबर के बाद इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। इन अनुच्छेद के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। अब कोई इसे याद भी नहीं करना चाहता। लोगों को उम्मीद है कि अंतिम सांसें ले रहा आतंकवाद और अलगाववाद नये जम्मू कश्मीर में पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

जम्मू कश्मीर के हालात को अगर किसी ने सबसे ज्यादा झेला है तो वे हैं यहां के स्थानीय युवा। न रोजगार के साधन, न शिक्षा के उचित प्रबंध। भ्रष्टाचार में लिप्त तंत्र और परिवारशाही ने युवाओं की उम्मीदों को पूरी तरह से कुचल दिया था। मनोरंजन के नाम पर जले हुए सिनेमाघर और खेल के नाम पर उदासीनता। यही कारण रहा कि अलगाववाद ने युवाओं के हाथों में पत्थर और आतंकवाद ने बंदूक थमा दी। पूरे देश व दुनिया के सामने कश्मीर के युवा पत्थरबाज और आतंकी बन गए। अब स्थानीय युवाओं को उम्मीद है कि नये जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश बनने से रोजागार के अवसर बढ़ेंगे। मनोरंजन के साधन होंगे। खेलों में युवा दमखम दिखा सकेंगे।

कश्मीर में पांच अगस्त के बाद पत्थरबाजी की नाममात्र घटनाओं ने साबित कर दिया है कि युवा क्या चाहते हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से देश-विदेश से निवेश की संभावना हैं। केंद्र सरकार जल्द ही यहां अंतरराष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन भी कराने जा रही है।

केंद्रीय कानून भ्रष्टाचार पर लगाएंगे लगाम: भले ही राज्यपाल शासन में भ्रष्ट तंत्र पर चोट शुरू कर दी गई और हजारों करोड़ के घोटाले सामने आए हों, मगर अब भी सख्त कानूनों के अभाव में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा पूरी तरह से नहीं कसा जा सका। केंद्रीय कानून लागू होने के साथ अब यह काम और सख्ती से किया जा सकेगा। भ्रष्ट तंत्र को चोट पहुंचेगी और तेज विकास की राह खुलेगी। इससे कश्मीर फिर से स्वर्ग बन पाएगा। पंचायतों के सशक्तीकरण से राज्य में ग्रामीण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। केंद्र सरकार सीधे पंचायतों के खाते में पैसा भेज रही है। अभी तक केंद्र के पैसे पर कुछ ही लोग कुंडली मारे रहते थे। फिर भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जाता था कि आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं की बाट जोहता रहता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा।

कर्मचारी भी हैं खासे उत्साहित: 31 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए दिवाली से कम नहीं होगा। केंद्र सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि राज्य कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से कर्मचारी खासे उत्साहित हैं।

बेटी कभी पराई नहीं होगी: जम्मू कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से राज्य की बेटियां बेहद खुश हैं। अनुच्छेद 35ए की वजह से पहले जम्मू कश्मीर से बाहर ब्याही गई बेटियों व उनके बच्चों के सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। वह अपने पिता की संपत्ति से भी वंचित हो जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर की बेटी कभी पराई नहीं होगी।

वाकई, कश्मीर की आबोहवा बदली हुई नजर आ रही है। सामान्य होते हालात के बीच परीक्षा देती छात्राएं। ● एएनआइ

अब गुलाम कश्मीर होगा मुद्दा

अनुच्छेद 370 और 35ए की वजह से ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हमेशा विवादित क्षेत्र कहकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जाने की गीदड़ भभकी देता रहता था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब मुद्दा कश्मीर नहीं बल्कि गुलाम कश्मीर बनेगा। दिवाली के दिन राजौरी में जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ शब्दों में कहा कि गुलाम कश्मीर की कसक मेरे अंदर है। इसके अलावा लद्दाख भी केंद्र शासित बनने से क्षेत्र में चीन का दखल कम होगा।

अब अलग निशान और विधान होगा खत्म, लागू होंगे 106 केंद्रीय कानून

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 31 अक्टूबर को उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण करने के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम समेत 106 केंद्रीय कानून लागू हो जाएंगे। साथ ही 153 प्रादेशिक व राज्य अधिनियम के तहत बने 11 कानून समाप्त हो जाएंगे।

गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 लागू होने के चलते जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था, जिसका अपना संविधान था। यह संविधान जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा को अपने स्तर पर कानून बनाने और किसी केंद्रीय कानून के राज्य में क्रियान्वयन को रोकने में समर्थ बनाता था। अलबत्ता, पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद जम्मू कश्मीर का अलग निशान-विधान समाप्त हो गया है। अब 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सभी केंद्रीय कानून लागू हो जाएंगे।

ये हैं मुख्य कानून : एक अधिकारी ने बताया कि अधिकांश केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में पहले से ही लागू थे, जो नहीं थे, वह 31 अक्टूबर के बाद लागू हो जाएंगे। इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, केंद्रीय सूचना अधिनियम, शत्रु संपत्ति अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर रोक संबंधी कानून व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम मुख्य हैं।

35ए पूरी तरह से निष्प्रभावी : जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35ए पूरी तरह से निष्प्रभावी रहेगा। यही संवैधानिक प्रावधान था, जो यहां स्टेट सब्जेक्ट को अनिवार्य बनाते हुए राज्य विस को स्थानीय लोगों के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार देता था। कोई भी गैर रियासती नागरिक जम्मू कश्मीर में न राज्य सरकार के अधीन नौकरी कर सकता था और न राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिला ले सकता था। यह कानून अन्य राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में स्थायी तौर पर बसने और जमीन खरीदने से भी रोकता था।

कई अधिनियमों में होगा संशोधन : अधिकारी के मुताबिक केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, जम्मू कश्मीर एलाइनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जम्मू कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम, जम्मू कश्मीर कृषि व कृषक सुधार अधिनियम में नई व्यवस्था के मुताबिक आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

बदलाव की बयार

जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में सचिवालय के बाहर सरकारी दस्तावेज से भरे ट्रक की जांच करते सुरक्षाकर्मी। ● जागरण

- **जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में मानवाधिकार आयोग प्रभावी होगा**
- **अन्य राज्यों के लोग भी अब बना सकेंगे स्थायी आशियाना**

ऐतिहासिक भूल सुधार

भारत के भू राजनीतिक एकीकरण के सूत्रधार 'लौहपुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल की आज 144वीं जयंती है। आजादी के बाद बंटवारे के समय भारतीय रियासतों के विलय से स्वतंत्र भारत को नए रूप में गढ़ने वाले पटेल भारत के सरदार के रूप में जाने जाते हैं। वह अपने अदम्य साहस व प्रखर व्यक्तित्व के कारण ही भारत को एक धागे में पिरोने में कामयाब हो सके। किसान परिवार में जन्मे पटेल ने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की, लेकिन मन मस्तिष्क पर महात्मा गांधी के विचारों का ऐसा असर हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने को समर्पित कर दिया। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने और उसे एक सूत्र में पिरोने में उनके योगदान के लिए 2014 से हर साल उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) पर विशेष

भारतीय एकता के शिखर पुरुष सरदार पटेल को जम्मू-कश्मीर एकीकरण का मसला न देना हुई ऐतिहासिक भूल

कश्मीर पर नेहरू नीति से नाखुश

कश्मीर छोड़ देश की सभी छोटी–बड़ी रियासतों के विलय का जिम्मा पटेल उठा रहे थे। कश्मीर मसले को उन्होंने कभी स्वतंत्र रूप से डील नहीं किया।

कश्मीर का मसला **जवाहर लाल नेहरू** के पास था। कश्मीर को लेकर भारत के अंतिम वॉयसराय माउंटबेटन का मानना था कि अब यह विवाद दोनों देशों की आपसी बातचीत से नहीं सुलझने वाला है। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा करे। नेहरू इसके लिए तैयार हो गए। वहीं पटेल को इस पर आपत्ति थी लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। संघर्षविराम को मान लेने की वजह से जम्मू–कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था और इससे भी पटेल खुश नहीं थे। अगर इस रियासत के विलय के जिम्मा पटेल पर होता तो इसकी ऐसी हालत नहीं होती। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर इस ऐतिहासिक भूल का सुधार कर दिया है।

562 रियासतों का विलय कराने वाले सरदार

जब भारत आजाद हुआ तो उस समय देश में छोटी–बड़ी 562 रियासतें थीं। इन देशी रियासतों का स्वतंत्र शासन में यकीन था और यह सोच ही सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी। सरदार पटेल तब अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री के साथ देश के गृहमंत्री थे। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को छूट दी थी कि वे स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। या फिर स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। यह अंग्रेजों की कुटिल चाल थी। उधर **मोहम्मद अली जिन्ना** इन रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने के लिए प्रलोभन दे रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में पटेल ने तबके वरिष्ठ नौकरशाह वीपी मेनन के साथ मिलकर नवाबों व राजाओं से बातचीत शुरू की। पटेल ने रियासतों के समक्ष प्रिवी पर्सेज के माध्यम से आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रखा। परिणाम हुआ कि आजादी के दिन तक अधिकतर रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया। बच गए तो जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू–कश्मीर।

त्रावणकोर की कहानी

त्रावणकोर के दीवान ने घोषणा कर रखी थी कि महाराजा एक अलग देश बनाएंगे। महाराजा को अपने पास से एक बंदरगाह व यूरेनियम के भंडार छिन जाने का डर था। जिन्ना ने भी महाराजा से स्वतंत्र रिश्ते रखने का अनुरोध किया। इसी दौरान एक युवक ने त्रावणकोर के दीवान के चेहरे पर छुरे से वार कर दिया। डरे महाराजा 14 अगस्त को विलय पर राजी हो गए।

हैदराबाद के निजाम को घुटने के बल आना पड़ा

हैदराबाद देश की सबसे बड़ी रियासत थी। उसका क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा था। हैदराबाद के निजाम अली खान आसिफ ने फैसला किया कि उनका रजवाड़ा न तो पाकिस्तान और न ही भारत में शामिल होगा। हैदराबाद में निजाम और सेना में वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम थे लेकिन वहां की लगभग 85 प्रतिशत आबादी हिंदू थी। निजाम ने 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और पाकिस्तान से हथियार खरीदने की कोशिश में लग गए। तब पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। 17 सितंबर को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए।

जूनागढ़ के नवाब की ना नुकुर

जूनागढ़ के **नवाब महावत खान** की रियासत का अधिकतर हिस्सा हिंदुओं का था। जिन्ना और मुस्लिम लीग के इशारे अल्लाबख्श को अपदस्थ करके यहां शाहनवाज भुट्टो को दीवान बनाया गया। जिन्ना नेहरू के साथ जूनागढ़ के बहाने कश्मीर की सौदेबाजी करना चाहते थे। 14 अगस्त, 1947 को महावत खान ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का एलान किया, तब सरदार पटेल उखड़ गए। उन्होंने जूनागढ़ में सेना भेज दिया। जूनागढ़ की जनता ने भी नवाब का साथ नही दिया। इस बीच बढ़ते आंदोलन को देखकर नवाब महावत खान कराची भाग गया। आखिरकार नंवबर, 1947 के पहले सप्ताह में शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को खारिज कर उसके हिंदुस्तान में विलय की घोषणा कर दी। इस तरह 20 फरवरी, 1948 को जूनागढ़ देश का हिस्सा बन गया।

लक्षद्वीप समूह पर भारतीय ध्वज देख

पटेल ने लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज भेजा। इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लक्षद्वीप के पास मंडराते देखे गए, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा।

नहीं रहेगा विधायक और मुख्यमंत्री का वह रुतबा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी होगा और विधायक भी। मंत्रिपरिषद भी होगी। अगर नहीं होगा तो विधायक-मुख्यमंत्री का वह रुतबा व प्रोटोकाल, जो पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर में उन्हें प्राप्त था।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में राज्य विधानसभा होगी। घाटी में हालात पूरी तरह सामान्य होते ही केंद्र सरकार राज्य विधानसभा के गठन को अंतिम रूप देने की कार्ययोजना लागू करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र, राज्य, केंद्र शासित राज्यों, अदालतों व अन्य संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों की प्रतिष्ठा और प्रोटोकाल का जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, उसके मुताबिक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख के उपराज्यपाल को 11वें स्थान पर रखा गया है और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री प्रोटोकाल वारंट के मुताबिक 15वें स्थान पर रहेंगे। प्रोटोकाल में किसी भी पूर्ण राज्य के राज्यपाल को चौथे नंबर पर रखा गया है। पहले पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री हैं।

ये होंगें उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से ऊपर : पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपप्रधानमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्यसभा व लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत रत्न से सम्मानित विशिष्ट नागरिक, राजदूत, सर्वोच्च न्यायालय के जज, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव अधिकारी, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक भारत सरकार, पूर्ण राज्यों के उपमुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैबिनेट सचिव भी प्रोटोकाल के मामले में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से ऊपर होंगे। मुख्यमंत्री जब भी राज्य से बाहर होंगे तो उन्हें 25वें स्थान के मुताबिक प्रोटोकाल व सुविधाएं मिलेंगी।

पुलिस पर नहीं चलेगा हुक्म

राज्य पुलिस और इससे संबंधित संस्थाएं पूरी तरह से उपराज्यपाल के जरिये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन रहेंगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और अखिल भारतीय सेवा कैडर की नौकरशाही भी उपराज्यपाल के अधीनस्थ होगी।

तबादले भी नहीं कर सकेंगे

केंद्र शासित राज्य को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए गत दिनों अभियोजन शाखा को एक अलग प्रशासनिक विंग के रूप में मान्यता दी गई। पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप पूरी तरह बंद हो जाएगा, क्योंकि यह फैसला उपराज्यपाल या फिर केंद्रीय गृहमंत्रालय ही अपने स्तर पर लेगा। फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी के दल–बल में भी आवश्यक सुधार के कदम उठाए गए हैं।

दिल जीत गए मलिक

राज्य ब्यूरो, जम्मू : भ्रष्टाचार, अलगाववाद और एजेंडों की राजनीति पर आघात कर राज्यपाल सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर का दिल जीत गए। उन्होंने राजनीतिक दलों की कमियों को उजागर किया। लोगों को बताया कि लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहे दलों ने केंद्र सरकार से मिले अरबों रुपये के फंड का दुरुपयोग किया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मलिक ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के खिलाफ हमला तेज कर दिया था। उन्होंने अपना घर भरने वाले कश्मीर के नेताओं के साथ नौकरशाहों को भी नहीं बख्शा। मलिक ने जम्मू कश्मीर बैंक के भ्रष्ट प्रबंधन का चेहरा बेनकाब किया। उनके प्रयासों से 582 ऐसे युवाओं को नौकरी मिली जिनसे फर्जीवाड़ा कर उनकी जगह दूसरे युवाओं को नौकरी दे दी गई थी। नौकरी पाने वाली ऐसी ही एक युवती ने श्रीनगर में उनसे कहा था कि अल्लाह ने राज्यपाल को उनके लिए ही जम्मू कश्मीर में भेजा था।

असीम संभावनाएं | 31 कंपनियों ने 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जताई, लगभग 45 एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट भी जमा कराए

यूं बदल जाएगा बहुत कुछ, बड़े पैमाने पर होगा निवेश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लददाख में 31 अक्तूबर को सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बदलेगी, रोजगार से लेकर औद्योगिक निवेश का परिदृश्य भी बदल जाएगा।सूचना प्रौद्योगिकी, ढांचागत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, होटल, प्रतिरक्षा, कौशल विकास और पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में देश के 31 नामी व्यावसायिक घरानों और कंपनियों ने लगभग 15 हजार करोड़ का पूंजी निवेश करने की इच्छा जताते हुए लगभग 45 एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट भी जमा कराए हैं। इनमें से कई ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का हवाला देते हुए डेढ़ दशक के लिए टैक्स हॉलिडे का आग्रह भी किया है।

यहां कहना असंगत नहीं होगा कि राज्य में 2013 के दौरान भी देश विदेश की विभिन्न कंपनियों से करीब 450 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो वर्ष 2017 में बढ़कर 1008 करोड़ तक पहुंचे थे। लेकिन 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर व लद्दाख में निवेश को लेकर विभिन्न कंपनियों ने बेझिझक दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। करीब 70 कंपनियों ने निवेश के लिए राज्य प्रशासन के साथ विभिन्न स्तरों पर संपर्क किया है।

ये हैं निवेश के लिए आगे आने वाली प्रमुख कंपनियां: राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अनुसार, केंद्र शाासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख में निवेश की इच्छा के साथ ईओआइ (एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट) जमा कराने वाली कंपनियों में श्री सीमेंट्स, डालमिया सीमेंट्स, कृष्णा हायड्रो प्रॉजेक्ट, एसकाट इंफ्रास्ट्रकचर, एलएम एनर्जी एंड साफ्टवेयर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, रिलायंस कम्यूनिकेशन्स, प्रिसिशन इंडस्ट्रीयल सिस्टम, इंडस वैली अयूर विलास, ओंकारेश्वर ट्रेड लिंक्स, सीवीके ग्रुप, पेपर बोट डिजायन स्टुडियो, केआर पेपर लिमिटेड, पोवाल लैब्स, विशाल एजूटेक प्राईवेट लिमिटेड, सेवक लिमिटेड, प्रकाश एम्यूजमेंट राईड्स एंड फन वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड और मचानी ग्रुप हैं। यह कंपनियां शुरू में 15 हजार करोड़ का निवेश कर रही हैं। इस निवेश को मार्च माह के दौरान 35 हजार करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुछ और औद्योगिक घरानों व निवेशकों के साथ भी संपर्क-संवाद किया जा रहा है।

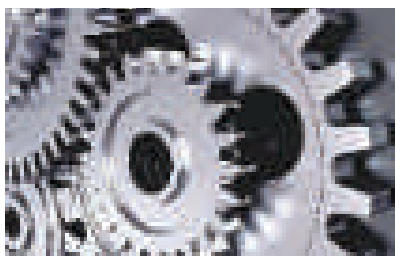

12 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर काम शुरू

ईओआई जमा कराने वाली कंपनियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा इन कंपनियों को उनके निवेश लायक इकाईयां स्थापित करने के लिए योग्य जमीन को चिह्नित करने में भी कंसल्टेंसी की मदद ली जा रही है। वादी में 250 कनाल से ज्यादा जमीन चाहिए। संबधित कंपनियों को अपने उपक्रम में 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को ही देनी होगी। निवेश की इच्छुक कंपनियों ने कारोबार और विभिन्न इलाकों को विकसित करने की पूरी योजना सामाजिक और पर्यावरण के अनुकूल तैयार की है।

कंबल निर्माता फिरोज बोले– अब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

कंबल निर्माता फिरोज अहमद फाफू ने कहा कि कश्मीर में हर प्रकार के उद्योग के लिए काफी संभावनाएं हैं। यहां लोग निवेश से डरते थे, क्योंकि अनुच्छेद 370 की दीवार थी। इससे भी ज्यादा सरकारी तंत्र में कथित भ्रष्टाचार और उस पर आतंकवाद का डर था। अब वह खत्म हो गया है। प्रशासनिक तंत्र भी बदल गया है। केंद्र सरकार अब सीधे राज्य के प्रशासन को देख रही है। आतंकवाद में भी कमी आई है। इसलिए अब यहां बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होगा। दिल्ली,पंजाब और हरियाणा में कई व्यापारियों व निवेशकों ने मुझसे संपर्क कर, मेरे साथ भागीदारी में यहां होटल इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा जताई है। यहां अब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

1949 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मुहिम छेड़ी थी। चार मई 1949 को एसोसिएशन के प्रधान छिवांग रिगजिन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को ज्ञापन सौंप कर लद्दाख को केंद्र सरकार से अपने नियंत्रण में लेने की अपील की थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 31 अक्टूबर 2019

कश्मीर पर बाहरी दखल कुबूल नहीं की नीति सरकार ने पलटी : कांग्रेस

हमला ▶ यूरोपीय सांसदों के कश्मीर दौरे को बताया इतिहास की सबसे बड़ी चूक

प्रियंका ने पूछा, इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर की पहुंच पीएमओ तक कैसे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने यूरोपीय संघ के सांसदों के जम्मू-कश्मीर दौरे को लेकर सरकार को घेरा है। पार्टी ने इसे भारत के आंतरिक मामले में तीसरे पक्ष का दखल करार दिया है। कांग्रेस के अनुसार 72 साल से जम्मू-कश्मीर में किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करने की भारत की सफल नीति को मोदी सरकार ने तोड़ दिया है। कांग्रेस ने इन सांसदों को घुमाने के फैसले को अपरिपक्व, विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण करार दिया है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इन सांसदों को बुलाने वाली मादी शर्मा की पीएमओ तक पहुंच पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, 'किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री से मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है, ताकि वो अपनी परेशानियां उनको सुना सकें। लेकिन, हां, मादी शर्मा जैसी इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर गर्व से लिख सकती हैं, 'भारत आइए हम आपके खर्चे भी वहन करेंगे।' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'पीएम दफ्तर तक हमारी पहुंच है, हम प्रधानमंत्री के साथ बैठक की व्यवस्था करेंगे। इन बिजनेस ब्रोकरों की पीएमओ तक पहुंचे कैसे हो गई।'

रणदीप सुरजेवाला। एएनआइ

कांग्रेस नेताओं को कारण बताओ नोटिस

राज्य, जम्मू : प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से दिल्ली और श्रीनगर में मिलने वाले नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें पूर्व विधायक उस्मान मजीद, सुरिंदर सिंह और प्रवक्ता फारूक अंद्राबी शामिल हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि कुछ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व से अनुमति लिए बिना यूरोपीय संघ के सांसदों से मुलाकात की है। उनसे एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के औपचारिक बंटवारे की अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इन सांसदों को प्रचार के हथकंडे के तहत बुलाकर मोदी सरकार ने पिछले 72 साल की भारत की जांची और परखी जम्मू-कश्मीर नीति को उलटने का सबसे बड़ा चूक किया। शुरू से भारत का यह मत रहा है कि जम्मू-कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है और हमें किसी तीसरे पक्ष, समूह या व्यक्ति का दखल स्वीकार नहीं है। लेकिन बीते तीन दिनों में पीएम मोदी की इन सांसदों से मुलाकात से लेकर उन्हें श्रीनगर भेजने की कवायद कर सरकार ने इस नीति को पलटने का अक्षम्य अपराध किया है।

सरकार ने प्रजातंत्र का किया अपमान: विपक्षी सांसदों को एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर वहीं से वापस भेजे जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने विदेशी सांसदों को वहां भेज भारत की संसद और प्रजातंत्र का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत की कूटनीति को एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के हाथों गिरवी रख दिया गया है।

यूरोपीय सांसदों को भारत लाने वाली मादी शर्मा से सरकार के जुड़ाव पर सवाल दागते हुए इनके महिला आर्थिक व सामाजिक थिंक-टैंक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉन अलाइड स्टडीज से रिश्ते स्पष्ट करने की मांग की। सुरजेवाला ने सरकार से यह भी पूछा कि मादी शर्मा किस हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन सांसदों की मीटिंग तय कर रही थीं। इस मामले में विदेश मंत्रालय की भूमिका को क्यों दरकिनार किया गया और भारत सरकार ने इस यात्रा का खर्च क्यों वहन किया?

भारतवंशी अटॉर्नी ने कहा कश्मीर भेजें विशेष टीम

वाशिंगटन, प्रेट्र : एक भारतवंशी अटॉर्नी ने अमेरिकी सांसदों से कश्मीर के लिए संसद की विशेष समिति गठित करने की मांग की है। यह मांग यूरोपीय संघ (ईयू) के 23 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर पहुंचने के एक दिन बाद ही उठाई गई है।

अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की एशिया, प्रशांत और अप्रसार उप समिति को मंगलवार को सौंपे हलफनामे में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी रवि बत्रा ने एक संसदीय दल कश्मीर भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने इस दल में ऐसे अमेरिकी सांसदों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जिनकी छवि बेदाग हो। उन्होंने कहा है कि इससे विश्वसनीय सूचना मिलेगी और लोग आश्वस्त होंगे। साथ ही वहां पाबंदियों को खत्म करने में भी मदद मिलेगी व भारत या किसी आगंतुक पर खतरे का भी पता चल सकेगा।

हलफनामे में बत्रा ने कहा है कि 9/11 के बाद दुनिया से आतंकवाद का सफाया करना अमेरिका की प्राथमिकता में शामिल हो चुका है।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पहले से सक्रिय हैं मादी शर्मा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संग्रप के कार्यकाल में भी यूरोपीय देशों से राजनेताओं के दल को भारत लाती रहीं हैं डल्यूइएसटीटी की प्रमुख

यूरोपीय संघ के सांसदों के जम्मू-कश्मीर दौर में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चित हुआ है तो वह है मादी शर्मा का। माना जाता है कि यूरोपीय संघ के 27 सांसदों को एक साथ जुटाकर भारत लाने और उन्हें जम्मू-कश्मीर के भ्रमण पर ले जाने में मादी शर्मा और उनके एनजीओ वूमंस इको-नोमिक एंड सोशल थिंक टैंक (डब्ल्यूइएसटीटी) का ही योगदान रहा है। वैसे मादी शर्मा भारतीय कूटनीतिक सर्किल में खास तौर पर यूरोपीय देशों के साथ कूटनीति से जुड़े वर्ग में जाना-पहचाना चेहरा हैं। संग्रप के कार्यकाल में भी वह यूरोप से राजनेताओं के दल को भारत लाती रही हैं। उन्होंने 2018 में भी मालदीव में चुनाव के दौरान यूरोपीय संघ के सांसदों को वहां ले जाने का काम किया था।

समूह के बारे में कहा जा रहा है कि यह कई अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क यूरोपीय देशों के राजनेताओं को भारत के अलावा दूसरे देशों में भी यात्रा आयोजित कराती रही है। मादी शर्मा का असली नाम मधु शर्मा है। शर्मा बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में रहने वाली भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में खुद को सोशल कैप्टिलिस्टः इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर व स्पीकर के तौर पर बताया है। उनके संगठन ने यूरोपीय सांसदों को भारत आने के लिए जो पत्र लिखा था उसे खुद कुछ सांसदों ने सार्वजनिक किया है। इसमें उनसे वादा किया गया है कि भारत दौरे के दौरान उन्हें कश्मीर की यात्रा कराई जाएगी और उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलवाया जाएगा। इस बारे में ईयू के 30 सांसदों को सात अक्टूबर को ईमेल भेजा गया था।

मादी शर्मा। फाइल फोटो

मादी की वेबसाइट के मुताबिक, यह संस्था महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करती है। राजनीतिक स्तर पर यह एनजीओ अहम मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन इससे कोई व्यावसायिक फायदा नहीं उठाता। मादी शर्मा यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी की सदस्य भी हैं। मादी ने अनुच्छेद-370 पर एक लेख भी लिखा था, जो एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। लेख का शीर्षक था-आर्टिकल-370 को खत्म करना जीत और कश्मीरी महिलाओं के लिए चुनौती क्यों है? मादी शर्मा कई कंपनियों की प्रमुख भी हैं। उनकी आयात-निर्यात कंपनी, टूर कंपनी, बिजनेस ब्रोकरेज कंपनी, कंसल्टेंसी फर्म और बैंक ऑफिस रिसोर्स सॉल्यूशन कंपनी भी है। उनकी इस एनजीओ के कम से कम 14 देशों में सदस्य मौजूद हैं। सनद रहे कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी ईयू सांसदों के भारत लाने, उनकी पीएम मोदी से मुलाकात कराने और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ले जाने में मादी शर्मा की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि मादी शर्मा की यहां कितनी पैठ है।

घाटी छोड़ने के लिए श्रमिकों को मिल रही थीं आतंकियों की धमकियां

दीपक भट्टाचार्य, मुर्शिदाबाद

एक दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर से लौटे जरीस शेख भोजन करने बैठे ही थे कि बेटे नइमुद्दीन शेख को आतंकियों द्वारा गोलियों से छलनी कर दिए जाने की खबर पहुंच गई। यह सुनने के बाद पिता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का हाल-बेहाल हो गया। मारे गए अन्य श्रमिकों के परिजनों का भी यही हाल है। उधर, जरीस शेख ने बताया कि श्रमिकों को घाटी छोड़ने के लिए आतंकियों की ओर से लगातार धमकियां मिल रहीं थीं।

मजदूरी करने जम्मू-कश्मीर गए लोगों की हत्या की खबर से जिले के सागरदीघी थाना अंतर्गत बहालनगर तथा बोखरा-2 ग्राम पंचायत के बांभोनी गांव के लोग सकते में हैं। परिवारों में मची चीख पुकार से सियासतदानों से लेकर आम लोगों के आंखें नम हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कश्मीर में सेब का मौसम अगस्त के दूसरे सप्ताह में शुरू होता है और अक्टूबर माह तक चलता है। इसके बाद मजदूर घर लौट आते हैं। बीते मंगलवार को आतंकियों की गोली से छलनी हुए नइमुद्दीन शेख के पिता जरीस शेख भी कश्मीर में एक सेब बागान में मजदूरी करते हैं। उनका आरोप है कि प्रवासी श्रमिकों को घाटी छोड़ने के लिए लगातार आतंकियों की ओर से धमकियां मिल रही थीं। हर हाल में श्रमिकों को कश्मीर छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उन्हें धमकाया जा रहा था कि वे लोग कश्मीरियों की नौकरी खा रहे हैं। धमकी के चलते वे बीते सोमवार को वापस लौट आए थे, लेकिन मजदूरी नहीं मिलने की वजह से बेटा नइमुद्दीन वहीं रुक गया था।

मुर्शिदाबाद जिले के सागरदीघी थाना अंतर्गत बहालनगर में बिलखते मृतकों के परिजन। जागरण

उसे 31 अक्टूबर को घर लौटना था। वापसी के पल को याद कर जरीस के आंखें छलक उठीं। कहा कि लौटते वक्त बेटे को एक नजर नहीं देख पाया था, जिसका मलाल जीवन भर रहेगा। घर की दहलीज पर पछाड़ें मार रही पत्नी आबिदा बीबी अब भी यकीन करने को तैयार नहीं कि उसके पति की मौत हो चुकी है। मां नतून बीबी को अब भी बेटे नइमुद्दीन के गुरुवार को घर लौटने का इंतजार है।

भाई ने बताया था वादी में हालात ठीक नहीं : आतंकियों के हाथों मारे गए कमरुद्दीन शेख के बड़े भाई अमीनिरूल के अनुसार गत सप्ताह ही फोन पर भाई से बात हुई थी। उसने बताया था कि वादी में हालात ठीक नहीं हैं इसलिए दिवाली बाद गांव लौटने पर वापस कश्मीर नहीं जाएगा। लेकिन, उसके आने से पहले की उसकी मौत की खबर पहुंच गई।

दुआ के बीच पहुंची दुखद सूचना : मुर्सलीम शेख की पत्नी सायरा बीबी मानने को तैयार नहीं है कि आतंकियों ने उसके पति के साथ ऐसी बर्बरता की होगी। बेटी सुहाना ने टीवी में कश्मीर में किसी अनहोनी के होने की खबर को देखा था। अल्लाह से पिता को सुरक्षित रखने की दुआ ही कर रही थी कि तभी थाने से पहुंची खबर ने घर की दहलीज पर दस्तक दे दी। मां मासूदा बीबी बेटे से हाल ही में हुई बात को याद कर दहाड़े मारने लगीं। सिर्फ इतना ही कह रही थी कि बेटे ने कहा था यहां बहुत ठंड है जल्दी ही घर लौट आऊंगा। मातम का यह आलम रफीक अहमद शेख और रफीकुल आलम के घर पर भी है। पूरा गांव सन्न है।

ममता ने परिजनों को पांच-पांच लाख देने का किया एलान

जासं, कोलकाता : जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में मुर्शिदाबाद के पांच श्रमिकों की हत्या पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को तत्काल पांच-पांच लाख रुपये देने का एलान किया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कश्मीर में मंगलवार को दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पूर्व नियोजित तरीके से निर्दोष मजदूरों को बेरहमी से मार दिया गया। हम पूरी तरह से हैरान हैं। वर्तमान में कश्मीर में कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं हैं और संपूर्ण कानून-व्यवस्था भारत सरकार के पास है। हम इसलिए कड़ी जांच की मांग करते हैं ताकि असली सच्चाई सामने आए।

ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीर में हुई इस नृशंस हत्या पर वह स्तब्ध हैं। कोई भी शब्द मृतकों के स्वजनों के दुख को दूर नहीं कर सकता है। ऐसे में हम उनके परिजनों के साथ हैं और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी।

राज्यपाल ने की निंदा : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कश्मीर में श्रमिकों की हत्या किए जाने की बुधवार को निंदा की। साथ ही संवेदना जताते हुए उन्होंने राज्य सरकार व गैर सरकारी संगठनों से मृतकों के परिजनों की मदद करने की अपील की। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा कि गहरी पीड़ा हो रही है व बहुत दुखी हूं। मैं मुर्शिदाबाद के श्रमिकों की जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की गई नृशंस हत्या की निंदा करता हूं। मानवता का दुश्मन ही ऐसा कायरतापूर्ण और घृणित कार्य करता है। हमें हिंसा से दूर रहने की जरूरत है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों से शोक संतप्त परिवारों की मदद करने की अपील करता हूं।

जम्मू से कश्मीर तक सुरक्षा के किए गए अभूतपूर्व प्रबंध

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

आइएसआइ और आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए चौकसी बढ़ी

जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित राज्यों लद्दाख व जम्मू कश्मीर में पुनर्गठित होने के मौके पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और आतंकी संगठनों की साजिश नाकाम करने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, इमारतों, सुरक्षा शिविरों की सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। धर्म स्थलों और अल्पसंख्यकों व दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों की बस्तियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना और बीएसएफ को पूरी तरह चौकस रहने के लिए कहा गया है।

राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से बेशक कोई आतंकी खतरा नहीं है, लेकिन हम कोई चूक नहीं चाहते। आतंकी इस समय हर मौके का फायदा उठाने की फिराक में हैं। गुरुवार का दिन बहुत ही अहम है। इस मौके पर कोई भी छोटी सी आतंकी वारदात एक बड़ी खबर बन सकती है।

अधिकारी ने बताया कि हाईवे और हाईवे को आतंकग्रस्त इलाकों से जोड़ने वाली, अंतरराष्ट्रीय सीमा व एलओसी से हाईवे व अन्य मुख्य सड़कों की तरफ आने वाले रास्तों पर विशेष नाके लगाए गए हैं। शरारती तत्वों की निगरानी के लिए सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। श्रीनगर और जम्मू में सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। प्रमुख बाजारों, बस अडडों, रेलवे स्टेशनों पर विशेष एहतियात बरता जा रहा है।

बड़े स्तर पर खूनखराबे रची साजिश : सूत्रों ने बताया कि लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने वादी में बड़े स्तर पर खूनखराबे की साजिश रची है। भय पैदा करने के लिए आतंकी भीड़ भरे इलाकों में विस्फोट, सुरक्षाबलों पर हमले, अल्पसंख्यकों और श्रमिकों को निशाना बनाने के अलावा किसी बड़ी इमारत में घुसकर बंधक संकट भी पैदा सकते हैं।

गोलाबारी की आड़ में घुसपैठ की आशंका: सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सैन्य व नागरिक ठिकानों पर गोलाबारी करते हुए युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास करेगी। वह गोलाबारी की आड़ में बैट और आतंकी दस्तों की घुसपैठ कराकर अग्रिम इलाकों में स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला भी करा सकती है।

क्यूआरटी और क्यूएटी दस्ते तैनात राज्य पुलिस में डीआइजी रैंक के एक अधिकारी ने कहा कि हालात को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने क्यूआरटी और क्यूएटी दस्ते तैनात किए हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है।

दौरे को लेकर विवाद अनावश्यक

प्रथम पृष्ठ से आगे

थेरी मैरानी ने मुस्लिम विरोधी और नाजीवादी होने के लग रहे आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। हम हिटलर के समर्थक नहीं हैं। अगर नाजीवादी होते तो जनता हमें नहीं चुनती। इस दौरे को लेकर विवाद अनावश्यक है। यह किसी वर्ग विशेष के समर्थन में नहीं है, यह तो कश्मीर की सच्चाई को समझने का हमारा एक प्रयास है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की कश्मीर के संदर्भ में कवरेज पक्षपाती : पोलेंड के सांसद रिचर्ड चेरनेकी ने कहा कि कश्मीर को लेकर जिस तरह से मीडिया में छप रहा था, उसे पढ़ने के बाद ही हमने यहां के हालात देखने का फैसला किया। एक स्थानी नागरिक ने हमें बताया कि भ्रष्टाचार कश्मीर में प्लेग की तरह है। केंद्र सरकार आम लोगों के कल्याण और विकास के लिए जो पैसा भेजती है, वह सिस्टम में ही कहीं खप जाता है और कभी भी विकास कार्यों में पूरी तरह नहीं लगता। यहां लोग अस्पताल चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की कश्मीर के संदर्भ में कवरेज पूरी तरह दुराग्रहपूर्ण और पक्षपाती है। हम सब अपने मुल्क में जाकर कश्मीर की सच्चाई बताएंगे।

विपक्ष को भी कश्मीर दौरे की अनुमति दी जाए : सांसद निकोल्स फेस्ट ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर यूरोपीय संघ को अनुमति दी गई है तो विपक्ष को भी मौका देना चाहिए। कोई असंतुलन है तो उसे दूर किया जाना चाहिए।

कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा देने में केंद्र फेल : अधीर

जागरण संवाददाता, मुर्शिदाबाद : कश्मीर में आतंकियों द्वारा मुर्शिदाबाद के पांच श्रमिकों की हत्या किए जाने के बाद मातम के बीच कई दलों के नेताओं ने उनके घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार को फेल बताया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर जंगीपुर से तृणमूल सांसद खलीलुर्रहमान और बंगाल के श्रम राज्यमंत्री जाकिर हुसैन तथा बहरमपुर के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बहालनगर गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने शोकाकुल परिवारों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद ने हत्याकांड की निंदा करते हुए कश्मीर नीति को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर को शांत बताकर केंद्र सरकार वास्तविक हालात से लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने बंगाल के श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार पर फेल होने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मृतकों के परिवारों की आर्थिक मदद के साथ ही एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की।

सांसद अधीर चौधरी ने गांव में ही खड़े होकर केंद्रीय गृह सचिव से वारदात को लेकर फोन पर बातचीत की। उन्होंने गृह सचिव से मृतकों के शवों को उनके घरों तक भिजवाने की व्यवस्था के बाबत पूछा। इसके अलावा आतंकियों की गोली से घायल जहीरुद्दीन शेख के उपचार तथा कश्मीर में मौजूद मुर्शिदाबाद के अन्य श्रमिकों की सुरक्षा व सभी को घर वापस भिजवाने की व्यवस्था के बाबत जानकारी हासिल की। सांसद के अनुसार गृह सचिव ने उन्हें उचित व्यवस्था का आश्वासन दिया है। तृणमूल सांसद खलीलुर्रहमान ने कहा कि जिला प्रशासन मृतक के परिजनों के साथ हमेशा खड़ा है। मदद के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

माकपा की मांग-सीएम कश्मीर भेजें प्रतिनिधिमंडल : माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने कश्मीर में बंगाली श्रमिकों की हत्या किए जाने की निंदा करते हुए बुधवार को ट्वीट कर इस पर रोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से बात करने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री से एक टीम गठित कर कश्मीर भेजने की मांग की है।

वीके सिंह बोले-गुलाम कश्मीर हमारा है

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत सरकार उस पर नियंत्रण हासिल कर लेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री वीके सिंह ने बुधवार को कहा कि गुलाम कश्मीर पर कब्जा करने की क्या जरूरत है। वह तो हमारा ही है। हम उस पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। सिंह ने एसोचैम की ओर से आयोजित के एक कार्यक्रम के इतर एक सवाल के जवाब में यह बातें कहीं। यूरोपीय संघ के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर दौरे पर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि विपक्ष विरोध करने के अलावा कुछ नहीं करता है। वह कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें टीका-टिप्पणी करने दीजिए।

पाकिस्तानी गोलाबारी में ग्रामीण की मौत, सात जख्मी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के दौरे के दौरान साजिश के तहत पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे मच्छल (कुपवाड़ा) सेक्टर में बुधवार को भारतीय क्षेत्र में गोलाबारी की। इसमें एक ग्रामीण 65 वर्षीय मुहम्मद यूसुफ खान की मौत हो गई और सात जख्मी हुए हैं। घायलों में दो बच्चे भी हैं। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। उसका लांचिंग पैड भी बर्बाद हो गया है। हालांकि, एलओसी पार हुए नुकसान का पूरा ब्योरा नहीं मिल पाया है। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

पाकिस्तान की करतूत को देखते हुए प्रशासन ने मच्छल और आसपास के इलाकों में रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कई ग्रामीण घरों के पास बने बंकरों में चले गए हैं। प्रशासन ने फिलहाल उन्हें एलओसी के साथ सटे खेतों और चारागाहों में न जाने की हिदायत दी है।

पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार की रात भी मच्छल के साथ सटे टंगडार सेक्टर में भी गोलाबारी की थी। भारतीय जवानों ने इस पर टंगडार के सामने नीलम घाटी में स्थित दुदनियाल में पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया।

जज्बा

10वीं व 12वीं की परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों को डरा नहीं पाया हमलों और बंद का माहौल, 99 फीसद से ज्यादा छात्र परीक्षाओं में हुए शामिल

कश्मीरी बच्चों की काबिलियत के आगे दुश्मन पस्त

सतनाम सिंह, जम्मू

वाकई कश्मीर के बच्चों में भविष्य संवारने का जुनून दिखा। एक तरफ आतंकी 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहे थे तो दूसरी ओर बच्चे बेखौफ होकर परीक्षा केंद्रों में रुख कर रहे थे। हमलों व बंद से पैदा डर का माहौल भी कश्मीरी बच्चों की ललक के आगे हार गया। उन्होंने तमाम मुश्किलें पार करते हुए परीक्षाएं देकर अलगाववाद समर्थकों और आतंकियों को तमाचा मारा।

10वीं और 12वीं कक्षा में 99 फीसद से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। इससे उन तत्वों को झटका लगा है जो युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में काफी समय तक स्कूल, कॉलेज बंद रहे। उसके बाद सरकार ने बच्चों के भविष्य को देख स्कूल खोले। पर बच्चों की हाजिरी कम रही। वार्षिक परीक्षाएं करवाने को लेकर प्रशासन के आगे चुनौती बन गई थी। अभिभावक बंद के दौरान बने हालात में बच्चों को सुरक्षा के कारण स्कूल नहीं भेज रहे थे। बड़ी बात यह रही कि विद्यार्थियों ने दो महीने तक घरों में पढ़ाई कीं। कुछ सामुदायिक स्कूलों में गए और कई बच्चे सुबह-शाम शिक्षकों के घरों में पढ़ने जाते रहे। बच्चों को पता था कि परीक्षाएं अक्टूबर- नवंबर में हर हाल में होंगी क्योंकि दिसंबर में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। सरकार ने पूरे प्रबंध करते हुए परीक्षाएं करवाने का फैसला किया। सरकार के तमाम प्रबंध सही निकले।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कश्मीरी युवक अपना और कश्मीर का भविष्य संवारना चाहते हैं। इन दिनों कश्मीर संभाग में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। कश्मीर के एक शहर में दुकान के शटर के बाहर बैठकर परीक्षा की तैयारी करता छात्र संदेश दे रहा है कि मुझे शिक्षा हासिल करके न केवल अपना बल्कि कश्मीर का भी भविष्य संवारना है। कामरान रशीद बट

बच्चों की हाजिरी 99 फीसद रही : 10वीं कक्षा की परीक्षा में पहले ही दिन हाजिरी 99 फीसद रही। कश्मीर में परीक्षाएं देकर बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए जम्मू समेत अन्य राज्यों की तरफ रुख करेंगे। अगले वर्ष होने वाली प्रतिस्पर्धा की मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य परीक्षाओं में भाग लेंगे।

12वीं की परीक्षा में 99.4 फीसद हाजिरी : कश्मीर संभाग की बारहवीं कक्षा की परीक्षा बुधवार से शुरू हुई। परीक्षा में 99.4 फीसद हाजिरी रही। करीब 48 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 433 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन 12वीं कक्षा का पहला पेपर जनरल इंग्लिश का हुआ। केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राज्य शिक्षा बोर्ड की चेयरपर्सन प्रो. वीना पंडिता का कहना है कि परीक्षाएं पूरी तरह से सुचारु रूप से हो रही हैं। विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया। कश्मीर संभाग के विभिन्न जिला प्रशासनों ने विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के विशेष प्रबंध किए हैं। कश्मीर में ऐसी कोई क्षेत्र नहीं था यहां बच्चों और उनके अभिभावकों की हलचल नहीं थी। हर जगह रौनक थी।

इस्तीफा नहीं दिया, कार्यकाल पूरा हुआ : विजय कुमार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

राज्यपाल की पांच सदस्यीय सलाहकार परिषद के सदस्य थे आइपीएस कुमार

जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित राज्यों में पुनर्गठित होने से एक दिन पहले ही बुधवार को सलाकार के विजय कुमार का कार्यकाल भी संपन्न हो गया है। उन्होंने सलाहकार पद से इस्तीफे की अटकलों का खंडन किया।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर बुधवार को आधी रात के बाद दो केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंतिम और 13वें राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रशासनिक कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए पांच सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाई थी। इसमें के विजय कुमार, के स्कंदन, केके शर्मा, खुर्शीद अहमद गनई और फारूक खान शामिल थे।

सरकार ने भी दिया स्पष्टीकरण : सुबह के विजय कुमार के इस्तीफे की अफवाह फैल गई। हालांकि सरकार ने बाद में उनके इस्तीफे की खबरों को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सेवाएं राज्यपाल सत्यपाल मलिक के कार्यकाल तक ही थीं। के विजय ने भी ट्वीट कर कहा कि मेरे इस्तीफे की खूब अफवाहें चल रही हैं। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए बतौर सलाहकार मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुजरा वक्त स्मरणीय है। मेरी तरफ से पूर्व राज्यपाल, मेरे साथी सलाहकारों व अन्य सभी लोगों को शुभकामनाएं।

के. विजय कुमार। फाइल फोटो

141 और डेंगू के मरीजों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार को भर्ती कराया गया। अब तक अस्पताल में इस बीमारी से भर्ती होने वालों की संख्या 2760 हो गई है।

अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ी सतर्कता

तैयारी ▶ राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी नजदीक आते ही मुस्तैद हुईं सुरक्षा एजेंसियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में एक बार फिर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सरगर्मी बढ़ गई है। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, पुलिस ने भी संवेदनशील स्थानों की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है।

अयोध्या में अर्द्धसैनिक बल, पीएसी व पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाये जाने के साथ ही आइबी भी लगातार नजर बनाये हुए है। इंटेलीजेंस के अधिकारी रोजाना सुरक्षा के सभी बिंदुओं की समीक्षा कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को सभी जिलों में धर्मगुरुओं व विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर शांति-व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

अयोध्या के अलावा बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच समेत अन्य जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मिलीजुली आबादी वाले क्षेत्रों में सभी संवेदनशील स्थानों को चिह्नित करने को कहा गया है, ताकि वहां अतिरिक्त पुलिस का प्रबंध सुनिश्चित किया जा सके। खासकर सभी जिलों में ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिनकी गतिविधियां पहले भी संदिग्ध रही हैं। पुलिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सभी परिस्थितियों का आकलन भी कर रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। खासकर भड़काऊ संदेशों पर नजर रखी जा रही है। आइजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार का कहना है कि सभी जिलों की पुलिस को हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

विवादित जमीन हिंदुओं को गिफ्ट कर दें मुसलमान : कल्बे सादिक

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और अगले महीने फैसला आने वाला है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना डॉ. कल्बे सादिक ने अयोध्या मामले में बड़ा बयान देकर हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर जीत भी जाएं तब भी वे विवादित भूमि हिंदू भाइयों को सौंप दें।

बढ़ती फोर्स कराने लगी फैसले की आहट का अहसास

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या

रामनगरी में फोर्स की बढ़ती आमद सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले की आहट का अहसास कराने लगी है। पीएसी (प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी) और अर्द्धसैनिक बलों को मिलाकर पहले चरण में सुरक्षाबलों की करीब 100 कंपनियां यहां आ चुकी हैं। अब दूसरे चरण में भी सुरक्षाकर्मियों की आमद शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में पीएसी व अर्द्धसैनिक बलों को मिलाकर 200 कंपनियां मिलने की संभावना है। शहर के अधिकांश विद्यालय पुलिस छावनी बन चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी पहले से ही अयोध्या में डेरा डाले हैं।

फैसला आने के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों की ओर से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या के प्रमुख मठ-मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या पुलिस ने फोर्स के समन्वय के लिए विशेष सेल का गठन किया है। जिले में हर प्रमुख स्थानों को अभी से ही फोर्स के हवाले कर दिया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जिले की जनता के बीच मिल रहे सद्भाव के संकेत सुरक्षातंत्र को राहत देने वाले हैं।

रूट मार्च के जरिये भौगोलिक स्थिति का अध्ययन : बाहर से मिली फोर्स जिले की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, इसलिए रूट मार्च किया जा रहा है। अर्द्धसैनिक बलों को भौगोलिक स्थिति से वाकिफ कराया जा रहा है। सभी प्रमुख अधिकारियों व चौकी प्रभारियों को यह दायित्व सौंपा गया है।

बड़े अधिकारियों के लिए बड़े होटल

पुलिस के बड़े अधिकारी भी अयोध्या में मोर्चा संभालेंगे। इसलिए शहर के नामचीन होटलों में कमरे बुक कराए जा रहे हैं। शहर के लगभग सभी होटलों में आठ-दस कमरे बुक कराए गए हैं।

चढ़ाने के लिए भक्त पॉलीथिन में नहीं ले जा सकेंगे रामलला का प्रसाद

जागरण संवाददाता, अयोध्या : पॉलीथिन प्रतिबंधित होने का असर रामलला के प्रसाद पर भी पड़ा है। श्रद्धालु कई दिनों से रामलला के लिए प्रसाद नहीं ले जा पा रहे हैं। प्रसाद बिक्री करने वाले अधिकांश दुकानदार पॉलीथिन का विकल्प नहीं तलाश सके हैं।

सुरक्षा कारणों से अब तक पारदर्शी पॉलीथिन में श्रद्धालु प्रसाद ले जाते थे। इस पर रोक लग जाने से अब श्रद्धालु पॉलीथिन का विकल्प तलाश रहे हैं, ताकि वे अपने आराध्य को प्रसाद चढ़ा सकें। रामलला के पुजारी सत्येंद्रदास कहते हैं कि श्रद्धालुओं को पॉलीथिन का विकल्प तलाशना होगा। दुकानदारों व श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे पॉलीथिन के स्थान पर कागज के लिफाफे अथवा बाजार में आ रहे नए थैलों का इस्तेमाल करें। प्रशासन को श्रद्धालुओं की दिक्कत का ध्यान रखते हुए इस संबंध में कोई पहल करनी चाहिए ताकि पॉलीथिन पर लगा प्रतिबंध बरकरार रहे और भगवान को प्रसाद भी चढ़ सके। उधर, पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगने के बाद विगत दो-तीन दिन से प्रसाद चढ़ने की प्रक्रिया धीमी हुई है।

कमलेश हत्याकांड का पाकिस्तान कनेक्शन !

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- आतंकी संगठनों की भूमिका का सिरा टटोल रहीं जांच एजेंसियां
- दुबई में काम कर चुके राशिद के बारे में जुटाई जा रहीं और जानकारियां

हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड का पाकिस्तान कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। किसी आतंकी संगठन की भूमिका को लेकर की जा रही जांच के दायरे में कई संदिग्ध भी हैं। हत्यारोपित कट्टपंथियों को वारदात के बाद जिस तरह बरेली, शाहजहांपुर समेत अन्य स्थानों पर मदद पहुंचाई गई और साजिशकर्ताओं के तार महाराष्ट्र से लेकर नेपाल तक पाए गए, उससे एक नया ट्रेंड भी सामने आया है। यही वजह है कि हत्याकांड में किसी आतंकी संगठन के स्लीपिंग मॉड्यूल्स का पर्दे का पीछे का रोल भी खंगाला जा रहा है।

कमलेश हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल गुजरात निवासी राशिद अहमद खुर्शीद अहमद पठान दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक की कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करता था। कमलेश हत्याकांड की साजिश रचे जाने से करीब दो माह पहले ही राशिद दुबई से आया था। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) समेत अन्य जांच एजेंसियां इस बिंदु की भी गहनता से पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक पकड़े गए आरोपितों से जुड़े कुछ अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी छानबीन की जा रही है। इनमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक पूर्व छात्र भी है, जो मूलरूप से गुजरात का निवासी है। पुलिस पहले उनकी भूमिका से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास कर रही है। जांच एजेंसियां कमलेश हत्याकांड में आरोपितों व उनके मददगारों की पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की गतिविधियों को लगातार खंगाल रही हैं। सोशल मीडिया के जरिये ही आरोपित एक-दूसरे के लगातार संपर्क में थे।

उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर को लखनऊ के खुर्शेदबाग में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपित अशफाक व मोइनुद्दीन समेत अब तक 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया चुका है। बरेली के मौलाना कैफी अली भी आरोपितों में शामिल हैं। कमलेश हत्याकांड में गुजरात एटीएस ने सबसे पहले सूरत निवासी साजिशकर्ता मौलाना मोहसिन शेख सलीम, फैजान व राशिद अहमद खुर्शीद अहमद पठान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूरी घटना की कड़ियां खुलती चली गई थीं।

अयोध्या मुद्दे के दो ध्रुवों मुलायम और कल्याण से मिले योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- दोनों नेताओं को दी दीपावली की शुभकामना
- अखिलेश ने योगी से बनाई दूरी, शिवपाल रहे मौजूद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के राजनीतिक निहतार्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह अनौपचारिक मुलाकात थी। प्रेट्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दीपावली की शुभकामना देने गए थे लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले गए। अयोध्या मुद्दे पर मुलायम और कल्याण दो ध्रुव रहे हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले दोनों दिग्गजों से योगी की इस मुलाकात से सियासी हलचल बढ़ गई है।

योगी बुधवार सुबह जब मुलायम सिंह यादव के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर मिलने पहुंचे तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। योगी लोकसभा चुनाव के बाद भी मुलायम से मिलने गए थे। तब योगी के स्वागत में मुलायम के पुत्र व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाई शिवपाल सिंह यादव समेत पूरा परिवार मौजूद था। इस बार अखिलेश नहीं थे। अखिलेश यादव की नामौजूदगी ने सवाल खड़े किए। दरअसल, अखिलेश यादव अब भाजपा पर आक्रामक हैं और वह किसी भी हाल में मोर्चे पर जमे रहना चाहते हैं। हाल के विधानसभा उप चुनाव के नतीजों ने भी अखिलेश का उत्साह बढ़ाया है।

दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव के प्रति योगी सरकार मेहरबान भी रही है। उनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बंगला आवंटित किये जाने और व्यक्तिगत तौर पर उनके आइएएस दामाद की उप्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाए जाने जैसे कुछ मामले हैं जिनके हवाले से अखिलेश भाजपा से शिवपाल की करीबी का दावा करते हैं। अपना विरोधी चेहरा बनाये रखने के लिए भी अखिलेश ने योगी से दूरी बनाई।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह यादव की कुशलक्षेम पूछी। करीब 25 मिनट तक उनके आवास पर रहे योगी ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आपसी व्यवहार में नहीं आनी चाहिए। योगी ने मुलायम से मिलने के बाद माल एवेन्यू स्थित राज्यमंत्री संदीप सिंह के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात की और कुशलक्षेम पूछी। इस मौके पर कल्याण के पुत्र और एटा के भाजपा सांसद राजवीर सिंह राजू भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह और कल्याण सिंह को कुंभ 2019 से संबंधित पुस्तक व मिठाई भेंट की।

उल्लेखनीय है कि नवंबर-दिसंबर का महीना अयोध्या के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। कल्याण सिंह की सरकार में अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस हुआ था जबकि मुलायम सिंह यादव की सरकार में कारसेवकों पर गोली चली थी।

श्योपुर के कांग्रेस विधायक की एक साल की सजा बहाल

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल व अन्य के खिलाफ श्योपुर की निचली अदालत के निर्णय को भोपाल की विशेष अदालत ने बरकरार रखा है। 2008 में एक नहर में बने बांध को तोड़ने व बलवा के मामले में निचली अदालत ने जंडेल समेत 16 आरोपितों को एक-एक साल का कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपितों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। यहां से अपील भोपाल की विशेष अदालत में स्थानांतरित हो गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है। सजा बहाल होते ही कोर्ट के आदेश पर विधायक जंडेल व अन्य दोषियों को गिरफ्तार कर भोपाल जेल भेज दिया गया।

साल 2008 में चंबल नहर के गेट जबरन बंद करने और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धमकाने के मामले में बाबू जंडेल सहित 16 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने व धमकाने की धाराओं में एफआइआर दर्ज हुई थी।

हत्यारोपितों को नेपाल पहुंचाने वाला कामरान हिरासत में

जागरण संवाददाता, बरेली

कमलेश तिवारी हत्याकांड में आरोपितों की मदद करने के मामले में पुलिस ने एक और युवक को हिरासत में लिया है। वह पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए वकील नावेद का पार्टनर है। मंगलवार देर रात लखनऊ के नाका थाने की पुलिस ने स्थानीय पुलिस व क्राइम ब्रांच की मदद से कामरान को हिरासत में लिया और लखनऊ ले गई।

18 अक्टूबर को लखनऊ में हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद दोनों आरोपित अशफाक व मोइनुद्दीन बरेली आए थे। यहां मलूकपुर निवासी नावेद व प्रेमनगर निवासी कैफी ने उनकी मदद की थी। एटीएस ने पिछले सप्ताह कैफी व नावेद को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पता चला कि नावेद की ट्रैवल्स एजेंसी के पार्टनर कामरान ने भी हत्यारोपितों की मदद की थी। जांच टीमों का कहना था कि उसी ने कमलेश तिवारी के हत्यारोपितों को नावेद के कहने पर नेपाल तक पहुंचाया था।

बरेली पुलिस ने वाहन का इंतजाम कर भेजा लखनऊ

हाई प्रोफाइल हत्याकांड के मामले में लखनऊ पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उससे बरेली पुलिस भी अचंभित रह गई। कामरान को पकड़ने व लखनऊ ले जाने के लिए सिर्फ दो ही पुलिसकर्मी आए थे। उनके पास कोई वाहन तक नहीं था। गिरफ्तारी के बाद बरेली पुलिस ने वाहन का इंतजाम कर कामरान को लखनऊ के लिए रवाना किया।

होटल मालिक को तलाश रही है पुलिस : दोनों हत्यारोपित शुक्रवार रात में बरेली के ही एक होटल में रुके थे। वहां ठहराने का इंतजाम भी नावेद ने कराया था। पुलिस के मुताबिक आरोपित मलूकपुर स्थित कादिरी होटल में रुके थे। होटल में नीचे रेस्तरां और ऊपर ठहरने की व्यवस्था है। पुलिस होटल मालिक की भी तलाश कर रही है।

अमेठी में हिरासत में हुई मौत के मामले को लेकर भड़के परिजन, शव रखकर 19 घंटे दिया धरना

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़

अमेठी पुलिस की हिरासत में व्यवसायी की मौत के मामले में परिवार वालों ने दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने, 50 लाख की सहायता देने सहित कुछ और मांगों को लेकर शव रखकर 19 घंटे धरना दिया। प्रभारी डीएम ने मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया तब अंतिम संस्कार किया जा सका। इस बीच कई बार हालात बेकाबू होते-होते बचा।

प्रतापगढ़ के अंतू क्षेत्र के बरबंडा गांव निवासी व्यवसायी सत्य प्रकाश उर्फ साजन शुक्ला ने बाबूगंज बाजार में आटो पार्ट्स की दुकान खोली थी। इन्हीं के मकान में किराए पर यूको बैंक की शाखा है। पांच अक्टूबर को बैंक से कैश ले जाते समय अमेठी के पीपरपुर क्षेत्र के परसोइया गांव के पास बदमाशों ने 26 लाख रुपये लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने दीपावली के दूसरे दिन यानी सोमवार रात साजन शुक्ला के घर दबिश देकर उनको व बेटे अंकित, साहिल को गिरफ्तार किया था। मंगलवार सुबह साजन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए शव सुल्तानपुर ले जाया गया। परिवार वाले पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सुल्तानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और मंगलवार शाम सात बजे शव लेकर चिलबिला जगदीशपुर हाईवे पर धरना देकर बैठ गए।

सुल्तानपुर से ही शव के साथ आए कांग्रेस नेता नीरज त्रिपाठी भी साथ बैठे। रात करीब 11 बजे एएसपी सुरेंद्र दूबे ने मांगों के संबंध में ज्ञापन मांगा। तब उनके भाई ओम प्रकाश शुक्ला ने घटना की सीबीआइ जांच कराने, दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी व उनकी बर्खास्तगी, पीड़ित परिवार को 50 लाख की सहायता, बेटे को नौकरी व शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की लिखित मांग रखी। साथ ही सुबह छह बजे तक मांग पूरी करने की मांग करते हुए शव को हाईवे से हटाकर दरवाजे पर रखकर बैठ गए। सुबह तक मांगों पर विचार न होने पर फिर हाईवे पर धरने पर बैठ गए। प्रभारी डीएम धीरेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवार की सभी मांगों पर विचार के लिए संस्तुति के साथ मांगपत्र शासन को भेजा तब परिजन माने और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।

पुलिस का दावा, साजिश में सत्य प्रकाश भी था शामिल

जागरण संवाददाता, अमेठी : अमेठी में पुलिस हिरासत में हुई मौत पर मचे हंगामे के बीच बुधवार को एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने यूको बैंक प्रबंधक व कैशियर से हुई 26 लाख की लूट के पर्दाफाश का दावा किया। पुलिस ने पकड़े गए तीन बदमाशों के साथ ही तमंचा, बाइक, साढ़े तीन लाख रुपये बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि लूट की साजिश में मृतक सत्य प्रकाश उर्फ साजन भी शामिल था।

हालांकि, एसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले तीनों लुटेरे अब भी पकड़ से दूर हैं। लूट का तानाबाना बुनने वाले जाकिर अली उर्फ गुडडू के साथ रेकी करने वाले दो बदमाशों को आलमपुर रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट की साजिश में मृतक सत्य प्रकाश भी था। वे पिछले डेढ़ साल से वारदात को अंजाम देने में लगे थे। कैश, बोलेरो गाड़ी से लाने-ले जाने की वजह से उनके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे थे। लूट की वारदात के 15-20 दिन पहले से कैश कार से प्रबंधक द्वारा लाया जाने लगा, जिसके बाद बदमाशों ने पांच अक्टूबर को लूट को अंजाम दिया।

भारत के साथ अभ्यास के लिए बीकानेर पहुंची फ्रांस की सेना

राज्य ब्यूरो, जयपुर: भारतीय सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए फ्रांस की सेना बीकानेर पहुंच गई है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक दोनों सेनाएं युद्धाभ्यास 'शक्ति-2019' में भाग लेंगी। द्विपक्षीय अभ्यास की शृंखला के तहत पांचवीं बार युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है। इसके लिए फ्रांस की सेना के 38 सैनिक यहां पहुंचे हैं। सेना के प्रवक्ता कर्नल सोंबित घोष ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत यह संयुक्त अभ्यास किया जाता है। इसके तहत अर्ध- रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद निरोधी कार्रवाई पर फोकस किया जाएगा।

जनमत
मुद्दा

क्या हम अपनी जीवनशैली को बदलकर जलवायु आपातकाल की नौबत को रोक सकते हैं?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

आदिवासी गांवों में रोजगार सृजन के जरिये नक्सलवाद से निपटेगी सरकार

अनिल मिश्रा, जगदलपुर

- छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से नक्सल उन्मूलन की योजना साझा की
- आक्रामक अभियान के साथ गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएगी सरकार

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन नीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। आदिवासी गांवों में रोजगार सृजन के जरिये नक्सलवाद से निपटने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है। धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिलों से इसकी शुरुआत की गई है। यहां सलवा जुडूम की वजह से डेढ़ दशक पहले बंद हो चुके स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। ज्ञानदूत के तौर पर गांव के स्थानीय युवाओं की नियुक्ति की जा रही है।

सरकार की मंशा साफ है, पहले नक्सलियों को मारो, फिर जब इलाका साफ हो जाए तो वहां स्कूल, अस्पताल, बिजली-पानी का इंतजाम कर इलाके के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ो। पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव ने बस्तर में नक्सल समस्या पर बैठक ली थी, जिसमें राज्य सरकार ने इस नई योजना का खाका पेश किया। दरअसल, केंद्र चाहता है कि नक्सलियों को थोड़ी भी ढील न दी जाए। हालांकि, राज्य सरकार इससे दो कदम आगे जाकर समस्या के स्थाई समाधान की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। पक्के भवनों पर व्यय करने की जगह रोजगार सृजन के लिए जिला खनिज न्यास से धन लेने की अनुमति कलेक्टरों को दी गई है। अभी ढह चुके स्कूल झोपड़ी में खोले जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानदूतों को डीएमएफ से दस हजार रुपये दिए जा रहे हैं। यहां रसोइया व चपरासी आदि की नियुक्ति का भी प्रावधान है। अब तक नक्सल इलाके के युवाओं को पुलिस में शामिल किया जाता रहा, लेकिन अब शिक्षा-स्वास्थ्य व दूसरे कामों में भी उन्हें लगाया जाएगा। धुर नक्सल इलाकों में छोटे-छोटे उद्योग लगाने की योजना भी बनाई गई है। इलाके में शांति आने के बाद आदिवासियों की मांग के हिसाब से विकास के दूसरे काम किए जाएंगे

नक्सलियों पर शिकंजा और कसेगी सरकार : राज्य सरकार ने नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए छह महीने की योजना तैयार की है। अब नक्सलियों पर शिकंजा और कसेगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया को बताया कि पिछले दस महीने में फोर्स ने कई हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है। पिछले तीन साल में चार सौ से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 2005 से 2013 के दौरान ताड़मेटला, झीरम समेत कई बड़ी नक्सल घटनाएं हुईं, लेकिन इस साल अब तक कोई बड़ी घटना करने में वे कामयाब नहीं हो पाए हैं। बारिश थमते ही फोर्स नक्सलियों पर कहर बनकर टूटने को तैयार है। उन्होंने कहा कि निर्दोष ग्रामीणों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

नक्सलियों को नहीं मिल रहे लड़ाके

फोर्स के दबाव के साथ ही नक्सल इलाकों तक सरकार की पहुंच पहले से बेहतर हुई है। यही कारण है कि नक्सल संगठन को नए लड़ाके नहीं मिल रहे हैं। इसका पर्दाफाश इनामी नक्सली देवा के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद मौके से मिले तेलगू भाषा के पत्रों से हुआ है। इन पत्रों में नक्सली नेताओं ने दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिलों में अंदरूनी इलाकों तक सरकारी योजनाओं के पहुंचने की वजह से संगठन में भर्ती कम होने की बात कही है।

करतारपुर कॉरिडोर

नींव पत्थर समारोह में जाकर विवादों से घिर गए थे सिद्धू, न्योते पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, कई दिनों से चल रहे हाशिए पर

पाक ने सिद्धू को दिया समारोह का न्योता

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

पाकिस्तान सरकार ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी कर दी है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि, सिद्धू की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सीनेटर फैजल जावेद खान ने प्रधानमंत्री इमरान खान के दिशा-निर्देशों पर यह न्योता भेजा है। इमरान ने प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मना करने के बावजूद वह इस समारोह में शामिल होने के लिए चले गए। समारोह में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने जब सिद्धू के सामने करतारपुर कॉरिडोर के खोलने का प्रस्ताव रखा तो सिद्धू ने उन्हें जफ्फी डाल ली। इसको लेकर बवाल बच गया। सिद्धू पूरे विपक्ष के निशाने पर आ गए। हालांकि, उन्होंने जफ्फी डालने को सही साबित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। यहां तक कि उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में उनसे दूरी बना ली। आज सिद्धू हाशिए पर हैं।

नौ नवंबर को रवाना होगा जत्था : नौ नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन डेरा बाबा नानक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि पाकिस्तान की ओर इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इमरान खान करेंगे। भारत ने कॉरिडोर के रास्ते जाने वाले पहले जत्थे में शामिल 575 श्रद्धालुओं की सूची पाकिस्तान सरकार को सौंप दी है। इस जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के सभी 117 विधायक, मंत्री, सांसद और विभिन्न पार्टियों के नेता शामिल हैं।

पासपोर्ट बनाने के लिए लगेंगे कैंप

जासं, अमृतसर: पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए बने कॉरिडोर से पाक जाने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मुनीश कपूर ने कहा कि लोगों को पासपोर्ट की सुविधा देने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसके तहत पांच नवंबर को फाजिल्का के लोगों के लिए मलोट रोड स्थित आइटीआइ में और छह नवंबर को अबोहर के हनुमानगढ़ रोड स्थित डीएवी कॉलेज ऑफ एजूकेशन में सुबह 9.30 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक कैंप लगाया जाएगा। 31 अक्टूबर शाम पांच बजे के बाद विभाग की वेबसाइटwww.passportindia.gov.in पर फीस जमा करवा कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन कैंपों में आए लोगों के पासपोर्ट पहल के आधार पर बनाए जाएंगे। पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। यह वृद्धि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हुई है।

क्या है मामला

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

एक अप्रैल 2017 को पहलू खान को गो तस्करी के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर घायल कर दिया था। अस्पताल में चार अप्रैल 2017 को उनकी मौत हो गई थी। अलवर पुलिस ने 24 मई 2017 को राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम-1995 के तहत इरशाद, आरिफ और खान मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू खान की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया। हालांकि, उनका नाम चार्जशीट की समरी में था। पुलिस अपने रुख पर कायम थी कि जांच में पहलू खान, उसके बेटों और खान मोहम्मद के खिलाफ मामला साबित हुआ है।

इस मामले में दूसरा केस उन्मादी हिंसा के तहत दर्ज किया गया था, जिसके सभी छह आरोपितों को पिछले दिनों बरी कर दिया गया है। निचली अदालत के इस निर्णय को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

परमाणु ऊर्जा निगम के सिस्टम को हैक करने की हुई कोशिश

नई दिल्ली, रायटर : देश में बिजली पैदा करने वाले परमाणु रिएक्टरों को संचालित करने वाली सरकारी कंपनी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआइएल) के सिस्टम को पिछले महीने हैक करने की कोशिश की गई थी। उसके एक कंप्यूटर में मालवेयर पाया गया था, लेकिन कंपनी ने कहा कि संयंत्र से जुड़ा उसका सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और उस मालवेयर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

कंपनी ने एक बयान में कहा है कि जिस कंप्यूटर में मालवेयर पाया गया, उसे प्रशासनिक कार्यों के लिए इंटरनेट से जोड़ा गया था। मालवेयर पाए जाने के बाद उसे गहन आंतरिक नेटवर्क से अलग कर दिया गया।

कंपनी ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दक्षिण भारत के कुडनकुलम स्थित रूस निर्मित रिएक्टरों पर साइबर हमला हुआ था। कुछ साइबर विशेषज्ञों ने भी मंगलवार को इस संभावित हमले को लेकर ट्वीट किया था।

- पिछले महीने कंपनी के एक कंप्यूटर में पाया गया था मालवेयर
- कंपनी ने कहा, संयंत्र से जुड़े सिस्टम पर नहीं पड़ा कोई असर

इनमें से एक पुखराज सिंह, जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने की चार तारीख को ही सरकार को इस हमले को लेकर आगाह किया था।

एनपीसीआइएल ने कहा कि इस तरह के हमलों से निपटने के लिए बनाई गई सरकारी एजेंसी सीईआरटी-इन ने चार सितंबर को इस मालवेयर को पकड़ा था और परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों ने तत्काल उसकी जांच की थी। जांच में यह पाया गया था कि इस मालवेयर से संयंत्र के सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। एनपीसीआइएल इस समय देश में 22 व्यावसायिक न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों का संचालन कर रही है, जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 6,780 मेगावाट है।

दैनिक जागरण

असफलताएं उपलब्धि की राह पर मील के पत्थर हैं

यूरोपीय सांसदों का दौरा

यह समय ही बताएगा कि कश्मीर पहुंचे यूरोपीय संघ के सांसदों का नजरिया भारत के इस हिस्से के बारे में विश्व समुदाय के रुख-रवैये को प्रभावित करने में कितना सहायक होगा, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि यह घाटी के हालात पर भी निर्भर करेगा। यूरोपीय देशों के सांसदों के श्रीनगर पहुंचते ही आतंकियों ने जिस तरह पश्चिम बंगाल के मजदूरों को निशाना बनाया उससे यह स्पष्ट है कि कश्मीर के हालात ठीक करने में अभी समय लगेगा। निःसंदेह इसमें सफलता तब मिलेगी जब आतंकियों को छिपने-भागने के लिए विवश किया जाएगा। यदि आम कश्मीरी जनता कश्मीर को बदनाम करने और वहां दहशत फैलाने में जुटे आतंकियों के खिलाफ मुखर हो सके तो माहौल कहीं आसानी से बदला जा सकता है। हालांकि कश्मीर में पहले भी बाहरी लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में घाटी के बाहर के लोगों को जिस तरह चुन-चुनकर मारा गया उससे न केवल यह स्पष्ट है कि पाकिस्तानपरस्त आतंकी गैर कश्मीरियों में खौफ पैदा करने पर आमादा हैं, बल्कि यह भी कि उनकी तथाकथित लड़ाई का राजनीतिक अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं। सच तो यही है कि कश्मीर में अधिकारों के नाम पर आतंक का कारोबार जारी है और इसीलिए उन निर्दोष-निहत्थे लोगों को भी मारा जा रहा जो कश्मीर की भलाई के लिए वहां मेहनत-मजदूरी कर रहे हैं।

यूरोपीय देशों के सांसदों के साथ विश्व समुदाय इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि कश्मीर गए ट्रक ड्राइवरों और वहां प्रवास कर रहे मजदूरों पर किए गए आतंकी हमलों में एक दर्जन लोगों को जान गंवानी पड़ी है। चूंकि ये आतंकी हमले पाकिस्तान के इशारे पर ही हो रहे हैं इसलिए इससे एक सीमा तक ही संतुष्ट हुआ जा सकता है कि यूरोपीय देशों के सांसदों ने कश्मीर में आतंक के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की हामी भरी। आखिर पाकिस्तान को जवाबदेह कब बनाया जाएगा? इससे भी जरूरी सवाल यह है कि उसे आतंकवाद को खाद-पानी देने के लिए दंडित कब किया जाएगा? इन सवालों के बीच यह अच्छा नहीं हुआ कि यूरोपीय देशों के सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया। इससे बचा जाना चाहिए था। इन सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर उठाए गए विपक्ष के सभी सवालों को निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मांग में वजन है कि आखिर इन सांसदों को कश्मीर आमंत्रित करने के पहले विपक्षी नेताओं को वहां क्यों नहीं भेजा गया? इस जायज सवाल के बावजूद यह भी सही है कि विपक्षी नेताओं के कश्मीर दौरे को विश्व समुदाय में कोई अहमियत मिलने वाली नहीं थी।

भागीदारी से बचेगी सांस

पटाखे कम फूटने के बाद भी बिहार में पटना की हवा मानक से 11 गुना ज्यादा जहरीली रही। कम आतिशबाजी के बाद भी दिवाली की आधी रात के बाद राजधानी की वायु गुणवत्ता में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर 697 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक बढ़ गया, जो सामान्यतः 60 होना चाहिए। वैसे यह मात्रा 2018 की दिवाली से कम है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। हमें हर कीमत पर प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा। इस बात का इंतजार छोड़ना होगा कि सरकार कुछ नियमन कर रोक लगाएगी। अक्सर लोगों के मुंह से सुना जाता है कि पटाखे पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती है? ग्रीन पटाखा क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? ग्रीन पटाखा व्यावहारिक तौर पर इतना कीमती होगा कि उसे बाजार में सर्वसुलभ करना आसान नहीं है। कानून के माध्यम से पटाखे पर रोक न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है। कानून जरूर लागू हों, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों की काउंसिलिंग की जाए। लोगों को जागरूक किया जाए। बच्चों के पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को समर्पित किया जाए। केवल दिवाली के समय प्रदूषण की चिंता न की जाए। साल भर स्कूल-कॉलेज और समाज में इस पर चर्चा हो, तभी कोई सार्थक नतीजा सामने आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, दोनों ही बिजली से चार्ज होने वाली कार का इस्तेमाल करने लगे हैं। सरकार का यह निर्णय भी है कि अधिक से अधिक सीएनजी के केंद्र खोले जाएं और डीजल-पेट्रोल वाले वाहनों की संख्या कम की जाए। इसका असर दिखने भी लगा है। बिहार के छोटे शहरों में भी ई-रिक्शा का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। प्रदूषण की हालत यह है कि डॉक्टर सुबह की सैर तक न करने की सलाह दे रहे हैं। इस हालत को समझना होगा। जहरीली हवा बच्चे और उम्रदराज लोगों के लिए और भी जानलेवा है। पीएम (पार्टिकुलेट मैटर)-2.5 और इससे छोटे कण फेफड़े के जरिये रक्त में पहुंच जाते हैं। इस वजह से धमनियों में ब्लॉकेज की आशंका रहती है। अच्छी बात है कि पटना में कुछ नई जगहों पर भी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि लोग और भी जागरूक होकर प्रदूषण की वास्तविक चिंता करें।

बच्चों के पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को समर्पित किया जाए। केवल दिवाली के समय प्रदूषण की चिंता न की जाए

नई चुनौतियों से जूझती भाजपा

प्रदीप सिंह

भाजपा के राजनीतिक विस्तार के रास्ते की बाधा केवल सामाजिक संतुलन को साधने और उसे मजबूत बनाने की ही नहीं है, कुछ सहयोगी भी हैं

महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों ने क्या मोदी के अपराजेय होने के मिथक को तोड़ दिया है? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे इसी रूप में देखता है। लेफ्ट लिबरल बिरादरी ऐसा फतवा जारी करने की बहुत जल्दी में है। ऐसे विश्लेषकों के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिलना और हरियाणा में भाजपा का एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनना, लेकिन बहुमत से कुछ दूर रह जाना, मोदी की हार है। हार-जीत के खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता भी है। यदि मोदी हार गए तो जीता कौन? 54 सीटें पाने वाले शरद पवार या 31 सीटें पाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा? जाहिर है कि तथ्यों से मतलब नहीं। बस कह दिया कि मोदी की हार हो गई या मोदी को हराया जा सकता है तो बात खत्म।

किसी भी घटना का विश्लेषण संदर्भ से काटकर नहीं किया जा सकता। सवाल है कि इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों का संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि साल 2014 से पहले महाराष्ट्र में भाजपा चौथे और हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी थी। मोदी लहर और महाराष्ट्र की 15 साल, हरियाणा की 10 साल और केंद्र सरकार की 10 साल के जबरदस्त सत्ता विरोधी रुझान के बूते दोनों राज्यों में वह पहले नंबर की पार्टी बन पाई। इस चुनाव में पांच साल का सत्ता विरोधी रुझान भाजपा के खिलाफ था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती नंबर एक की स्थिति बरकरार रखने और सत्ता में वापसी की थी। पार्टी ने दोनों लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरी ओर पांच साल के सत्ता विरोधी रुझान के बाद भी विपक्ष उसे पहले नंबर से हटा नहीं पाया। यही नहीं हरियाणा में भाजपा के वोट में तीन फीसद की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में जरूर दो फीसद वोट की कमी आई, लेकिन पार्टी इस बार सौ सीटें कम पर लड़ी थी। यदि यह विपक्ष की जीत और मोदी-शाह की हार है तो ऐसा सोचने वालों की समझ की बलिहारी। ये ऐसे लोग हैं जो अपनों की गर्दन कटने का शोक मनाने के बजाय विरोधी की अंगुली कटने का जश्न मनाने में यकीन करते हैं। यह भी ध्यान रहे कि इन पांच वर्षों में दोनों राज्यों में तीन बड़े आंदोलन हुए। इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों को मोदी की हार और विपक्ष की जीत के रूप में पेश किया जाना राजनीतिक विश्लेषण का नया तरीका है। इसका सिलसिला गुजरात विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुआ था। जब स्पष्ट बहुमत से जीतने वाली भाजपा को इसलिए पराजित घोषित कर दिया गया कि उसकी सीटें कुछ कम हो गईं और पिछले करीब तीन दशक से सत्ता तक न पहुंच पाने वाली कांग्रेस को विजेता के रूप में पेश किया गया।

जनसंघ से भाजपा के राजनीतिक सफर में पार्टी जिस भी राज्य में पहली बार सत्ता में आई वह अगले चुनाव में वापसी नहीं कर सकी। वह चाहे 1977 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हो या फिर 1991 में उत्तर प्रदेश या 2008 में कर्नाटक हो। गुजरात इस मामले में अब तक एकमात्र अपवाद था। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए नहीं कि ये दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा रह चुके हैं। इतना ही नहीं भाजपा संगठन की दृष्टि से भी इन राज्यों की महाराष्ट्र और हरियाणा से तुलना नहीं की जा सकती। तो क्या इन दोनों राज्यों में भाजपा में कोई समस्या नहीं है। ऐसा कहना सच्चाई से भागना होगा। दरअसल समस्या पुरानी है, लेकिन वह मोदी-शाह के युग में भी कम नहीं हो रही है। भाजपा का एक विशेष गुण है। सत्ता में आते ही उसकी सरकार के मंत्री पहले अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करते हैं, फिर आम जनता को। इसके बाद चुनाव आते-आते दोनों मिलकर पार्टी को हराते हैं। मोदी-शाह के युग में फर्क इतना हुआ है कि यह नुकसान अब मंत्रियों तक सीमित हो गया है। दोनों राज्यों में हारने वाले मंत्रियों की संख्या और पार्टी की कम हुई सीटों की संख्या गिन लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। मतलब यह कि जितने मंत्री, लगभग उतनी सीटें हारना तो तय है। यह नतीजा है उस सोच का जो मानती है मोदी नाम केवलम यानी हम मंत्री बन गए तो अब जनता ठेंगे पर। मोदी जी तो चुनाव जिताने के लिए हैं ही।

जब यह सोच 15 साल (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) से चल रही हो तो मोदी-शाह के लिए भी कठिन हो जाता है। इसी तरह यदि पांच साल में लुटिया डुबोने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया हों तो मोदी-शाह के लिए रफू करना और कठिन हो जाता है। मतादाता ने ऐसे नेताओं को संदेश दिया है कि भरोसा मोदी-शाह पर है, आप पर नहीं। ऐसे में देवेंद्र फड़नवीस और मनोहर लाल खट्टर की जीत की अहमियत और बढ़ जाती है। पार्टी के लिए भी संदेश है कि मंत्री काम करने के लिए होते हैं, ऐशो आराम के लिए नहीं। भाजपा के लिए इन दो राज्यों के जनादेश का यह भी संदेश है कि जब बात मोदी की हो तो मतदाता मुकाबले में खड़े किसी नेता पर भरोसा नहीं करता, पर जब मनोहर लाल खट्टर के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों और देवेंद्र फड़नवीस के सामने शरद पवार हों तो मुकाबला वैसा एकतरफा नहीं रहता। यह मोदी पर भरोसे का ही नतीजा है कि पवार और हुड्डा सारी ताकत लगाकर भी जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाए। भाजपा के राजनीतिक विस्तार के रास्ते की बाधा केवल सामाजिक संतुलन को साधने और उसे मजबूत बनाने की ही नहीं है। कुछ सहयोगी भी हैं। इसमें शिवसेना का नाम सबसे ऊपर है।

अवधेश राजपूत

शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो सत्तारूढ़ और विरोधी दल की भूमिका एक साथ चाहती है। वह भीख भी मांगती है और गाली भी देती है। उसे जो मिलता है उससे वह कभी संतुष्ट नहीं होती। चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन से वह परेशान नहीं होती। उसके वोट भाजपा से ज्यादा घटे और उसकी स्ट्राइक रेट भी भाजपा से खराब है। शिवसेना को भाजपा से लगभग आधी सीटें मिली हैं, फिर भी उसे ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए। उसकी समस्या यह है कि लंबे समय तक देने वाली पार्टी से अब वह मांगने वाली पार्टी हो गई है। यह बात उसे हजम नहीं हो रही है।

शिवसेना के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ना भाजपा की रणनीतिक भूल थी जिसका खामियाजा वह भुगत रही है। अब देखना यह है कि भाजपा 2014 की तरह अपने रुख पर कायम रहती है या शिवसेना की ब्लैकमेलिंग के आगे झुक जाती है? महाराष्ट्र के बाद अगला मोर्चा बिहार में खुलेगा। भाजपा शिवसेना के आगे झुकी तो उसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सामने भी झुकना पड़ेगा। आखिर जब शिवसेना पांच महीने में ही भूल गई कि लोकसभा में उसे जो सीटें मिलीं वे उद्धव ठाकरे के नहीं मोदी के नाम पर मिली हैं तो जनता दल यूनाइटेड क्यों याद रखेगा?

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

भारत को एक करने वाले सरदार

केसी त्यागी

यदि दृढ़ निश्चयी सरदार पटेल न होते तो शायद आज भारत का भौगोलिक नक्शा भिन्न होता

सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती इसलिए विशेष है, क्योंकि उनके स्मरण में 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर को आधिकारिक रूप से दो भागों में विभाजित करने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसके पहले गृह मंत्रालय की ओर से यह घोषणा की गई थी कि पुलिस एवं सभी अर्द्धसैनिक बलों के कार्यालयों में उनका चित्र अवश्य इस्तेमाल किया जाए। इससे यही स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार के लिए महात्मा गांधी के बाद लौह पुरुष सरदार पटेल सर्वाधिक सम्मानित शख्सियत हैं। कांग्रेस सरकार ने तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने में लगभग 40 वर्ष लगा दिए थे। यह सर्वविदित है कि कैसे सरदार पटेल अपनी अनुशासनात्मक क्षमता और मजबूत नेतृत्व के बल पर 565 प्रांतों को भारत के साथ जोड़ने में कामयाब हुए थे। सरदार पटेल के इस योगदान के लिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी 182 मीटर लंबी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया था। यह मूर्ति स्थल आज पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। यह सच है कि सरदार पटेल न होते तो आज भारत का भौगोलिक नक्शा शायद भिन्न होता। जूनागढ़, जोधपुर और खासतौर पर हैदराबाद तथा जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखने में उनकी साम, दाम, दंड एवं भेद की नीतियां आज भी उन्हें इतिहास के पन्नों पर सजीव और प्रासंगिक बनाए हुए हैं।

जब पाकिस्तान का बनना तय हो गया था तब देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां थीं। 1946 के कैबिनेट मिशन की प्रस्तावित योजना के अनुसार बंगाल, पंजाब और असम पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे थे। तब दूरदर्शी सरदार पटेल द्वारा इस योजना का कड़े शब्दों में विरोध किया गया। उन्होंने कहा, 'यह प्रस्ताव तो पाकिस्तान बनाने के प्रस्ताव से भी ज्यादा खराब है।' बाद में सरदार पटेल ने पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया और पूरा का पूरा असम भारत का हिस्सा बना लिया गया। यह ध्यान रहे कि तब असम एक तरह से पूरा पूर्वोत्तर था। देश के एकीकरण के अपने प्रयासों के दौरान सरदार पटेल ने समय की मांग को बखूबी समझने और उसके अनुरूप चलने का काम किया। हैदराबाद और जूनागढ़ के नबाव के खिलाफ उन्होंने बल और विवेक, दोनों का इस्तेमाल किया।

सरदार पटेल दबे-कुचले, मजदूरों, गरीबों एवं किसानों की भी मजबूत आवाज थे। आजादी के आंदोलनों में मुख्य भूमिका निभाने के साथ ही वे उन सभी सामाजिक वर्गों का भी नेतृत्व कर रहे थे जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से शोषित हो रहे थे। जनवरी 1928 में में अंग्रेजी हुकूमत ने एक तालुका के समूचे किसानों का भूमि कर लगभग 22 प्रतिशत बढ़ा दिया, जो लगभग दोगुने के करीब था। उसी तालुका के अंतर्गत बारदोली भी आता था। जहां के आश्रमों के संघ अध्यक्ष के पद पर पटेल आसीन थे। इस मुद्दे को पटेल ने चुनौती के रूप में लिया। किसानों को एकजुट कर उन्होंने बारदोली आंदोलन किया। पटेल ने किसानों से अंग्रेजों के आदेश के खिलाफ जाकर भू-कर नहीं देने का आह्वान किया। उन्हें बारदोली की महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी के साथ खेड़ा किसान आंदोलन का अनुभव भी सरदार पटेल के इस आंदोलन के मार्गदर्शन में सहायक रहा। उनके सफल नेतृत्व और किसानों की एकता के फलस्वरूप अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। भू-कर में संशोधन किया गया, किसानों को रियायत दी गई, जबरन हड़पी गई जमीनें तथा पालतू जानवर वापस किए गए। इससे किसानों में विश्वास, संतोष और साहस का संचार हुआ। अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के अलावा उन्होंने समाज को सशक्त करने का काम भी किया। उनके अनुयायियों ने गांव के सभी समुदायों के लोगों को चरखा चलाना तथा सूत कातना सिखाया। किसानों के बीच पटेल की सकारात्मक पैठ को देखते हुए स्वयं महात्मा गांधी ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि से नवाजा। यह पटेल की पहली सफलता नहीं थी। खेड़ा के प्रसिद्ध किसान आंदोलन में भी महात्मा गांधी के साथ उनकी भूमिका अहम रही थी। उस आंदोलन की भी शुरुआत भूमि कर के लिए ही हुई थी। 1918 में गुजरात का यह क्षेत्र भीषण अकाल की मार झेल रहा था। किसान भूमि कर देने में लाचार एवं असहाय हो चुके थे। किसानों की समस्याओं की अनदेखी करते हुए अंग्रेजों ने कर में बढ़ोतरी कर दी थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन का मोर्चा संभाला जिसमें सरदार पटेल उनके मुख्य सिपहसालार की भूमिका में थे। आंदोलन इतना सशक्त हो चुका था कि अंततः ब्रिटिश शासन को द्विपक्षीय समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके तहत कर माफी पर विचार, बढ़ाए गए कर में कटौती और जबरन हड़पी गई जमीनें एवं वस्तुओं की वापसी पर सहमति बनी।

सरदार पटेल के निर्णय दूरगामी एवं अनुशासित प्रवृत्ति के होते थे। उन पर गांधी जी का बड़ा प्रभाव था। धर्मनिरपेक्षता उन्हें गांधी जी से दीक्षा में प्राप्त हुई थी। गांधी जी के कारण ही उन्होंने खादी के प्रति अपनी आस्था जागृत की थी। गांधी जी के संपर्क में आने से पहले वह पश्चिमी वेशभूषा से प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी के कदमों पर चलकर 'विदेशी सामग्री जलाओ' नामक कई विरोध प्रदर्शनों को भी अंजाम देने का कार्य किया। दांडी मार्च के दौरान स्वयं महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि खेड़ा सत्याग्रह में मुझे सरदार पटेल की वजह से ही सफलता मिली और आज इन्हीं की वजह से मैं यहां दांडी में भी हूं। सरदार पटेल जिन्हें गांधी जी अपनी सफलता का कारण मानते थे, आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे वह किसानों का सवाल हो या फिर जवानों का। धर्मनिरपेक्षता उनकी दूसरी मजबूत कड़ी थी। इसके जरिये ही वे मजबूत और अखंड भारत का सपना देखते थे। आज यह कहीं आवश्यक है कि हम सरदार पटेल के आदर्शों और मार्गों का अनुसरण कर उनके सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। यही उनकी जयंती पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संतोष धर्म

चाणक्य कहते हैं, 'शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई धर्म नहीं।' सुख के लिए विश्व में सभी जगह चाहत है, पर सुख उसी को मिलता है, जिसे संतोष करना आता है। एक जिज्ञासा उठती है कि संतोष है क्या? संतोष का अभिप्राय है, इच्छाओं का त्याग। सभी इच्छाओं का त्याग करके अपनी स्थिति पर संतोष करना ही सुख को प्राप्त कर लेना है। जीवन के साथ इच्छाएं, कामनाएं एवं आकांक्षाएं रहती ही हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि सुखी जीवन के लिए हमारी इच्छा शक्ति पर कहीं तो विराम होना चाहिए। इच्छा के वेग में विराम को ही संतोष की संज्ञा दे सकते हैं। आचार्य गोरेलाल जी का मत है, 'संतोष मन की वह अवस्था है, जिसमें मनुष्य पूर्ण तृप्ति या प्रसन्नता का अनुभव करता है, अर्थात इच्छा रह ही नहीं पाती।' जीवन की गति के साथ संपत्ति और समृद्धि की दौड़ से वह सुख नहीं मिलता, जो संतोष रूपी वृक्ष की शीतल छांव में अनायास मिल जाता है। हमें चाहिए कि हम प्रयत्न और परिश्रम के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली प्रसन्नता पर संतोष करना सीखें। निष्काम कर्मयोग, इच्छाओं का दमन, लोभ का त्याग अथवा इंद्रियों पर अधिकार-ये सभी उपदेश संतोष की ओर ले जाने वाले सोपान ही तो हैं।

सच है, संतोष प्राकृतिक संपदा है, ऐश्वर्य कृत्रिम गरीबी। संतोष का आदर्श यही है कि हम इच्छाओं को सीमित रखकर सत्य एवं ईमानदारी से भरा श्रम करें और फल की चिंता न करते हुए उसे परमात्मा और परिस्थितियों पर छोड़ दें। हमें इस तथ्य का भली प्रकार बोध होना चाहिए कि सुखी होने का भाव है-दूसरों को सुखी बनाना। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध व्यक्तित्व ही सच्चे सुख की रसधार में सदैव स्नान करता है। आत्मा में सुख-सौंदर्य की विपुल वर्षा के लिए संतोष एक सजीला मेघ है। सुख और संतोष प्रायः साथ चलते हैं। संतोष मेघ है और सुख उससे बरसने वाला जल। संतोष सुख का सबसे बड़ा साधन है, जो मस्तिष्क के झुकाव पर निर्भर करता है। यदि मन से सुख मान लिया तो विपुल व्याधियां भी क्षण भर में उड़ जाती हैं।

श्रीमती रमन त्रिपाठी

महिला सुरक्षा के चिंतनीय हालात

मीनाक्षी भटनागर

दुख की बात है कि कानूनी सख्ती भी आधी आबादी के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है

हाल ही में आए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़े महिलाओं की सुरक्षा की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश में आधी आबादी के खिलाफ अपराध में करीब छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 359849 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2016 में 338954 मामले दर्ज किए गए थे। घर के भीतर अपनों का दुर्व्यवहार हो या नाबालिग बच्चियों के शोषण के मामले, हर उम्र, हर वर्ग की महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 56011 मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा पूरे देश में हुए अपराधों का 15.6 फीसद है। महिलाओं के खिलाफ सबसे असुरक्षित पांच राज्यों की फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पायदान पर बंगाल, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश और पांचवें पायदान पर राजस्थान है। अफसोस कि देश के बड़े राज्यों में महिला सुरक्षा के मोर्चे पर हालात चिंतनीय हैं। वहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित पांच राज्यों में लक्षद्वीप, दादर-नगर हवेली, दमन-दीव, नगालैंड और पुदुचेरी जैसे छोटे प्रांत हैं।

एनसीआरबी के आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश में बहुत सी महिलाएं अपने पति या रिश्तेदारों की क्रूरता का भी शिकार बन रही हैं। अपनों की बर्बरता के बंगाल से 16800, उत्तर प्रदेश से 12653, राजस्थान से 11508, असम से 9782 और तेलंगाना से 7838 मामले सामने आए हैं। ये पांच राज्य महिलाओं को घर में मिलने वाली अपनों की प्रताड़ना में सबसे आगे हैं। गौरतलब है कि एनसीआरबी वही आंकड़े सामने रखता है, जो पुलिस से मिलते हैं। जाहिर है महिला अपराधों से जुड़े वास्तविक आंकड़े इनसे कहीं ज्यादा ही होंगे। चिंतनीय है कि कानूनी सख्ती भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए आरोपी को फांसी की सजा देने का प्रावधान भी किया गया है। कई राज्यों ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर नियम भी बनाए हैं। बावजूद इसके समाज में महिलाओं के प्रति आपराधिक प्रवृत्ति रखने वालों के बढ़ते दुस्साहस और नकारात्मक सोच की बदौलत सामने आए ये आंकड़े भयभीत करने वाले हैं।

देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में समाज की संरचना काफी हद तक बदल गई है। बेटियां अब पढ़-लिख कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। कामकाजी स्त्रियां दोहरी जिम्मेदारी उठा रही हैं। वे विज्ञान की दुनिया से लेकर घर की देहरी तक अपनी भूमिका का निर्वहन पूरे मनोयोग से कर रही हैं। साथ ही वे समाज और परिवार में संस्कार, सरोकार और जिम्मेदारी के भाव की बुनियाद भी पुख्ता कर रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनके जीवन से भी असुरक्षा का अंधकार मिटे। अपनी पहचान बनाने और सपने पूरे करने की राह पर भय नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का भाव उनके हिस्से आए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सही कूटनीति

कूटनीति को नई धार देता भारत शीर्षक से लिखे अपने आलेख में ब्रिगेडियर आरपी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के नए खेवनहार बने तुर्की और मलेशिया की भौगोलिक-कूटनीतिक स्थिति की सटीक समीक्षा की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, जो लंबे समय से वहां की सत्ता पर काबिज हैं, ने एक मुहिम चलाकर वहां के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट करने का काम किया है। उन्होंने तुर्की में कुर्दिश राष्ट्रीयता की पहचान के लिए लड़ रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) को कठोरता से दबाने की कोशिश की है। इसके अलावा अब सीरिया से लगी सीमा पर कुर्दों के खिलाफ हमला बोल दिया है। यह तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। भारत ने उचित ही तुर्की की इस एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया है। उसके पास यह विकल्प है कि जरूरत पड़ने पर वह इन कुर्दों को रणनीतिक-कूटनीतिक सहायता देने पर विचार कर सकता है। भारत ने पहले ही ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों, जिनके तुर्की के साथ गंभीर सीमा विवाद हैं, की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही है। बात करें मलेशिया की तो उसे साधने के लिए भारत सरकार ने वहां से पाम ऑयल के आयात को बंद करने के संकेत दिए हैं। इससे उसकी अकड़ कम होती है तो ठीक वर्ना भारत को चाहिए कि वह दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में सिंगापुर और इंडोनेशिया से उसके सीमाई विवादों में उन देशों का साथ दे। मलेशिया ने पूर्व में हुए जोहोर समझौते का उल्लंघन कर किया है, जिससे सिंगापुर काफी चिंतित है। इसके अलावा पेड्रा ब्रांका क्षेत्र पर सिंगापुर दावा कर रहा है और जो इस समय मलेशिया के नियंत्रण में है। भारत अपनी तरकश में रखे इस तीर का भी इस्तेमाल कर सकता है। एक बार ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्सटन ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में केवल हमारे हित स्थाई होते हैं, दोस्त या दुश्मन नहीं। निःसंदेह मोदी सरकार ने राष्ट्र हित में इस सोच पर आगे बढ़ने का हौसला दिखाया है।

चंदन कुमार, देवघर

मेलबाक्स

आस्था का महापर्व

छठ कभी पूर्वांचल क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे देश के विभिन्न भागों के साथ ही विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इसका कारण बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का रोजगार की तलाश में बाहर निकलना है। वे जहां भी गए वहीं पर इसे शुरू कर दिया और दूसरे लोगों ने भी इसकी महत्ता को समझा। इसी वजह से बहुत से दूसरे इलाके के लोग भी इस पूजा में भाग लेने लगे हैं। यह महापर्व भाईचारा एवं एकता को दर्शाता है। कई जगह मुस्लिम महिलाएं भी छठ व्रत करती हैं। दुनिया में सबसे पवित्र पर्व में छठ पर्व के गिनती होती है, इसके साथ ही यह दुनिया का पहला ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते एवं उगते दोनों अवस्थाओं में सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। छठ महापर्व स्वच्छता एवं पर्यावरण का संदेश देता है। इस महापर्व में सफाई का ध्यान एवं प्रकृति से जुड़ी हुई ज्यादातर वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है।

जय किशोर तिवारी, शिक्षक, नई दिल्ली

युवाओं को मिले रोजगार

आज भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। उससे लगता है कि भारत जनसंख्या में विश्व में पहले स्थान पर आ जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज्यादा असर रोजगार पर पड़ रहा है। देश में मेडिकल व इंजीनियरिंग के तमाम कॉलेज हैं और वहां से हर साल बड़ी मात्रा में बच्चे पढ़कर निकलते हैं, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिल पाता है। इनमें से कुछ बच्चे रोजगार के अभाव में अपराध का रास्ता अपना लेते हैं, जिससे एक शिक्षित व्यक्ति अपराधी बन जाता है। सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करे, जिससे हर शिक्षित को रोजगार मिल सके।

मो. जमील, नई दिल्ली

सोच बदलने की जरूरत

हमें स्वस्थ बेटा तो चाहिए पर जो बेटी उस पुत्र को जन्म देगी उसके स्वास्थ्य, लालन-पालन व शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता बरती जाती है। हमें यह क्यों समझ नहीं आता कि अस्वस्थ बेटियां क्या स्वस्थ बेटा पैदा कर सकती हैं? कभी नहीं। हमें बेटियों के प्रति अपनी इस पुरानी घटिया सोच को तुरंत तिलांजलि देकर उनके जन्म और उनके लालन पालन को एक उत्सव के रूप में अपनाना होगा तभी हमारी अगली पीढ़ियां बलशाली होंगी ।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

17 सतत विकास के लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक पूरा करने का संकल्प आज दुनिया भर की तमाम संस्थाओं और विभिन्न देशों द्वारा लिया जा रहा है, जिसे सामाजिक उद्यमशीलता के बिना हासिल करना संभव नहीं है।

आजकल

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

सामाजिक उद्यमशीलता की राह पर बढ़ती दुनिया

इथोपिया के हालिया राजनीतिक और सामाजिक इच्छाशक्ति से यह जाहिर होता है कि यह एक विशुद्ध ग्लोबल सोशल एंटरप्राइज मूवमेंट की नींव रख सकता है। इथोपिया के राष्ट्रपति को इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है जो इस तथ्य को इंगित करता है कि दुनिया के किसी भी देश में शांति कायम रखने के लिए एक सही नेतृत्व व उसकी मजबूत इच्छाशक्ति की सोच काफी है। महज दशक भर पहले बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद युनूस भी इस सोच को धरातल पर उतार चुके हैं। दुनिया भर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस सोच को आगे बढ़ा रही हैं

प्रतीकात्मक

विगत 23 से 25 अक्टूबर के मध्य 70 देशों के 1,200 प्रतिनिधियों ने इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सोशल एंटरप्राइज वर्ल्ड फोरम में सहभागिता दर्ज की। इथोपिया में ऐसा आयोजन समूचे अफ्रीकी महाद्वीप में शांति, स्थिरता और समृद्धि में सामाजिक पूंजी और उद्यमों की भूमिका को रेखांकित करता है। इस बैठक में कहा गया है कि इथोपिया और अफ्रीका में समावेशी आर्थिक विकास आंदोलन को दिशा देने में सोशल एंटरप्राइज वर्ल्ड फोरम की महत्वपूर्ण भूमिका का समय आ गया है। इसमें स्थानीय परंपराओं के संरक्षण पर बल दिया गया है। बैठक में बौद्धिक सामाजिक नवाचारी उद्यमियों ने माना कि संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों अथवा एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक सामाजिक उद्यमशीलता आंदोलन को दिशा देने में इथोपिया प्रशंसनीय भूमिका निभा रहा है।

इथोपिया इस समय विश्व समुदाय के लिए कई क्षेत्रों में एक उदाहरण बना हुआ है। इथोपिया के राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना इस बात का सबूत है कि विश्व के किसी भी महाद्वीप के किसी भी क्षेत्र में शांति स्थापना या शांति बहाली के लिए एक सही नेतृत्व और उसकी मजबूत इच्छाशक्ति की सोच काफी है। इथोपिया ने अफ्रीकी देशों खासकर सूडान जैसे देशों को यह संदेश दिया है कि गृह युद्ध, नृजातीय संघर्ष और जातीय संहार आदि से ऊपर उठकर आर्थिक सुधारों, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक उद्यमशीलता, सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी के निर्माण और नवाचारों को बढ़ावा देने का काम किया जा सकता है और इस तरह बीमार कहे जाने वाले देश में भी विकास की संस्कृति शुरू की जा सकती है। इरीट्रिया के साथ सीमा विवाद हल करने, आपातकाल हटाने, राजनीतिक बंदियों की रिहाई करने की इथोपिया की पहल सराहनीय है। यही वजह है कि आज इथोपिया सहित कई अफ्रीकी देशों में सामाजिक निवेश, सामाजिक व्यवसाय और सामाजिक उद्यमशीलता के मध्य गठजोड़ स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ऐसे देशों में सामाजिक उपक्रमों और सामाजिक उद्यमियों की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है।

अन्य देशों की ओर बढ़ता सामाजिक उद्यमशीलता आंदोलन : विगत 28- 29 जून को बैंकाक, थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के युनूस सेंटर द्वारा नौवें सोशल बिजनेस डे यानी सामाजिक व्यवसाय दिवस का आयोजन किया गया जिसमें 40 देशों के लगभग एक हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सामाजिक नवाचार और उद्यमशीलता पर विशेष जोर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता सामाजिक अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने 'सोशल बिजनेस' शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक गैर-लाभांश कंपनी (नॉन-डिविडेंड कंपनी) है जिसका निर्माण एक सामाजिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। इसमें निवेशकों को निजी लाभ की अपेक्षा नहीं होती है। इस व्यवसाय में कंपनी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और साक्षरता, निर्धनता उन्मूलन, कमजोर वर्गों के लिए वहनीय लागत पर आवास निर्माण, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में परार्थवादी मानसिकता के साथ निवेश करती है। इस तरह के कदम को प्रोफेसर अमर्त्य सेन और मार्था नुसबाम के ह्यूमन कैपिबिलिटी डेवलपमेंट एप्रोच के जरिये भी समझा जा सकता है यानी मानव पूंजी के निर्माण के लिए क्षमता निर्माण और अधिकारिता को बढ़ावा देना सरकारों का मुख्य दायित्व होना चाहिए।

प्रोफेसर मुहम्मद युनूस का कहना है कि आर्थिक समृद्धि और विकास का एक मानवीय चेहरा भी होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो सोशल कैपिटल का निर्माण होता है। सामाजिक निवेश की संकल्पना विश्व भर में विकास उद्योग यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, गैर सरकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन, सिविल सोसायटी संगठन, परोपकारी संगठन, ट्रस्ट आदि को सामाजिक हित के उद्देश्य के लिए कार्य करने हेतु संचालित करती हैं। यूएनडीपी हर वर्ष इक्वेटर प्राइज के लिए ऐसे लोगों, संगठनों को चुनता है जो किसी देश के स्थानीय समुदायों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं, उनके जीविकोपार्जन और क्षमता निर्माण की दिशा में काम करते हैं।

वास्तव में आर्थिक गतिविधियों का अस्तित्व समाज के लिए ही तो है। इसलिए अर्थव्यवस्था के सामाजिक उद्देश्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज चाहे विश्व बैंक हो, आइएमएफ हो, विश्व व्यापार संगठन हो, एशियाई विकास बैंक हो, संयुक्त राष्ट्र हो या कोई भी अन्य क्षेत्रीय संगठन हो, सभी 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की बात करते दिखाई देते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक परियोजनाओं के उप-उत्पाद के रूप में स्वच्छता, पर्यटन, नदियों की सफाई, अवसंरचना का विकास होता आया है। सामाजिक पूंजी के निर्माण को प्राथमिक क्षेत्र जैसा सत्कार मिलना चाहिए। आदिम जनजातियों (पीवीटीजी), महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों, किशोरियों, नवजात शिशुओं और युवाओं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का सशक्तीकरण समय और देशकाल की मांग है। देश में सामाजिक पूंजी और विकास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नियोजन में सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति को आंदोलन जैसा रूप देने की जरूरत है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सोशल बिजनेस डे पर कहा कि सामाजिक उपक्रम और उद्यम वैश्विक समृद्धि में अहम भूमिका निभाती है। हाल ही में सोशल और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को एसडीजी गोल से भारत के रिसर्च एंड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सामाजिक आर्थिक विश्लेषकों ने भी एसडीजी इंडेक्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ कर देखा है। इनका कहना है कि यदि 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का काम किया जाए तो इससे कारोबारी सुगमता भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2019 के लिए सोशल बिजनेस डे थीम वर्तमान विश्व के लिए अति प्रासंगिक है। धन के सृजन में प्रसन्नता है, लेकिन अन्य लोगों को प्रसन्न बनाना सुपर हैप्पीनेस है- वर्ष 2019 का यह थीम मानव सभ्यता की सबसे बुनियादी जरूरत को पूरा करने की बात करता है।

सामाजिक पूंजी और नवाचार सृजन के मायने : अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतकार रॉबर्ट पटनम ने वर्ष 2000 में अपनी पुस्तक 'बोवलिंग अलोन : दि कोलेप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी' में सामाजिक पूंजी के क्षरण के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उनका कहना था कि यद्यपि अमेरिकी वित्तीय रूप से समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन उनकी समुदाय और सामुदायिकता की भावना का लोप होता जा रहा है। अमेरिकी सामाजिक अलगाव और एकाकीपन का जीवन जी रहे हैं, शहरी सुख सुविधाओं के मकड़जाल में सोशल बॉन्ड और सांस्कृतिक संपर्कों को लोग भूलते जा रहे हैं। यह स्थिति मानव विकास, समावेशी विकास और सोशल फैब्रिक के लिए घातक है। यही स्थिति विकासशील देशों में भी जारी है। सामाजिक बंधुत्व, समरसता, समाज की खुशी, सामाजिक साझापन, सहानुभूति आदि की भावना का क्षरण होता जा रहा है, इसलिए समाज में चुनौतियां और जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं। एक जीवंत समाज के हित में व्यक्ति जब सोच ही नहीं रहा हो, समाज के मूल्यों, परंपराओं के प्रति उसमें निष्ठा मरती जा रही हो तो समाज व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है, समाज में मॉब लिंचिंग, किशोर अपराध, महिलाओं का यौन शोषण, दुष्कर्म, अछूत के नाम पर सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं देखने को मिलेंगी ही। समाज में विश्वास निर्माण और विश्वास निर्माण बहाली के उपाय करने जरूरी हैं, तभी व्यापार, वाणिज्य, कला-संस्कृति, राजनीति का स्वस्थ विकास संभव हो सकेगा।

सामाजिक उत्तरदायित्व में सभी की भागीदारी

वसुधैव कुटुंबकम और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भारतीय धारणा भी इस वर्ष के सोशल बिजनेस डे से जुड़ी थीम पर आधारित है, जो इसी सार्वभौमिक प्रसन्नता के लक्ष्य पर आधारित है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने एक हैप्पीनेस कमीशन के गठन का निर्णय किया है। इसके पहले मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का गठन किया था। वर्ष 2018 में असम में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भूटान के प्रधानमंत्री के समक्ष असम ने राज्य जीडीपी गणना में सकल प्रसन्नता यानी ग्रॉस हैप्पीनेस को शामिल करने की घोषणा की। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में भूटान विश्व का पहला देश था जिसने अपने सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की गणना करने की शुरुआत की थी और इसके लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स भी बनाया। आज दुनिया भर के राष्ट्र इस विचार से प्रेरित हो कर राष्ट्रीय आय में जनता की खुशी और संतुष्टि को शामिल करने की पहल कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क हर वर्ष वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है। इसमें प्रसन्नता को मापने के लिए कई कारकों जैसे जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, आय और सज्जनता का इस्तेमाल किया जाता है। आज भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान किया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व का विचार दिया गया। इसी प्रकार आइयूसीएन, लार्सन एंड टूब्रो, एनटीपीसी और धमारा बंदरगाह ने मिलकर ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए पर्यावरणीय सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना विकसित की है। इन सब उदाहरणों का एक ही आशय है कि अर्थव्यवस्था, कॉरपोरेट और वाणिज्यिक संगठनों को समाज के लिए बहुत कुछ करना है।

संबंधित वैश्विक क्रांति का प्रयास

वर्तमान जटिल विश्व व्यवस्था में सभी क्षेत्रों में जीवंत उद्यमशीलता और नवाचारी समाधानों की जरूरत है ताकि सामाजिक, पर्यावरणीय, वित्तीय संकटों को दूर करने की राह मिल सके। जो संस्थाएं केवल वित्तीय लाभों के लिए काम करती हैं और गैर लाभकारी संगठनों, जो सोशल मिशन के लिए काम करती हैं, उन सभी को कई प्रकार के जोखिमों के समाधान के लिए एक मंच पर लाने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखकर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2015 में सामाजिक उद्यमशीलता की दिशा में वैश्विक क्रांति लाने के लक्ष्य के साथ यूनाइटेड नेशंस सोशल एंटरप्राइजेज फैसिलिटी का गठन किया। इस फैसिलिटी का गठन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप के मल्टीपार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस के तहत किया गया है जो वर्तमान में 103 देशों में सामाजिक उद्यमशीलता को एक वैश्विक क्रांति बनाने के लक्ष्य के साथ सात बिलियन डॉलर की राशि का प्रबंधन कर रही है। यहां यह जानना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस सोशल एंटरप्राइजेज फैसिलिटी संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट शाखा है। इसका उद्देश्य उच्च क्षमता संभावना वाले सामाजिक उपक्रमों, स्टार्ट-अप्स बिजनेस को समर्थन प्रदान करना है, यह आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, क्षमता निर्माण और प्रतिभा अवसंरचना के विकास में सहयोग करती है। यह प्रत्येक ऐसे उच्च विकास संभावनामूलक सोशल एंटरप्राइज को एक लाख डॉलर तक अनुदान देती है। इस प्रकार वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर सामाजिक पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया अबाधित रूप से चलती रहनी चाहिए। विकास का सामाजिक और मानवीय चेहरा तैयार करना, वैश्विक स्तर पर कई विवादों और तनावों को दूर करने का एक ठोस जरिया बन सकता है।

खरी-खरी

बहुत कुछ मीठा हो जाए!

अमित शर्मा

त्योहारों, विशेषकर दिवाली पर हर इंसान चाहता है कि (बहुत) कुछ मीठा हो जाए। मीठे के लिए इंसान अक्सर एकांत में मिठाइयों पर धावा भी बोल देता है। मिठाइयों में सोन पापड़ी की हैसियत शरणार्थी की तरह होती है जिसे कोई स्थायी रूप से बसाना नहीं चाहता। सोन पापड़ी के पैकेट्स अपना जीवनकाल एक अतिथि से दूसरे अतिथि के यहां बिताकर अंत में गुमनामी में दम तोड़ देते हैं। ड्राइफ्रूट्स आम आदमी की जेब से दूर जा चुके हैं। ऐसे में मावे की मिठाइयां नेताओं के चुनावी वादों की तरह हर वर्ग को लुभाती हैं। नेताओं के चुनावी वादों की तरह मावे में भी मिलावट होती है।

छोटा मुंह-छोटी बात, लेकिन कहना होगा कि अब दिवाली केवल असत्य पर सत्य की विजय का पर्व नहीं रहा, बल्कि यह नकली मावे पर असली मावे की विजय का भी पर्व है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के 'बांकुरे' शुद्ध मावे के लिए माइक लिए यहां-वहां दिखते हैं, उससे लगता है कि नकली मावे का दहन बुराई रूपी रावण के दहन सरीखा जरूरी है।

दिवाली आते ही मीडिया को अचानक जनता के स्वास्थ्य की चिंता सताने लगती है। हालांकि ये स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है, क्योंकि अगर दर्शक त्योहार के दौरान 'हेल्दी' नहीं रहेंगे, तो वे टीवी चैनल पर अवतरित होने वाले विविध विज्ञापनों के दर्शन कर अलग-अलग ऑफर्स की गिरफ्त में आकर 'वेल्दी' कैसे बनेंगे।

जिस तरीके से दिवाली पर दीप जलाना शुभ माना जाता है, उसी तरीके से नकली मावे की बिक्री और उसके जब्त होने की खबर देखना और पढ़ना लाभ-शुभ की बोहनी का संकेत होता है। क्योंकि जब मीडिया, बाजार में नकली मावे की खबरें चलाता है, तब जाकर आमजन को विश्वास होता है कि बाजार और मीडिया, दोनों दिवाली पर अपनी तैयारियों को लेकर सचमुच गंभीर हैं।

मीडिया हमें यह 'भरोसा' दिलाता है कि दिवाली पर आतंकी हमले से ज्यादा नकली मावे से सुरक्षा की जरूरत है। सारी मिठाई की दुकानों पर दुश्मन के बंकर की तरह नजर रखी जाती है। रसद विभाग जगह-जगह सर्जिकल स्ट्राइक कर नकली मावा और अपने हिस्से की लाइम लाइट जब्त करता है। फिर बिना मांगे इस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी उपलब्ध कराता है। आम आदमी इसी ऊहापोह में जीता है कि दीपावली पर जो मावा उसके पेट में गया है, न जाने उसके दूरगामी परिणाम कितने भयावह होंगे!

ट्वीट-ट्वीट

कश्मीर घाटी में मजदूरों की हत्या स्थानीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट करने का षड्यंत्र है। कश्मीरी जनता को इस पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ खुलकर सामने आना होगा। आखिर कब तक वे अपनी रोजी-रोटी को इस तरह चोट पहुंचने देंगे? यह उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

राष्ट्रगान पर खड़ा न होने पर किसी को परेशान या मारपीट करना समझ नहीं आता। यह भी समझ नहीं आता कि राष्ट्रगान पर खड़े होने में कुछ को इतनी तकलीफ क्यों? क्या आप छोटे हो जाते हैं? क्या आपका अपमान होता है? आपको फख्र महसूस नहीं होता इसमें? कोई और वजह?
ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। हम इस बारे में किसी तीसरे पक्ष, समूह, संस्था या व्यक्ति की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले तीन दिन में इस नीति को पलट मोदी सरकार ने एक अक्षम्य अपराध किया है!
रणदीप सिंह सुरजेवाला@rssurjewala

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या यूरोपीय संघ के सांसदों को कश्मीर दौरे की इजाजत देकर मोदी सरकार ने सही किया है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आप मुकेश अंबानी के कथन से सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती अस्थाई है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सुलझाते कश्मीर को यदि सरदार पटेल,
पक्का है चलता नहीं तब जिन्ना का खेल।
तब जिन्ना का खेल पीटता रहता छाती,
आज घूमते आप शान से पूरी घाटी।
आजादी के बाद न नेहरू टांग अड़ाते,
तो गुत्थियां पटेल चुटकियों में सुलझाते।
– ओमप्रकाश तिवारी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश डायरी

संसाधनों की जुगत में एक आयोजन

धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। उत्तराखंड के मॉडल से प्रेरित होकर उठाया गया यह कदम हिमाचल प्रदेश की तरक्की के रास्ते खोलेगा, ऐसा समझा जा रहा है। ताजा खबर यह भी है कि बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम इसकी ब्रांड एंबेसडर होंगी। उन्होंने ट्वीट कर इस आशय की सूचना भी दे दी है और हिमाचली होने के नाते इसे गौरवान्वित करने वाला पल भी बताया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।

इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मुख्य सचिव व अन्य अफसरों को जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके मुताबिक पूरे कार्यक्रम को शक्ल दी जा रही है। जाहिर है कि केवल नौकरशाही नहीं, राजनीतिक नेतृत्व तय करेगा कि कार्यक्रम की शक्ल क्या होगी। इधर, कांगड़ा या गगल हवाई अड्डे से धर्मशाला को जोड़ने वाले पुल की मरम्मत भी युद्ध स्तर पर जारी है।

ग्लोबल मीट में आ रहे 2,200 प्रतिनिधियों को एक-एक संपर्क अधिकारी भी मिलेगा। विमान से लेकर गाड़ियों तक के प्रबंधन का खूब माहौल है। धर्मशाला शहर के रास्तों के आसपास जो दीवारें रंग रोगन के लिए तरस रही थीं, उनके दिन भी बहुरे हैं। वर्ष 1980 के समय का परिवार नियोजन का नारा धरोहर की तरह खुद में समेटे अस्पताल के सामने की दीवार पर भी नया रंग चढ़ गया है।

इससे पहले धर्मशाला उपचुनाव के कारण चर्चा में रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीट कड़ी मेहनत के बाद निकाल ली। सीट तो सिरमौर के पच्छाद की भी भाजपा ने किसी तरह निकाल ली। यह दीगर है कि लोकसभा चुनाव में धर्मशाला में भाजपा की लीड एक तिहाई रह गई और पच्छाद में एक बटा छह। पराजय मिलती तो मंथन की तत्काल आवश्यकता थी। जरूरत तो अब भी है, लेकिन विजयश्री साथ है इसलिए इन्वेस्टर मीट पहले होगी और उसके बाद मंथन। किसने मुंह फुलाए रखा, किसकी तबीयत लगातार नासाज रही, किसके जोन का

प्रतीकात्मक

प्रबंधन किसने किया... यानी काम भी किया या नहीं... यह सब पता चलना चाहिए। उसके बाद अपने वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल भी करेंगे। मुख्यमंत्री जोर न लगाते तो राहें कठिन थीं। मंथन की जरूरत इसलिए भी है कि जीत के तत्काल बाद एक वरिष्ठ नेता ने यह कहते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, 'सात-आठ नवंबर को मोदी जी, अमित शाह जी धर्मशाला आने वाले हैं, भगवान का शुक्र है जीत गए, वरना हम क्या मुंह दिखाते। जीत पर क्या कहें, आपके सामने ही है।'

बहरहाल, दो दिवसीय आयोजन में पहले दिन यानी सात नवंबर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विदेशी भारतीयों के सत्र हैं। पर्यटन, स्वास्थ्य व आयुष के अलावा सहभागी देश का सत्र भी है। अगला और अंतिम दिन ऊर्जा, और पन-बिजली पर रहेगा, खाद्य प्रसंस्करण डेयरी विकास, पहाड़ी राज्यों में निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और लाभ आदि पर बात होगी और अंततः सूचना-तकनीक पर बात होगी। पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश में संसाधन बढ़ाने के लिए पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजन होने जा रहा है, इसकी सफलता वस्तुतः हिमाचल की सफलता होगी। कांग्रेस बेशक इसे हिमाचल को बेचने के प्रयास बताए, लेकिन अब यह आयोजकों की जिम्मेदारी है कि आलोचकों को परिणाम से जवाब दें। कुल मिलाकर जैसे उपचुनाव मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम की जिम्मेदारी बन कर रह गया था, इन्वेस्टर मीट भी उन्हीं का सूचकांक बनेगा। इसलिए, नजर उन्हें स्वयं ही रखनी चाहिए।

चले गए काव : हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य बनने के समय एक लिपिकीय गलती के कारण हिमाचल काडर में आए महाराज कृष्ण काव का सोमवार को 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में देहांत हो गया। वह केंद्र में वित्त सचिव भी रहे। बाद में केंद्रीय मानव संसाधन सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके रहते ही मूल्यों की शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी थी। पांचवें वेतन आयोग के वह सदस्य सचिव थे। मूलतः कश्मीरी काव को अपने हिमाचल संबंध पर गर्व होता था। अंग्रेजी में कई बेस्ट सेलर देने वाले एमके काव की करीब 14 किताबें हैं। इनमें कविता, उपन्यास और कहानी के अलावा नौकरशाही के अंदर के हाल पर 'ब्यूरोक्रेजी गेट्स क्रेजियर' और 'एन आउटसाइडर एवरीवेयर' ऐसी किताबें हैं जिनकी चर्चा हर नौकरशाह करता है।

संजय गांधी के समय में उन्होंने हिमाचल निर्माता मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार का बेहद साथ दिया था। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले वह हिमाचल में शिक्षा, वित्त और सामान्य प्रशासन जैसे विभागों के सचिव रहे। उनकी बहन आशा स्वरूप भी हिमाचल प्रदेश की मुख्य सचिव रही हैं। बीते वर्ष वह धर्मशाला आए तो जिलाधीश कार्यालय भी गए जहां यह देख कर दुखी हुए कि उनका लगाया चिनार का पेड़ अब नहीं है। वह देवदार और चिनार को एक जगह देखना चाहते थे। ऐसे ही सुंदर सपनों के लिए काम करते थे काव। उन्हें नियमों का पाबंद, संवेदनशील और हिमाचल में साहित्यिक अभिरुचियों को मंच देने वाले अधिकारी के रूप में याद किया जा रहा है।

मुद्दा

प्रदीप
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आंकड़ों की निजता का सवाल!

विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये बड़ी आबादी जुड़ी हुई है जिनसे व्यापक आंकड़े सृजित होते हैं। संबंधित कंपनियां इनका कहां-कैसे इस्तेमाल करती हैं, अधिकांश इससे अनभिज्ञ हैं

प्रतीकात्मक

सोशल नेटवर्किंग की दुनिया का बेताज बादशाह फेसबुक अपने नए सिक्युरिटी फीचर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के दौरान यूजर्स से आजकल उनके एकाउंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उनके मोबाइल नंबर की मांग कर रहा है। लेकिन बहुत से तकनीकी विशेषज्ञ और गोपनीयता के हिमायती फेसबुक यूजर्स को चेता रहे हैं कि मोबाइल नंबर को एकाउंट में जोड़ने से प्राइवेसी खत्म होने का खतरा है। मोबाइल फोन नंबर किसी को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है, इसके जरिये कोई भी यूजर की गतिविधियों पर निगरानी रख सकता है। इस पर फेसबुक का कहना है कि उसके इस फीचर का मकसद यूजर्स के एकाउंट को ज्यादा सुरक्षित बनाना है।

ऑथेंटिकेशन की इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले यूजर अपने एकाउंट में पासवर्ड डालकर लॉग-इन करता है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन के दूसरे चरण में फेसबुक यूजर के मोबाइल फोन पर एक कोड भेजता है, इस कोड को पासवर्ड एंटर करने के बाद डालना होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही यूजर अपना फेसबुक एकाउंट नए डिवाइस पर एक्सेस कर पाता है। अगर फेसबुक पर आपका कोई लोकप्रिय पेज है, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर के जरिये लॉग-इन किए बगैर अपने पेज पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं। पिछले दो-तीन माह से फेसबुक इस मामले में जबरदस्ती से काम ले रहा है।

पहली नजर में लगता है कि फेसबुक ऐसा यूजर की पहचान को पुख्ता करने और उसके एकाउंट को हैकर्स से बचाने के लिए कर रहा है। मगर क्या फेसबुक जैसी कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है? फेसबुक के पुराने रिकार्ड्स को देखें तो वह कई बार अपने यूजर्स की बेहद निजी जानकारियों को अवांछित लोगों के हाथों में पहुंचने से नहीं रोक पाया है। वैसे भी फेसबुक के मौजूदा बिजनेस मॉडल को देखें तो यही लगता है कि डाटा सिक्युरिटी जैसे मुद्दों पर फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां ज्यादा गंभीर नहीं है। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोबाइल नंबर डालने के कई खतरे हैं जिसमें सबसे अहम है कि आपके नंबर की मदद से कोई भी फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल को आसानी से ढूंढ सकता है। कोई भी इंटरनेट यूजर फेसबुक पर अपना नंबर डालने वाले किसी भी यूजर की निजी जानकारी निकाल सकता है! एक अमेरिकी अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जब यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को फेसबुक प्रोफाइल से जोड़ते हैं तो वे मार्केटिंग से जुड़ी चीजों के लिए भी अनुमति देते हैं। यानी फेसबुक फोन नंबर का इस्तेमाल विज्ञापन टारगेट करने के लिए यूजर्स से पहले ही हामी भरवा लेता है।

हम इंटरनेट युग में सांस लेनेवाले प्राणी हैं। आज गूगल, फेसबुक, ब्लॉग, ट्वीटर, वाट्सएप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जहां इन सभी प्लेटफॉर्मों ने हमें अभिव्यक्ति के मजबूत मंच प्रदान किए हैं, वहीं यहां कुछ खास कंपनियों का ही वर्चस्व चल रहा है। और ये कंपनियां हमारी गोपनीयता का उतना ख्याल नहीं कर रहीं हैं जितनी इन्हें करनी चाहिए।

तमाम सोशल मीडिया कंपनियां अपनी सेवाओं के लिए यूजर से एक भी रुपये नहीं लेतीं हैं। हमें यह समझना होगा कि मुफ्त नाम की कोई भी चीज नहीं होती, पीछे से जेब में हाथ डाला ही जाता है। भले ही ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुद को मुफ्त बताते हों, मगर इनकी ज्यादातर कमाई का स्रोत यूजर्स की निजी जानकरियां या डाटा हैं जिसे वे अपनी सहायक कंपनियों को बेच देते हैं और फिर वे इस डाटाबेस का इस्तेमाल विज्ञापन टारगेट करने के लिए करते हैं। ये कंपनियां यूजर्स की डेमोग्राफिक डाटा के साथ-साथ उनके काम-काज, उम्र, लिंग, स्थान, पसंद-नापसंद, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक झुकाव, रहन-सहन आदि निजी जानकारियों को सहेज कर रखती हैं। यूजर के बारे में जितना डाटा जिस कंपनी को मालूम होगा उसकी विज्ञापन प्रणाली उतनी ज्यादा प्रभावी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा इकट्ठी की जाने वाली ये जानकारियां आदि हजारों ऐसे चीजें बनाने वाली कंपनियों के लिए मूल्यवान साबित होती हैं। इन्हीं डाटाबेस के जरिये उन्हें अपने वास्तविक ग्राहक वर्ग का पता चलता है। इन कंपनियों के लिए यूजर्स डाटा उगाही का कारखाना भर हैं जिनको बहला फुसलाकर ज्यादा से ज्यादा डाटा उगलवाना इनका मकसद है! टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। आज सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों में हम इतने रमे रहते हैं कि वास्तविक दुनिया से बेखबर आभासी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने हमारी सामाजिकता को कमजोर किया है। टेक्नोलॉजी हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है। यह एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। यह आधुनिक युग भी बड़ा विरोधाभासी है, जो दिखता है, होता उससे अलग है। आधुनिक तकनीक दिखावे पर जोर देता है यानी इसके लिए गुणात्मक पहलुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण मात्रात्मक पहलू है। पारंपरिक तकनीक दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती थी, और आधुनिक तकनीक इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। विभिन्न समाजशास्त्रियों का मानना है कि आधुनिक और पारंपरिक तकनीक के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि जहां पारंपरिक तकनीक को समाज व्यवस्थित करता था, वहीं आधुनिक तकनीक समाज को व्यवस्थित करती है। आधुनिक तकनीक इच्छा और आवश्यकता के बड़े अंतर को धूमिल कर देती है। इसलिए आधुनिक तकनीक समाज के लिए नहीं, बल्कि मोटी रकम कमाने वाली कंपनियों या फिर कहें कि बाजार के लिए बनी है, तो अतिशयोक्ति नहीं।

बहरहाल तकनीक जिस तरह से हमारे दिमाग पर कब्जा कर रही है, क्या यह भविष्य में मनुष्य को बेकाम और अप्रासंगिक बना सकती है? क्या भविष्य में मनुष्य तकनीक के अधीन हो जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें समय रहते गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

कड़ा हुआ कानून तो अब झारखंड में धर्म नहीं बदल रहे लोग

सितंबर, 2017 में धर्म स्वतंत्र कानून लागू होने के बाद से राज्य में अप्रत्याशित ढंग से धर्मांतरण के मामलों में आई कमी

जागरण विशेष

उत्तम नाथ पाठक, रांची

धर्मांतरण के बड़े आंकड़ों को लेकर देशभर में सुर्खियों में रहने वाले झारखंड में सितंबर, 2017 में धर्म स्वतंत्र कानून (झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017) के लागू हो जाने के बाद से राज्य में धर्मांतरण अप्रत्याशित ढंग से थम गया है। धर्म परिवर्तन के मामले एकाएक खत्म हो गए हैं।

सिमडेगा, गुमला, खूंटी, कोडरमा सहित झारखंड के अन्य प्रमुख जिलों में की गई पड़ताल से यह तथ्य सामने आया। सितंबर, 2017 से लेकर अब तक की अवधि में जिला उपायुक्तों के पास धर्म परिवर्तन के लिए दिए गए आवेदनों की संख्या नगण्य है। सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और खूंटी में जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के धर्मांतरण की बात पहले सामने आती थी, वैसा अब बिलकुल नहीं है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस दौरान सिमडेगा और गुमला में गिनती के कुछ आवेदन आए। सिमडेगा तो धर्मांतरण का गढ़ ही बन गया था। वहीं, अन्य जिलों की बात करें तो इक्का-दुक्का आवेदन भी उपायुक्तों के पास नहीं पहुंचे।

सिमडेगा, गुमला, खूंटी, कोडरमा सहित अन्य प्रमुख जिलों में की गई पड़ताल। प्रतीकात्मक

कानून लागू होने के बाद से गुमला जिला में धर्मांतरण के लिए कुल 35 लोगों ने उपायुक्त को आवेदन देकर अनुमति मांगी है। जांच प्रतिवेदन अपर्याप्त होने के कारण अब तक किसी को अनुमति नहीं मिली है। धर्मांतरण के लिए प्रदेश भर में सबसे अधिक चर्चित रहने वाले सिमडेगा में कानून लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए सिर्फ आठ आवेदन उपायुक्त कार्यालय आए, जबकि आवेदन करने वाले मंजूरी लेने के लिए दोबारा उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ही नहीं। जांच पूरी न होने से अब तक किसी को अनुमति नहीं मिली है। उपायुक्त कार्यालय के अनुसार संबंधित फाइल प्रक्रियाधीन है।

पलामू के उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि का कहना है कि धर्मांतरण को लेकर जिले से कोई भी आवेदन उनके पास नहीं आया है। वहीं गढ़वा के उपायुक्त हर्ष मंगला ने बताया कि प्रशासन को कोई आवेदन नहीं मिला है। धर्मांतरण के लिए चर्चित रहे खूंटी जिले के एसडीएम प्रणव कुमार पाल ने बताया कि अब तक कोई आवेदन धर्मांतरण के लिए नहीं आया है। वहीं लोहरदगा जिले की उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने कहा कि उनके यहां भी धर्मांतरण के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। लातेहार के उपायुक्त जिशान कमर ने बताया कि जिले से किसी भी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन की इच्छा जताते हुए आवेदन नहीं दिया है। इसी तरह रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा के उपायुक्त कार्यालय के अनुसार उनके यहां भी धर्मांतरण के लिए एक भी आवेदन नहीं पहुंचा है। यह आंकड़े बयां कर रहे हैं कि झारखंड में बड़ी संख्या में होने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लग गई है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

लग रही लगाम

दरअसल, धर्म स्वतंत्र विधेयक लागू होने के बाद बिना अनुमति धर्मांतरण करने वाले और धर्मांतरण करवाने वाले को चार साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन करने से पहले उपायुक्त को आवेदन देकर अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। धर्मांतरण के लिए होने वाले संस्कार या समारोह के लिए भी जिला उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में किसी भी तरह के प्रलोभन या कपट आदि युक्तियों के बूते धर्मांतरण कराने के चलन पर प्रभावी लगाम लगती दिख रही है।

- देशभर में बड़ी संख्या में धर्मांतरण के लिए बदनाम रहा है झारखंड
- गुमला में 35 और सिमडेगा में महज आठ लोगों ने किया आवेदन, दोबारा नहीं पहुंचे अनुमति लेने
- खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लातेहार, गढ़वा में एक भी आवेदन नहीं पहुंचा उपायुक्त के पास
- यहां अब किसी भी व्यक्ति को कपट से या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता

मप्र के इस सरकारी स्कूल की सभी छात्राएं 'भारतीय'

शासकीय आदर्श कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं। नवदुनिया

अंजली राय, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित शासकीय आदर्श कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्राओं का एक ही सरनेम होता है- 'भारतीय'। देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को ये बालिकाएं निराले तरीके से परिभाषित कर रही हैं। प्रदेश का यह एकमात्र ऐसा स्कूल है, जहां पढ़ने वाली हर जाति, वर्ग की छात्रा का सरनेम दाखिले के समय ही बदलकर 'भारतीय' कर दिया जाता है।

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इससे उनमें न सिर्फ समानता का भाव आता है, बल्कि यह उनके जीवन में भी उतर जाता है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2018 में साउथ टीटी नगर में शासकीय आदर्श कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया। इसमें छठवीं और नौवीं कक्षा से दाखिला होता है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 106 छात्राएं यहां अध्ययनरत हैं, जिनमें से 90 फीसद एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग से हैं। टीकमगढ़, अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल सहित अन्य आदिवासी बहुल जिलों की ज्यादातर छात्राएं यहां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। इन सभी छात्राओं का सरनेम भारतीय है।

संस्थान के निदेशक पीआर तिवारी बताते हैं कि बालिकाओं में समानता का भाव बना रहे, जात-पांत के दुष्चक्र से दूर रहें, देश सबसे पहले का सूत्रवाक्य जीवन में उतर सके और उनकी खुद की अलग पहचान बने, इसलिए सभी छात्राओं को भारतीय सरनेम दिया गया है। सरनेम माता-पिता के नाम का द्योतक होता है। इससे बच्चों के साथ माता-पिता की पहचान जुड़ती है। जब यह भारतीय हो जाता है तो उनके साथ देश की पहचान जुड़ जाती है। इन बच्चियों के माता-पिता भी इस पहल को सहर्ष स्वीकार रहे हैं।

इस विद्यालय में छात्राओं को अन्य विषयों के साथ विशेष रूप से संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। वे संस्कृत के साथ वेद-पुराण, उपनिषद में पारंगत हो रही हैं। सभी छात्राएं स्वास्ति वाचन, गीता श्लोक, वेदों की ऋचाएं आदि धारा प्रवाह बोलती हैं। यही नहीं, वे आपस में संस्कृत में ही बात करती हैं।

विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से छात्राओं को संस्कृत के श्लोक-मंत्र या अन्य विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। संस्कृत के तहत तीन विषय संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और भारतीय संस्कृति विज्ञान पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

सुशिक्षित समाज

देश की एकता, और संस्कृति को इस तरह परिभाषित कर रहीं ये बालिकाएं

- भोपाल स्थित शासकीय आदर्श कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का एक ही सरनेम 'भारतीय'
- वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 106 छात्राएं यहां अध्ययनरत हैं

विद्यालय की छात्राओं को संस्कृत में पारंगत बनाया जा रहा है, साथ ही आधुनिक विषयों को भी पढ़ाया जा रहा है, जिससे बेहतर भविष्य के रास्ते खुलें। विशेष बात यह कि यहां सभी का जाति-धर्म सिर्फ भारतीय ही है।

- स्नेहा सालोडकर, प्राचार्य, शासकीय आदर्श कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय, भोपाल, मप्र

उम्मीद : जल्द मिलेगा यूरिक एसिड का कारगर इलाज

शोध ▶ गठिया के साथ ही किडनी पर भी असर डाल रहा यूरिक एसिड

जीएसवीएम के चार माह के अध्ययन के दौरान कारगर इलाज मिलने का दावा

ऋषि दीक्षित, कानपुर

यूरिक एसिड सिर्फ गठिया ही नहीं बल्कि किडनी (गुर्दा) की बीमारी भी दे रहा है। यह खतरनाक स्थिति गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय (जीएसवीएम) के चार माह के अध्ययन में सामने आई है। अध्ययन में जिन मरीजों को दवाएं दी गईं, उन पर सकारात्मक असर हुआ है। बहुत जल्द मरीजों को कारगर इलाज मिलने की उम्मीद है।

हर मरीज में किडनी खराब होने की वजह अलग होती है इसलिए मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. ऋचा गिरि ने अध्ययन शुरू किया। उनके साथ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. समीर गोविल भी जुड़े। ओपीडी में आए मरीजों में से 60 मरीजों को शोध का हिस्सा बनाया गया। पहले उनकी सभी पैथालॉजिकल जांचें कराई गईं।

इसमें 40 मरीजों का यूरिक एसिड और सीरम क्रिएटनिन बढ़ा मिला। उन्हें सॉल्ट विशेष की दवाएं दी गईं। एक माह बाद दोबारा जांच में पहले की अपेक्षा यूरिक एसिड कम मिला। इससे उनका सीरम क्रिएटनिन भी कम हुआ। चार माह के अध्ययन में पता चला कि यूरिक एसिड बढ़ने से सीरम क्रिएटनिन बढ़ता है, जो किडनी पर असर डालता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अब तक के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं, दो माह बाद निष्कर्ष सामने आएगा।

40 मरीजों के खानपान में बदलाव और दवा सेवन से मिला फायदा

दो से ऊपर क्रिएटनिन घातक

अगर सीरम क्रिएटनिन दो से ऊपर है। इसका मतलब किडनी 50 फीसद डैमेज हो चुकी है। ऐसे में क्रिएटनिन-यूरिक एसिड की जांच करानी चाहिए।

60 मरीजों को शोध का हिस्सा बनाया गया। प्रतीकात्मक

अध्ययन में यूरिक एसिड को किडनी मार्कर के रूप में देखा जा रहा है। शोध में यूरिक एसिड का असर किडनी पर देखा गया है। इसे नियंत्रित रखना जरूरी है। कारगर इलाज के लिए विशेष प्रकार के मॉलीक्यूल पर कार्य कर रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम मिले हैं।

प्रो. ऋचा गिरि, विभागाध्यक्ष, मेडिसिन, जीएसवीएम कॉलेज।

दूर किया प्रोटीनयुक्त भोजन से : जिन मरीजों का यूरिक एसिड बढ़ा था। उनके खानपान तथा दवाओं की सूची तैयार की गई। खानपान में बदलाव कराया गया। प्रोटीन युक्त आहार दाल, मीट, रेड मीट, पनीर, अंकुरित अनाज का सेवन कम कराया। सुबह और शाम टहलने के साथ ही योग एवं व्यायाम से उन्हें लाभ मिला।

सबसे पहले बायो टॉयलेट से लैस हुआ पश्चिम मध्य रेलवे जोन

अतुल शुक्ला, जबलपुर

रेलवे ट्रैक की गंदगी को खत्म करने और प्लेटफार्म को साफ-सुधरा रखने के लिए भारतीय रेलवे ने अब तक कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यात्री ट्रेनों के कोच में बायो टॉयलेट लगाना है। इस काम में पश्चिम मध्य रेलवे जोन (पमरे- मुख्यालय जबलपुर) ने बाजी मार ली है। जोन ने अपने तीनों रेल मंडल जबलपुर, भोपाल और कोटा की सभी ट्रेनों के 1750 से अधिक कोच में बायो टॉयलेट लगाने का काम पूरा कर लिया है। खास बात यह है कि पश्चिम मध्य रेलवे ने यह काम देश के सभी 16 रेल जोन में सबसे पहले किया है। दरअसल, स्वच्छ रेल-स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे ने ट्रेनों के सभी कोच में बायो टॉयलेट लगाने को कहा था। इसके बाद सभी रेल जोन ने अपने-अपने रेल मंडल में यात्री कोच में बायो टॉयलेट लगाने का काम शुरू किया।

ऐसे बना बॉयो टॉयलेट लगाने में अव्वल : पश्चिम मध्य रेलवे के मैकेनिकल विभाग के पास कोच में बायो टॉयलेट लगाने की जिम्मेदारी थी। विभाग के मुखिया चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ने जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल के मैकेनिकल विभाग के अधिकारियों को अपने सभी कोचों में जल्द से जल्द बॉयो टॉयलेट लगाने के निर्देश तो दिए ही, उन्होंने हर दिन काम की समीक्षा की। बायो टॉयलेट की आपूर्ति समय पर हो, यह जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड ने संभाली। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य रेलवे स्टेशन स्थित कोचिंग डिपो जैसे जबलपुर, भोपाल, कोटा में स्थानीय कर्मचारियों को ही विशेष प्रशिक्षण देकर यह काम करवाया गया। इससे कोच को अन्यत्र भेजे जाने में लगने वाला समय बचा।

ट्रैक मेंटीनेंस के काम की बढ़ी रफ्तार : यात्री ट्रेनों के कोच में बायो टॉयलेट लगाने के पीछे की मुख्य वजह टॉयलेट की गंदगी को रेलवे ट्रैक पर गिरने से रोकना था। इससे ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले और सफाई कर्मचारी, दोनों को परेशानी होती थी। इतना ही नहीं पटरियों को भी नुकसान पहुंचता था लेकिन बायो टॉयलेट लगाने के बाद ट्रैक पर होने वाली गंदगी में तकरीबन 80 से 90 फीसदी की कमी आई है। वहीं ट्रैक मेंटेनेंस के काम की रफ्तार भी बढ़ी है।

80 से 90 फीसदी तक रुकी रेलवे ट्रैक की गंदगी

- जबलपुर, भोपाल और कोटा, तीनों मंडल की सभी यात्री ट्रेनों में लगाए गए बायो टॉयलेट
- देश के सभी 16 रेल जोन में सबसे पहले पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने किया काम

पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल के सभी 1750 कोचों में बायो टॉयलेट लग चुके हैं। पश्चिम मध्य रेल जोन इस काम को सबसे पहले करने वाला देश का पहला रेल जोन बन गया है।

- प्रियंका दीक्षित, सीपीआरओ, पश्चिम मध्य रेलवे

मध्य प्रदेश के रीवा की लता का नाम गिनीज बुक में दर्ज

नईदुनिया, रीवा

मध्य प्रदेश के रीवा की लता टंडन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक 87 घंटे खाना पकाकर कीर्तिमान बनाया था। परिवार के लोगों ने बताया कि मंगलवार की रात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड लंदन से उन्हें ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। जैसे ही प्रमाण पत्र मिला पूरा परिवार खुशी से झूम उठा।

अमेरिका के रिकी का तोड़ा था रिकॉर्ड : लता टंडन ने पिछले माह 6 से 9 सितंबर तक शहर के एक होटल में रसोई तैयार कर 87 घंटे 45 मिनट तक खाना पकाया। उन्होंने 81घंटे 11 मिनट तक लगातार खाना बनाया और 6 घंटे का विश्राम लिया था। इसके पूर्व अमेरिका मूल के रिकी लैंउकिन ने 68 घंटे 30 मिनट तक 2018 में खाना पकाया था।

इस तरह लता ने 19 घंटे ज्यादा समय तक खाना पकाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लता को खाना पकाने के दौरान ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया था। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस इवेंट की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कराई थी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगवाई थी। अब उनका नाम दर्ज कर लिया गया है।

87 घंटे 45 मिनट खाना पकाकर पिछले माह बनाया था रिकॉर्ड

लता टंडन। फाइल

वैश्विक धरोहर फूलों की घाटी ने कायम किए रिकॉर्ड

संवाद सूत्र, जोशीमठ (चमोली)

विश्व विख्यात फूलों की घाटी गुरुवार को शीतकाल में पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। एक जून को इसे पर्यटकों के लिए खोला गया था। इस साल यहां पर्यटकों की आमद और राजस्व का नया रिकॉर्ड बना। 17 हजार से ज्यादा पर्यटकों ने फूलों की घाटी के दीदार किए, इनसे 27 लाख से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ।

फूलों की घाटी वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन भारती ने बताया कि इस साल फूलों की घाटी में रिकार्ड 17,424 पर्यटक पहुंचे। इनमें 16,904 भारतीय और 520 विदेशी शामिल हैं। यह संख्या अब तक की सर्वाधिक है। पिछला रिकॉर्ड वर्ष 2018 में 14742 पर्यटकों की आमद का था। इसी तरह आय के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना है। इस साल अब तक 27 लाख 825 रुपये की आय हो चुकी है। घाटी में पर्यटकों की खासी आमद से स्थानीय पर्यटन और होटल व्यावसाइयों के भी चेहरों पर रौनक है, इस दौरान उन्होंने उम्मीदों से बढ़कर कारोबार किया। बताते चलें कि वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद कुछ सालों तक यहां पर्यटकों का रुख बहुत कम रहा। आपदा के अगले साल यानि वर्ष 2014 में 484 पर्यटक और 2015 में 181 पर्यटक ही फूलों की घाटी पहुंचे थे।

जैवविविधता का खजाना : 87.5 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली विश्व धरोहर फूलों की घाटी को जैवविविधता के खजाने के रूप में जाना जाता है। यहां प्राकृतिक रूप से खिलने वाली 500 से अधिक प्रजातियों के फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। साथ ही घाटी में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों, पशु-पक्षियों का संसार भी यहां बसता है। इस खूबसूरत घाटी के दीदार के लिए हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। इन्हीं खूबियों को देख यूनेस्को ने 2005 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।

इस साल घाटी में सबसे अधिक पर्यटक और आय का बना नया रिकॉर्ड

17,424 देशी-विदेशी पर्यटकों ने किया दीदार

520 विदेशी पर्यटक भी पहुंचे, 27 लाख रुपये से ज्यादा की हुई कमाई। फाइल

पूरे सीजन सूना रहा नंदा देवी पार्क

विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसे एक जून को खोला गया था। हैरत देखिए कि इस साल एक भी पर्यटक पार्क के दीदार को नहीं पहुंचा, जबकि बीते तीन सालों में सिर्फ तीन पर्यटक ही यहां पहुंचे हैं। वन क्षेत्राधिकारी धीरेश चंद्र बिष्ट ने बताया कि जोखिमभरे ट्रैकिंग रूट पर सुविधाओं का घोर अभाव और बुग्यालों में कैंपिंग बंद होने से पर्यटकों ने इधर का रुख करना बंद कर दिया है। खास बात यह कि सुरक्षा कारणों के चलते पार्क को आधा-अधूरा ही खोला जाता है। जिससे पर्यटक पार्क की जैवविविधता का दीदार नहीं कर पाते।

एक लाइब्रेरी ऐसी भी...

- बीएचयू के छात्रों के सामूहिक प्रयास ने दिया नया नजरिया
- 'ट्री लाइब्रेरी' से मुफ्त ले जाएं पौधे, मनचाहे स्थान पर रोपें

मुहम्मद रईस, वाराणसी : दुनिया की सबसे प्राचीन व जीवंत नगरी काशी ने हमेशा ही देश-दुनिया को राह दिखाई है। यह शहर बौद्धिक पहल का अगुआ रहा है। ऐसे में इन दिनों असी घाट के नजदीक बीएचयू के कुछ छात्रों ने मिलकर एक छोटी मगर प्रभावी पहल की है, जो न सिर्फ तेजी से लुप्त हो रही शब्द-संस्कृति को पोषित कर रही है, बल्कि युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की अलख भी जगा रही है।

बात असी घाट के नजदीक 'मुफ्त लघु लाइब्रेरी' व 'मुफ्त ट्री लाइब्रेरी' की हो रही है। मंच कला संकाय-बीएचयू के शोध छात्र संदीप मुखर्जी, एमएससी छात्र आकाश बिंद सहित पूर्व छात्र बलजीत सिंह व सुमित ने 'हेल्पिंग वर्ब फाउंडेशन' के माध्यम से स्वयं के खर्च पर यह कारनामा कर दिखाया है। लाइब्रेरी में उपलब्ध किताबों को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। बदले में अपने पास धूल फांक रही किताबें यहां दान भी दे सकते हैं, ताकि वह किसी और के काम आए।

इसके ठीक बगल में छोटी सी 'ट्री लाइब्रेरी' भी है, जहां से मुफ्त पौधे लेकर मनपंसद जगह पर रोप सकते हैं। संदीप मुखर्जी के मुताबिक लाइब्रेरी करीब एक माह पहले शुरू की गई थी। हमारा उद्देश्य लाइब्रेरी के माध्यम से शब्द-संस्कृति को बचाने के साथ ही बेहतरीन किताबें जो अक्सर धूल फांकती रहती हैं, उनका सदुपयोग करना है। लोगों से सराहना मिली तो 'ट्री लाइब्रेरी' का भी विचार आया, जिसे दीपावली के दिन शुरू किया गया।

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लुप्त हो रही शब्द-संस्कृति को बचाने के मकसद से हम सभी ने यह पहल की है। उम्मीद है हमारी तरह अन्य युवा भी अपने-अपने तरीके से पर्यावरण की फिक्र करेंगे।

- संदीप मुखर्जी

पर्यटन

चंबल में है उत्तर गुप्त काल का भव्य शिव मंदिर समूह और संसद के नक्शे वाला चौसठ योगिनी मंदिर, डकैतों के खौफ से बचे रहे मंदिरों पर साल 2000 में पड़ी थी एएसआइ की नजर, देश-दुनिया में हो रही चर्चा

डकैतों के भय ने बीहड़ में सहेजे रखी एक भव्य विरासत, अब दुनिया में चर्चा

अपना देस खुशबू माटी की

शिवप्रताप सिंह जादौन, मुरैना

भारत सरकार अब नए संसद भवन के निर्माण को औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, 2022 का संसद सत्र नए भवन में ही होगा। आइये अब चंबल के बीहड़ों का रुख करें, कहा जाता है कि यहां मौजूद भव्य स्थापत्य को देख ही लुटियन ने वह भवन बनाया, जो भारतीय संसद भवन बना। जिसे डकैतों के खौफ से संरक्षण मिला, वह विरासत देश-दुनिया में पहचान बना रही है। वर्ष 2000 के बाद से भारतीय पुरातत्व विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से मुरैना, मप्र के निकट स्थित यह स्थल लगातार सुर्खियों में है।

चंबल घाटी को डकैतों के आतंक के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन डकैतों के आंतक के पीछे छिपे यहां के गौरवशाली इतिहास को अब देशभर में पहचान मिल रही है। जिन डकैतों के कारण चंबल कुख्यात रही, उन्हीं डकैतों के भय ने इस शानदार विरासत को सहेज कर रखा। यह वह विरासत है, जो किसी को भी हैरत में डाल सकती है। विस्तृत शिवमंदिर श्रृंखला और चौसठ योगिनी मंदिर के रूप में ऐसी गोलाकार संरचना, जिसे भारतीय संसद भवन की प्रेरणा बताया जाता है, यहां मौजूद है। बिना किसी प्रचार प्रसार के ही इन स्मारकों की ख्याति देश भर में फैल चुकी है।

लंबे दायरे में फैले मुरैना के बटेश्वरा शिव मंदिर समूह ने इस बात को स्थापित किया है कि संसद भवन से कई सदी पहले ही इसी तरह की हू-ब-हू संरचना चंबल घाटी के जंगलों में बनाई जा चुकी थी। खुद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग अपने दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख कर चुका है कि मितावली मंदिर, बटेश्वरा और नरेश्वर शिवमंदिर समूह जैसी संरचनाएं और कहीं नहीं मिलतीं।

साल 2000 तक मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर पथरीली चट्टानों और कटीली झाड़ियों के बीच छिपी यह संरचनाएं किसी की नजर में नहीं आई थीं। चंबल के डकैतों के डर से इन जंगलों में कभी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं पहुंचा। यही वजह रही कि पानी के वेग और भूचालों को सहते हुए भी यह संरचनाएं मूर्ति तस्करों और खनन माफिया से बची रहीं।

मुहम्मद को सपने में दिखे थे ये मंदिर... : साल 2000 में स्थानीय पुरातत्व विभाग की जानकारी में आया कि इस तरह की कुछ संरचनाएं यहां हैं। लेकिन इनकी कस्मत तब बदली जब साल 2005 में सीनियर ऑर्कलॉजिस्ट केके मुहम्मद की पदस्थापना सेंट्रल जोन में हुई। केके मुहम्मद अब रिटायर हो चुके हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने शिवमंदिर समूहों को यथारूप सपने में देखा था और अगले दिन अपने साथियों से इसकी चर्चा की तो पता चला कि उनका ख्वाब झूठा नहीं था। उन्हें जब शिवमंदिर समूह के खंडहरों के बीच ले जाया गया तो सब हैरान थे।

मुरैना के मितावली में स्थित प्राचीन चौसठ योगिनी मंदिर। नई दुनिया

मुरैना के निकट स्थित बटेश्वरा शिव मंदिर समूह। नई दुनिया

सैलानियों को लुभा रहा अद्भुत स्थापत्य

एक शिलालेख के अनुसार मितावली इकत्तोसर मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में कच्छपघात राजा देव पाल ने करवाया था। 170 फीट की त्रिज्या वाले इस मंदिर का नक्शा भारत के संसद भवन जैसा ही है। जिसमें शिवलिंग वाले 64 कमरे हैं और बीचों बीच शिवलिंग वाला मंडप है। इसे चौसठ योगिनी मंदिर भी कहा जाता है। इन मंदिरों का अद्भुत स्थापत्य देश-दुनिया के सैलानियों को यहां तक खींच लाता है।

दैनिक जागरण
सबरंग
साहित्य के...
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 31 अक्टूबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

पुरानी दिल्ली अलग ही मिजाज में नजर आती थी

दिल्ली मेरी यादें

कवि उपेंद्र कुमार यूं तो सिविल सेवा में रहे, लेकिन दिल्ली शहर ने उन्हें साहित्यकार भी बनाया। तभी साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के लिए नेशनल प्रेस इंडिया, साहित्यिक कृति सम्मान, साहित्यकार जैसे सम्मान भी मिले। कवि उपेंद्र ने दिल्ली शहर को जैसे जिया वैसे ही उस पर रचनाएं भी की।

हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे अनेकानेक मिथकों की थाती, अपने खजाने में संजोए इतराती दिल्ली...वहीं एक दूसरी कविता की पंक्तियां, इतनी बलशाली है दिल्ली कि पराजय के बाद भी
टूटी दीवारों पर रहते हैं सभी सदा वहीं...

मैंने दिल्ली को इसी रूप में देखा है। एक संबल-सशक्त शहर। मुझे इस शहर में आने के बाद कुछ ज्यादा मशक्कत तो नहीं करनी पड़ी हां, जिदंगी ने अद्भुत...अतुलनीय अनुभव जरूर दिए। दिल्ली मेरे लिए हमेशा दोस्त सी रही। जब पहली बार दिल्ली आया था एक बड़ा रोचक सा प्रसंग हुआ। मैंने कहीं जाने के लिए ऑटो किया। रास्ता पता था तो ऑटो वाले को बताने लगा दाएं चलो, बाएं मोड़ो। थोड़ी देर बाद वो तंग आकर बोला साहब, आप पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा हां, भई, तो ऑटो ड्राइवर बोला फिर दाएं-बाएं क्यों बोल रहे हैं लेफ्ट-राइट बोलिए। यह मेरे लिए हास्यास्पद तो था कि एक कल्चरल शौक भी था, क्योंकि मैं पटना से आया था।

यूं तो कभी प्रदर्शनी तो कभी क्रिकेट मैच देखने दिल्ली आना-जाना लगा रहता था लेकिन वर्ष 1973 में सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के बाद यहीं ट्रांसफर हुआ, फिर तब से यहीं का हो गया हूं। इस शहर में उन दिनों मुझे दो तरह की दिल्ली नजर आती थी। एक बंटवारे के बाद वाली दिल्ली और एक जो लोग यहां पहले से रहते थे उन लोगों की दिल्ली। उन दिनो पुरानी दिल्ली अलग ही मिजाज में नजर आती थी। वहां ऐसी भीड़ या धमाचौकड़ी सी नहीं थी। आप कुछ भी पसंद की चीज खाने या लेने जाएं तो आराम से मिल जाती थी। नई दिल्ली और पुरानी वैसे आज भी अलग दिखती है लेकिन तब और ज्यादा अलग नजर आती थी। मैं दफ्तर के बाद अक्सर विजय चौक पर घंटो बैठा रहता था। उस जगह के सौंदर्य को देखकर मेरे मन में बहुत सी उमंग उठती थीं। कह सकते हैं मेरे मन में रचनात्मक बादलों का उमड़ना इसी सौंदर्य के बीच बैठकर हुआ। इसी दौरान मैंने दिल्ली पर कई कविताएं भी लिखीं और मन साहित्यिक होने लगा। मंडी हाउस, साहित्य अकादमी, जगह-जगह साहित्यिक ठियों पर जाने लगा।

हालांकि बीच-बीच में कई बार बाहर भी ट्रांसफर हुआ लेकिन उसके बाद जब भी लौटकर दिल्ली आया तो ये शहर मुझे पहले से और नया व खूबसूरत लगा। दफ्तर से इतर समय निकाल मैं अपने साहित्यिक मन को कविता रूपी शब्द देने लगा था। मेरे सबसे पहले मित्र डॉ लक्ष्मीनारायण लाल बने। एक दिन वे खाने के लिए घर पर आए तो किताबों के बीच रखी मेरी डायरी देखी। और मुझे किताब लिखने को कहा। मैंने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए किताब लिख ली। मैं जब भी कोई किताब पढ़ता था तो उसमें देखता था कि बड़े साहित्यकारों द्वारा उस लेखक और किताब के बारे में लिखा होता था। ऐसे में मेरा भी मन हुआ तो मैं पहली बार बगैर किसी का सहारा लिए अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र और अमृता प्रीतम के घर पहुंच गया। अब तीनों के लिए ही मैं अनजान। उसी नजर से तीनों ने मुझे डील भी किया। मेरी रचना रख ली और मैं चला आया। मुझे उस मुलाकात के बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई कुछ लिखेगा लेकिन कुछ दिन बाद ही सबसे पहले अज्ञेय ने दो पेज लिखकर भेजे। और मेरी दुधमुही कविताओं की सराहना की। इसी क्रम में भवानी और अमृता ने भी लिखकर भेजा। मेरे इस पहले कविता संग्रह का नाम था 'बड़ी जड़ों का नवजात जंगल'। इसमें दिल्ली की भी कई कविताएं थीं।

मुझे उन दिनों साहित्यकारों की एक बात बहुत अच्छी लगा करती थी। कहीं भी साहित्यिक गोष्ठी होती थीं तो उसमें सभी निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, विश्वनाथ त्रिपाठी, गंगा प्रसाद विमल, केदारनाथ और भी बहुत से साहित्यकार आते थे। इन सभी के सामने आप कुछ भी सुनाओ सभी बड़ी शिद्दत से सुनते थे। उसके बाद उसमें कुछ बदलाव-सुधार के साथ सराहना भी करते थे। अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा। साहित्य अकादमी, शास्त्री भवन पुस्तकालय, भारतीय विद्या भवन इन जगहों पर गोष्ठियों में जाते-जाते राजेंद्र यादव से अच्छे संबंध हो गए थे। इसी बीच 1988 के आसपास मैंने भी बरगद नाम से संस्था शुरू कर दी थी। इसमें हर माह अनौपचारिक तरीके से गोष्ठी होती थी। हालांकि मेरे ट्रांसफर की वजह से यह लंबे समय तक नहीं चली लेकिन उस समय के सभी बड़े साहित्यकार उसमें शिरकत करते थे। किसी को यह नहीं लगता था कि हमे नहीं बुलाया, सभी यह सोचकर चले आते थे कि शायद बुलाना भूल गया होगा। अब तो लोगों को निमंत्रण भेजिए तो भी आने का समय नहीं होता। राजेंद्र यादव जी के जन्मदिन पर भी मैं लंबे समय तक आयोजन कराता था। उसमें तो सारे साहित्यकारों का मजमा जुटता था। साहित्य का एक अनोखा माहौल होता था। अब भले दिल्ली शहर बहुत बदल गया है, विकास की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा है लेकिन इस शहर का अतीत हमेशा इसके वर्तमान पर सौंदर्य बोध कराता रहेगा।

-मनु त्यागी से बातचीत पर आधारित

हिंदी के वरिष्ठ आलोचक मैनेजर पांडेय के साहित्यिक सफर में काफी बदलाव आए। तुलसीदास और रामचरितमानस को पढ़ते-पढ़ते उनके आलोचक बनने तक की यात्रा में शिक्षकों व मित्रों का मार्गदर्शन व प्रोत्साहन उन्हें मिलता रहा है। मैनेजर पांडेय ने समय की मांग के साथ साहित्य को अपनाया है। लेकिन आज के युवा लेखक और आज हो रहे लेखन में असंतोष जताते हैं। खुद को दिल्ली शहर के बेहद करीब तो पाते हैं, पर व्यथित हैं अस्त-व्यस्त सी साहित्यिक राजधानी को देखकर। **रितु राणा** ने **मैनेजर पांडेय** के साहित्यिक सफर व उनके अनुभवों पर विस्तार से बातचीत की प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

दिल्ली तो साहित्य की राजधानी है

सम्मान
- हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा शलाका सम्मान
- राष्ट्रीय दिनकर सम्मान
- दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का सुब्रह्मण्यम भारती सम्मान
- रामचंद्र शुक्ल शोध संस्थान द्वारा वाराणसी का गोकुल चंद्र शुक्ल पुरस्कार

बातचीत

● पहली बार साहित्य में रुचि कैसे जागी, किन-किन लोगों से प्रेरित हुए?

-मैं बिहार गोपालगंज जिले के लोहटी गांव से हूं। वहां सप्ताह में दो-तीन बार रामचरितमानस का गायन होता था, वह मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं। उसी गायन से मेरी दिलचस्पी साहित्य की ओर बढ़ी। माध्यमिक शिक्षा के दौरान शेखवाजिद और रघुनाथ गुप्ता मेरे इन दोनों शिक्षकों ने भी मेरी साहित्य में दिलचस्पी जगाई। इन दोनों शिक्षकों ने मेरे नाम से मुझसे चंदा ले लिया और मेरे पास पाञ्चजन्य पत्रिका आने लगी। उसे पढ़कर मेरे मन में रामचरितमानस के साहित्य और पत्रिका के साहित्य को लेकर एक टकराव आने लगा। यह दोनों साहित्य अलग-अलग थे, मुझे लगा कि समय के साथ मुझे पत्रिका के साहित्य की ओर जाना चाहिए। हाई स्कूल में मेरे शिक्षक लक्ष्मण पाठक प्रदीप जो कि हिंदी और भोजपुरी में कविता लिखते थे। उनसे मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। आसपास कवि सम्मेलनों में भी जाने लगा। इसके बाद 1959-69 तक बनारस में इंटरमिडिएट से लेकर पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। वहां का साहित्यिक वातावरण अलग था तो अब मुझे कविताएं निरर्थक लगने लगीं। स्थानीय तौर पर कविता का महत्व था लेकिन बनारस में नहीं। यहां मेरे एक अध्यापक थे शिव प्रसाद सिंह, वह कहानी और उपन्यास लिखते थे, मैं उन्हें पढ़ता जरूर था, बगैर रुचि के। आलोचना के क्षेत्र में मेरी दिलचस्पी मेरे दूसरे अध्यापक शीतकंथ मिश्र द्वारा उत्पन्न हुई, वह आलोचना लिखा करते थे। जब मैं बनारस में था उस वक्त तक आचार्य राम चंद्र शुक्ल का स्वर्गवास हो चुका था लेकिन वहां की फिजा में उनका नाम मौजूद था।

●...और लिखना कब-कैसे शुरू हो गया?

-बनारस से एक प्रज्ञा पत्रिका निकलती थी उसमें मेरा पहला आलोचनात्मक लेख 'प्रतिभा का स्वरूप' नाम से मेरा पहला लेख छपा था जो मेरी पीएचडी का भी विषय रहा। 1969-71 तक दो वर्ष मैं बरेली कॉलेज में अध्यापक पद पर रहा। वहां साहित्यकार आलोचक मधुरेश मेरे मित्र बने जो अब तक मेरे साथ हैं। 1971 में जोधपुर से ही मेरी असल साहित्यिक यात्रा की शुरुआत हुई। 1980 में मैंने पहली पुस्तक शब्द और कर्म लिखी जिसे बीकानेर के प्रकाशक धरती प्रकाश ने छापा। 1981 में मेरी दूसरी किताब आई 'साहित्य और इतिहास दृष्टि' बस फिर मैं लिखता चला गया।

● दिल्ली से नाता कब जुड़ा यहां किस तरह एक नए साहित्यिक सफर की शुरुआत हुई?

-वैसे तो बनारस में पढ़ाई के दौरान ही जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय आने का मन बना लिया था लेकिन आ नहीं सका। लेकिन इस शहर ने मुझे 1977 में बतौर प्रोफेसर जेएनयू में हिंदी पढ़ाने का अवसर दिया। जब से जेएनयू आया तभी से दिल्ली मेरे मन में बस गई और मैं दिल्ली में बस गया। 1977 से 2006 तक मैं जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रोफेसर रहा। जेएनयू में आकर साहित्यिक माहौल के और करीब हो गया जिससे आलोचनात्मक लेखन का सफर और आगे बढ़ता गया।

● जेएनयू में नामवर सिंह भी थे तो उस दौर में खुद को कैसे स्थापित किया?

-इसमें कोई शक नहीं नामवर सिंह एक बड़ा नाम था, खासकर जेएनयू में उनके साथ अपना नाम बनाना एक चुनौती थी लेकिन नामुमकिन नहीं था। लोग अपने लिखने, पढ़ने और बोलने के आधार पर स्थापित और खारिज होते हैं। क्योंकि साहित्य में अच्छा बोलने और लिखने वालों का ही नाम होता है, मेरा बचपन से ही साहित्य से नाता रहा तो जेएनयू में स्थापित होने में दिक्कत नहीं आई मैंने अपने लिखने, पढ़ने और बोलने के आधार पर ख्याति पाई। जेएनयू में विचार-विमर्श का वातावरण होता था जो अब भी है। वहां की हवा में एक अलग ही बात है। हमारे समय में वहां के शिक्षक और छात्र-छात्राएं आपस में बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद-विवाद करते थे उनके बीच भेद होता था और मतभेद भी होता था।

● दिल्ली विश्वविद्यालय के लेखकों का भी ज्यादा दबदबा रहा था?

-डॉ नगेंद्र के समय तक दिल्ली विश्वविद्यालय के लेखकों का खूब दबदबा था। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू दोनों में से किसी का भी दबदबा लेखन के क्षेत्र में नहीं है। अब लेखन में पहले जैसी बात भी नहीं रही है।

● अपने समकालीन लेखकों के बारे में बताइए?

-दिल्ली में समकालीन लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी और नित्यानंद तिवारी दोनों ही मेरे अच्छे मित्र रहे और यह दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे। इनसे मेरी घनिष्ठ मित्रता है और दोनों आधुनिक काल के साथ भक्तिकाल पर भी लिखते हैं। नित्यानंद दिल्ली के राजधानी कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष भी रहे। वहीं, वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी किरोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में भी प्रोफेसर रहे हैं। वह बेझिझक और निसंकोच लिखते हैं। दोनों का व्यक्तित्व और लेखन विशिष्ट है।

● उस दौर में साहित्य की कौन सी पत्रिकाएं निकलती थीं, क्या प्रक्रिया होती थी?

-1950 से लेकर 2019 तक हमारा समय रहा। इस दौरान निकलने वाली पचासों हिंदी पत्रिकाएं रहीं। पहले कल्पना और माध्यम, प्रज्ञा निकलती थी। दिल्ली से दिनमान साप्ताहिक और कथादेश, आलोचना, कृति, आजकल, इंद्रप्रस्थ, भारती, पांचजन्य, धर्मयुग आदि निकलती हैं। अब मैं पत्रिकाएं ज्यादा नहीं पढ़ता किताबों में ज्यादा मन लगता है। पहले पत्रिकाओं के लिए लेखक तो खूब थे लेकिन प्रकाशक मिलने मुश्किल हो जाते थे। पत्रिकाओं का दौर बहुत संघर्ष भरा रहा है। कुछ पत्रिकाएं प्रकाशक न मिलने के कारण बंद भी हो गईं। पहले की पत्रिकाएं सामाजिक विषयों पर केंद्रित होती थी। उनमें गहन विचार और दिशा हुआ करती थी।

● साहित्यिक अड्डे और साहित्यिक गतिविधियों पर आपकी क्या राय है?

-1975 से 1995 तक दिल्ली में गोष्ठी व सम्मेलनों में मैं लगातार जाया करता था। बड़े शौक से सभी साहित्यिक गतिविधियों में शामिल होता था। उस समय में कनॉट प्लेस स्थित कॉफी हाउस सभी साहित्यकारों का अड्डा हुआ करता था। लगभग सभी साहित्यकार वहां आते थे। हिंदी के बड़े कवि नागार्जुन, जेएनयू में कवि केदारनाथ, आलोचक नामवर, विष्णु प्रभाकर, हंसराज रहबर, विष्णु चंद्र शर्मा यह सभी कॉफी हाउस में आया करते थे। इसले अलावा मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, विवि के अलग-अलग कॉलेज, साहित्य अकादमी और हिंदी अकादमी आदि जगहों पर होने वाली गोष्ठियों में जाया करता था। गोष्ठी में भाग लेकर चिंता, चेतना व समझ का विकास होता था। एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी। अब वैसे गोष्ठियां व सम्मेलन नहीं होते और होते भी हैं तो अब मैं स्वास्थ्य खराब रहने के चलते उनमें शामिल नहीं हो पाता।

● किसी बड़े साहित्यकार के साथ संस्मरण, उनके साथ उठना बैठना आदि कुछ रोचक किस्से रहे हों?

-जनकवि नागार्जुन अपने घर से दूर महीनों मेरे घर पर ही रहा करते थे। उनका घर यमुनापार स्थित करावल नगर के सदतपुर क्षेत्र में था, लेकिन वह वहां ज्यादा रहना पसंद नहीं करते थे जब उनकी पत्नी दरभंगा से आती थीं, बस तभी अपने घर जाते थे। जेएनयू में उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि वह हमेशा वहां के छात्र-छात्राओं से घिरे रहते थे। उनके साथ काफी समय बिताया है। इसके अलावा कहानी नाटककार रमेश उपाध्याय व आलोचक व कवि विष्णु चंद्र शर्मा मेरे अच्छे मित्र रहे हैं और आज भी हैं। अब तो ज्यादातर मैं सभी से घर पर ही मिलता हूं।

● साहित्यिक दृष्टि से दिल्ली शहर को कितना समृद्ध पाते हैं? इसे कैसे बनते-संवरते देखा?

-दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की भी राजधानी है। पूरे देश में दिल्ली हिंदी साहित्य का एक बड़ा केंद्र थी और आज भी है। बड़े-बड़े लेखकों का सपना होता था कि वह दिल्ली में आकर लेखन करें। अधिकांश प्रकाशक यहां हैं जिस कारण लेखक दिल्ली में ही आना चाहते हैं। यहां पुरस्कार है, सम्मान है, उपाधि है। एक लेखक को जो चाहिए वह सब कुछ दिल्ली में है यहां आकर लेखकों को एक पहचान मिलती है इसलिए लेखक दिल्ली में आकर रहना पसंद करते थे। अधिकांश और अन्य भाषाओं के लेखक भी यहां आकर रहते हैं। दिल्ली ने बड़े-बड़े साहित्यकारों को नाम दिया और पहचान दी।

● युवा साहित्यकारों का लेखन किस दिशा में जा रहा है?

-आज के युवा व्यक्तिगत तौर पर लिखते हैं उनका लेखन व्यक्तिगत है सामाजिक नहीं, साहित्य का काम है अपने समाज को समझना जो यह समझ गया मैं उसे साहित्यकार मानता हूं। मैं युवा लेखकों को पढ़ता हूं, उनके व पुराने लेखकों के लेखन में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के लेखक एक दिशा के साथ लिखते थे लेकिन अब साहित्य में कोई दिशा और आंदोलन नहीं है। पूरे समाज पर उपभोक्तावाद का असर है जिससे हिंदी का नाश हो रहा है।

● आलोचक के नजरिए से आप आज के लेखन को कैसे देखते हैं अब कैसा लेखन हो रहा है?

-मैं आलोचना लिखता हूं, यह कविता, कहानी, उपन्यास आदि सभी विधाओं से अलग लेखन है। यह साहित्य की व्याख्या व समीक्षा करने की विधा है। लेखकों को आलोचना से सीखने को मिलता है वहीं, छात्रों को हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य की जानकारी मिलती है। अब हिंदी में कोई साहित्यिक आंदोलन नहीं है जैसे पहले हो चुके हैं छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि। नए व युवा साहित्यकारों की व्यक्तिगत सोच है। आज के लेखन में बहुलता है। अनेक रूप, दृष्टि व प्रकार हैं। साहित्य में बाजारवाद आ गया है। लेखक वही लिख रहा है जो बिकाऊ है। मैं हाल ही में एक कॉलेज में भाषण देने गया तो चार छात्र मेरे पास आकर पूछने लगे कि आजकल हिंदी में अंग्रेजी घुस रही है पांच शब्द हिंदी के तो चार शब्द अंग्रेजी के हैं। मैंने कहा मुझे यह प्रवृति पसंद नहीं है। पहले के जो लेखक थे वह आज के लेखकों से अच्छी अंग्रेजी जानते थे लेकिन लेखन में उन्होंने हिंदी का ही प्रयोग किया, आज का लेखन वैसा नहीं रहा।

● हाल में कोई किताब आ रही है?

-हां, मेरी दो किताबें आने वाली हैं, एक 'बतकही' जो कि साक्षात्कार पर आधारित है और दूसरी आलोचनात्मक लेखन का संग्रह है 'शब्द और साधना'

● दिल्ली कैसी है और आपके नजरिए से इसे कैसा होना चाहिए?

– देश की राजधानी दिल्ली अन्याय, अत्याचार व स्त्रियों के साथ ज्यादती का शहर है। यह शहर बिगड़ा हुआ है और पतित है। काफी हद तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार में सुधार हुए हैं। उनके द्वारा कई अच्छे व जनहित के फैसले लिए गए हैं जैसे बिजली, पानी मुफ्त और शिक्षा व्यवस्था में भी काफी सुधार आया है। केंद्र और निगम में भाजपा सरकार है और पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है, इसलिए कानून व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में ही है। उन्हें अपराध पर रोक लगानी चाहिए। लोगों का कहना है कि बिहार व उत्तर-प्रदेश से आए ऑटो चालकों, मजदूरों के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नौकरियों के अभाव में अपराध बढ़ रहे हैं। मेरी दिल्ली शहर को लेकर जैसी कल्पना थी वैसी दिल्ली नहीं है।

'खाकी फाइल्स' खोलेगी बहुत सारे अपराधों की जांच के राज

बातचीत

खाकी, जिसे हमने हमेशा कठोर छवि में ही देखा। लेकिन ऐसे खाकीनुमा दिल के भीतर भी लेखन का हुनर छिपा होता है। हम हमेशा जो जीते हैं, देखते हैं सोचते हैं, पाते हैं, महसूस करते हैं उसे ही तो कलम शब्दों में सी देती है और एक किताब का आकार दे देती है। कुछ ऐसा ही पूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार की किताब भी बयां करती है। देश के धुरंधर इन्वेस्टिगेटर माने जाने वाले नीरज कुमार की बुधवार को ही 'खाकी फाइल्स' नाम से पुस्तक आई है। जो दिल्ली की कई बड़ी अपराधिक घटनाओं की परतों को खोलते हुए शब्दबद्ध करती है। **मनु त्यागी** ने **नीरज कुमार** से विस्तार से बातचीत की प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

नई दिल्ली: कांस्टीट्यूशन क्लब में दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त नीरज कुमार की पुस्तक खाकी फाइल्स का लोकार्पण करते जस्टिस मदन लोकर (दाएं से दूसरे) एडवोकेट पिंकी आनंद (दाएं से पहली) यशोवर्धन झा आजाद (बाएं से पहले)

● जब अपराध की गुत्थियां सुलझाने में उलझे रहते थे, क्या तभी तय कर लिया था कि इन तहकीकातों को किताब का भी रूप देंगे?

-नहीं, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लेखन भी करूंगा। यह तो बस एक बार मैं एस हुसैन जैदी जो बहुत बड़े लेखक रहे हैं उनकी किताब के विमोचन में गया था। वहां मैंने उनसे किताब से संबंधित कई सवाल किए, जिनके जवाब बमुश्किल ही मिल सके। बाद में मुझे भी लगा कि कुछ ज्यादा सवाल कर लिए। अगले दिन उनका फोन आया। मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपने जो आपराधिक मामलों की इन्वेस्टिगेशन की है उसे लिखना चाहिए। फिर प्रकाशक से मिलवाया। उन्होंने मुझे लिखने के लिए समय सीमा में बांध दिया। और फिर मैं तहकीकात वाले अंदाज में ही सभी बड़े मामलों को कलमबद्ध करने बैठ गया।

● दिल्ली की कौन सी बड़ी आपराधिक घटनाओं पर लिखा है?

-दिल्ली में पुलिस आयुक्त रहते मेरे सामने कई घटनाएं हुईं उन्हीं में से एक वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड भी था। उस दौरान मुझ पर इस मामले में ठीक से जांच न करने के आरोप भी लगे थे। मैंने इस केस के हर पहलू को किस तरह जांच हुई, उस रात क्या हुआ, पीड़िता की पूरी स्थिति। कहां-कैसे-क्यों उलझनें आईं और मामले की तह तक पहुंचा गया। वो सारे सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। इसके अलावा संसद हमले की जांच, इंडिया गेट टेरर अटैक, लॉट्री फ्रॉड्स जैसे मामलों की बारीकी को बयां किया गया है।

● मतलब इन मामलों को किस तरह से लिखा है कि पाठक क्या जान सकेगा?

-वर्ष 2001 में संसद पर जब हमला हुआ था उस वक्त आतंकियों को मार गिराने में पूरे ऑपरेशन के दौरन दिल्ली पुलिस ने भी अन्य सैन्य बलों के साथ अहम भूमिका निभाई थी। जिस वक्त पूरा ऑपरेशन चल रहा था। सांसद, नेतागण किस तरह डरे सहमे हुए थे। उन्हें किस तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा था। सभी सैन्य बल किस तरह जूझ रहे थे, उन दृश्यों को शब्द दिए हैं। कई बार पुलिस के लिए आम आदमी भी किस तरह से मददगार साबित होता है उसी का उदाहरण है इंडिया गेट पर होने वाला आतंकी हमला। पुलिस को सूचना तो मिल गई थी कि इंडिया गेट पर हमला होने वाला है लेकिन हम उससे जुड़ी कोड भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, जिसे एक आम आदमी ने ही सुलझा दिया और पुलिस इंडिया गेट पर आतंकी हमला होने से बचा सकी। यह अनुभव किताब में लिखना इसलिए जरूरी था कि एक आम आदमी की सजगता भी पुलिस के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है। बशर्ते हम चौकन्ने रहें, पुलिस पर भरोसा करें। एक और बात बहुत कम जानी है। ये 1980-1990 के बीच की बात है मैं तब डीसीपी क्राइम था। उन दिनों दिल्ली में लॉट्री फ्रॉड बहुत होता था लोग आसानी से उसके जाल में फंस जाते थे। तब हमने इस मामले की तहकीकात की थी और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच के आधार पर ही लॉट्री फ्रॉड पर पूरी तरह रोक लगाई थी।

● अब बात कुछ किताब से अलग करते हैं दिल्ली में वर्तमान में आपराधिक स्थिति पर क्या कहेंगे?

-दिल्ली में एक बड़ी समस्या यहां की संस्कृति है, जिससे आज भी लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। यदि सड़क पर कोई लड़की जा रही है तो उसे अजीब निगाहों से देखा जाता है। चाहे वह किसी उम्र वर्ग की हो, जबकि मैंने दक्षिणी राज्यों में, पूर्वोत्तर में देखा है वहां महिलाओं को लेकर ऐसा माहौल नहीं है। लोगों को सोच बदलनी होगी। साथ ही बेरोजगारी और अशिक्षित होना भी अपराध का एक बड़ा कारण है। तिहाड़ जेल गवाह है कि आज भी बगैर पढ़े लिखे लोग किस तरह अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने अपने समय में तिहाड़ जेल में ऐसे कैदियों के लिए पढ़ो-पढ़ाओ अभियान भी चलाया था।

● दिल्ली की भौगोलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति पर आप क्या कहेंगे?

-1970 में मैं सेंट स्टिफन कॉलेज में पढ़ाई करने आया था। 1976 में इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हुआ और 1978 में दिल्ली में पोस्टिंग मिली। उस वक्त इस शहर में शांति थी। इतनी गाड़ियां नहीं थीं न ही प्रदूषण था। इस शहर का विकास तो हुआ लेकिन सुचारु रूप से नहीं, जिसका फर्क यहां की सामाजिक स्थिति पर भी नजर आता है।

● आप खानपान के शौकीन हैं तो फूड इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं?

-आपने मन खुश कर दिया फूड इन्वेस्टिगेशन नाम देकर। सचमुच मुझे दिल्ली में सभी जगह का खाना अच्छा लगता है। और सबसे खास बात यह है कि यहां हर जगह हर तरह का खाना मिलता है। सब की अलग विशेषता भी है। मैं अपने जो भी जानने वाले होते हैं, या कहीं भी कोई मिलता है तो उनसे खाने की नई जगहों के बारे में पूछता रहता हूं और वहां परिवार के साथ खाने भी जरूर जाता हूं।

ये बुर्केवालियां

कह कर रहूंगा

प्रेम जनमेजय
वरिष्ठ व्यंग्यकार

दीवाली के अगले दिन की जहरीली सुबह। तमाम चेतावानियों के बावजूद मैं घर से निकला। सब्जी-दूध खत्म हो गया था। दीवाली की बची हुई मिठाई देखकर मन में उबकाई आ रही थी। इन दिनों महाराष्ट्र में, ये दोस्ती हम न छोड़ेंगे की कसम खाने वाली दो 'समानधर्मा' पार्टियों को, एक दूसरे को देख उबकाई आ रही है। सब्जी-दूध नहीं लाता तो पापी पेट भूख-भूख चिल्लाता। बाहर निकला तो देखा पापी पेट के मारे रिक्शेवाले, कामवालियां, दिहाड़ी मजदूर आदि बिना मास्क के निडर चले जा रहे हैं। पापी पेट, कैसा भी जहर पीने को विवश कर ही देता है। जिस झोपड़ी में खिड़की और दरवाजे ही न हों उसके लिए अंदर-बाहर की जहरीली हवा क्या! गरीबी के जहर से हर तरह का जहर कटता है। तो मैं जहरीली हवा का सामना करते हुए चला जा रहा था। तभी पीठ पीछे किसी के घनघोर खांसने की आवाज आई। यह आम आदमी पार्टी के कंधे पर चढ़, खांसते हुए मुख्यमंत्री की खांसी नहीं थी। ये वो खांसी नहीं थी जिसे खांसने के लिए माईक चाहिए होता है। ये वो खांसी भी नहीं थी जो वोट दिलाती है। वो खांसी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शांत हो गई थी। राजनैतिक खांसी की अचूक दवा है मुख्यमंत्री पद। यह तो आमजन की खांसी थी जो मौत के साथ ही जाती है। ये मेरे प्यारे दोस्त राधेलाल की खांसी थी। राधेलाल मुझे पकड़ने के लिए लगभग भाग-सा रहा था, हांफने के कारण खांस रहा था। इन दिनों कांग्रेस भी राधेलाल- सी हो गई है। हकलाने और हांफने लगी है। सत्ताविहीन खांसी हांफती और हकलाती है।

'यार! प्रेम भाई... यार मेरे दोस्त...मेरे अन्नदाता...आपसे बहुत जरूरी काम आ गया है? मैं तेरा वोटर नहीं, दोस्त हूं। मुझे तदर्थ सम्मान मत दे। आप कहकर मुझसे राजनीतिक भाषा में बात मत कर। हक से मांग जो मांगना है।' यार वो भाभी जी की मुस्लिम सहेली है न...मुझे उनका बुर्का चाहिए। बुर्का ! क्या तुम और भाभी आबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद देखने जा रहे हो जहां औरतों को बिना बुर्के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। चिंता मत कर भाभी को वहां बुर्का मिल जाएगा, लादकर ले जाने की जरूरत नहीं है।

- अरे, तेरी भाभी को नहीं मुझे बुर्का चाहिए। और मुझे बुर्का आबू धाबी की मस्जिद के लिए नहीं दिल्ली की सड़कों के लिए चाहिए। महिलाओं पर तो दिल्ली सरकार बहुत मेहरबान हैं। उनके लिए बसें मुफ्त, मेट्रो होने वाली है, ऑड-इवेन का डर नहीं आदि आदि। अभी तो चुनाव की आहट है, पता नहीं क्या-क्या मुफ्त मिलने वाला है। तू तो जानता है मेरे बेटे की शादी इसी नवंबर में है। चार से ऑड-इवेन शुरू होने जा रहा है। अपने पास ऑडी नहीं है, पर दोनो कारों के नंबर में ऑड है। दस काम होते हैं जो मैं ही कर सकता हूं। बुर्का पहनकर कार चलाउंगा।' प्रदूषण से बचने के लिए लोग मास्क पहन रहे हैं और राधेलाल बुर्का पहनना चाहता है। कभी हमारे समय के महान कथाकार अमृतलाल नागर ने उपन्यास लिखा था-ये कोठेवालियां। अपने समय में हिंदी साहित्य की अछूत विधा का अकिंचन मैं व्यंग्यकार लिख रहा हूं- ये बुर्केवालियां। न...न इन बुर्केवालियों का किसी धर्म से लेना-देना नहीं है। यहां तो सर्वधर्म समभाव वाला नजरिया है। मैं प्रजातंत्र संचालित राजनैतिक सर्वधर्म समभाव की बात कह रहा हूं जहां हर दल में बुर्केवालियां और कोठेवालियां-दोनों हैं। या कहूं कि कोठेवालियां चुनावकाल में बुर्केवालियां हो जाती हैं। ग्राहक न फंसे तो बेहिसाब गालियां देती हैं, पर ग्राहक पट जाएं तो सर्वस्व समर्पण कर देती हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र की बुर्केवालियां आप देख ही चुके, दिल्ली में जल्दी देखेंगे। कांग्रेस ने बुर्कों का अभी ऑर्डर तक नहीं दिया है। भाजपाई केंद्र से मिले बुर्के की फिटिंग जांच रहे हैं और आप वाले बुर्के बांट रहे हैं।

मुझे अक्सर दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुग्राम से दिल्ली आना होता है। यदि मैं सुबह छह बजे आऊं-जाऊं तो 44 किमी का सफर 45 मिनट में सुविधा से कट जाता है, पर यदि पीक टाइम में जाऊं तो सफर दूभर होता है, 'सफर' करना पड़ता है। सफर तनाव युक्त होता है और काटे नहीं कटता है। गुरुग्राम के बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। कुछ दिन के लिए दिल्ली का पीक टाइम खत्म होने वाला है। सत्ताधारी दल से मिलने वाली सुविधाएं जीवन के सफर को सुविधा संपन्न बनाने वाली है। पांच वर्ष के अंधेरे से पूर्व चार दिन की चांदनी आने वाली है। मेरी पत्नी गुलाबी पर्ची ले प्रसन्न है। ईद से पहले बकरे की खूब खिलाई-पिलाई होती है। और जब देश सेवकों की ईद आती है तो कटाई भी खूब होती है। सावधान मेरे देश के गरीब बकरों!

ह्युंडई-एएनआइ सौदा सीसीआइ को मंजूर

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने ह्युंडई मोटर और किया मोटर्स द्वारा एएनआइ टेक्नोलॉजीज और ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की खरीद संबंधी सौदे को मंजूरी दे दी है। एक ट्वीट में सीसीआइ ने कहा कि ह्युंडई मोटर कंपनी और किया मोटर्स ने एएनआइ टेक्नोलॉजीज और ओला इलेक्ट्रिक में शेयरों की खरीद के लिए कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया है। उन परिवर्तनों के साथ उन्हें इस सौदे की इजाजत दी जाती है। सीसीआइ के मुताबिक सौदे से स्पर्धा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत किसी भी मुक्त व्यापार समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर नहीं करेगा। हम घरेलू उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।
— पीयूष गोयल
वाणिज्य व उद्योग मंत्री

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
40,178.12	11,844.10	₹ 38,842	₹ 47,220	₹ 70.90	$ 61.54
▲ 220.03	▲ 57.25	▲ ₹ 87	▲ ₹ 450	▲ ₹ 0.06	

खींचतान ▸ जियो ने टेलीकॉम उद्योग के संगठन पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, कहा – सरकार को गलत जानकारी दे रहा सीओएआइ

रिलायंस जियो और सीओएआइ में छिड़ी जंग

सीओएआइ ने कहा कि सरकार की मदद के बिना उठ नहीं पाएगा सेक्टर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो ने टेलीकॉम उद्योग के संगठन सीओएआइ पर उद्योग की माली हालत के बारे में सरकार के समक्ष गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। सीओएआइ के महानिदेशक राजन मैथ्यू को लिखे पत्र में जियो ने कहा है कि एसोसिएशन ने 'डराने' और 'ब्लैकमेल करने' के अंदाज में सरकार से ऐसे संकट का जिक्र किया गया है, जो असल में है ही नहीं।

जियो ने सीओएआइ की ओर से संचार मंत्री को रात में पत्र भेजने पर कहा है कि ऐसा जियो के साथ परामर्श से बचने के लिए किया गया। पत्र में सीओएआइ ने दो टेलीकॉम कंपनियों (भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की ओर इशारा) के बर्बाद होने का डर जताया गया है। लेकिन न तो ऐसा कुछ होने वाला है और न ही सरकार के डिजिटल इंडिया के एजेंडे पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। जियो ने सीओएआइ पर 'पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर एकतरफा ढंग से काम करने' तथा भरोसे को 'गंभीर चोट पहुंचाने' का आरोप लगाया है। जियो ने कहा है कि लगता है सीओएआइ पूरे टेलीकॉम उद्योग का संगठन नहीं, वरन केवल दो कंपनियों का मुखपत्र है। जबकि ये पुराने ऑपरेटर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्होंने अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया।

प्रतीकात्मक

गौरतलब है कि सरकार को भेजे पत्र में सीओएआइ ने कहा है कि केंद्र की ओर से तत्काल राहत नहीं मिलने की दशा में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अप्रत्याशित संकट का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों कंपनियां टेलीकॉम उद्योग में करीब 63 प्रतिशत ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीओएआइ के मुताबिक अगर सरकार ने इन कंपनियों को उचित तरीके से मदद मुहैया नहीं कराई तो टेलीकॉम उद्योग का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा और उद्योग पर एकाधिकार का खतरा मंडराने लगेगा।

सरकार से संतुलित नजरिये की आशा : एयरटेल

दूसरी ओर भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के निर्णय पर बुधवार को कहा कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मसले पर संतुलित नजरिया रखना ही सभी पक्षों के हित में होगा। टेलीकॉम उद्योग में शुल्क से जुड़े एजीआर जैसे विशाल मसलों और विवादों का उचित तरीके से निपटारा ही अपेक्षित है।

सुनील मित्तल के नेतृत्व वाली एयरटेल का कहना है कि भारत की टेलीकॉम कंपनियों ने इस क्षेत्र को विकसित करने और विश्वस्तरीय सेवा मुहैया कराने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त आया है जब टेलीकॉम सेक्टर गंभीर वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। निवेशकों को संबोधन में एयरटेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कंपनी को आशा है कि सरकार एजीआर पर 'संतुलित दृष्टिकोण' अपनाएगी। एयरटेल

प्रतीकात्मक

ने अपने सितंबर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही परिणामों की खास झलकियां तो पेश कीं। परंतु ये कहते हुए 14 नवंबर तक की पूरी आय नहीं दर्शाई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एजीआर की परिभाषा बदलने के कारण अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल तथा उनके भाई राजन मित्तल ने सोमवार को संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की थी।

भारतीय बाजार से निकलने की तैयारी में वोडाफोन

▸ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी की राह हुई और मुश्किल

नई दिल्ली, आइएएनएस : टेलीकॉम सेक्टर में कर्ज संकट के बीच एक और बुरी खबर सामने आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन भारत से बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी में है। वोडाफोन आइडिया की संयुक्त कंपनी का परिचालन नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी हर महीने लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर गंवा रही है। इसके साथ ही शेयरों में गिरावट के चलते इसका बाजार पूंजीकरण भी लगातार घटता जा रहा है। इन सब कारणों के चलते वोडाफोन अपना भारतीय बिजनेस कभी भी समेट सकती है।

आइएएनएस ने मूल रूप से इस ब्रिटिश कंपनी के प्रवक्ता से इन खबरों का सच जानना चाहा। एजेंसी को वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के कॉरपोरेट कम्यूनिकेशंस प्रमुख बेन पैडोवान से यह सवाल पूछने को कहा गया। हालांकि उन्होंने अभी तक न तो इन खबरों की पुष्टि की है और न खंडन किया है। लेकिन चर्चा है कि कंपनी भारतीय परिचालन किसी भी वक्त बंद करने पर विचार कर रही है।

खबरें यह भी थीं कि वोडाफोन आइडिया ने कर्ज पुनर्गठन के लिए कर्जदाताओं से बातचीत शुरू की है। हालांकि कंपनी ने बुधवार को स्पष्ट तौर पर इसका खंडन करते हुए कहा कि ऐसी खबरें निराधार हैं और कंपनी सभी कर्ज का तय समय पर भुगतान करने की हालत में है।

जानकारों के मुताबिक एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के फैसले ने वोडाफोन की राह और मुश्किल कर दी है। इसकी वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया पर एकाएक हजारों करोड़ रुपये का टैक्स चुकाने का संकट सामने है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह फैसले का अध्ययन कर रही है और जरूरत पड़ी तो कानूनी मदद लेने से भी नहीं हिचकेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजीआर के मामले में अब कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी।

अमेजन, एपल और अलीबाबा को टेक लीडर्स ने बताया खतरा

बेंगलुरु, प्रेट्र : टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लीडर्स कुछ बड़ी कंपनियों को अपने बिजनेस के लिए खतरा मानते हैं। इनको डर है कि यह कंपनियां उनके बिजनेस में खलल डाल सकती हैं। ऐसी ही बड़ी कंपनियों की एक सूची में अमेजन, एपल और अलीबाबा को टेक इंडस्ट्री लीडर्स ने अपने बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है।

केपीएमजी ने एक सर्वे के माध्यम से यह सूची तैयार की है। इस सर्वे में 740 से अधिक ग्लोबल कंपनियों को शामिल किया गया था। डीजेआइ, गूगल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और बाइडू जैसी कंपनियों का नाम शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले तीन वर्षों के दौरान टेक कंपनियों के बिजनेस में सबसे ज्यादा व्यवधान ई-कॉमर्स कंपनियां पैदा करेंगी। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के बिजनेस मॉडल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। केपीएमजी की इस स्टडी में टेक इंडस्ट्री के मिलेनियल और लीडर्स के बीच तकनीकी इनोवेशन को लेकर मतभेद दिखाई दिया। टेक्नोलॉजी बिजनेस लीडर्स की सूची में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पहला स्थान मिला।

खरीफ की कटाई में देरी से रबी की बोआई प्रभावित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ धान समेत अन्य फसलों की कटाई में विलंब, मंडियों में आवक की गति धीमी

▸ अनुकूल मौसम से रबी सीजन वाली फसलों में रिकॉर्ड पैदावार का दावा

मानसून की लंबे समय तक सक्रियता और अधिक बारिश ने रबी सीजन की फसलों की बोआई को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद रबी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का दावा किया जा रहा है। दलहनी और तिलहनी फसलों के साथ गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की कई राज्यों में तो बोआई चालू नहीं हो सकी है। उत्तरी राज्यों में रबी फसलों के पकने और कटाई का समय मार्च से शुरू हो जाता है। देर से हुई बोआई से पैदावार में कमी आने की आशंका बनी रहती है।

कई राज्यों में खेतों में बारिश का पानी भरा हुआ है। खरीफ फसलों की कटाई बाधित होने से रबी सीजन की तैयारी नहीं हो पा रही है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में देश की विभिन्न मंडियों में खरीफ फसलों की आवक की गति बहुत धीमी रही है। खरीफ सीजन की प्रमुख 11 फसलों में से सात फसलों की आवक मात्र 30 फीसद हो सकी है। इनमें भी तिल, धान और कपास की आवक नाम मात्र की रही है। अक्टूबर से शुरू हुए रबी सीजन का बोआई का सरकारी आंकड़ा कृषि मंत्रालय की ओर से अभी जारी नहीं किया जा रहा है। दरअसल, मानसून सीजन की बारिश जून में जहां 33 फीसद कम हुई थी, वहीं सितंबर माह में मानसून की बरसात सामान्य से 52 फीसद अधिक हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई से पहले ही नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो गया है। इसके चलते खरीफ की कटाई और रबी की बोआई दोनों पर असर पड़ रहा है। हालांकि मौसम के इस मिजाज पर गेहूं और जौ के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक डॉक्टर जीपी सिंह का कहना है, 'इससे रबी सीजन की फसलों की उत्पादकता में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मानसून के देर से लौटने से मिट्टी में पर्याप्त नमी का फायदा असिंचित क्षेत्र वाली फसलों को मिलेगा।'

सिंह के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में धान की 80 फीसद कटाई हो चुकी है, और गेहूं की बोआई चालू हो गई है। लेकिन पूर्वी राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में मानसून की जबर्दस्त बारिश हुई है। इसके चलते रबी की पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर स्थित सरसों अनुसंधान संस्थान के निदेशक पीके राय का कहना है कि इस बार असिंचित क्षेत्रों में बोई जाने वाली सरसों की पैदावार में रिकॉर्ड वृद्धि हो सकती है। सरकार का तिलहनी फसलों की खेती पर इस बार बहुत जोर है।

कृषि आयुक्त डॉ. सुरेश मल्होत्रा का कहना है कि लेट मानसून की बारिश से सिर्फ निचले हिस्से वाले क्षेत्रों में ही बोआई में थोड़ी देरी होगी। बाकी हिस्सों में खेती जोर पकड़ेगी। रबी की तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। राज्यों की जरूरत के हिसाब से बीज, फर्टिलाइजर और कीटनाशक पहुंचा दिए गए हैं।

बाजार में पहुंचा खरीफ सीजन का प्याज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्याज और दालों की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। बाजार में खरीफ सीजन का प्याज पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। उपभोक्ता मामले सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि अगले दो-तीन दिनों के भीतर बाजार में नया प्याज पहुंच जाने से कीमतें नीचे आएंगी। बैठक में कृषि मंत्रालय के अफसरों के साथ नैफेड, मदर डेयरी और केंद्रीय भंडार के अफसरों ने हिस्सा लिया।

बैठक में कृषि मंत्रालय के अफसरों ने बताया कि दीपावली की छुट्टियों के चलते उत्पादक मंडियों से प्याज की आपूर्ति प्रभावित हुई है। अगले दो तीनों दिनों में देश की सभी मंडियों में खरीफ सीजन की नई फसल वाला प्याज पहुंच जाएगा, जिससे कीमतों में कमी आने की संभावना है। नैफेड ने मदर डेयरी के सफल खुदरा बिक्री केंद्रों पर प्याज की आपूर्ति बढ़ा दी है। नैफेड ने देश के सभी राज्यों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्याज उठाने की पेशकश की है।

दिल्ली समेत अन्य कई राज्य सरकारों ने अरहर की दाल और साबुत अरहर की मांग की है, जिसे एक और आधा किलोग्राम के पैकेट में आपूर्ति करने को कहा गया है। केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के खुदरा केंद्रों पर पहले से ही रियायती दरों पर दालों की बिक्री की जा रही है।

सोने के रूप में पड़ा कालाधन सफेद बनाने का मौका देगी सरकार

▸ टैक्स का भुगतान कर सोने को बनाया जा सकेगा वैध

▸ टैक्स की दर अभी नहीं हुई है सुनिश्चित

नई दिल्ली, आइएएनएस : सोने के रूप में रखे कालाधन को रिकवर करने के लिए सरकार गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई योजना के तहत अघोषित सोने की जानकारी और उस पर टैक्स देकर इसे वैध सोने में बदला जा सकेगा। इस दौरान जिस खरीद की रसीद उपलब्ध नहीं होगी उस पर पूरा टैक्स चुकाना होगा।

भारतीय इस बहुमूल्य धातु में निवेश को काफी सुरक्षित मानते हैं। कालाधन छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर सोने का उपयोग होता है। हालांकि इस स्कीम के तहत सोने पर लगाई जाने वाली टैक्स दर पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन इस पर 30 परसेंट टैक्स लगाए जाने की बात चल रही है। अगर इस टैक्स दर पर सहमति बन जाती है तब दो परसेंट एजुकेशन सेस के बाद प्रभावी टैक्स दर 33 परसेंट हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस स्कीम के जरिये लाखों करोड़ रुपये का कालाधन रिकवर किया जा सकेगा।

जानकारों का मानना है कि सोने में छिपाया गया कालाधन रिकवर करने के लिए यह स्कीम अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन इसका उचित क्रियान्वयन काफी चुनौतीपूर्ण होगा। टैक्स के तौर पर सोने की मूल कीमत में एक तिहाई कमी होने पर भी लोग सोने के बारे में जानकारी देने से बचेंगे। इसके अलावा संपत्ति की जानकारी जाहिर होने पर टैक्स अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के डर से भी लोग सामने नहीं आएंगे। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, जब टैक्स अधिकारियों ने लोगों से उनकी संपत्ति का स्रोत बताने की बात कही है। नोटबंदी के समय भी टैक्स अधिकारियों द्वारा स्रोत की जानकारी के लिए लोगों को लाखों मोबाइल संदेश भेजे गए थे।

इससे पहले उद्योग जगत ने गोल्ड एमनेस्टी स्कीम के तहत एकमुश्त राशि चुकाकर सोने को वैध करने सलाह दी थी। इनकम टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तरह यह स्कीम भी सीमित अवधि के लिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली बीजेपी सरकार काले धन को लेकर पहले भी प्रयास करती रही है। गौरतलब है कि करेंसी में कालाधन रिकवर करने के लिए सरकार 2017 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) लेकर आई थी। पीएमजीकेवाई की आंशिक सफलता के बाद यह उसी तरह की एक और योजना है।

नीति आयोग का था सुझाव

नीति आयोग ने दो वर्ष पहले इस संबंध में सुझाव दिए थे। आयोग ने अनुमान लगाया था कि भारतीयों के पास करीब 20 हजार टन सोना हो सकता है। लेकिन अगर इसमें बगैर जानकारी के आयात और पैतृक सोने को मिला लिया जाए तो यह मात्रा 25–30 हजार टन तक पहुंच जाएगी। वर्तमान भाव के मुताबिक इस सोने की कीमत 70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

बीएसएनएल को वीआरएस पर पहले वर्ष लगेंगे 7,500 करोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ दो वर्ष बाद से कंपनी को होने लगेगी सालाना करीब इतनी ही बचत

बीएसएनएल और एमटीएनएल के पचास फीसद कर्मचारियों को वीआरएस देने में सरकार पर पहले वर्ष लगभग 7,500 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। जबकि लगभग इतना ही बोझ उसे अगले वर्ष भी उठाना होगा। दो वर्ष में लागू होने वाले वीआरएस पैकेज पर सरकार के कुल 14,800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लेकिन वेतन बिल आधा होने से शीघ्र ही इसकी भी भरपाई हो जाएगी। बीएसएनएल और एमटीएनएल के करीब 80 हजार कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजना के अनुसार इच्छुक कर्मचारियों से एक महीने के भीतर वीआरएस के आवेदन देने को कहा जाएगा।

सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र की घाटे से जूझ रहीं दोनों पीएसयू बीएसएनएल और एमटीएनएल के आपस में विलय के साथ इनके कर्मचारियों की संख्या आधी करने के लिए उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का लाभ देने का फैसला पिछले हफ्ते ही किया था। इसके तहत बीएसएनएल के 1.59 लाख और एमटीएनएल के 22 हजार कर्मचारियों में से 53.5 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों को वीआरएस का ऑफर मिलेगा।

वीआरएस के तहत कर्मचारियों को दो किस्तों में एकमुश्त अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया) सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके दो विकल्प हो सकते हैं। एक के तहत कर्मचारियों को एकमुश्त अनुग्रह राशि के साथ नियमित मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। जबकि दूसरे के तहत 60 वर्ष के पूर्ण सेवा काल के अनुसार शेष बचे महीनों के वेतन का सवा गुना वेतन (हर महीने के वेतन की गणना अंतिम महीने के वेतन के अनुसार की जाएगी) एकमुश्त दिया जाएगा। वीआरएस पैकेज का भुगतान 2019-20 और 2020-21 के दौरान दो किस्तों में होगा। दोनों ही स्थितियों में समय-सीमा की शर्तों के साथ ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

ओसीआइ भी होंगे नेशनल पेंशन सिस्टम का हिस्सा

▸ एनआरआइ के लिए पहले से ही खुले थे इसके दरवाजे

▸ एनपीएस में निवेश पर मिलती है अतिरिक्त टैक्स छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। नई घोषणा के मुताबिक भारत में काम कर रहे भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (ओसीआइ) इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एनआरआइ यानी अनिवासी भारतीय पहले से ही इस स्कीम का हिस्सा थे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने बुधवार को ओएसआइ को एनपीएस में निवेश की इजाजत दे दी है।

पीएफआरडीए दो तरह की पेंशन योजनाएं चलाता है। इसमें से पहली एनपीएस है और दूसरी अटल पेंशन योजना है। इनमें एनपीएस योजना सरकारी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, जबकि अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से गैर-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इस समय इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 3.18 करोड़ से अधिक है।

एनपीएस में निवेश पर 50 हजार तक की अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान है, जिसकी सीमा बढ़कर एक लाख 50 हजार तक हो सकती है। इस वर्ष के बजट में एनपीएस से निकलने या निवेश के परिपक्व होने पर एकमुश्त राशि पर छूट की सीमा 40 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट कर दी गई थी। शेष 40 परसेंट हिस्से पर पहले से टैक्स छूट मिली होती है।

क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम?

यह सरकार की ओर से पेश रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसे जनवरी 2004 में लांच किया गया था। इस योजना के लांच होने के बाद सरकारी नौकरियों में शामिल हुए सभी कर्मचारी इस योजना का हिस्सा हैं। मई 2009 के बाद से कोई भी भारतीय नागरिक स्वैच्छिक रूप से इसमें निवेश कर सकता है। इसके बाद दिसंबर 2011 से कॉरपोरेट जगत को और अक्टूबर 2015 से एनआरआइ को भी इससे जोड़ लिया गया।

ईयू के साथ बढ़ेगी एफटीए की गाड़ी

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

▸ आगामी जनवरी–मार्च में शुरू हो सकती है भारत–यूरोपीय संघ में एफटीए को लेकर वार्ता

▸ वर्ष 2013 से नहीं हो सकी है दोनों पक्षों में एफटीए पर बातचीत

यूरोपीय संघ के सांसदों ने अपनी वर्तमान भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के वक्त मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) का मुद्दा जोर-शोर से उठाया है। पीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत परस्पर आर्थिक हितों को ध्यान में रखने वाले समझौते के प्रति गंभीर है और इस पर जल्द समझौते की उम्मीद रखता है। इस शुक्रवार को जब जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ नई दिल्ली में मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी, तब भी यह मुद्दा उठेगा। जर्मनी ईयू का सबसे मजबूत देश है और वह लगातार भारत के साथ विशेष व्यापार समझौते का समर्थक रहा है।

माना जा रहा है कि भारत व यूरोपीय संघ के बीच एफटीए जैसा ही द्विपक्षीय व्यापार व निवेश समझौता (बीटीआइए) के लिए अगले वर्ष बातचीत नए सिरे से शुरू हो जाएगी।

पूर्व में भारत व यूरोपीय संघ के बीच होने वाली ट्रेड वार्ता से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक पांच मुद्दे हैं जिन पर दोनो पक्षों के बीच भारी असहमति रही है। इसमें भारत की तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कोई भी व्यापार व निवेश समझौता व्यापक असर वाला होना चाहिए जिसमें सेवा उद्योग को भी शामिल किया जा सके। ईयू की सबसे बड़ी मांग यह रही है कि भारत उनके यहां से पूरी तरह से तैयार ऑटोमोबाइल को आयात की छूट दे और इन पर मौजूदा शुल्क दरों को कम करे। ईयू की दूसरी मांग यह है कि यूरोपीय वाइन पर शुल्क की दरें कम की जाएं। यूरोपीय संघ यह भी चाहता है कि भारत में होने वाली सरकारी खरीद में उसकी कंपनियों को हिस्सा लेने का मौका मिले। उक्त अधिकारी के मुताबिक सरकारी खरीद और वाइन पर सीमा शुल्क की दर घटाने की मांग पर भारत अब लचीला रुख अपना सकता है। वैसे भी पिछले छह वर्षों में वैश्विक कारोबार के परिदृश्य में काफी बदलाव आ गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद भारत का निर्यात नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ संयुक्त तौर पर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। वर्ष 2018 में भारत व ईयू के बीच 115 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ था।

भारत–ईयू एफटीए वार्ता : अब तक

भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए के लिए जारी वार्ता वर्ष 2013 में स्थगित कर दी गई थी। उस समय कहा गया था कि कई मुद्दों पर दोनो पक्षों में सहमति नहीं बन पाने की वजह से इसे स्थगित किया जा रहा है। वर्ष 2016 में बताया गया कि नए सिरे से बातचीत फिर शुरू की जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लेकिन उसके बाद ब्रेक्जिट और बाद में भारत में होने वाले चुनावों की वजह से बातचीत शुरू करने को लेकर तिथि निर्धारित नही हो पाई। अब दोनो पक्षों के बीच बातचीत फिर शुरू किए जाने को लेकर सहमति बन गई है। बातचीत के लिए यूरोपीय संघ की तरफ से प्रमुख वार्ताकार (आयुक्त) की नियुक्ति अगले कुछ दिनों के भीतर ही किए जाने की संभावना है।

अहम पड़ाव

एसबीआइ, टीसीएस और आइटीसी जैसे शेयरों ने प्रमुख सूचकांक को दी गति, इक्विटी निवेश के लिए टैक्स ढांचे में सुधार की सूचना से उत्साह

सेंसेक्स फिर 40 हजार के पार

मुंबई, प्रेट्र : ब्लूचिप कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों और इक्विटी निवेशकों के लिए टैक्स ढांचे में बदलाव की उम्मीद में बुधवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स चार महीने बाद एक बार फिर 40 हजार का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर गया। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 220.03 अंक यानी 0.55 परसेंट उछाल के साथ 40,178.12 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 57.25 अंकों का सुधार हुआ। यह 11,844.10 के स्तर पर बंद हुआ।

बुधवार के कारोबार के दौरान सेंसेक्स में एसबीआइ, टीसीएस, आइटीसी, एयरटेल, सन फार्मा, इन्फोसिस और बजाज ऑटो के शेयरों में 3.37 परसेंट की तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर यस बैंक, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 2.41 परसेंट तक की गिरावट देखी गई। जानकारों के मुताबिक सरकार द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) समाप्त करने और लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर दोबारा विचार किए जाने की खबरों के चलते निवेशकों में उत्साह देखा गया। इसके अलावा ब्लूचिप कंपनियों के तिमाही नतीजे भी काफी

प्रतीकात्मक

उत्साहजनक रहे हैं। कॉरपोरेट टैक्स में कमी के चलते इन कंपनियों के मुनाफे में इजाफा हुआ, जिसका बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

दिन के कारोबार में बीएसई में आइटी, टेक, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में 1.47 परसेंट तक की तेजी देखी गई। हालांकि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, रिएल्टी, मेटल और ऑटो सेक्टर में 0.98 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। यूएस-चीन ट्रेड डील में देरी की खबरों के चलते एशिया के अन्य शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। शंघाई, हांगकांग, सियोल और टोक्यो के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं सत्र के शुरुआती कारोबार में यूरोप के बाजारों का रुख मिलाजुला रहा।

सुस्त, मगर सकारात्मक रहा सराफा बाजार

नई दिल्ली, प्रेट्र : मांग में तेजी और रुपये में गिरावट के चलते बुधवार को सोने–चांदी के भाव में इजाफा दर्ज किया गया। दिन के कारोबार में सोना 87 रुपये की बढ़त के साथ 38,842 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ, जबकि पिछले सत्र में यह 38,755 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। इस दौरान चांदी की मांग में तेजी के चलते इसकी कीमत में 450 रुपये का उछाल दर्ज किया गया। दिन के कारोबार में चांदी 47,220 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। ग्लोबल मार्केट में भी सोने–चांदी के भाव में तेजी देखी गई। इस दौरान सोना 1,489 .50 डॉलर और चांदी 17 .82 डॉलर प्रति औंस (28 .35 ग्राम) के भाव पर बिके।

इन शेयरों में रही खास गहमागहमी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया : निदेशक बोर्ड द्वारा तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की अनुमति मिलने के बाद बैंक के शेयरों में 17 परसेंट का इजाफा दर्ज किया गया। बैंक प्रिफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करके 3,353 करोड़ रुपये का फंड जुटाएगा। बीएसई में बैंक के शेयर 15 .32 परसेंट इजाफे के साथ 20 .70 रुपये बंद हुए। वहीं एनएसई में इसके शेयरों की कीमत में 16 .94 परसेंट की तेजी दर्ज की गई।

वोडाफोन आइडिया

कर्ज के संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बेल–आउट पैकेज की खबरों के बीच सेक्टर के शेयरों में तेज उतार–चढ़ाव दर्ज किया गया। इस दौरान बीएसई में वोडाफोन आइडिया के शेयर 1 .04 परसेंट की गिरावट के साथ 3 .81 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। हालांकि इंट्रा–डे के दौरान इनमें 8 .57 परसेंट की तेजी देखी गई। दूसरी ओर भारती एयरटेल के शेयरों में 2 .31 परसेंट की तेजी दर्ज की गई। कंपनी के शेयर 368 .25 रुपये के भाव पर बंद हुए।

इंटरग्लोब एविएशन

लगातार तीन सत्रों में गिरावट के बाद बुधवार को इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में 7 .19 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। कंपनी के शेयरों में यह तेजी इंडिगो द्वारा 300 नए एयरक्राफ्ट के आर्डर दिए जाने की सूचना के बाद आई।

पेट्रोनेट एलएनजी

मजबूत तिमाही नतीजों के चलते पेट्रोनेट एलएनजी के शेयरों में 2 .20 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। दिन के कारोबार में बीएसई में कंपनी के शेयर 2 .20 परसेंट की तेजी के साथ 285 .35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। चालू वित्त वर्ष की जुलाई–सितंबर तिमाही के दौरान इसके मुनाफे में दोगुना इजाफा हुआ है।

कंबल व शॉल उद्योग पर संकट के बादल

जागरण संवाददाता, अमृतसर : माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के तहत काम करने वाले शॉल और कंबल के छोटे औद्योगिक यूनिट भारी वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। मार्केट में मंदी के दौर, कच्चे माल की दरों में गिरावट और बैंकों द्वारा उद्योगपतियों को बैंक लिमिट घटाने वाले नोटिस जारी करने से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उद्योगों की मौजूदा मार्केट स्थिति के मद्देनजर अमृतसर टैक्सटाइल मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के मानद महासचिव राजीव खन्ना ने कहा कि कंबल और शाल उद्योग के साथ जीएसटी में बड़ा भेदभाव हो रहा है। एक हजार रुपये कीमत तक के शॉल और कंबल पर जीएसटी पांच प्रतिशत है, जबकि इसमें एक रुपये की भी वृद्धि होने पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत हो जाती है। दूसरी तरफ पचास हजार रुपये साड़ी पर भी जीएसटी दर पांच प्रतिशत ही है। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें एमएसएमई के तहत शॉल व कंबल उद्योगों को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, वहीं उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा रही हैं।

47 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं अफगानिस्तान के दक्षिणपूर्वी हिस्से में स्थित जाबुल प्रांत में सेना के हवाई हमले में। अफगान सेना के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को किए गए इस हमले में 15 आतंकी घायल भी हुए हैं।

पाक की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग

आजादी मार्च ▶ इमरान सरकार के खिलाफ आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे प्रदर्शनकारी

प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी

इमरान सरकार के खिलाफ देशव्यापी 'आजादी मार्च' का काफिला बुधवार को लाहौर पहुंच गया। इसकी अगुवाई मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। एएफपी

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ देशभर में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 'आजादी मार्च' के रूप में गुरुवार को राजधानी इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुल्क की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग इमरान खान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

आजादी मार्च के आयोजक जमीयत उलमा ए इस्लाम-एफ (जेयूआइ-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है। लाहौर के यतीमखाना चौक पर आजादी मार्च में शामिल लोगों से रहमान ने कहा, 'प्रधानमंत्री के पास समय था और वह इज्जत के साथ इस्तीफा दे सकते थे। अब पाकिस्तान की जनता उन्हें इसका मौका नहीं देगी। आजादी मार्च को पाकिस्तान की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है।'

पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को आजादी मार्च को लेकर चिंता जताई गई थी। इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री कभी इस्तीफा नहीं देंगे। कैबिनेट बैठक के बाद इमरान खान के विशेष सहयोगी फिरदौस आशिक ने कहा था, 'हमारे पास आजादी मार्च का वीडियो है, जिसमें शामिल लोग क्लाशनिकोव राइफल लिए हुए हैं।' सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने जेयूआइ-एफ प्रमुख से फोन पर बात की है। शाहबाज ने उन्हें आजादी मार्च को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया।

पाकिस्तानी मंत्री गंडापुर ने दी परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी

इस्लामाबाद, एएनआइ : कश्मीर के मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर बुरी तरह परास्त हुए पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर सामने आई है। नापाक पड़ोसी देश के एक मंत्री ने भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जो भी देश नई दिल्ली का समर्थन करेंगे पाकिस्तान उन पर भी मिसाइलें दागेगा।

कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा, 'कश्मीर पर भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान युद्ध के लिए मजबूर होगा। इसलिए इस मुद्दे पर जो देश भारत का समर्थन कर रहे हैं पाकिस्तान का नहीं, उन्हें अपने देश का दुश्मन मानते हुए भारत के साथ ही उन पर भी मिसाइल से हमला किया जाएगा।' पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने मंत्री के भड़काऊ भाषण वाले हिस्से का वीडियो ट्वीट किया है। गंडापुर ने यह धमकी ऐसे समय में दी है, जब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान दुनियाभर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है।

पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपने पहले भाषण में ज्यादातर समय कश्मीर राग ही अलापते रहे। उन्होंने भी परमाणु युद्ध की धमकी दी थी और अन्य देशों से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था। लेकिन वो अपनी चाल में नाकाम रहे और हर तरफ से उन्हें मुंह की खानी पड़ी।

पाकिस्तान अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही दुष्प्रचार में जुटा है। जबकि, भारत ने एकदम साफ कर दिया है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। भारत के इस पक्ष को सार्क और अरब देशों के संगठन के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य देशों ने भी समर्थन किया है। इससे पहले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भी भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस बार भारत के साथ पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, बल्कि सीधा परमाणु युद्ध होगा।

नापाक पड़ोसी

- कहा, भारत का समर्थन करने वाले देशों पर भी मिसाइलें दागेगा पाक
- इससे पहले रेल मंत्री शेख रशीद ने भी दी परमाणु युद्ध की धमकी

अली अमीन गंडापुर। फाइल

गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान ने जारी किया सिक्का

पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किया गया विशेष सिक्का। साभार : ट्विटर

इस्लामाबाद, प्रेटू : पाकिस्तान सरकार ने गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को 50 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक पर इस सिक्के की तस्वीर साझा की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, 'गुरु नानक देवजी के 550वें प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान ने विशेष सिक्का जारी किया।'

गुरु नानक के प्रकाश पर्व से तीन दिनों पहले पाकिस्तान सरकार ने नौ नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन का फैसला किया है। इससे पहले यह खास सिक्का जारी किया गया है। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के चेयरमैन डॉ. आमिर अहमद ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि करतारपुर आने वाले सिख तीर्थयात्री इस सिक्के को खरीद भी सकते हैं। इस दौरान आठ रुपये मूल्य का एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत ने पिछले साल ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब तक कॉरिडोर के निर्माण पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान के करतारपुर स्थित दरबार साहिब गुरु नानक का अंतिम विश्राम स्थल है।

बगदादी का सुराग देने वाले को मिलेंगे 175 करोड़ रुपये

वाशिंगटन, आइएएनएस : दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के सरगना अबू बकर अल-बगदादी के खात्मे में उसके करीब रहे एक व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई थी। उसने ऐसे अहम सुराग दिए थे, जिनकी मदद से अमेरिकी सैन्य अभियान में बगदादी को मार गिराने में सफलता मिली। अब अमेरिका बगदादी के सिर पर रखे गए ढाई करोड़ डॉलर (करीब 175 करोड़ रुपये) के इनाम का कुछ या पूरा हिस्सा इस व्यक्ति को दे सकता है। बगदादी के बारे में सूचना देने वाले आइएस के इस सदस्य की पहचान जाहिर नहीं की गई है।

डेली मेल अखबार में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसएफडी) के जनरल मजलूम अब्दी के हवाले से कहा गया है, 'तुर्की सीमा के पास सीरिया के जिस परिसर में बगदादी रहता था, वहां हमारा एक आदमी भी था। उसने हर कमरे की जानकारी देने के साथ बगदादी की सटीक लोकेशन भी बताई थी। परिसर में तैनात आइएस कारिंदों के अलावा उसने घर का नक्शा और सुरंगों की भी जानकारी दी थी।' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते रविवार को बगदादी के मारे जाने का एलान किया था।

- आइएस सरगना के करीबी ने दी थी परिसर की हर छोटी-बड़ी जानकारी
- बीते रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था आतंकी के मारे जाने का एलान

आइएस सरगना के रक्त का नमूना भी कराया था उपलब्ध

माना जा रहा है कि इसी व्यक्ति ने बगदादी के दो अंडरवियर और रक्त का नमूना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को मुहैया कराया था। इनसे लिए गए डीएनए नमूनों से ही बगदादी की पहचान की गई थी। अब्दी के अनुसार, 'हमारे आदमी की आइएस सरगना तक सीधी पहुंच थी। उसी ने इस साल बगदादी के अंडरवियर और रक्त का नमूना अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मुहैया कराया था।'

उन्होंने बताया था कि शनिवार रात सीरिया के इदलिब में अमेरिकी बलों के विशेष अभियान में बगदादी मारा गया।

बोइंग के सीईओ मुइलेनबर्ग को थी पायलट की चेतावनी की जानकारी

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- पायलट ने विमान में गड़बड़ी के प्रति किया था आगाह
- दो 737 मैक्स विमान हादसों में गई थी 346 लोगों की जान

बीते साल इंडोनेशिया और इस साल मार्च में इंडोनेशिया में हुए विमान हासदों में 346 लोगों की मौत हो गई थी। फाइल

वाशिंगटन : बोइंग के कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डेनिस मुइलेनबर्ग दो 737 मैक्स विमान हादसों के मामले में मंगलवार को अमेरिका की एक संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। उन्होंने पहली बार माना कि हादसे से पहले ही एक पायलट ने मैक्स विमान में गड़बड़ी के प्रति आगाह किया था। दरअसल, बोइंग अपने 737 मैक्स विमानों को लेकर विवादों में है। दो हादसों के बाद दुनियाभर में इन विमानों का संचालन बंद है। पहला मैक्स विमान हादसा गत वर्ष 29 अक्टूबर को इंडोनेशिया में हुआ था, जबकि दूसरा विमान गत दस मार्च को इथोपिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इन दो हादसों में 346 लोगों की जान गई थी।

इंडोनेशिया में लायन एयर के विमान हादसे की बरसी वाले दिन अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की एक समिति के समक्ष पेश हुए मुइलेनबर्ग को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, 'अगर हम सब कुछ जानते तो हमारा निर्णय अलग हो सकता था।' मुइलेनबर्ग ने यह माना कि दूसरे हादसे से पहले एक पायलट ने विमान की खामियों को लेकर चिंता जताई थी। इस स्वीकारोक्ति के बाद यह सवाल पूछा गया कि इथोपिया में गत दस मार्च को हुए विमान हादसे पहले बोइंग ने निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए? सुनवाई के दौरान कॉमर्स मामलों की समिति के सदस्यों ने हादसों को लेकर बोइंग के रवैये की तीखी आलोचना भी की। इस पर मुइलेनबर्ग ने कहा, 'कंपनी से गलती हुई और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे।'

मुइलेनबर्ग ने पीड़ित परिवारों से मांगी माफी : डेनिस मुइलेनबर्ग ने विमान हादसों के पीड़ित परिवारों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा, 'हम माफी मांगते हैं।' बोइंग के सीईओ की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताने और माफी मांगने में विफलता को लेकर आलोचना हुई थी।

डेमोक्रेट्स ने उठाया राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया से पर्दा

- व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेट्स के प्रस्ताव को बताया गैरकानूनी ढकोसला
- ट्रंप पर है अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ यूक्रेन पर दबाव डालने का आरोप

वाशिंगटन, प्रेटू : डेमोक्रेट पार्टी ने बुधवार को उस प्रस्ताव को सार्वजनिक कर दिया जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के कदमों के बारे में बताया गया है। डेमोक्रेट पार्टी का अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेंजेंटेटिव में बहुमत है। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव को गैरकानूनी ढकोसला करार दिया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं और उन पर अपने राजनीति प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन और उनके पुत्र के खिलाफ बेबुनियाद भ्रष्टाचार के आरोपों के दावों की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने का आरोप है। जो बिडेन का पुत्र यूक्रेन की गैस कंपनी बुरिस्मा में कार्यरत है। डेमोक्रेट पार्टी के आठ पन्नों के प्रस्ताव के मुताबिक अब लोग भी जांच प्रक्रिया से रूबरू हो सकेंगे और इस सुनवाई में सदन की खुफिया मामलों की समिति के अध्यक्ष एडम स्किफ की भूमिका प्रमुख होगी। पार्टी के इस कदम पर सदन में गुरुवार को मतदान होने के संभावना है। सदन की नियम समिति के अध्यक्ष जेम्स पी. मैक्गवर्न ने कहा, 'इस बात के काफी सुबूत हैं कि राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अमेरिकी चुनाव की प्रामाणिकता से समझौता करते हुए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी धोखा किया।' सदन की चार समितियों के प्रमुखों ने एक संयुक्त बयान में कहा, 'सदन की महाभियोग जांच में व्यापक सुबूत और गवाह जुटाए गए हैं और जल्द ही अमेरिकी जनता खुले तौर पर गवाहों को सुनेगी। सदन की नियमन समिति में बुधवार को पेश किया गया प्रस्ताव आगे का मार्ग दिखाएगा।'

उक्त चार समितियों के प्रमुखों में खुफिया मामलों पर स्थायी चयन समिति के अध्यक्ष एडम स्किफ, न्यायिक समिति के अध्यक्ष जेरोड नाडलर, विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष इलियट एंजेल और ओवरसाइट एंड रिफॉर्म समिति की कार्यकारी अध्यक्ष कैरोलीन मैलोनी शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'हमने जो सुबूत इकट्ठे किए हैं वे साबित करते हैं कि राष्ट्रपति ने 2020 के चुनावों में हस्तक्षेप के लिए एक बाहरी देश पर दबाव डालने की खातिर सरकार के विभिन्न तंत्रों का इस्तेमाल कर अपने पद का दुरुपयोग किया है।'

ब्रेक्जिट पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खेला आम चुनाव का जुआ

लंदन, एजेंसियां : यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया ब्रेक्जिट के भाग्य का फैसला अब दिसंबर महीने में हो सकता है। ब्रेक्जिट पर करो या मरो की बात करने वाले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस मुद्दे पर आम चुनाव कराने का जुआ खेला है। 12 दिसंबर को आम चुनाव कराने के प्रस्ताव पर संसद के निचले सदन में मुहर लगा दी है। इस बीच, ईयू ने ब्रेक्जिट के लिए और तीन महीने की मोहलत दे दी है। अब ब्रेक्जिट की आखिरी तारीख 31 जनवरी होगी।

जॉनसन ने कहा था कि ब्रेक्जिट पर समझौता हो या नहीं, ब्रिटेन 31 अक्टूबर के तय समय पर ईयू से अलग हो जाएगा। लेकिन संसद में जब विपक्ष ने उनका रास्ता रोका तो वो आम चुनाव कराने की कोशिशों में जुट गए। तीन बार प्रयास के बाद आखिरकार मंगलवार की रात वह आम चुनाव से संबंधित प्रस्ताव को हाउस ऑफ कॉमंस से पारित कराने में सफल रहे। 12 दिसंबर को चुनाव कराने के प्रस्ताव को संसद के निचले सदन ने 20 के मुकाबले 438 मतों से पारित कर दिया। अब इसे संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा जाएगा, जहां पूरी उम्मीद है कि उसे मंजूरी मिल जाएगी। उच्च सदन से मंजूरी मिलने के बाद अगले हफ्ते सदन को भंग कर दिया जाएगा।

- 12 दिसंबर को चुनाव कराने के प्रस्ताव पर हाउस ऑफ कॉमंस ने लगाई मुहर
- ईयू ने ब्रेक्जिट के लिए समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई

बोरिस जॉनसन। फाइल

ब्रिटेन की मौजूदा संसद का कार्यकाल 2022 तक था। चार साल के भीतर तीसरी बार आम चुनाव होने जा रहा है। ब्रेक्जिट पर पूर्व प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने भी आम चुनाव कराने का जुआ खेला था। 2017 में हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी का जनाधार घट गया था, हालांकि, सरकार उन्हीं की बनी थी। 1923 के बाद से यह पहला मौका है जब दिसंबर के महीने में आम चुनाव कराया जाएगा, जब लोग क्रिसमस की छुट्टियों के मूड में होते हैं।

ब्रेक्जिट को लेकर पिछले चार साल से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 55 साल के जॉनसन को उम्मीद है कि उन्हें पर्याप्त बहुमत मिल जाएगा। जबकि, चुनाव के समर्थन की घोषणा करने वाले लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन को अपनी सरकार बनने और ब्रेक्जिट पर दोबारा जनमत संग्रह कराने की उम्मीद है।

अगर आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो एक बार फिर ब्रेक्जिट का भाग्य अधर में लटक जाएगा। उस अवस्था में ब्रिटेन के सामने बिना समझौते के ईयू से अलग होने या फिर दोबारा जनमत संग्रह कराने का रास्ता बच जाएगा, जो ब्रेक्जिट को ही खत्म कर सकता है।

प्रदर्शनों के कारण लेबनान के पीएम ने दिया इस्तीफा

बेरुत में बुधवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान सड़क बंद करने के लिए डाले गए कंक्रीट ब्लॉक्स को हटाते पुलिसकर्मी। एपी

बेरुत, एएफपी : लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के एलान के बाद प्रदर्शनकारियों ने खुशी जाहिर की है। इस पश्चिम एशियाई देश में गत 17 अक्टूबर से भ्रष्टाचार और संप्रदायवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

साद हरीरी ने मंगलवार को टीवी संबोधन में कहा, 'मैं अपनी सरकार का इस्तीफा देने के लिए बाबदा पैलेस (राष्ट्रपति भवन) जा रहा हूं। समस्या को दूर करने के लिए यह जरूरी है। मेरा यह फैसला बदलाव की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लेबनान के बहुत से लोगों की इच्छा के जवाब में है। मैं सियासी वर्ग से देश को बचाने का आग्रह करता हूं।' हरीरी के इस्तीफे के एलान के बाद देशभर में प्रदर्शनकारियों ने खुशी मनाई। प्रधानमंत्री हरीरी के गढ़ त्रिपोली में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हुए और उनके इस्तीफे का स्वागत किया। 35 वर्षीय महिला प्रदर्शनकारी टिमा समीर ने कहा, 'इस्तीफे का स्वागत है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।' लेवेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक अफेयर्स के निदेशक सामी नादर ने कहा, 'हरीरी ने समाधान निकालने का रास्ता खोल दिया है क्योंकि मौजूदा संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता पीएम का इस्तीफा था।'

विरोध प्रदर्शनों से ठहर गया लेबनान : समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, लेबनान की सरकार ने गत 17 अक्टूबर को वाट्सएप कॉल पर टैक्स लगाने लगाने समेत खर्च में कटौती के कई उपायों की घोषणा की थी। इसके बाद पूरे देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते लेबनान में जनजीवन ठहर सा गया है।

मजबूत इरादे

कहा-अब और किसी सम्मान की जरूरत नहीं, इसी साल संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में दिया था साहसिक व यादगार भाषण

ग्रेटा ने पर्यावरण पुरस्कार लेने से किया इन्कार

कोपेनहेगन (डेनमार्क), एपी : जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली किशोर कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने पर्यावरण पुरस्कार लेने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जलवायु आंदोलन को अब और किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है। वह इसी साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में साहसिक भाषण देने के बाद वैश्विक रूप से चर्चित हो गई थीं।

स्टॉकहोम में आयोजित सम्मान समारोह में ग्रेटा की तरफ से उनके दो सहयोगियों ने विचार रखे। क्षेत्रीय अंतर संसदीय नॉर्डिक काउंसिल के पुरस्कार के लिए चयनित किए जाने पर उन्होंने आभार जताया। सोफिया और इसाबेला एक्सेल्शन ने ग्रेटा के हवाले से कहा, 'हमें बस यही चाहिए कि हमारे शासक व राजनेता शोध पर ध्यान दें।' 16 वर्षीय ग्रेटा इन दिनों कैलिफोर्निया में हैं।

नॉर्डिक काउंसिल की तरफ से हर साल साहित्य, युवा साहित्य, फिल्म, संगीत व पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार के साथ 52 हजार अमेरिकी डॉलर की राशि भी दी जाती है। ग्रेटा को दिया जाने वाला यह कोई पहला पुरस्कार नहीं है। नॉर्वे के तीन सांसदों ने उन्हें इसी साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया था।

ग्रेटा थनबर्ग। फाइल

पर्यावरण कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया में साझा किया फैसला

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने इस फैसले को साझा किया। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'जलवायु अभियान को और पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सत्ता में बैठे लोग वर्तमान में उपलब्ध विज्ञान का अनुसरण करना शुरू कर दें।' उन्होंने यह सम्मान देने के लिए नॉर्डिक काउंसिल का आभार व्यक्त किया लेकिन जलवायु से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात पर कायम नहीं रहने के लिए नॉर्डिक देशों की आलोचना भी की।

स्वीडन निवासी ग्रेटा ने पाया कि विमान भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। इसलिए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में शामिल होने के लिए समुद्री मार्ग को अपनाया। वह पालों वाले जहाज (सेलबोट) के जरिये दो सप्ताह में अटलांटिक महासागर को पार कर न्यूयॉर्क पहुंची थीं। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद दुनिया भर के नेताओं से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कई सवाल किए थे और अपने भाषण में 'आपकी हिम्मत कैसे हुई' जैसी पंक्ति का कई बार इस्तेमाल किया था।

कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर जुर्माना भरने को तैयार फेसबुक

लंदन, रायटर : दुनिया की दिग्गज सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर डाटा सुरक्षा कानून के उल्लंघन के मामले में ब्रिटिश नियामक को पांच लाख पौंड (करीब साढ़े चार करोड़ रुपये) का जुर्माना भरने को तैयार हो गई है। ब्रिटिश कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका ने एक एप के जरिये करीब आठ करोड़ 70 लाख फेसबुक यूजर्स का डाटा हासिल किया था। इसे लेकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सांसदों के सवालों का सामना करना पड़ा था।

ब्रिटेन के सूचना अधिकार नियामक ने बुधवार को एक बयान में बताया कि फेसबुक जुर्माना भरने को तैयार हुआ है। डाटा सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत के पालन को सुनिश्चित करने के लिए हम कदम उठाते रहेंगे। सूचना आयुक्त कार्यालय (आइसीओ) ने कहा था कि जिन लोगों का डाटा चोरी किया गया था, उनमें दस लाख ब्रिटिश यूजर्स भी थे।

वाट्सएप ने इजरायली सर्विलांस फर्म एनएसओ पर किया मुकदमा

- राजनयिकों, विरोधियों और पत्रकारों की जासूसी में सरकारों की मदद करने का लगाया आरोप

इस तरह होती है जासूसी

वाट्सएप ने आरोप लगाया कि यूजर्स के मोबाइल डिवाइस पर मे मालवेयर भेजने के लिए हमारे वीडियो कॉलिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया। इस मेलवेयर के जरिये एनएसओ की ग्राहक बताई जा रहीं सरकारें और खुफिया एजेंसियां यूजर्स के मोबाइल फोन की जासूसी करती हैं।

वाशिंगटन, रायटर : इजरायल की दिग्गज सर्विलांस फर्म एनएसओ जासूसी के आरोप में घिर गई है। वाट्सएप का आरोप है कि यह कंपनी चार महाद्वीपों में करीब 1400 यूजरों के मोबाइल फोन हैक करने में सरकारी खुफिया तंत्र की मदद कर रही है। जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनमें राजनयिक, सियासी विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इस मामले को लेकर वाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मंगलवार को अमेरिका में मुकदमा दायर किया।

सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे में फेसबुक के स्वामित्व वाले वाट्सएप ने एनएसओ पर 20 देशों में सरकार की हैकिंग को सुगम बनाने का भी आरोप लगाया। हैकिंग में निशाना बनाए गए देशों में सिर्फ मेक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की ही पहचान हो पाई है। वाट्सएप के अनुसार, सिविल सोसायटी के करीब 100 सदस्यों को भी निशाना बनाया गया। एनएसओ ने हालांकि इन आरोपों से इन्कार किया है। इस फर्म ने कहा, 'हम कड़े शब्दों में इन आरोपों का विरोध करते हैं और पूरे जोश के साथ इनका मुकाबला करेंगे। एनएसओ का इकलौता मकसद आतंकवाद और अपराध से मुकाबले में मदद करने के लिए सरकारी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीक मुहैया कराना है।'

दिल्ली में दम घोटने वाले प्रदूषण से आंखों में बहुत जलन होती है।
— सुनील छेत्री, कप्तान भारतीय फुटबॉल टीम

आइएमजी रिलायंस से जुड़े श्रेयस अय्यर

मुंबई, आइएएनएस : भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आइएमजी रिलायंस के साथ जुड़ गए हैं। अय्यर से पहले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या पहले ही आइएमजी रिलायंस के साथ जुड़ चुके हैं। 23 वर्षीय अय्यर आइपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तान हैं। उन्होंने हाल में वेस्टइंडीज दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया था।

टेस्ट में गुलाबी गेंद से कम नहीं होंगी चुनौतियां

कलाई के स्पिनरों को फ्लड लाइट में खेलना हो जाता है मुश्किल, लाल गेंद की तरह रिवर्स स्विंग नहीं मिलना भी है परेशानी

निखिल शर्मा • नई दिल्ली

टेस्ट क्रिकेट किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट फ्लड लाइट में और गुलाबी गेंद से खेला जाए तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 22 नवंबर से 26 नवंबर तक कोलकाता में पहली बार भारतीय सरजमीं पर डे-नाइट टेस्ट खेला जाएगा। दोनों ही टीम अब तक डे-नाइट टेस्ट नहीं खेली हैं। ऐसे में भारत और बांग्लादेश की टीमों के लिए इस टेस्ट में चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है।

कम घास में रफ होने का डर : 2016 में पहली बार बीसीसीआइ ने दलीप ट्रॉफी को गुलाबी गेंद से फ्लड लाइट में कराया था। ग्रेटर नोएडा में हुए इस टूर्नामेंट में पिच बनाने वाले एक क्यूरेटर ने बताया कि दिन में यह गेंद ज्यादा स्विंग नहीं हो रही थी, लेकिन रात में यह गेंद स्विंग कर रही थी। लाइट में यह गेंद ज्यादा परेशान कर रही थी। पिच पर कम घास रहने से यह जल्दी रफ हो जाती थी और फ्लड लाइट में कलाई के स्पिनरों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही थी। उनका मानना है कि पिच पर चार से पांच मिलीमीटर की घास रखने पर गेंद की चमक ज्यादा देर तक रहेगी।

लाल गेंद की तरह नहीं होती रिवर्स स्विंग : गुलाबी गेंद से दलीप ट्रॉफी में खेलने का अनुभव रखने वाले उत्तर प्रदेश के युवा तेज गेंदबाज अंकित राजपूत का मानना है कि 2016 में जब पहली बार गुलाबी गेंद से खेले, तो किसी को कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा था। यहां पर विकेट सपाट था, इसीलिए स्पिनरों खासकर कलाई के स्पिनरों को ज्यादा फायदा पहुंचा। आप देखें तो यहां पर कुलदीप यादव और श्रेयस गोपाल जैसे स्पिनरों ने काफी विकेट लिए। अगले वर्ष डिंडिगुल में हुए दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में बताते हुए अंकित ने कहा कि यहां विकेट पर घास थी, जिससे अच्छा उछाल मिल रहा था। हालांकि यह गेंद लाल गेंद की तरह से रिवर्स स्विंग नहीं होती है, लेकिन सफेद गेंद की तरह से ठोस जरूर बनी रहती है। अंकित ने कहा कि यहां पर मैंने और रजनीश गुरबानी ने पारी में चार से पांच विकेट लिए थे। हमें फ्लड लाइट में अच्छी मदद मिल रही थी।

स्पिनरों को खेलना मुश्किल: अंकित ने बताया कि फ्लड लाइट में स्पिनरों खासकर कलाई के स्पिनरों को खेलना बल्लेबाजों के लिए इस गेंद से मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कलाई के स्पिनरों की गेंद की सीम पर ध्यान रखना होता है, लेकिन गुलाबी गेंद की सीम काली हो जाती है और बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आता है। यही वजह है कि 2016 में जब पहली बार दलीप ट्रॉफी हुई तो कुलदीप और गोपाल ने काफी विकेट चटकाए थे। ऐसे में कोलकाता टेस्ट में कलाई के स्पिनरों को खेलना मुश्किल होगा। साथ ही बल्लेबाजों को गेंद की चमक किस ओर है, यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है।

घास ज्यादा, बल्लेबाज मुश्किल में: अब तक जो डे-नाइट टेस्ट विदेश में हुए हैं उसके मुकाबले भारतीय मैदान वैसे नहीं हैं। ऐसे में गेंद की चमक जल्द खोने का डर कोलकाता टेस्ट में बना रहेगा। इसके लिए क्यूरेटर को पिच पर सामान्य से ज्यादा घास छोड़नी पड़ेगी, जिससे गेंद को लंबे समय तक बचाया जा सके। ज्यादा घास छोड़ने का मतलब है कि पिच से तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता मिलेगी और बल्लेबाजों की मुश्किल बढ़ जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि 2015 में टेस्ट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के बीच जो पहला डे-नाइट टेस्ट खेला गया था, उसमें दोनों टीम के तेज गेंदबाजों ने कुल मिलाकर 29 विकेट हासिल किए थे। बल्लेबाजी की बात करें तो 66 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज पीटर नेविल सबसे ज्यादा रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने थे।

बीसीसीआइ के पूर्व क्यूरेटर दलजीत ने दी सलाह, कोलकाता टेस्ट में पिच पर अधिक घास हो, लेकिन आउटफील्ड पर कम घास हो

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीसीसीआइ के पूर्व क्यूरेटर दलजीत सिंह ने सलाह दी है कि गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले कोलकाता टेस्ट मैच में विकेट पर अधिक घास होनी चाहिए, लेकिन साथ ही आउटफील्ड पर घास कम होनी चाहिए। इससे ओस से बचा जा सकता है। कोलकाता में होने वाले इस डे-नाइट टेस्ट मैच की तैयारियों में हालांकि बहुत कम समय बचा है। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) को हालांकि गुलाबी गेंद से मैचों के आयोजन का अनुभव है। भारतीय क्रिकेट में 22 साल तक सेवा देने के बाद बीसीसीआइ के मुख्य क्यूरेटर पद से पिछले महीने सेवानिवृत होने वाले दलजीत ने कहा कि ओस मुख्य चिंता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्हें समझना होगा कि आप इससे बच नहीं सकते हो। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए आउटफील्ड में घास कम रखनी होगी और पिच पर आम घास से अधिक लंबी घास रखनी पड़ेगी। आउटफील्ड में जितनी अधिक घास होगी, ओस की परेशानी उतनी ज्यादा होगी। इस मैच के दोपहर बाद एक बजकर 30 मिनट से शुरू होने की संभावना है और खेल रात आठ बजकर 30 मिनट तक चल सकता है। दलजीत का मानना है कि गुलाबी गेंद की चमक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पिच पर अधिक घास रखनी होगी। आपको याद होगा जब एडिलेड में पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेला गया था तो उन्होंने पिच पर 11 मिलीमीटर घास रखी थी। आपको इतनी घास को तैयार करना होगा।

बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ी बुधवार को दिल्ली हवाईअड्डे से बाहर आते हुए • प्रेट्र

ईमानदारी से कहूं तो, मुझे (घरेलू डे-नाइट मैच के बारे में) कुछ भी याद नहीं है। कैब के घरेलू टूर्नामेंट के फाइनल में शमी ने वास्तव में तेज गेंदबाजी की थी और हमारी टीम (मोहन बागान) जीत गई थी। एक चीज मुझे याद है वह यह है कि गेंद को पकड़ने में मुझे कठिनाई हो रही थी। **रिद्धिमान साहा**, भारतीय विकेटकीपर

यह ऐतिहासिक मैच दोपहर एक बजे तक शुरू हो सकता है। हालांकि, इसके लिए बीसीसीआइ की सहमति की जरूरत होगी। शुरुआत जल्दी होगी, इसलिए दिन का खेल करीब रात 8-8.30 बजे तक खत्म हो जाएगा। ओस ज्यादातर उसके ही बाद खेल में खलल डालती है जैसा कि हमने ईडन में हुए सीमित ओवर के मैचों में देखा है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि ओस की समस्या होगी। **सुजान मुखर्जी**, ईडन गार्डेंस के क्यूरेटर

शाकिब की गैरमौजूदगी देगी प्रेरणा : महमूदुल्लाह

नई दिल्ली, प्रेट्र: बांग्लादेश की टी-20 टीम के कप्तान महमूदुल्लाह रियाद ने कहा कि भारत दौरे पर शाकिब हल हसन की कमी उनके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि अच्छे प्रदर्शन की प्रेरणा साबित होगी। बांग्लादेश की 15 सदस्यीय टीम बुधवार को यहां पहुंची, जबकि एक दिन पहले ही उनके महानतम खिलाड़ियों में से एक शाकिब पर सटोरिये की पेशकश की जानकारी नहीं देने के कारण दो साल का प्रतिबंध (एक साल का निलंबित प्रतिबंध) लगाया गया है। बांग्लादेशी टीम तीन टी-20 नई दिल्ली (तीन नवंबर), राजकोट (सात नवंबर) और नागपुर (10 नवंबर) में खेलेगी। इसके अलावा दो टेस्ट इंदौर (14 से 18 नवंबर) और कोलकाता (22 से 26 नवंबर) खेले जाएंगे। कोलकाता में दोनों देशों के बीच पहली बार डे-नाइट टेस्ट खेला जाएगा।

महमूदुल्लाह ने कहा कि हम अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। शाकिब की गैर मौजूदगी हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी। देश के लिए खेलने से बड़ा सम्मान कोई नहीं है। मुझ पर कप्तानी की जिम्मेदारी है और मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। महमूदुल्लाह ने हालांकि स्वीकार किया कि यह दौरा कठिन होगा। उन्होंने कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यह कठिन दौरा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। टीम के एक अन्य सीनियर खिलाड़ी मुश्फिकुर रहीम ने कहा कि निश्चित तौर पर मुझे शाकिब की कमी खलेगी क्योंकि हम लंबे समय से साथ खेल रहे हैं।

एक नजर में

शिव और पूजा फाइनल में

टोक्यो : पूर्व विश्व कांस्य पदक विजेता शिव थापा (63 किग्रा) ने कड़े मुकाबले में जीत से पूजा रानी (75 किग्रा) के साथ बुधवार को यहां मुक्केबाजी के ओलंपिक टेस्ट इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि दो अन्य भारतीयों को शुरुआती दौर में हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सुबह के सत्र में सेमीफाइनल में चार बार के एशियाई पदकधारी और इस महीने के शुरू में तीसरा राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले थापा ने जापान के दाइसुके नारीमात्सु को शिकस्त दी। एशियन गेम्स की पूर्व कांस्य पदकधारी रानी ने ब्राजील की बीट्रीज सोरेस को सर्वसम्मत फैसले में पराजित किया। रानी ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। हालांकि, पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन निखत जरीन (महिला 51 किग्रा) और पुरुष वर्ग में वाहलीमपुइया (75 किग्रा) को अपनी सेमीफाइनल बाउट हारने से कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। दोनों मुक्केबाजों ने छोटे ड्रॉ की बदौलत अंतिम चार चरण में प्रवेश किया था। जरीन को जापान की सना कावानो से हार मिली, जबकि वाहलीमपुइया को स्थानीय प्रबल दावेदार युइतो मोरीवाकी ने पराजित किया। (प्रेट्र)

रवींद्र ने किया पदक पक्का

बुडापेस्ट: रवींद्र ने यहां 61 किग्रा वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक पक्का किया। 22 साल के रवींद्र ने सीनियर यूरोपीयन चैंपियन अर्मेनिया के आर्सेन हारुतयुनान को मंगलवार रात 4-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय कुश्ती महासंघ ने यह जानकारी दी। इससे पूर्व अपने पहले मुकाबले में रवींद्र ने हंगरी के मार्सेल बुदाई कोवाक्स को 12-1 से हराया था, जबकि क्वार्टर फाइनल में रूस के दिनिस्लाम ताखतोरोव को 11-0 से रौंदा था। साउथ एशियन गेम्स 2016 में स्वर्ण और 2014 में कैडेट एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले सोनीपत के इस पहलवान की नजरें अब अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर टिकी हैं। फाइनल में उनका सामना किर्गिस्तान के उलुकबेक झोलदोशबेकोव से होगा। 74 किग्रा वर्ग में गौरव बालियान को रेपेचेज के जरिये पदक जीतने का मौका मिलेगा। उनका सामना अमेरिका के ब्रेडी गैरी बर्ज से होगा। बालियान ने क्वालीफायर में ओलेकसांद्र व्यश्नियाक को 11-0 से रौंदा था। बालियान को हालांकि रूस के रजामबेक जामालोव के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन, रजामबेक के फाइनल में पहुचंने पर बालियान को पदक के लिए चुनौती पेश करने का मौका मिला। (प्रेट्र)

वार्नर-स्मिथ ने दिलाई ऑस्ट्रेलिया को आसान जीत

तीन मैचों की टी-20 सीरीज में श्रीलंका पर बनाई 2-0 की अजेय बढ़त, दोनों बल्लेबाजों ने खेली अर्धशतकीय पारियां

ब्रिसबेन, एएफपी: डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के नाबाद अर्धशतकों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। पाकिस्तान पर 3-0 से जीत दर्ज करने के बाद यहां पहुंचे श्रीलंका ने इसी के साथ तीन मैचों की सीरीज गंवा दी है। एडिलेड में खेले गए पहले मैच में उसे 134 रन से हार झेलनी पड़ी थी। तीसरा और अंतिम मैच मेलबर्न में शुक्रवार को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कसी हुई गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई टीम 19 ओवर में 117 पर ढेर हो गई, जिसमें कुशल परेरा ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और इस तरह से 42 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली।

वार्नर (नाबाद 60) और स्मिथ (नाबाद 53) ने आरोन फिंच के पहले ओवर में आउट होने के बाद जिम्मेदारी संभाली और दूसरे विकेट के लिए 117 रन की अटूट साझेदारी की। फिंच को लसित मलिंगा ने विकेट के पीछे कैच कराया। वार्नर ने पिछले मैच में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना पहला शतक लगाया था और उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में नौ चौके लगाए। स्मिथ ने भी 2016 के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की और अपने शानदार ड्राइव और तेजी से रन चुराने की कला दिखाई। उनकी पारी में छह चौके शामिल हैं।

इससे पहले श्रीलंकाई बल्लेबाजी शुरू में लड़खड़ा गई। मलिंगा ने पहले मैच में हार के बाद अपने खिलाड़ियों से जज्बा दिखाने की अपील की थी, लेकिन मिशेल स्टार्क की जगह लिए गए बिली स्टेनलेक, एस्टन एगर, एडम जांपा और पैट कमिंस ने दो-दो विकेट लेकर फिर से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को नहीं चलने दिया। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ओवर में ही पहली सफलता मिली जब कुशल मेंडिस (01) रन आउट हो गए। उन्हें आउट करवाने वाले दनुष्का गुणातिलका (21) ने स्टेनलेक पर छक्का जमाया और इसी तेज गेंदबाज ने उन्हें बोल्ड कर दिया। स्पिनर एगर ने इसके बाद अविष्का फर्नांडो (17) को पवेलियन भेजा। निरोशन डिकवेला (05) को कमिंस ने पवेलियन भेजा, जबकि परेरा ने एगर की गेंद अपने विकेटों में खेली।

दूसरे टी-20 में जीत दिलाने के बाद लौटते डेविड वार्नर (बायें) और स्टीव स्मिथ • एएफपी

द्रविड़ से मिले गांगुली एनसीए को बेहतर बनाने के लिए की बात

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बुधवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख राहुल द्रविड़ से मुलाकात करके वर्षों से भारतीय क्रिकेट की 'सप्लाई लाइन' रही अकादमी को बेहतर बनाने पर बात की। भारत के लिए वर्षों तक साथ खेलने वाले दोनों धुरंधरों ने अकादमी को लेकर बात की। गांगुली ने भी अपनी राय रखी।

गांगुली ने उस प्रस्तावित भूमि का भी मुआयना किया जहां एनसीए की नई अकादमी बनने वाली है। बीसीसीआइ ने कर्नाटक सरकार से मई में 25 एकड़ भूखंड के लिए करार किया था। अब उसे बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 15 एकड़ भूमि अतिरिक्त मिल गई है। भारतीय क्रिकेट को नई पौध प्रदान करने के लिए बनाया गया एनसीए दरअसल पुनर्वास केंद्र बन गया है और गांगुली ने खुद यह बात स्वीकार की थी।

भारत प्लेऑफ में पहुंचा

योगेश शर्मा • दुबई

मैन ऑफ द मैच सलामी बल्लेबाज ट्रेयाश बाली की विस्फोटक पारी की मदद से भारत ने यहां अपने ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 33 रनों से हराकर रेड बुल कैंपस क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड फाइनल्स के प्लेऑफ में जगह बनाई। बाली ने अपनी 94 रनों की अर्धशतकीय पारी के दौरान 65 गेंदों का सामना किया, जिसमें सात चौके और छह छक्के जड़े।

भारत ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 186 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में जल्दी विकेट गंवाने के कारण इंग्लिश टीम दबाव में आ गई और 20 ओवर में नौ विकेट पर 153 रन ही बना पाई और उसे हार का सामना करना पड़ा। हिमांशु शर्मा ने चार ओवर में 33 रन देकर सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए। पंकज शर्मा और सागर शर्मा ने दो-दो विकेट झटके। इंग्लिश बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों को खेलने में परेशानी हो रही थी। इंग्लिश टीम के शीर्ष तीन बल्लेबाज 36 रन पर ही पवेलियन लौट गए थे। टीम को सम्मानजनक स्कोर तक एंगस डाहल लेकर गए, जिन्होंने 32 गेंदों में चार चौके की मदद से 39 रन बनाए। डाहल के अलावा एंड्रयू नील ने 13 गेंदों में तेजी से 31 रन बनाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अन्य बल्लेबाजों के सरेंडर करने के कारण इंग्लिश टीम को शिकस्त मिली। नील ने अपनी पारी में एक चौका और तीन छक्के जड़े।

इससे पहले भारतीय टीम ने 17 रन पर ही रिपिन चौधरी (02) का विकेट गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद बाली और मयंक ने दूसरे विकेट के लिए 103 रनों की अटूट साझेदारी करके टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। बाली के अलावा मयंक ने भी 39 रनों की उपयोगी पारी। यूनिवर्सिटी स्तर के सबसे बड़े क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में भारत ने ग्रुप में अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 101 रनों से रौंदा था।

अफगानिस्तान में हो रहे बदलाव का श्रेय भारत को : नबी

हाल के वर्षों में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपने दमदार खेल की बदौलत दुनियाभर के प्रशंसकों का ध्यान खींचा है और अब छह नवंबर से यह टीम लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी तो यहां भी इसके प्रदर्शन पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें होंगी। अफगान टीम यहां वनडे के अलावा टी-20 और टेस्ट मैच की सीरीज भी खेलेगी। बेशक विश्व कप में अफगानिस्तान का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन उसने सितंबर में बांग्लादेश को टेस्ट मैच में करारी शिकस्त देकर इस प्रारूप में भी मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज को लेकर अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर **मुहम्मद नबी** से **विकास मिश्र** ने कई अहम मुद्दों पर विशेष बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:

साक्षात्कार

- **वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम की क्या रणनीति होगी?**

-देखिए, वनडे विश्व कप में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में ऐतिहासिक जीत ने हमारी टीम के लिए संजीवनी का काम किया है। बेशक, वेस्टइंडीज तीनों प्रारूप में अच्छी टीम है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम उन्हें वनडे और टी-20 के अलावा टेस्ट सीरीज में भी कड़ी चुनौती देंगे। हमारे पास कई विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं जिनके दम पर किसी भी टीम को हराने में सक्षम हैं।

- **आप और राशिद खान आइपीएल में भी एक ही टीम से खेलते हैं। अब राशिद टीम के कप्तान हैं। क्या टीम की रणनीति पर राशिद आपसे भी बात करते हैं?**

-राशिद दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। वह एक ऐसे गेंदबाज हैं, जो किसी भी पिच पर विकेट निकाल सकते हैं। राशिद अच्छे खिलाड़ी होने के साथ, अच्छे कप्तान भी हैं और उनके सभी निर्णय में टीम साथ होती है। आइपीएल और देश के लिए एक साथ खेलने से हम दोनों को काफी फायदा भी मिलता है।

- **अफगानिस्तान में क्रिकेट के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे?**

-अफगानिस्तान अब धीरे-धीरे बदल रहा है। अब हमारे देश में भी स्टेडियम बन गया है, प्रथम श्रेणी के मैच भी खेले जाते हैं। क्रिकेट अकादमी भी खुल गई हैं जहां बड़ी संख्या में युवा क्रिकेट सीखने के लिए दाखिला ले रहे हैं। अब टीम में युवा खिलाड़ी आ रहे हैं। हां, इतना जरूर कहूंगा कि वहां भारत जैसे माहौल के लिए अभी कम से कम 15-20 साल इंतजार करना पड़ सकता है। अफगानिस्तान में हो रहे इस बदलाव का श्रेय हम भारत को देते हैं, जिसने हमें घरेलू मैदान दिया। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं जरूर चाहूंगा कि भविष्य में अफगानिस्तान भी किसी टीम की मेजबानी करे और हम लोग अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलें।

- **अफगानिस्तान की समस्या अन्य देशों की तुलना में काफी अलग है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के लिए यहां तक का सफर कितना मुश्किल रहा है?**

-अफगानिस्तान ने रिफ्यूजी कैंप से क्रिकेट का ककहरा सीखा। इसके बाद भारत जैसे देशों की मदद से हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। यहां आइपीएल के प्लेटफॉर्म पर हमारी प्रतिभा को दुनिया ने देखा। टीम के सभी सदस्यों ने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया है।

स्विस दिग्गज फेडरर एटीपी कप से हटे

टेनिस डायरी

पेरिस, एएफपी: स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर पारिवारिक कारणों का हवाला देकर एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट से हट गए, जिसका आयोजन पहली बार जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा।

फेडरर ने कहा, 'बेहद खेद के साथ मुझे पहले एटीपी कप टूर्नामेंट से हटना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह जब मैंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की हामी भरी थी तो यह बेहद मुश्किल फैसला था क्योंकि इसका मतलब था कि परिवार को कम समय और सत्र की बेहद कड़ी शुरुआत।' दुनिया के तीसरे नंबर के पुरुष खिलाड़ी फेडरर ने आगे कहा, 'आगामी वर्ष के बारे में अपने परिवार और टीम के साथ काफी चर्चा के बाद मैंने फैसला किया कि घर में दो अतिरिक्त सप्ताह बिताना मेरे परिवार और मेरे टेनिस दोनों के लिए फायदेमंद होगा।' 38 वर्षीय फेडरर के हटने के बाद आयोजकों ने उनके देश स्विट्जरलैंड को भी इस टूर्नामेंट से हटा दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी।

एटीपी कप का आयोजन तीन से 12 जनवरी के बीच ब्रिसबेन, पर्थ और सिडनी में किया जाएगा। अब फेडरर 10 नवंबर से लंदन में शुरू हो रहे एटीपी टूर फाइनल्स में उतरेंगे। उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों से अगले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिलने की उम्मीद जताई। फेडरर ने हाल ही में बासेल में अपना 10वां स्विस इंडोर टूर्नामेंट का खिताब जीता था।

पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में मेदवेदेव को चार्डी ने चौंकाया

पेरिस, एएफपी: फ्रांस के जेरेमी चार्डी ने मंगलवार को पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर चौंका दिया और उनकी लगातार सातवें फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें तोड़ दीं। वहीं साथी रूसी खिलाड़ी और गत चैंपियन कारेन खचानोव को भी जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्ट्रफ से हार मिली। अपने शानदार खेल की वजह से विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचने वाले मेदवेदेव ने पहला सेट अपने नाम किया, लेकिन अगले दो सेट गंवा बैठे। चार्डी ने उन्हें 4-6, 6-2, 6-4 से हराकर अंतिम-16 में प्रवेश किया। दूसरे सेट में मिली हार के साथ ही मेदवेदेव के पिछले 19 सेट से चला आ रहा जीत का क्रम भी टूट गया। साथ ही उनका पिछले नौ मुकाबलों से चला आ रहा विजय क्रम भी टूट गया। इससे पहले खचानोव पर दूसरे दौर में लेनार्ड स्ट्रफ ने 7-6, 3-6, 7-5 से जीत हासिल की। वहीं, छठी वरीय जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फर्नांडो वर्डास्को को 6-1, 6-3 से शिकस्त दी।

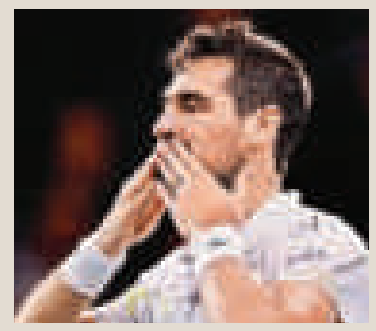

फ्रांस के जेरेमी चार्डी • रायटर

पहले भी विवादों में रहे हैं शाकिब

- फरवरी 2014 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में शाकिब के आउट होने के बाद कॉमेंटेटर उनके आउट होने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे, तभी कैमरा उनकी ओर केंद्रित हुआ। शाकिब ने तब कैमरे को देखकर आपत्तिजनक इशारा किया था। इसके बाद शाकिब पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तीन वनडे मुकाबलों का प्रतिबंध लगाया था। इसमें एशिया कप में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ दो मुकाबले और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का आखिरी मैच शामिल था।
- जुलाई 2014 में शाकिब पर आचरण संबंधी परेशानियों के चलते छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल, मीरपुर में भारत के खिलाफ खेले गए वनडे के दौरान एक दर्शक ने उनकी पत्नी पर ताना कसा था, जिसके बाद शाकिब ने दर्शक की पिटाई कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने तब टीम के कोच रहे चंद्रिका हथुरुसिंघे के साथ भी खराब व्यवहार किया था। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद उनका प्रतिबंध कम कर दिया गया था।

आइसीसी ने जारी की शाकिब व सटोरिये के बीच हुई पूरी बातचीत, दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं बांग्लादेशी ऑलराउंडर

शाकिब से सटोरिये ने पूछा, भाई इस सीरीज में कुछ है

दुबई, प्रेट्र: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन पर दो साल का प्रतिबंध लगाने के बाद आइसीसी ने सटोरिये के साथ हुई उनकी बातचीत को भी सार्वजनिक किया है। दीपक अग्रवाल नाम के सटोरिये से हुई बातचीत के बारे में आइसीसी ने कहा है कि पहली बार शाकिब से उसने 2017 में संपर्क किया था। उसके बाद से वह शाकिब के लगातार संपर्क में था।

आइसीसी के मुताबिक नवंबर, 2017 में जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) में शाकिब ढाका डायनामाइट्स टीम में थे तब किसी शख्स ने अग्रवाल को हसन का नंबर दिया था। अग्रवाल ने उस शख्स से बीपीएल में खेल रहे खिलाड़ियों के नंबर मांगे थे। 19 जनवरी, 2018 को अग्रवाल ने शाकिब को मेसेज कर उन्हें बांग्लादेश, जिंबाब्वे और श्रीलंका की त्रिकोणीय सीरीज में मैन ऑफ द मैच चुने जाने पर बधाई दी थी। आइसीसी ने कहा कि सटोरिये ने इसके बाद हसन को एक और मेसेज किया और लिखा कि क्या हम इस पर काम कर सकते हैं या आइपीएल तक मुझे इंतजार करना होगा। इस मेसेज में 'काम' से अर्थ अग्रवाल को मैचों की आंतरिक जानकारी मुहैया कराने से था। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और 23 जनवरी, 2018 को शाकिब को अग्रवाल ने एक और मेसेज किया, भाई इस सीरीज में कुछ है? शाकिब ने खुद पुष्टि की है कि अग्रवाल का यह मेसेज त्रिकोणीय सीरीज की जानकारी को लेकर था। हालांकि, तब शाकिब ने भ्रष्टाचार रोधी इकाई या फिर अन्य किसी अथॉरिटी को इसकी जानकारी नहीं दी थी। यही नहीं, शाकिब 2018 में हुए आइपीएल टूर्नामेंट में भी सटोरिये के संपर्क में थे और उन्हें अग्रवाल से मेसेज मिले थे। अग्रवाल ने शाकिब को बिटकॉइंस, डॉलर अकाउंट्स के बारे में मेसेज किए थे। इसके अलावा उनकी अकाउंट डिटेल भी मांगी थी। इन मेसेज के जवाब में शाकिब ने लिखा था कि वह पहले उनसे मिलना चाहते हैं।

यह मेरे लिए स्तब्ध करने वाला था, लेकिन यह तथ्य राहत देने वाला है कि शाकिब को लंबे समय से जानने के कारण मुझे पता है कि वह कभी किसी भ्रष्ट काम में शामिल नहीं होंगे। आइसीसी ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा नहीं दी है। उनकी वापसी आसान नहीं होगी। **हबीबुल बशर**, प्रमुख चयनकर्ता

निश्चित तौर पर मुझे भी 13 साल से अपने साथी के साथ हाल की घटनाओं के कारण कुछ रातों तक नींद नहीं आएगी। लेकिन, यह सोचकर चैन की नींद सो सकता हूं कि वह 2023 विश्व कप में टीम की अगुआई करेंगे क्योंकि उनका नाम शाकिब अल हसन है। **मशरफे मुर्तजा**, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज

मैं नहीं जानता कि क्या कहना चाहिए। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें उनके बिना खेलना है। लेकिन, मैं एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप दमदार वापसी करोगे। हम उस दिन का इंतजार करेंगे शाकिब भाई। हम शाकिब के साथ हैं। **मुश्फिकुर रहीम**, बांग्लादेश के विकेटकीपर

शाकिब का प्रतिबंध खिलाड़ियों और उनके प्रशंसकों के लिए सबक है कि खेल से बड़ा कुछ नहीं है। अगर वह कुछ गलत करते हैं तो सजा तो मिलेगी ही। **रमीज राजा**, पाक के पूर्व बल्लेबाज

मुझे शाकिब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। दो वर्ष का प्रतिबंध बहुत कम है। उन पर इससे अधिक समय के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए था। **माइकल वॉन**, पूर्व कप्तान, इंग्लैंड

शाकिब अल हसन • फाइल फोटो, ट्विटर

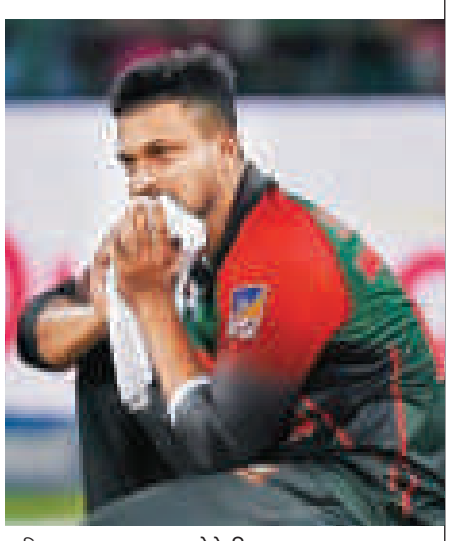

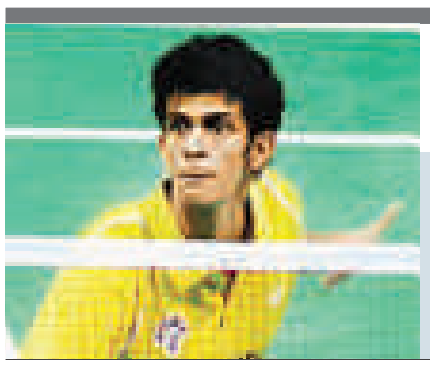

मकाऊ ओपन के पहले दौर में भारतीय खिलाड़ी हारे

मकाऊ (चीन), आइएएनएस : भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम को यहां जारी मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में ही बुधवार को हार का सामना करना पड़ा। जयराम को चीन के सुन फेई जियांग के खिलाफ 39 मिनट तक चले मुकाबले में 16-21, 16-21 से हार झेलनी पड़ी। महिला वर्ग में साई उत्तेजिता राव चुक्का को भी पहले दौर में ही हार देखनी पड़ी। चीन की केई यान यान ने उत्तेजिता को 21-19, 21-12 से पराजित किया।

गैरेथ बेल ने कभी मुझसे रियल मैड्रिड छोड़ने के बारे में नहीं कहा है।
– जिनेदिन जिदान, कोच रियल मैड्रिड

फुटबॉल डायरी ▶ ला लीगा में रीयल वालाडोलिड को 5-1 से हराया, लियोन मेसी ने दागे दो गोल

मेसी ने बार्सिलोना को शीर्ष पर पहुंचाया

इस जीत के साथ बार्सा के अंक तालिका में 10 मुकाबलों में 22 अंक हुए

गोल करने के बाद लियोन मेसी को बधाई देते साथी खिलाड़ी। रायटर

बार्सिलोना, रायटर : स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने मंगलवार को रीयल वालाडोलिड को 5-1 से करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इस दौरान बार्सिलोना के कप्तान लियोन मेसी ने दो गोल दागने के अलावा गोल करने दो मौके भी तैयार किए।

कैंप नाउ में खेले गए इस मुकाबले में क्लेमेंट लेंगलेट के गोल की बदौलत बार्सिलोना ने दूसरे ही मिनट में बढ़त हासिल की थी, लेकिन रीयल वालाडोलिड के किको ओलिवास (15वें मिनट) ने गोल करके स्कोर को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मेसी के पास पर अर्तुरो विडल (29वें मिनट) ने गोल करके बार्सिलोना को बढ़त दिलाई। इसी बीच अर्जेंटीनी दिग्गज मेसी (34वें व 75वें मिनट) ने पहले एक शानदार फ्री किक के जरिये गोल किया और फिर अपना दूसरा गोल दागने के बाद लुइस सुआरेज (77वें मिनट) के लिए एक गोल का मौका भी तैयार किया। इस जीत के साथ बार्सिलोना अंक तालिका में 10 मुकाबलों में 22 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया।

मैनेजर हुए मेसी के कायल : मेसी ने सभी प्रतियोगिताओं के पिछले चार मुकाबलों में चार गोल दागे, जबकि बार्सिलोना के मैनेजर ईर्नेस्टो वाल्वर्डे के मार्गदर्शन में अपना 100वां गोल पूरा किया। इस मुकाबले में वाल्वर्डे मेसी के खेल के कायल हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेसी को लेकर मैं और क्या कह सकता हूं। उनके पैरों से जादू निकल रहे थे। आप केवल उनकी सराहना कर सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। मेसी ने अपने इस प्रदर्शन से स्पष्ट कर दिया कि वह फिट हैं और वह अपनी पुरानी लय में लौट आए हैं।

सिटी ने साउथैंप्टन को हराया

लंदन, रायटर : इंग्लिश लीग कप के चौथे दौर के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने साउथैंप्टन को 3-1 से हरा दिया, जहां सिटी की ओर से सर्जियो अग्यूरो (38वें व 56वें मिनट) ने दो गोल दागे। गत विजेता सिटी पिछले मुकाबले से अपनी टीम में नौ बदलाव करके मैदान में उतरी, जिसमें उसके पूर्व कप्तान माइक डायले के 18 वर्षीय पोते टॉमी बोयले को पदार्पण करने का मौका मिला। सिटी की ओर से अग्यूरो के दो गोल करने से पहले निकोलस ओटेमेंडी (20वें मिनट) ने सिटी को बढ़त दिलाई। वहीं साउथैंप्टन की ओर से जैक स्टीफंस ने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले इकलौता गोल दागा। वहीं, लीग कप के एक अन्य मुकाबले में एवर्टन ने वाटफोर्ड को 2-0 से हरा दिया। साथ ही लीसेस्टर सिटी ने बर्टन एल्बियोन को 3-1 से और कोलचेस्टर युनाइटेड ने क्रावली टाउन को इसी स्कोर से हराया।

लुकाकू ने इंटर को दिलाई जीत

ब्रेशिया, रायटर : रोमेलू लुकाकू के शानदार गोल की मदद से इटली के सीरी-ए लीग में इंटर मिलान ने ब्रेशिया को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ इंटर अंक तालिका में जुवेंटस को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गया। हालांकि, जुवेंटस अपने अगले मुकाबले को जीतकर फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है। लॉतारो मार्टिनेज के गोल की बदौलत इंटर ने शुरुआती बढ़त बनाई और इसके बाद दूसरे हाफ में लुकाकू ने इंटर की बढ़त को दोगुना किया। हालांकि, दूसरे हाफ में इंटर के मिलान स्क्रिनियर आत्मघाती गोल कर बैठे, लेकिन अंत में इंटर ने मुकाबले को अपने नाम किया।

ओमान और अफगानिस्तान के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे

फुटबॉल

सुनील ने कहा, टीम अब तक पूरी तरह से कोच की रणनीति को नहीं अपना पाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने बुधवार को वादा किया कि उनकी टीम ओमान और अफगानिस्तान के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालीफायर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी।

एशियन चैंपियन और 2022 विश्व कप के मेजबान कतर के खिलाफ गोलरहित (0-0) ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम को कोलकाता में दूसरे दौर के अपने पिछले क्वालीफाइंग मैच में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के दौरान जूझना पड़ा था। यहां एक कार्यक्रम में पहुंचे छेत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि इसमें से एक मैच दुशांबे में होगा क्योंकि वे (अफगानिस्तान) अपने घरेलू मैच वहां खेल रहे हैं और फिर ओमान के खिलाफ (मस्कट में) खेलना है। दोनों काफी कड़े और अहम मैच हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा है। अगर हम कतर के खिलाफ वाले प्रदर्शन को दोहराने में सफल रहे तो हम अच्छा कर सकते हैं। हम डरे हुए नहीं हैं।' दूसरे दौर के क्वालीफायर में अब तक जीत दर्ज करने में नाकाम रहे भारत को 14 नवंबर को अफगानिस्तान और 20 नवंबर को ओमान से खेलना है। छेत्री ने कहा कि टीम बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन से खुश नहीं है। टीम अच्छा खेली, लेकिन हमारे स्ट्राइकरों ने कई मौके गंवाए और इसलिए हमने दो अंक गंवा दिए जो हमें नहीं गंवाने चाहिए थे।

मिनर्वा पंजाब का नाम बदला

मोहाली, एएफपी : आइ-लीग के पूर्व चैंपियन मिनर्वा पंजाब एफसी को अब पंजाब फुटबॉल क्लब के नाम से जाना जाएगा। क्लब ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। क्लब के मुताबिक, राउंड ग्लास स्पोर्ट्स प्राि के साथ करार के अनुरूप मिनर्वा पंजाब एफसी को अब पंजाब फुटबॉल क्लब के नाम से जाना जाएगा। क्लब के निदेशक रंजीत बजाज ने कहा, 'आगामी सत्र के लिए सकारात्मकता का भाव और उत्साह बना हुआ है और हम अच्छा प्रदर्शन करने के प्रति आश्वस्त हैं।'

एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने हाल में आइएसएल को देश की शीर्ष लीग के रूप में मान्यता दी है। इस बारे में पूछे जाने पर छेत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने एएफसी के साथ बात की होगी और उम्मीद है कि सभी हितधारक साथ आएंगे, मेरे हिसाब से जितनी अधिक टीमें होंगी, उतना बेहतर होगा। इससे प्रतिस्पर्धी मैचों की संख्या बढ़ेगी और यह खिलाड़ियों के लिए बेहतर है।' छेत्री ने कहा कि टीम प्रयास कर रही है लेकिन अब तक कोच इगोर स्टिमक की रणनीतियों को पूरी तरह अपना नहीं पाई है।

अपनी शक्ति और सहनशक्ति पर काम कर रहे हैं पंघाल

ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना चाहते हैं भारतीय मुक्केबाज

कोलकाता, आइएएनएस : विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने अमित पंघल की नजरें अब टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने पर लगी हैं। पंघाल (52 किलोग्राम) और मनीष कौशिक (63 किग्रा) ही दो ऐसे भारतीय मुक्केबाज हैं, जिन्होंने अब तक अगले साल फरवरी में होने वाले एशिया/ओसेनिया जोन क्वालीफायर्स के लिए क्वालीफाई किया है। यह टूर्नामेंट एक ओलंपिक क्वालीफायर टूर्नामेंट भी हैं।

पंघाल ने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिस पर उन्हें काम करने की जरूरत है। वह अब इंडियन मुक्केबाजी लीग में खेलने और अपने कौशल को बेहतर करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि तैयारियां अच्छी चल रही है। इंडियन मुक्केबाजी लीग में खेलकर मैं अधिक से अधिक अनुभव हासिल करना चाहूंगा। लेकिन, मुख्य चीज क्वालीफायर्स है। भारतीय मुक्केबाज ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में रियो ओलंपिक-2016 में स्वर्ण जीतने वाले उज्बेकिस्तान के शाखोबिदीन जोइरोव से 0-5 से हार का सामना करने के दौरान साफ दिखा था कि उन्हें अपनी ताकत को बेहतर करने की जरूरत है।

पंघाल ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी मुझे अपनी पॉवर पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं पहले 48 किग्रा वर्ग में खेलता था। अब मैंने 52 किग्रा में खेलने का फैसला किया है। ऐसे में मुझे अब और पावर की जरूरत है। उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज काफी मजबूत हैं।

जब नडाल को फुटबॉल और टेनिस में से एक को चुनना पड़ा

फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक हैं स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी

नई दिल्ली, आइएएनएस : द किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर राफेल नडाल को सर्वकालिक महान टेनिस खिलाड़ियों में गिना जाता है। इस स्पेनिश दिग्गज ने सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और दुनियाभर में उसके प्रशंसक हैं। हालांकि, बेहद कम ही लोग यह जानते हैं कि नडाल एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी भी थे और एक समय ऐसा आया था जब उन्हें इन दोनों खेलों में से किसी एक को चुनने के मुश्किल फैसले से भी गुजरना पड़ा था।

सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में नडाल केवल स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर (20) से पीछे हैं। 19 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता नडाल ने सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और इसमें सबसे अधिक फ्रेंच ओपन (12) हैं। उन्होंने इस साल भी दो ग्रैंडस्लैम जीते और उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जल्द ही स्विस दिग्गज की बराबरी कर लेंगे या उनसे आगे भी निकल जाएंगे।

नडाल के लिए हालांकि, चैंपियन बनने का सफर रोमांचक से भरा रहा। 3 जून 1986 को स्पेन के मालोर्का में बिजनेसमैन सिबेस्टियन नडाल के घर जन्मे राफेल को खेल के लिए जुनून विरासत में मिला। नडाल के पिताजी भले ही एक सफल व्यापारी हों, लेकिन उनके दोनों चाचा अपने-अपने खेल के दिग्गज हैं।

टोनी नडाल एक सफल टेनिस कोच हैं जबकि मिगुएल एंजल नडाल एफसी बार्सिलोना और स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए कई मैच खेल चुके हैं। टोनी ने नडाल को तीन वर्ष की उम्र में ही टेनिस से रुबरू कराया। हालांकि, बचपन से राफेल की रुचि टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलों में थी। 12 वर्ष की उम्र में नडाल ने अपने उम्र वर्ग के स्पेनिश और यूरोपियन टेनिस खिताब जीते। इस समय वह फुटबॉल को भी काफी समय दे रहे थे और इससे उनके पिता चिंतित हो गए। पिता को डर था कि खेल के कारण बेटे की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव न पड़े और फिर उन्होंने नडाल से सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए कहा। पिता ने नडाल से कहा कि वह टेनिस या फुटबॉल में से किसी एक को चुने। नडाल ने टेनिस को चुना और वहीं से उनके दमदार करियर की शुरुआत हो गई। एक रोचक तथ्य यह भी है कि नडाल प्राकृतिक रूप से दाएं हाथ का उपयोग करते हैं, लेकिन टोनी के कहने पर उन्होंने बाएं हाथ से टेनिस खेलने का निर्णय लिया। नडाल को अपने पिता के रक्षात्मक रवैये का सामना एक बार फिर करना पड़ा। स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने बेहद कम उम्र में नडाल की प्रतिभा को भांप लिया और 14 वर्ष की उम्र में उन्हें बार्सिलोना आकर ट्रेनिंग जारी रखने का आमंत्रण दिया। पिता को एक बार फिर लगा कि इससे उनके बेटे की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और नडाल को अपने घर पर ही रहकर ट्रेनिंग करनी पड़ी, लेकिन इससे उनकी ट्रेनिंग पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि पिता एक सफल व्यापारी थे और वह खेल से जुड़े अपने बेटे का सारा खर्चा उठाने में कामयाब रहे। इस बीच उन्होंने एक मैच में दिग्गज खिलाड़ी पैट कैश को मात देकर यह साबित कर दिया।

स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल। फाइल फोटो

विविध

सेना में नियुक्ति का झांसा देने वाले गिरोह का सरगना निकला जयप्रकाश

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार को सड़क हादसे में जान गंवाने वाला जयप्रकाश झा सेना में नियुक्ति का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना निकला। बुधवार को सेना और पुलिस के अधिकारी उसके सील मकान की तलाशी लेने पहुंचे। वहां से लेफ्टिनेंट की वर्दी और बिना रैंक लिखी वर्दी, प्रिंटर, नियुक्ति पत्र, कॉल लेटर, ट्रेनिंग की जानकारी सहित वर्तमान व सेवानिवृत्त कर्नल, मेजर स्तर के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर वाले दस्तावेज और कार बरामद हुई। देर शाम पुलिस ने टूटे लैपटॉप को रिपेयर करवाया और डी-कोड किया तो चार जीबी डेटा मिला। इसमें फर्जी अफसर व सैन्य कर्मचारियों की सूची, आइडी कार्ड और कुछ प्रोफॉर्मा मिला। अफसरों के मुताबिक सूची उन लोगों की है, जिन्हें वह फर्जी नियुक्ति पत्र दे रहा था। इसके बाद आर्मी इंटेलिजेंस, आइबी और एटीएस भी जांच में जुट गई हैं।

गौरतलब है कि आर्मी वॉर कॉलेज (महू) में पदस्थ सफाईकर्मी 24 वर्षीय जयप्रकाश झा की कार मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से कर रहा था ठगी

जांच में शामिल कर्नल के मुताबिक अभी जो सूची मिली, वह भृत्य, सर्वेयर, सफाईकर्मी, क्लर्क स्तर के कर्मचारियों की है। यह भी पता चला है कि वह उत्तर प्रदेश और बिहार से युवाओं को भी नौकरी के नाम पर ठग रहा था। एक रजिस्टर मिला है, जिसमें उनसे लिए गए लाखों रुपये की एंट्री दर्ज है।

इसमें न केवल जयप्रकाश बल्कि उसके बेटे और माता-पिता के साथ ही दो साथियों की जान चली गई थी। पत्नी और साली की हालत गंभीर बनी हुई है। सड़क हादसे के बाद पुलिस को पड़ताल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कार में लेफ्टिनेंट की नेम प्लेट भी मिली थी। झा को लेफ्टिनेंट समझ जांच कर रही पुलिस उस वक्त हैरान गई जब महू स्थिति सैन्य छावनी के अफसरों ने यह बताया कि वह लेफ्टिनेंट नहीं, बल्कि सफाईकर्मी था। अफसरों ने उसके पास मिले कार्ड को फर्जी बताया और संदेह जताया कि झा फर्जीवाड़े में लिप्त था। अफसरों ने कार में मिले सामान की छानबीन की तो दो स्टार लगी वर्दी मिली। बुधवार पुलिस अधिकारी और सेना से कर्नल बिजेंद्र सिंह उसके घर पहुंचे और छानबीन की। यहां से एक अलमारी में दो वर्दी मिलीं। पुलिस को पलंग के नीचे एक प्रिंटर भी मिला। सेना के जाली दस्तावेज मिले। पुलिस को पोर्च में एक कार भी मिली।

पिता ने कहा था गौरव की संगत छोड़ दे, तब जयप्रकाश बोला तुम्हें छोड़ दूंगा गौरव को नहीं : सूत्रों के मुताबिक कर्नल स्तर के एक अधिकारी ने मंगलवार रात जयप्रकाश के भाई चंद्रप्रकाश से सेना परिसर में पूछताछ की तो डरते हुए उसने कहा कि भाई के चाल-चलन पर शक था। इतने कम समय में उसने दो गाड़ियां खरीद ली थीं। पिता नूनू झा शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कुछ समय पूर्व जयप्रकाश से कहा था कि 'मुझे तुम्हारा काम समझ में नहीं आ रहा है। तू गौरव (हादसे में मृत सहयोगी) की संगत छोड़ दे। जयप्रकाश नाराज हो गया और कहा मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन गौरव को नहीं छोड़ूंगा।

पायदान पर यात्रा करने की मजबूरी...

हरियाणा के अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर आई जनसेवा एक्सप्रेस के बंद दरवाजे नही खुले तो दो यात्रियों ने एक कपड़े को दरवाजे के हैंडल पर मजबूती से बांध दिया और पायदान पर खड़े हो गए। इन दो यात्रियों ने अपना सामान साथ ही खिड़की पर कपड़े से बांध दिया इसी दौरान ट्रेन चल दी, लेकिन बोगी में बैठे किसी यात्री ने इन दोनो को भीतर लाने की कोशिश तक नहीं की। संदीप कुमार

एजेएल मामले में हुड्डा-वोरा को 6 नवंबर तक की अंतरिम जमानत

जागरण संवाददाता, पंचकूला

पांच-पांच लाख रुपये के मुचलके पर मिली राहत

ईडी के वकील ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मांगा था वक्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) प्लॉट आवंटन प्रकरण में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के बुजुर्ग नेता मोती लाल वोरा को 6 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। पांच-पांच लाख रुपये के मुचलके पर दोनों को यह राहत मिली है।

ईडी ने हुड्डा और वोरा के खिलाफ इसी वर्ष अगस्त में एजेएल प्लॉट आवंटन प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। बुधवार को हुड्डा और वोरा की नियमित जमानत याचिकाएं अदालत में सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गईं। अदालत ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है, जिस पर जवाब के लिए ईडी के वकील एचपीएस वर्मा ने समय मांगा है। हुड्डा और वोरा की तरफ से दलील दी गई कि उन्होंने जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है और जांच के दौरान उनका आचरण पारदर्शी था।

अदालत में हुड्डा और वोरा के साथ चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन बंसल, पलवल के पूर्व विधायक करण दलाल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, रोहतक के विधायक भारत भूषण बतरा भी पहुंचे थे।

गौरतलब है कि एजेएल प्लॉट आवंटन प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की पंचकूला स्थित विशेष अदालत ने हुड्डा और वोरा को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था। पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था। ईडी की जांच में पाया गया है कि हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यह भूखंड पुनः आवंटन की आड़ लेते हुए एजेएल को 1982 की दर (91 रुपये प्रति वर्ग मीटर) और ब्याज के साथ आवंटित कर दिया।

एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुनः आवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। ईडी के मुताबिक, इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपये था, जबकि इसे 69.39 लाख रुपये में आवंटित कर दिया गया था।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फाइल फोटो

आंध्र में फर्जी खबरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश जारी

सीएम जगनमोहन ने अपने पिता के शासन के दौरान स्थगित रखे आदेश को किया बहाल

विपक्षी दलों और मीडिया प्रतिष्ठानों ने सरकार के फैसले की निंदा की

अमरावती, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने दिवंगत पिता के शासनकाल के दौरान 12 साल पहले स्थगित रखे गए विवादास्पद सरकारी आदेश को बहाल करते हुए 'फर्जी, निराधार और मानहानिकारक खबरों' के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बुधवार को आदेश जारी किया। विपक्षी दलों और मीडिया प्रतिष्ठानों ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। भाजपा नेता लंका दिनाकर ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है और सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है।

मुख्यमंत्री के रूप में राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 2007 में जारी किए किया गया आदेश प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सीमित था, लेकिन बुधवार को जारी किया गया सरकारी आदेश सोशल मीडिया के लिए भी है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के कदम उठाए जा सकते हैं। पुराने आदेश में प्रकाशकों और संपादकों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने की जिम्मेदारी सूचना आयुक्त को दी गई थी, लेकिन बुधवार के आदेश में संबंधित विभागों के सचिवों को यह जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी 2007 को जारी किए गए सरकारी आदेश (नंबर 938) को बहाल करने की गत 16 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी। इस फैसले के बारे में सूचना आयुक्त टी विजय कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया में दुर्भावना के साथ फर्जी, निराधार और मानहानिकारक समाचार फैलाकर जानबूझकर सरकार और सरकारी अधिकारियों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद छह जवानों को वीरता पुरस्कार देने की सिफारिश

नई दिल्ली, एएनआइ : जम्मू-कश्मीर में 27 फरवरी को गलती से जिस एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था, उस घटना में शहीद हुए पायलटों और जवानों को वायु सेना ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की सिफारिश की है। यह घटना पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर किए गए एयर स्ट्राइक के अगले दिन हुई थी जब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। इस घटना में स्क्वॉड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ, स्क्वॉड्रन लीडर निनाद मांडवगने, कुमार पांडे, सार्जन्ट विक्रांत सहरावत, सिपाही दीपक पांडे और पंकज कुमार शहीद हो गए थे।

वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक, 'दो पायलटों को वायु सेना मेडल, जबकि चार क्रू मेंबर्स को मेंशन इन डिस्पैचेज से सम्मानित करने की सिफारिश की गई है।' सभी को वॉरटाइम गैलंट्री मेडल से सम्मानित करने की सिफारिश की गई है क्योंकि वे उस दौरान उन्हें दिए गए ऑपरेशनल टास्क को पूरा करने में लगे थे।

बाबा रामदेव से जुड़े आदेश को फेसबुक ने दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक विषयवस्तु को इंटरनेट से पूरी तरह से हटाने का दिया था निर्देश

योग गुरु रामदेव के खिलाफ अपमानजनक विषयवस्तु वाले वीडियो, लिंक और यूआरएल को इंटरनेट से हटाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को फेसबुक ने चुनौती दी है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ इस पर सुनवाई करेगी।

23 अक्टूबर को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने फेसबुक, गूगल व ट्विटर को बाबा रामदेव से जुड़े आपत्तिजनक विषयवस्तु को इंटरनेट से पूरी तरह से हटाने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था कि सिर्फ भारत के दर्शकों के लिए उक्त डाटा को हटाना पर्याप्त नहीं है क्योंकि भारत में रह रहे लोगों तक यह अन्य माध्यम से पहुंच सकता है। पीठ ने कहा था कि सोशल मीडिया वेबसाइट की यह जिम्मेदारी है कि वह पूरी तरह से डाटा को हटाएं न की कुछ हिस्से में। पीठ ने कहा था कि आइटी एक्ट की धारा 79 (3)(ए) के तहत डाटा को हटाना या अक्षम करने का मतलब भारत में रहने वाले यूजर के लिए हटाना या अक्षम करना नहीं है। पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म यह सुनिश्चत करें कि इससे जुड़े लिंक और यूआरएल को भारत के लोगों के लिए ब्लॉक किया जाए।

उक्त अपमानजनक वीडियो बाबा रामदेव के जीवन पर लिखी गई किताब के संबंध में है हाई कोर्ट ने सितंबर 2018 में इसे डिलीट करने का आदेश दिया था। 29 सितंबर को दिए गए फैसले में हाई कोर्ट ने 'गॉडमैन टू टायकून' नाम की किताब पर अपमानजनक तथ्यों को हटाए बिना प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी।

मौसम विशेष

दिल्ली व आस पास के क्षेत्रों में धुआं धुंध व हल्की हवाओं के कारण प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर बना रहेगा। राजस्थान के पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। पंजाब और हरियाणा में धुंध व बादलों के साथ मौसम आरामदयक होगा। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी।

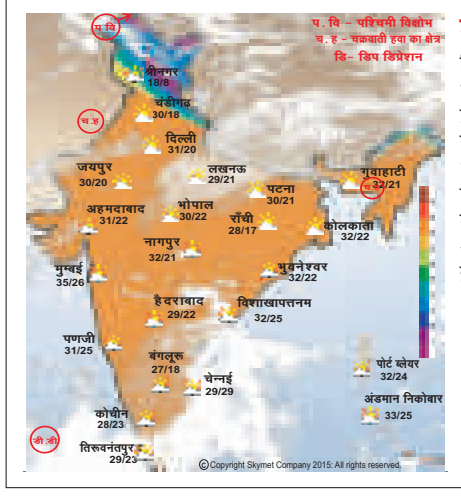

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/25/आंबा	अहमदाबाद	34/25/स
कोलकाता	32/22/आंबा	बड़ोदा	34/24/स
चेन्नई	31/23/व	नागपुर	32/21/आंबा
हैदराबाद	28/21/व	इन्दौर	30/22/आंबा
बंगलूरु	28/19/आंबा	रांची	30/19/आंबा
त्रिवेन्द्रम	30/24/आंबा	पटना	33/22/आंबा
गुवाहाटी	28/22/व	जमशेदपुर	32/23/स
जगटोक	08/-2/व	पुणे	30/21/व

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

16

गुरुवार 31 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई

1984 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश देना इस घटना की मुख्य वजह मानी जाती है। उन्हें एक असरदार और सख्त प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है।

7 बिलियन-डे मनाया गया

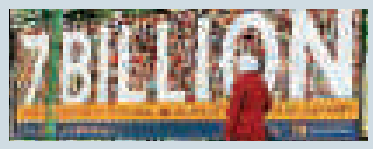

2000 में आज के दिन को 7 बिलियन डे के तौर पर मनाया गया था। इस दिन दुनिया की आबादी 7 अरब हो गई थी। वर्तमान में दुनिया की आबादी सात अरब 53 करोड़ है।

भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप के निर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल

भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म 1875 में आज ही गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने देश की 564 रियासतों को एकता के सूत्र में बांध कर अखंड भारत की रचना की थी। 1917 से 1924 तक अहमदनगर के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में सेवा दी। 1924 से 1928 तक वह इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सर्विस की नींव रखी। 1991 में भरत रत्न से सम्मानित हुए। 15 दिसंबर, 1950 को 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए।

इधर-उधर की

जिंबाब्वे में युवती ने मगरमच्छ से लड़ बचाई सहेली की जान

हरारे, आइएएनएस : घटना जिंबाब्वे के सिंडरेला गांव की है। स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल की रेबेका मुनकोंबे अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहा रही थी। तभी एक बड़े मगरमच्छ ने उनकी नौ वर्षीय सहेली को जबड़े में जकड़ लिया। वह बीच नदी में जाने को मुड़ा ही था कि सहेली की चीख सुनकर रेबेका लपककर मगरमच्छ की पीठ पर जा चढ़ी। सहेली को मगरमच्छ के जबड़े से निकालने के लिए उसकी आंखों पर अपने हाथों से चोट करने लगी। ताबड़तोड़ वार और अप्रत्याशित हमले से मगरमच्छ घबरा गया। उसने मुंह खोल लिया और लाटोया उसके चंगुल से बाहर निकली। लाटोया को लेकर तैरते हुए रेबेका नदी के बाहर आ गई। छोटी-सी लड़की के बड़े से साहस के आगे मगरमच्छ की दोबारा मुड़कर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। घायल लाटोया का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में रेबेका को खरोंच तक नहीं आई। उसकी बहादुरी की खबर मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है।

शोध अनुसंधान

विटामिन बी3 की उच्च खुराक से दृष्टिहीनता का खतरा

शोधकर्ताओं ने ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) नियासिन सप्लीमेंट की उच्च खुराक का संबंध दृष्टिहीनता से पाया है। नियासिन को विटामिन बी3 के तौर पर भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्राल कम करने में होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस सप्लीमेंट के चलते नियासिन-इंड्यूस्ट सिस्टॉइड मैक्यूलोपैथी नामक दुर्लभ विषाक्त प्रतिक्रिया हो सकती है। यह रेटिना में एक तरह की सूजन है। यह निष्कर्ष धुंधला दिखने की शिकायत करने वाले रोगियों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क आई एंड ईयर इंफर्मरी के शोधकर्ता रिचर्ड रोसेन ने कहा, 'इस अध्ययन से जाहिर होता है कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली ओवर-द-काउंटर दवाओं की ज्यादा खुराक कितनी खतरनाक हो सकती है।' -आइएएनएस

बालों के बढ़ने पर इलाज के प्रभाव की हो सकती है जांच

बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए ना जाने कितने उपचार करते हैं। लेकिन इस तरह के उपचार के प्रभाव का आकलन ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे ही लोगों के लिए शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विधि खोज निकाली है, जो बालों के बढ़ने पर विभिन्न इलाज के प्रभाव की जांच करने में उपयोगी हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, मैग्नेटोएंसेफलोग्राम (एमईजी) के उपयोग से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का खाका तैयार किया जा सकता है। इसके जरिये सिर के विभिन्न हिस्सों में हेयर फोलिकल्स की गतिविधि को मापा जा सकता है। शोधकर्ता शिराज खान ने कहा, 'इस विधि से हेयर फोलिकल्स की सेहत का अनुमान लग सकता है और बाल झड़ने का उपचार हो सकता है।' -एएनआइ

शरीर को उष्मा प्रदान करते हैं ब्राउन फैट सेल्स

कोपेनहेगन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने पहली बार एक वयस्क मनुष्य के ह्वाइट एंड ब्राउन फैट सेल्स से निकलने वाले सभी प्रकार के प्रोटीन का खाका तैयार किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ह्वाइट एंड ब्राउन फैट हमारे शरीर को ऊष्मा देने के साथ-साथ भोजन की कमी को भी पूरा करते हैं। साथ ही शरीर के हर हिस्से को सिग्नल भेजकर उसकी जरूरतों को पूरा करने में योगदान देते हैं।

ह्वाइट फैट हमारे आमाशय, कुल्हे और जंघा पर ऊर्जा भंडार के रूप में रहता है, जिसे हमारा शरीर भोजन की कमी होने पर इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार ब्राउन फैट तंत्रिका प्रणाली, रीढ़, कंठ के आसपास और किडनी के समीप रहता है। यह ऊष्मा प्रदान करता है।

वैज्ञानिकों का यह अध्ययन सेल मेटाबोलिज्म में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि ब्राउन फैट में 100 से अधिक ऐसे प्रोटीन स्रावित (निकलते) होते हैं, जो ह्वाइट फैट से नहीं निकलते।

अध्ययन

- ह्वाइट एंड ब्राउन फैट सेल्स से निकलने वाले प्रोटीन का खाका तैयार कर वैज्ञानिकों ने किया दावा
- कहा- ये सेल्स शरीर को सिग्नल भेजकर उसकी जरूरत को भी करते हैं पूरा

ह्वाइट फैट शरीर के ऊतकों को मजबूत और नरम बनाता है। प्रतीकात्मक

इस अध्ययन के शोधकर्ताओं में डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के शोधार्थी भी शामिल थे। शोधकर्ताओं ने कहा, 'ब्राउन फैट प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित कर उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जबकि ह्वाइट फैट से निकलने वाले प्रोटीन ऊतकों को मजबूत और नरम बनाते हैं।'

शिशुओं के शरीर में होता है ज्यादा ब्राउन फैट : अध्ययन में कहा गया है कि ब्राउन फैट की मदद से ही कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को खर्च या बर्न कर सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा, ' शिशुओं के शरीर में एक वयस्क की तुलना में ज्यादा ब्राउन फैट होता है। इसकी मदद से वे अपने शरीर को गर्म रखते हैं।'

दावा, हल की बड़ी पहेली : कोपेहेगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक कैमिला स्कील ने कहा, 'ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्राउन फैट के बारे में किसी ने इतने विस्तार से अध्ययन किया है। हमने उन सभी प्रोटीनों की मैपिंग की है जो वसा कोशिकाओं (फैट सेल्स) से स्रावित होते हैं और जिनका उपयोग वे अन्य कोशिकाओं के साथ संचार करने के लिए करते हैं ' शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने ब्राउन फैट के बनने की एक बहुत बड़ी पहेली को हल करने में सफलता हासिल की है।

कोशिकाओं के विकास में करते हैं मदद : स्कील ने कहा, ' एक प्रोटीन जो ब्राउन फैट से निकलता है, वह नए ब्राउन फैट सेल्स के विकास में मदद करता है। साथ ही नवजात कोशिकाओं को ऊष्मा भी प्रदान करता है।' अब शोधकर्ता यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोटीन शरीर के अन्य हिस्सों के साथ कैसे संवाद स्थापित करते हैं।

भारत में मां और शिशु के स्वास्थ्य में हो रहा सुधार

अध्ययन ▶ सामुदायिक स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों ने बदले हालात

फिर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है असमानता

नई दिल्ली, आइएएनएस: भारत, इथोपिया और नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मां और नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य सुधार करने में सफल रहे हैं, लेकिन असमानताएं अब भी बरकरार हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां देखभाल की अच्छी सुविधाएं हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया है। यह अध्ययन कनाडाई मेडिकल एसोसिएशन जर्नल (सीएमएजे) में प्रकाशित हुआ है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता का मतलब है कि ग्रामीणों क्षेत्रों में और अधिक काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रमों को उन गरीब परिवारों तक भी पहुंचाने की जरूरत है जो मां और नवजात की मृत्यु का सबसे बड़ा बोझ वहन करते हैं।

ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में भारतीय मूल की शोधकर्ता तान्या मर्चेंट ने कहा, 'हमारे निष्कर्ष आशावादी और निराशावादी दोनों तरह की व्याख्या करते हैं। सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के परिवारों ने इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ जरूर उठाया है, लेकिन फिर भी असमानताएं बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावों का आकलन करने के लिए शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने ग्रामीण भारत, इथोपिया और नाइजीरिया में मां और नवजात शिशुओं के आठ आवश्यक स्वास्थ्य संकेतकों का अध्ययन किया। इन संकेतकों में प्रसवपूर्व और प्रसव के बाद की देखभाल, जन्म के समय की सुविधाएं, हाइजीन और स्तनपान आदि शामिल थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अब भी बनी हुई हैं चिंता का कारण। प्रतीकात्मक

बदल रही है स्थिति : अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि सुविधाओं की बात की जाए तो इथोपिया और भारत के कुछ राज्यों में सुधार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 के मुकाबले 2015 में मातृत्व संबंधी कई सुविधाएं बेतहर हुई हैं।

सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत : शोधकर्ताओं ने कहा, 'सुविधाएं बेहतर होने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। इस अध्ययन के मुख्य लेखक तान्या मर्चेंट ने कहा, 'मां और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार के लिए न केवल संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता होती है बल्कि देखभाल करने वाले लोगों के व्यवहार में सुधार जरूरी होता है।

खेल प्रदर्शन में सुधार कर सकती है कॉफी

लंदन, आइएएनएस : कॉफी पीने से पुरुषों और महिलाओं दोनों के खेल प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। न्यूट्रीएंट्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के लिए ब्रिटेन की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 38 प्रतिभागियों (19 पुरुष, 19 महिलाएं) को चुना और उनकी शारीरिक गतिविधियों का आकलन किया।

इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि कैफीनयुक्त कॉफी पीने से प्रतिभागियों की साइकिल चलाने की गति में सुधार हुआ। कॉफी पीने के बाद पांच किलोमीटर साइकलिंग के समय में पुरुषों और महिलाओं के प्रदर्शन में क्रमशः लगभग नौ और छह सेकंड का सुधार देखने को मिला।

शोधकर्ताओं ने कहा, 'अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों कॉफी के सेवन के बाद समान प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कैफीन का सेवन बेहतर साबित हो सकता है।' कॉफी के फायदों पर प्रकाश डालते हुए शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि इसका सेवन बढ़ते शरीर के लिए अच्छा होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक इस विषय पर किए गए अधिकांश शोध केवल सूखे कैफीन और पुरुषों पर केंद्रित रहे हैं।

फिल्म रिव्यू

मुहब्बत चेहरे से नहीं, दिल से करने का संदेश

उजड़ा चमन

मुख्य कलाकार : सनी सिंह, मानवी गागरू, सौरभ शुक्ला, अतुल कुमार, गुशा कपूर, गगन अरोड़ा, शारिब हाशमी

निर्देशक : अभिषेक पाठक

अवधि : 2 घंटे

क ई दक्षिण भारतीय फिल्मों की हिंदी रीमेक बन रही है। इसी फेहरिस्त में शामिल है 'उजड़ा चमन'। यह फिल्म 2017 में रिलीज कन्नड़ फिल्म 'ओंडू मोट्टेया काठे' की हिंदी रीमेक है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शॉर्ट फिल्म 'बूंद' का निर्देशन कर चुके निर्देशक अभिषेक पाठक की यह पहली फीचर फिल्म है।

कहानी शुरू होती है दिल्ली के राजौरी गार्डन में रहने वाले कोहली परिवार से। परिवार में माता-पिता और दो बेटे हैं। बड़ा बेटा चमन कोहली (सनी सिंह) दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर है। 30 साल की उम्र में ही उसके बाल झड़ने लगे हैं। यह समस्या आनुवंशिक है। चमन के दादाजी को यही समस्या थी। चमन के पिता शशि कोहली (अतुल कुमार) और भाई गोल्डी (गगन अरोड़ा) के बाल अच्छे खासे हैं। मां सुषमा कोहली (ग्रुशा कपूर) के लिए उनका बेटा सबसे सुंदर है। चमन के जीवन की दो समस्याएं हैं। एक, उसके बाल कम हैं और दूसरा, गंजेपन की वजह से शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही।

शादी के कई प्रस्ताव गंजेपन की वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं। गुरुजी (सौरभ शुक्ला) ने कुंडली देखकर बता दिया है कि चमन की शादी 31 साल से पहले नहीं हुई तो वह आजीवन कुंआरा रह जाएगा। कॉलेज में विद्यार्थी चमन को टकला, उजड़ा चमन कहकर चिढ़ाते हैं। एक दिन डेटिंग एप पर चमन को मैच मिल जाता है। अप्सरा बत्रा (मानवी गागरू) और चमन जब मिलते हैं, तब अप्सरा को पता चलता है कि चमन गंजा है और चमन को पता चलता है कि अप्सरा मोटी है। क्या वे एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, कहानी इसी पर है।

निर्देशक-निर्माता अभिषेक पाठक की फिल्म को बनाने की नीयत अच्छी है। खूबसूरती को अक्सर घने बालों से जोड़कर देखा जाता है। फिल्म बाहरी खूबसूरती की बजाय इंसान की अंदरूनी खूबसूरती को देखने का संदेश देती है। पहला हिस्सा मजेदार है, जो शीर्षक को दर्शाता है। दूसरा हिस्सा गंजेपन की समस्या से हटकर मोटापे पर केंद्रित हो जाता है। गंजापन केवल शादी में ही नहीं, बल्कि और भी कई जगहों पर व्यक्ति को हीनभावना का शिकार बनाता है। उनसे जुड़ी दूसरी समस्याओं को भी निर्देशक कहानी में शामिल कर सकते थे। फिल्म में कुछ चीजें खटकती हैं, जैसे-अस्पताल में भर्ती अप्सरा को चमन द्वारा अस्पताल के बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाना या फिर स्टूडेंट्स का अपने प्रोफेसर का खुलेआम मजाक बनाना।

यूथ फिल्में करने वाले सनी सिंह 30 साल के चमन के किरदार में जंचे हैं। चमन के पिता के किरदार में अतुल कुमार और मां बनीं ग्रुशा कपूर का काम बेहतरीन है। कई दृश्यों में अतुल कुमार सनी सिंह पर भारी पड़ते हैं। मानवी गागरू अप्सरा के किरदार में सहज लगी हैं। शारिब हाशमी को स्पेस कम मिला है।

सौरभ शुक्ला ने गेस्ट अपीयरेंस में अच्छा काम किया है। दानिश सिंह का स्क्रीनप्ले और संवाद जैसे, 'कितना अजीब है कि दिलों की बात करता है जमाना पर मुहब्बत आज भी चेहरों से शुरू होती है...', 'प्रॉब्लम टकला बोलकर चिढ़ाने से है।' बाहरी खूबसूरती देखकर इंसान का आकलन करने वालों पर कटाक्ष करते हैं। फिल्म के गाने 'चांद निकला...', 'ओ बंदेया...' कहानी की सिचुएशन पर सटीक लगते हैं।

-प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

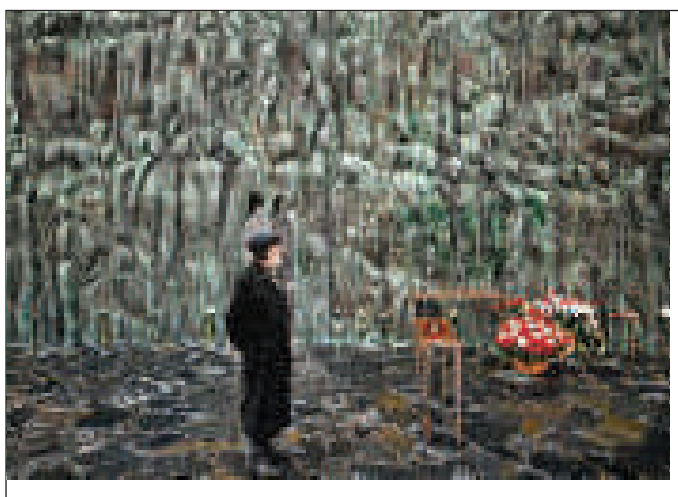

राजनीतिक दमन की याद दिलाती है वॉल ऑफ ग्रीफ

मास्को में वॉल ऑफ ग्रीफ, जिसे वॉल ऑफ सॉरो भी कहा जाता है, ऐसा स्मारक है जो सोवियत संघ में 1920 से 1950 तक स्टालिन शासन के दौरान दमन और राजनीतिक उत्पीड़न की याद दिलाता है। रूस में 30 अक्टूबर को राजनीतिक पीड़ितों के स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग यहां आकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि स्टालिन के शासनकाल के दौरान करीब साढ़े सात लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2014 में स्मारक के निर्माण का आदेश दिया। 30 अक्टूबर 2017 को इस स्मारक का अनावरण किया गया था। एएफपी

चॉकलेट से बनाई ड्रेस

दुनिया में सर्वाधिक पसंदीदा चॉकलेट के लिए अक्सर कुछ मीठा हो जाए कि पंक्तियां आपने सुनी अथवा कही होंगी। आपसी रिश्तों में मिठास घोलने के लिए यूं तो फरवरी में चॉकलेट डे भी मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि चॉकलेट की ड्रेस भी बनाई जा सकती है। जी हां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रतिवर्ष चॉकलेट फेयर का आयोजन किया जाता है। इस फेयर का प्रमुख आकर्षण है कि आर्टिस्ट स्वादिष्ट चॉकलेट से बेहद खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करते हैं। इतना ही नहीं, इन ड्रेसों को पहना भी जा सकता है। मॉडल्स ने चॉकलेट की ड्रेस पहनकर जब कैटवॉक किया तो लोग वाह-वाह कह उठे। एपी

स्क्रीन शॉट

'गिन्नी वेड्स सनी' के सेट पर यामी ने दी साफ-सफाई की नसीहत

सेट पर कलाकार अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काम के बीच एक-दूसरे से हंसी-मजाक करना, टांग खिंचाई करना आम बात है। ऐसा ही हंसी-मजाक यामी गौतम के साथ करते थे अभिनेता विक्रांत मेसी।

विक्रांत और यामी फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी' में एक साथ नजर आएंगे। यामी साफ-सफाई और हाइजीन का खास ख्याल रखती हैं। यामी का कहना है कि किसी भी इंसान के लुक्स से ज्यादा उसकी शारीरिक साफ-सफाई और हाइजीन ज्यादा मायने रखती है। वह कहती हैं कि मेरी इस आदत के बारे में मेरे को-एक्टर्स को पता है। ऐसे में जैसे ही मैं सेट पर पहुंचती थी, विक्रांत तुरंत किसी से कहकर हाथों के लिए सैनेटाइजर मंगवा लेते थे। यामी का कहना है कि जब वह उनसे पूछती थीं कि सैनेटाइजर मुझे देखकर लगा रहे हो, तो विक्रांत हंस कर कहते थे कि नहीं, मैं भी सफाई पसंद हूं। यामी का कहना है कि साफ-सफाई को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही अनुशासित हूं। मेरे लिए बेसिक हाइजीन ज्यादा मायने रखती है बजाय इसके कि इंसान कौन से बैग, जूते या चश्मे इस्तेमाल कर रहा है। यामी कहती हैं कि सेट पर फ्रेम में सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन फ्रेम के बाहर चीजें बहुत गंदी होती हैं। मेरी हमेशा से यह आदत रही है कि अगर मुझे आसपास कोई गंदगी नजर आती है, तो मैं बोल देती हूं। सेट पर जो चीजें यहां-वहां गिरी होती हैं उन्हें सफाई वालों को उठाने के लिए कह देती हूं और अगर वे नहीं उठा रहे हैं, तो मैं खुद साफ कर देती हूं।

यामी का कहना है कि साफ-सफाई अच्छी आदत है, सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए सेट पर क्रू मेंबर्स भी इस बात को समझते हुए खुद को इसी परिवेश में ढाल लेते हैं, जो अच्छी बात है।

अब 'सरकार की सेवा में' का निर्देशन करेंगे श्रेयस तलपड़े

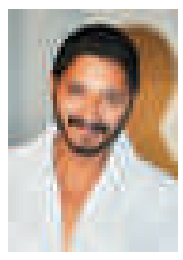

फिल्म 'पोस्टर ब्वॉयज' से अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने निर्देशन में कदम रखा था। सनी देयोल, बॉबी देयोल अभिनीत यह फिल्म इसी नाम से बनी मराठी फिल्म का हिंदी रीमेक थी। अब श्रेयस ने बतौर निर्देशक अपनी दूसरी फिल्म 'सरकार की सेवा में' निर्देशित करने का एलान किया है। सत्य घटना से प्रेरित यह फिल्म हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ सामाजिक संदेश भी देगी। कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर की है। फिल्म में श्रेयस अभिनय भी करेंगे। उनके अलावा सुधीर पांडे, लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री श्रद्धा जायसवाल, मुन्नाभाई फेम अनिल चरणजीत, बिजेंद्र काला, नवोदित कलाकार श्रेयस पांडे और निखिल मेहता अहम भूमिका में होंगे। फिल्म की शूटिंग नवंबर से आरंभ होगी। फिल्म की शूटिंग देश के अलग-अलग छोटे शहरों में की जाएगी।

28 फरवरी को रिलीज होगी 'गुलाबो सिताबो'

अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म 'गुलाबो सिताबो' तय समय से पहले रिलीज होगी। पहले फिल्म को अगले साल 20 अप्रैल को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। अब उसकी तारीख को पीछे खिसका दिया गया है। फिल्म अब 28 फरवरी को रिलीज होगी। उसके साथ ही आयुष्मान खुराना का लुक भी पहली बार सामने आया है। इसमें वह अमिताभ बच्चन के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। शुजीत सरकार द्वारा निर्देशित यह फिल्म किरायेदार और मकान मालिक के संबंधों के इर्द-गिर्द है। वहीं सैफ अली खान अभिनीत और प्रोड्यूस फिल्म 'जवानी जानेमन' की तारीख आगे खिसकने की खबर है। यह फिल्म पिता-पुत्री के संबंधों पर है।

'पागल' का नाम अब हुआ 'ये साली आशिकी'

बॉलीवुड में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने न केवल फिल्मों के गानों, कहानियों और संवादों, बल्कि फिल्मों के शीर्षक पर भी तेज नजर रखना शुरू कर दिया है। ऐसे में पिछले दिनों कंगना रनोट की फिल्म 'जजमेंटल है क्या' की खूब चर्चा हुई थी, जिसका पहले नाम 'मेंटल है क्या' था। अब फिल्म 'पागल'

को लेकर सेंसर बोर्ड ने सवाल खड़े किए और प्रोड्यूसर ने बोर्ड की आपत्ति के बाद इसका नाम 'ये साली आशिकी' कर दिया है। फिल्म के निर्माता जयंतीलाल गड़ा हैं और इसे निर्देशित किया है चिराग रूपारेल ने। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। गड़ा के अनुसार फिल्म का शीर्षक पहले 'पागल' था, लेकिन सेंसर बोर्ड को इसे लेकर आपत्ति थी। गड़ा ने बताया कि फिल्म के शीर्षक को लेकर बोर्ड का कहना था कि इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। निर्माता ने जानकारी दी कि फिल्म के ट्रेलर को यू/ए सर्टिफिकेट जारी किया गया है और फिल्म को बिना किसी काटछांट के 'ए' सर्टिफिकेट दिया गया है। इस फिल्म के साथ एक और दिलचस्प बात यह है कि इससे बॉलीवुड के लोकप्रिय खलनायक रहे अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी डेब्यू कर रहे हैं।

चिंताजनक

अमेरिकी संस्था 'क्लाइमेट सेंट्रल' ने एशियाई देशों पर किया अध्ययन, जलवायु परिवर्तन के खतरों पर प्रति किया आगाह, कहा- समय की जरूरत है ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती

भारत में हर साल 3 .6 करोड़ लोग होंगे बाढ़ से प्रभावित

नई दिल्ली, प्रेट्र : ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती नहीं होने की सूरत में भारत में 2050 तक करीब 3.6 करोड़ लोगों के हर साल बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। इसमें हमारे जीवनकाल में शहरों, अर्थव्यवस्थाओं और तटरेखाओं को नए आकार में ढाल सकने के जलवायु परिवर्तन के सामर्थ्य को दर्शाया गया है। साथ ही आगाह किया गया है कि 2100 तक समुद्र में जलस्तर बढ़ने के कारण 4.4 करोड़ लोगों के हर साल बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं।

छह देशों पर ज्यादा खतरा : अमेरिकी एनजीओ 'क्लाइमेट सेंट्रल' की तरफ से किए गए इस अध्ययन में कहा गया कि छह एशियाई देशों - भारत, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाइलैंड में 2050 तक हर साल तटीय बाढ़ आने का खतरा होगा। एनजीओ ने एक बयान में कहा कि ये परिणाम क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा विकसित नए डिजिटल एलिवेशन मॉडल 'कोस्टल डीईएम' पर आधारित हैं। अध्ययन के मुताबिक, 2100 तक दो और देश-जापान और फिलीपींस में भी हर साल बाढ़ आ सकती है, जहां 2.2 करोड़ लोगों के इसके जद में आने का खतरा होगा।

असम में इस साल अक्टूबर में आई बाढ़ के कारण कई गांवों से लोगों को पलायन करना पड़ा था। एएनआइ

जलवायु की चुनौतियां: 'क्लाइमेट सेंट्रल' में वरिष्ठ वैज्ञानिक और इस अध्ययन के मुख्य लेखक स्कॉट कुलप ने कहा, 'ये आकलन दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक रूप से हमारे जीवन काल में ही शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, समुद्र तटों का आकार पूरी तरह बदल सकता है।' उन्होंने कहा कि अब ज्वार भी सतह से कई फीट ऊंचे उठने लगे हैं। ये ज्वार उन निचले इलाकों के लोगों के लिए चिंता का विषय हैं, जो समुद्री तटों के आसपास बसे हुए हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती स्वयं की रक्षा करने के साथ-साथ यह भी है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए और कैसे समुद्र के तटों के आकार को पूर्ववत बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि समुद्र में हल्के ज्वार आने से तटों का कटाव तो होता ही है, साथ ही इन इलाकों में पानी भर जाता है और लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

करने होंगे अन्य उपाय: इस अध्ययन बताया गया है कि कार्बन उत्सर्जन में मामूली कटौती होने के बाद भी इस सदी के अंत तक वैश्विक रूप से 4.20 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसलिए हमें जलवायु के खतरों से निपटने के लिए अन्य उपायों पर भी काम करना होगा।